ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

निर्णायक दौर में जाते चुनाव

लोकसभा चुनाव अब निर्णायक दौर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इस दौड़ में शामिल होता दिखाई पड़ रहा है। हद यह हो गई है कि दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि उनको ही बहुमत मिलेगा। चुनाव प्रचार में दोनों पक्ष जिस प्रकार जीत का दावा कर रहे हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कांटे की लड़ाई हो रही है मगर जीत-हार का फैसला करने वाले मतदाता होते हैं। लोकतंत्र में मतदाता स्वयंभू होता है। यह अधिकार उसे सदियों की गुलामी के बाद मिला है। 200 वर्ष तक अंग्रेजों के शासन में रहने वाले भारतीय लोगों के दिलों में महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता की ज्वाला धधकाई थी उसी का परिणाम है कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार मिला है। लोकतंत्र में मतदाता स्वयंभू सम्राट माना जाता है क्योंकि उसके एक वोट की ताकत से ही सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मतदाताओं के रुख पर ही चुनाव परिणाम निर्भर करते हैं। भारत के चुनावी इतिहास में हमने सब प्रकार के दौर देखे हैं। वह दौर भी देखा है जब सत्ता पर काबिज पार्टी को पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि दो-तिहाई बहुमत तक मिला हो और वह दौर भी देखा है जब विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी को पटखनी देकर पूर्ण बहुमत ले गया हो।

वर्तमान चुनाव में जो लड़ाई हो रही है वह साधारण लड़ाई नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस समेत 27 राजनीतिक दलों का गठबंधन बना हुआ है जिसे इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है। इस गठबंधन में अधिसंख्य बलशाली क्षेत्रीय दल शामिल हैं जैसे कि दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। इनके अलावा जो अन्य पार्टियां शामिल हैं वे भी अपने-अपने राज्यों में मजबूत मानी जाती हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी। बेशक यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के दल आपस में ही एक-दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं परंतु यह उनका नीतिगत फैसला भी हो सकता है क्योंकि राज्य में पिछले चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में धमाकेदार प्रवेश हुआ था। भाजपा राज्य की 42 सीटों में से 18 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी की कोशिश यह है कि इस बार भाजपा की ताकत कम की जाए इसी वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन के सदस्य दलों कांग्रेस पार्टी व मार्क्सवादी पार्टी तथा अन्य वामपंथी पार्टियों के साथ राज्य में गठबंधन करने के बावजूद उनका मुकाबला करना बेहतर समझा।

भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस समेत 27 राजनीतिक दलों का गठबंधन बना हुआ है जिसे इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है। इस गठबंधन में अधिसंख्य बलशाली क्षेत्रीय दल शामिल हैं जैसे कि दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। इनके अलावा जो अन्य पार्टियां शामिल हैं वे भी अपने-अपने राज्यों में मजबूत मानी जाती हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी। बेशक यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के दल आपस में ही एक-दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं परंतु यह उनका नीतिगत फैसला भी हो सकता है क्योंकि राज्य में पिछले चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में धमाकेदार प्रवेश हुआ था।

राजनीति में शतरंजी चालें चली जाती हैं। सत्ताधारी भाजपा ने भी इसका तोड़ निकालते हुए बिहार में नीतीश बाबू के जनता दल-यू से दोबारा गठबंधन करके इंडिया गठबंधन के सामने कड़ी चुनौती पेश करने का प्रयास किया है। ऐसा ही हम केरल प्रदेश में भी देख रहे हैं जहां वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस आमने-सामने एक-दूसरे का मुकाबला कर रही हैं। यह सब शतरंज की चालें केवल भाजपा को बहुमत से दूर रखने के लिए ही चली जा रही हैं मगर भाजपा जिस प्रकार से अपनी गोटियां बढ़ा रही है उसका तोड़ निकालना भी इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भाजपा का पूरा चुनाव प्रचार टिका हुआ है। उनकी गारंटियां और जनकल्याणकारी कार्यक्रम जनता में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। इसके साथ ही हिंदुत्व भी भाजपा के प्रचार के केंद्र में रहता है जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर निर्भर कर रहा है जिसमें पांच गारंटियां दी गई हैं और महंगाई व बेरोजगारी को समाप्त करने के विभिन्न रास्ते सुझाए गए हैं। देखना केवल यह होगा कि आम मतदाता इन दोनों पक्षों में से किस पक्ष को अपनी वरीयता पर रखता है और मतदान के दिन अपना बटन ईवीएम मशीन में दबाता है। मगर यह भी निश्चित है कि भारत के बुद्धिमान मतदाताओं को कोई भी पार्टी या गठबंधन मूर्ख नहीं बना सकता।

भारत का चुनावी इतिहास गवाह है कि मौका पड़ने पर इस देश के मतदाताओं ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर जो भी फैसला दिया वह समय की कसौटी पर खरा ना उतरा हो ऐसा नहीं माना जा सकता। भारत के मतदाता भूल सुधार करने में भी देरी नहीं लगाते हैं। यह भी उनकी खूबी है। 1977 और 1980 के चुनाव इस बात के प्रमाण हैं जब जनता ने पहले जनता पार्टी को बहुमत देकर इंदिरा गांधी को हरा दिया और इसके 2 साल बाद ही जनता पार्टी को हराकर इंदिरा जी को पुन: गद्दी पर बैठा दिया। मौजूदा चुनाव हमें जिस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसमें देश को मतदाताओं की बुद्धिमत्ता पर ही भरोसा करना बुद्धिमानी होगी।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

और बिना Mother`s Day के भी...

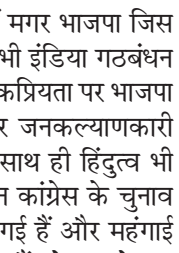

9 महीने सह अपार कष्ट मां तूने मुझे इस दुनिया में लाया,
छोड़ अपनी इच्छाओं को तूने दिन-रात मुझ पर लगाया,
डगमगाया कभी हौसला तो तूने साहस का दीप जलाया,
जीवन की प्रत्येक सच्चाई को मां तूने बड़े सहज तरीके से बताया,
मां कोशिश है आपके हर दिन को इसी तरह विशेष बनाएं,
और बिना Mother's day के भी हम आपके प्रति अपने सभी फर्ज निभाएं!!

गीता पाढा

दुर्घटनाग्रस्त वाहन से बरामद किए 7 करोड़ रुपये

अमरावती (आंध्र प्रदेश), (भाषा): आंध्र प्रदेश पुलिस ने शनिवार को पूर्वी गोदावरी जिले में एक टोल नाका के पास दुर्घटनाग्रस्त एक हल्के वाणिज्यिक वाहन से सात करोड़ रुपये नकद बरामद किए।

कोव्वुर उप-विभागीय पुलिस अधिकारी के सीएच रामा राव ने कहा कि नाल्लाजेर्ला मंडल में वीरावल्ली टोल नाका के पास एक ट्रक ने हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गया और उससे रासायनिक चूने की बोरियों के नीचे छिपाई गई नकदी मिली।

राव ने कहा-नकदी से लदा वाहन हैदराबाद के नचाराम से आया था और मंडपेटा की ओर जा रहा था। नकदी से भरे बक्शे रासायनिक चूने की बोरियों के बीच फंसे हुए थे। सात बक्से थे और प्रत्येक बक्से में एक करोड़ रुपये थे।

वाहन का चालक के वीरभद्र राव का एक पैर फ्रैक्चर हो गया और उसकी एक आंख में चोट लगी है।

ओडिशा में भाजपा और बीजद अंदर से एक

ओडिशा में भले ही भाजपा और बीजू जनता दल का चुनाव पूर्व जाहिर तौर पर गठबंधन नहीं हो पाया हो, पर खबर पक्की है कि अंदरखाने से दोनों दल कांग्रेस के खिलाफ मिल कर चुनाव लड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजद के शीर्ष नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केवल विधानसभा क्षेत्रों में ही अपनी चुनावी सभाओं का फोकस रख रहे हैं। शायद यही वजह है जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं वहां नवीन पटनायक अपने अधिकृत प्रत्याशियों के ही चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे। जैसे केंद्रपाड़ा से भाजपा के जय पांडा, पुरी से संबित पात्रा, संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वहीं सुंदरगढ़ से जुएल ओराव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, पर नवीन पटनायक की यहां जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

इन चुनावों में पटनायक करीबी पांडियन के सौजन्य से भाजपा और बीजद के बीच गठबंधन का मसौदा तय हो चुका था, पर नवीन पटनायक को ओडिशा के जमीनी सर्वे में यह पता चला कि 'अगर बीजद और भाजपा का गठबंधन होता है तो इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।' सो, एक फार्मूला बना कि लोकसभा में भाजपा 'लीड' करेगी और अंदरखाने से उसे बीजद 'सपोर्ट' करेगी वहीं विधानसभा का चुनाव पूरी तरह बीजद के हिस्से में रहेगा। भाजपा का अपना सर्वे बता रहा है कि अगर इस 'फ्रेंडली फाइट' का ग्राफ ठीक से परवान चढ़ा तो भाजपा ओडिशा की 21 में से 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करा सकती है।

क्या है भाजपा का 'कोड ब्ल्यू'

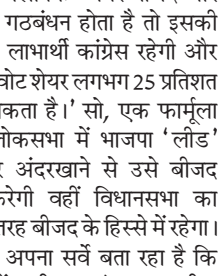

भाजपा ने इन चुनावों में ऐसी 18 प्रमुख सीटों को चिन्हित किया है जहां येन-केन प्रकारेण किसी भी तरह पार्टी उम्मीदवार का जीतना जरूरी है। इन 18 सीटों को 'कोड ब्ल्यू' का नाम दिया गया है। भले ही इन 18 सीटों पर संघर्ष कड़ा है, पर भाजपा और संघ कैडर यहां अपना पूरा दम दिखा रहा है। पिछले सप्ताह भाजपा के शीर्ष नेताओं जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल थे और संघ के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। कहते हैं इस बैठक में यह तय हुआ कि 'इन 18 सीटों को हर हाल में जीतना जरूरी है। सो, इन सभी 18 सीटों पर संघ और भाजपा के नेता 'डोर-टू-डोर' प्रचार करेंगे, सोशल और डिजिटल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल होगा और किसी भी स्थिति में संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी।

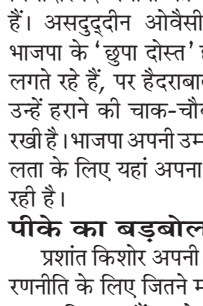

सूत्र बताते हैं कि 'कोड ब्ल्यू' की सीटों में सबसे अव्वल मंडी को रखा गया है, जहां से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद अमेठी का नंबर आता है जहां से प्रमुख भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी का मुकाबला गांधी परिवार के वफादार केएल शर्मा से है। इसके अलावा इसमें गुजरात के राजकोट की सीट भी शामिल है, जहां से मोदी दुलारे परुषोतम रूपाला चुनावी मैदान में हैं जो हाल के अपने विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर भले ही भाजपा के 'छुपा दोस्त' होने के आरोप लगते रहे हैं, पर हैदराबाद में भाजपा ने उन्हें हराने की चाक-चौबंद तैयारी कर रखी है। भाजपा अपनी उम्मीदवार माधवी लता के लिए यहां अपना पूरा जोर लगा रही है।

पीके का बड़बोलापन

प्रशांत किशोर अपनी अचूक चुनावी रणनीति के लिए जितने मशहूर हैं उससे ज्यादा विख्यात हैं अपने बड़बोलेपन के लिए। पिछले दिनों हैदराबाद के एक पंचतारा होटल की लॉबी में बैठ कर वे अपने स्पीकर फोन पर किसी से बतिया रहे थे। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उनसे पूछ रहा था कि 'अभी तक आप जगन के लिए काम रहे थे, अब चंद्रबाबू के लिए कर रहे हैं।' कहते हैं इस पर पीके ने ऊंचा फेंकते हुए कहा-क्या करूं, मेरा एक पैर नायडू ने पकड़ रखा है तो दूसरा जगन ने। उसी होटल की लॉबी में साथ वाले सोफा पर चंद्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश का एक अभिन्न मित्र बैठा था जो पीके की सारी बातें सुन रहा था। उसने फौरन नारा को फोन कर यह सारी बातें बताईं। उसी वक्त आग-बबूला होते नारा ने पीके को फोन किया और कहा कि 'हम रिश्ता रखते हैं सो आप रिश्ते की कद्र करें और बिलावजह अनर्गल प्रलाप न करें।'

कोपभवन से कैसे बाहर आए राज ठाकरे

शायद आपको याद हो 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य में भाजपा को बिना शर्त लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया था, इसकी पृष्ठभूमि दिल्ली में तैयार हुई थी जब राज ठाकरे दिल्ली आकर भाजपा शीर्ष से मिले थे। इसके बाद ही भाजपा शीर्ष ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यह जिम्मा सौंपा था कि 'वे राज ठाकरे का पूरा ध्यान रखें और उन्हें सहयोग करें।'

शिंदे की ओर से शुरूआत में थोड़ा सहयोग हुआ पर बाद में उनका रवैया उदासीन हो गया। इस पर नाराज़ होकर राज ठाकरे घर बैठ गए। जब यह बात भाजपा नेतृत्व को पता चली तो उसने जम कर शिंदे की क्लास लगाई, फिर शिंदे की ओर से राज को और सहयोग हुआ, जिसके बाद राज ठाकरे कोपभवन से बाहर निकले और अब वे महाराष्ट्र की पांचवें चरण की 13 सीटों पर जमकर भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जहां 20 मई को चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा वे 17 मई को शिवाजी पार्क में मोदी के साथ एक चुनावी रैली में मंच भी साझा करेंगे।

कंगना के अंगना में कांग्रेस

मंडी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत की तारणहार होकर उभरी है जहां उनका मुकाबला कांग्रेसी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह से है। सूत्र बताते हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु समेत 5 बड़े कांग्रेसी नेताओं की नाराज़गी विक्रमादित्य से है। इन्हें लगता है कि विक्रमादित्य समर्थकों ने ही सुक्खु सरकार गिराने की साजिश रची थी। सूत्र बताते हैं कि सुक्खु और उनके समर्थक नेता अंदरखाने से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की पूरी मदद कर रहे हैं। यहां तक कि स्थानीय प्रशासन भी कंगना के पक्ष में कदमताल करता नज़र आ रहा है।

...और अंत में

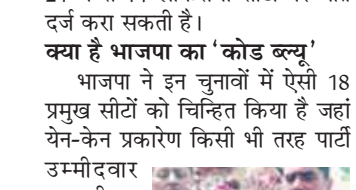

आप के एक प्रमुख युवा नेता अपने इलाज के सिलसिले में कई महीनों से लंदन में जमे हैं। सूत्रों की मानें तो अभी हाल में ही उन्होंने दुबई आकर भाजपा के एक बड़े नेता के पुत्र से गुपचुप मुलाकात की है। इस मुलाकात का आशय भारत में अपनी गिरफ्तारी से बचने का है। इसके लिए वे पार्टी छोड़ने और सरकारी गवाह बनने के लिए भी राज़ी नज़र आए। इस युवा नेता के प्रस्ताव पर इस नेता पुत्र ने फौरन एक नामी वकील को फोन लगा कर यह सारा वाकया बताया और यह जानना चाहा कि 'हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं?' इस पर वकील साहब ने कहा ये सज्जन एक सरकारी बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और इन्हीं पर गंभीर आरोप भी लगे हैं तो ऐसे में ये भला सरकारी गवाह कैसे बन सकते हैं?

2024 का रण : अपना-अपना दम

पिछले दिनों रायबरेली में बोलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों को मुफ्त राशन देने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुफ्त दी गई कोई भी चीज लोगों की आदतें खराब कर देती है और उन्हें अपना पैसा कमाने से रोक देती है। देशव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही वितरित किए जा रहे सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा मुफ्त राशन का प्रावधान सबसे पहले 2020 में मोदी सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण हुई कठिनाई को दूर करने के लिए किया गया था। इसे पिछले साल तक वार्षिक आधार पर जारी रखा गया था, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि यह कम से कम पांच और वर्षों तक चलेगा। मोदी ने वित्त मंत्रालय की आपत्तियों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 12 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। वैसे इन चुनावों में मुफ्त सुविधाओं पर पार्टियों के वादों की बात करें तो कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया है।

दरअसल, ऐसा इसलिए है, क्योंकि सरकार में रहते हुए भाजपा को कुछ संयम बरतना होगा क्योंकि सत्ता में लौटने पर, जैसा कि अधिकांश पर्यवेक्षक इस बात पर जोर देते हैं, उसे उन वादों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। इस मामले में कांग्रेस के पास लापरवाह होने की सुविधा है, क्योंकि इस चुनाव में उसके सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। किसी को उन कुछ मुफ्त सुविधाओं पर एक सरसरी नजर डालनी होगी, जिनकी घोषणा प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई राहुल प्रचार अभियान के दौरान कर रहे हैं। जैसा कि भाई-बहन कहते हैं, रुपये का वादा या गारंटी। परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को प्रतिवर्ष एक लाख रुपए देने का सीधा मतलब होगा केन्द्र सरकार के विकास बजट में भारी कटौती। एक तरह से यह विकास के पैसे का पूरी तरह से दूसरी तरफ चले जाने जैसा होगा।

मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस नेताओं ने एक और वादा किया है लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कुल आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक करने पर रोक लगा रखी है तब भला कांग्रेस के नेता ऐसा कब और कैसे करेंगे? भले ही वे कानून के तहत इस वादे को लागू करने में सक्षम हों या न लेकिन उन्होंने मतदाताओं को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। वहीं, कांग्रेस पार्टी में एक आंतरिक आकलन से पता चलता है कि प्रियंका गांधी 'सुरक्षित' और बेहतर प्रचारक हैं। हालांकि इसका जवाब समय देगा लेकिन वह आक्रामकता दिखा कर बैलेंस भी बना लेती हैं, कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों के लिए प्रियंका में एक करिश्माई नेता बनने की क्षमता है। वह भी अक्सर मंच से चौंकाने वाले बयान देती हैं, लेकिन अनाप-शनाप नहीं बोलती। हालांकि, कांग्रेस ने प्रचार के लिए गांधी परिवार से भाई-बहनों पर ही भरोसा जताया है, प्रचार के लिए अन्य नेताओं की सेवाओं का बमुश्किल उपयोग किया जाता है। यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सार्वजनिक बैठकें भी कांग्रेस समर्थकों को उत्साहित करने में विफल रहीं।

दूसरी ओर, भाजपा में यह भावना बढ़ती जा रही है कि वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जितना कि पार्टी ने चुनाव मैदान में उतरते समय उम्मीद की थी। इसका कारण यह है कि पार्टी के कट्टर समर्थक भी प्रचार करने के लिए पर्याप्त उत्साहित नहीं हैं, उनका मानना है कि उनके मतदान या प्रचार के बिना भी पार्टी को बड़ी जीत हासिल होगी। उन्होंने यह मान लिया है कि सभी मुद्दे पीछे छूट चुके हैं, और अब मतदाताओं के लिए केवल मोदी की छवि ही मायने रखती है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि मोदी का सर्वशक्तिमान आकर्षण ही इस चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए काफी है। फिर भी काउंटिंग डे यानि 4 जून का इंतजार करना ही होगा।

“ पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि मोदी का सर्वशक्तिमान आकर्षण ही इस चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए काफी है। फिर भी काउंटिंग डे यानि 4 जून का इंतजार करना ही होगा।

पंजाब केसरी के कर्णधारों की याद में महामृत्युंजय मंत्र जाप

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
f/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

आज बड़ी भावुकता और संवेदनाओं से भरा दिन है। 12 मई, 1984 को हमारे पूज्य पिता जी (पिता ससुर) आदरणीय रोमेश चन्द्र जी ने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया था। उस समय पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। किसी का भी एक मिनट का भरोसा नहीं था। हमारे परिवार में पहले पूज्य दादा जी लाला जगत नारायण जी को शहीद कर दिया गया, फिर रोमेश जी और फिर अश्विनी जी (मेरे पति) पर आतंकवादी हमले हुए। यहीं सिलसिला नहीं रुका, लगातार हमारे कई अखबार के एजैंट और हाकर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। अश्विनी जी और सभी परिवार के सदस्यों ने लम्बी लड़ाई लड़ी। हम सब नार्मल जिन्दगी की कल्पना करना भी भूल चुके थे। यहां तक कि आदित्य बेटे को तीसरी कक्षा तक स्कूल भी नहीं भेजा। हमारा परिवार 2 हिस्सों में बंट चुका था। आधों ने पंजाब में रहकर मोर्चा सम्भाला और अश्विनी जी और मैंने दिल्ली का मोर्चा सम्भाला और पंजाब केसरी को देश के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की तथा यह समाचार पत्र नेशनल बन गया। 18 जनवरी, 2020 को अश्विनी जी का समय से पहले मात्र 62 साल की उम्र में निधन हो गया। तब से पंजाब वालों ने पंजाब को सम्भाला और मैंने और मेरे तीनों बेटों ने पंजाब केसरी दिल्ली को।

यह कार्यक्रम पिछले 20 सालों से 12 मई को जन कल्याण और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए होता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सदस्य हिस्सा लेते हैं तथा जो बिस्तर पर हैं या आने में असमर्थ हैं उनके लिए सीधा प्रसारण होता है। इसी के साथ हम पंजाब केसरी के तीनों कर्णधारों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। यह मंत्र जाप बहुत शक्तिशाली होता है, जिसका एक आम व्यक्ति को अकेले बैठकर जाप करना मुश्किल होता है और जब सब मिल बैठकर इकट्ठे करते हैं तो इसका नजारा, इसका माहौल, इसकी पवित्रता ही अलग होती है। यह प्रार्थना मल्टीप्लाई होकर कई गुणा होकर सीधा ईश्वर के पास पहुंचती है। प्रसिद्ध भजन गायक इसे अपने अंदाज में करवाते हैं।

अश्विनी जी जब तक जीवित रहे इस मंत्र जाप का उच्चारण और इसका अर्थ सबको समझाते थे। इस दिन उनकी याद हर व्यक्ति को आती है। साथ ही उनकी निडर, निर्भीक पत्रकारिता की याद आती है और साथ ही साथ पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण और रोमेश चन्द्र जी की भी बहुत याद आती है तथा इस दिन हमारे अन्दर एक नई ऊर्जा भरती है कि हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे।

जब मंत्र जाप होता है तभी एक तरह की ओढ़नी ओढ़ते हैं ताकि सभी एक लगें, कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई किसी का धर्म अलग नहीं, सभी एक ही भक्ति भाव से जुड़े होते हैं और सभी का एक ही धर्म होता है मानवता। इसकी मिसाल आपको गेट पर प्रवेश करते ही मिल जाती है। जब सभी धर्मों के लोग वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार विभिन्नता में एकता झलकती है। चलो आओ सभी मिलकर पंजाब केसरी के कर्णधारों को नमन करें, जो आने में असमर्थ हैं, वो घर बैठे ही करें या इस प्रोग्राम को लाइव पंजाब केसरी डॉट कॉम पर देखें। साधना चैनल और एमएच-1 पर भी इसे दिखाया जाएगा। आज के दिन हम प्रतिज्ञा करें कि हम देश की एकता, अखंडता को कायम रखेंगे, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, विश्व में बड़ा नाम हो रहा है, कोई भीतरघात न कर सके, कोई विदेशी ताकतें इसे नाकाम न करें क्योंकि-

''अब कोई गुलशन न उजड़े
अब वतन आजाद है।''

छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में देवराजे गौड़ा को होलेनारासीपुरा ले जाया गया

● 36 वर्षीय महिला की शिकायत पर भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी

चित्रदुर्ग (कर्नाटक),(भाषा): कथित छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार भाजपा के नेता और पेशे से वकील जी. देवराजे गौड़ा को शनिवार को पूछताछ के लिए होलेनारासीपुरा ले जाया गया।

यह घटना कथित तौर होलेनारासीपुरा में ही हुई थी। हासन जिले की 36 वर्षीय महिला की शिकायत पर गौड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने उसकी संपत्ति बेचने में मदद करने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गौड़ा के खिलाफ एक अप्रैल को छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि गौड़ा को हासन पुलिस से मिली गुप्त सूचना पर शुक्रवार देर रात चित्रदुर्ग जिले के हिरियुर पुलिस ने गुलिहाल टोल नाका से गिरफ्तार किया। कानूनी प्रक्रिया के बाद हिरियुर पुलिस ने देवराजे गौड़ा को होलेनारासीपुरा पुलिस को सौंप दिया।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

रायबरेली में बीजेपी तैयार कर रही है राहुल विरोधी नेरेटिव

-अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से रायबरेली लोकसभा सीट एक मात्र ऐसी सीट है जहां कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। बाकी की 16 सीटों पर तो उसे जीत के लिये समाजवादी पार्टी का ही सहारा है। रायबरेली की जीत को गांधी परिवार ने साख का सवाल बना लिया है तो बीजेपी राहुल गांधी की साख को ह्यधूमिलह्व करने में लगी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी के प्रत्याशी बनने के बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या वो अपने परिवार की इस सीट को बचा पाएंगे? जहां सोनिया गांधी हमेशा से बड़ी जीत हासिल करती रहती थीं,लेकिन अभी से इस बात पर चर्चा छिड़ी हुई है क्या राहुल गांधी अपनी मॉ की जैसी शानदार जीत हासिल कर सकेंगे। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने आये जरूर हैं,लेकिन इसके पीछे का सबसे कारण यह है कि कांग्रेस को लगता है कि राहुल के लिए रायबरेली अमेठी के मुकाबले सुरक्षित है. पर रायबरेली जीतने के लिए बीजेपी पिछले पांच साल से काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ने प्रत्याशी का फैसला ही नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 03 मई को किया था। हालांकि इसके बावजूद गांधी परिवार की इस परंपरागत सीट पर राहुल गांधी की जीत की उम्मीद और पराजय का डर बराबर का बना हुआ है। इसी लिये प्रियंका गांधी के साथ-साथ कांग्रेस के कई कद्दावर नेता रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं।

वहीं बीजेपी की तरफ से ऐसी चर्चाओं को हवा दी जा रही है कि रायबरेली जीतने के बाद राहुल गांधी वायनाड के लिए इस सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान भी इस बात पर मुहर लगा रहा है। जयराम रमेश ने कहा है कि प्रियंका गांधी के लिए प्लान बी तैयार है। उस प्लान बी को राहुल के रायबरेली जीतने के बाद लागू किया जाएगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली जीतने के बाद वायनाड में ही बने रहें. क्योंकि केरल में जल्द हीविधानसभा चुनाव होने हैं। बहुत उम्मीद है कि इस बार केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ की सरकार बने. इसलिए यह तय है कि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ेंगे.अगर जनता के बीच ये संदेश चला जाता है कि राहुल गांधी रायबरेली जीतने के बाद यहां से रिजाइन कर देंगे तो निश्चित है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाएगा। उधर, राहुल गांधी और कांग्रेस से इत्तर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पिछले पांच साल से रायबरेली से चुनाव जीतने के लिए लगे हुए हैं. बीजेपी भी 2019 में दिनेश प्रताप सिंह के चुनाव हारने के बाद उन्हें भविष्य के सांसद के रूप प्रोजेक्ट करती रही है। दरअसल बीजेपी रायबरेली में अमेठी मॉड्यूल पर काम कर रही है। जैसे स्मृति इरानी 2014 में चुनाव हारने के बाद 5 साल सांसद के रूप प्रोजेक्ट करती रही है।

कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में कमल खिलाने के लिए भाजपा हर मोर्चे पर प्रयासरत है। इसी लिये भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह से नाराज चल रहे विधायकों को मनाने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी स्वयं संभाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने पहले पार्टी कार्यालय पर बैठक की, उसके बाद सदर विधायक अदिति सिंह से मिलले उनके आवास गए। वहां पर करीब एक घंटे तक उनके साथ बैठक की। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी पदाधिकारी और कार्यकताओं के साथ ऊंचाहार से विधायक डॉ. मनोज पांडे के गोराबाजार स्थित उनके आवास पहुंचे। यहां पर भी उन्होंने करीब एक घंटे तक ऊंचाहार विधायक से बात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष ने अधिकतर समय ऊंचाहार विधायक के साथ अकेले में बिताया। देर रात तक पदाधिकारियों की बैठकी रही, डॉ. मनोज पांडे भी के घर पर ही रही। दोनों विधायकों से मुलाकात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि दोनों से चुनाव में लगने का निवेदन करने गया था। पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक में कार्यकताओं से चुनाव में जुटने का आवाहन किया। कार्यकताओं से वोट परसेंट बढ़ाने की भी अपील की। इसके लिए सभी को जनसंपर्क करने के लिए कहा गया।बीजेपी की सदर विधायक अदिति सिंह का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट हुई। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने बताया कि पार्टी कार्यकताओं में उत्साह भरने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने रायबरेली का दौरा किया। दोनों विधायकों से मुलाकात कर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की।

रायबरेली लोकसभा सीट के जातीय और सामाजिक समीकरणों की बात करें तो यहां बीजेपी मजबूत स्थित में दिख रही है. करीब 11 फीसदी ब्राह्मण, करीब नौ फीसदी राजपूत हैं जो आजकल बीजेपी को वोट करते हैं. जबकि मुस्लिम 6 फीसदी और 7 फीसदी यादव वोटर्स हैं. जाहिर है कि यहां समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स कम हैं. समाजवादी पार्टी चूंकि कांग्रेस के साथ ही है इसलिए ये वोट राहुल गांधी को जा सकते हैं. हालांकि बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद यादव को खड़ाकर यादव वोटों में सेंध लगाने की तैयारी कर दी है। सबसे खास बात यह है कि रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कुल करीब 34 फीसदी दलित मतदाता हैं। पिछली बार दलित वोट सोनिया गांधी को जरूर मिला होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा थ और दोनों ने ही रायबरेली से अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए थे। इसके अलावा लोध 6 फीसदी, कुर्मी 4 फीसदी के करीब हैं, जो आज की तारीख में बीजेपी के कोर वोटर 23 फीसदी अन्य वोटों में कायस्थ-बनिया और कुछ अति पिछड़ी जातियां हैं जो बीजेपी के वोट देती हैं।

केजरीवाल निर्दोष नहीं शराब घोटाले में, चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर हैं

अशोक भाटिया

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 50 दिन तक तिहाड़ जेल की हवा खाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अब वह एक जून तक जेल के बाहर रहेगें और चुनाव प्रचार कर सकेंगे। जेल से बाहर आते ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल को ह्यभारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के क्रांतिकारी नारे याद आ गए। इन्हीं नारों के जरिए केजरीवाल ने माहौल बांधने की कोशिश की। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए।

गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद मुख्य आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें इस घोटाले का किंगपिन यानि कि सरगना करार दिया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी हो, लेकिन, वो चुनाव परिणाम नहीं देख पाएंगे। दरअसल, गुरुवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून को अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मियाद 5 जून तक बढ़ाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वोटिंग से 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार थम जाता है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।

आप पार्टी के अनुसार केजरीवाल को जमानत मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉफ्रेंस करके कहा कि बजरंगबली का उन पर आशिर्वाद है। जमानत मिलने से दिल्ली नहीं पूरा देश खुश है। उनको सियासी षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था, ताकि लोकसभा चुनाव से दूर रहें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा, ह्य सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तानाशाही का अंत होगा। सत्यमेव जयते। देश देखेगा केजरीवाल का कमाल।

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। यह फैसला आज के राजनीतिक माहौल के लिए काफी सकारात्मक होगा और विपक्ष को फायदा होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अंततः सत्य और न्याय की जीत होगी। केजरीवाल की बेगुनाही और एनडीए/बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति बिना किसी संदेह के बाहर हो जाएगी। हालांकि, बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में केजरीवाल लिप्त हैं। ये कोर्ट में साफ हो गया है। एक जून के बाद उनको जेल जाना ही होगा।

केजरीवाल के जेल से बाहर आने को लेकर सियासी नफा-नुकसान पर सभी के अपने-अपने दावे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि , सीएम केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार ठंडा पड़ा हुआ था। उन्हें लीडरशिप की जरूरत महसूस हो रही थी। जमानत मिलने और जेल से बाहर आने से चुनाव पर सियासी प्रभाव जरूर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के लोगों के हौसले बुलंद होंगे और कार्यकताओं में उत्साह भरेगा। केजरीवाल के जेल में रहने के चलते उनकी पार्टी प्रचार का माहौल नहीं बना पा रही थी। मगर, अब उनके बाहर से आने से सियासी बज क्रिएट होगा। सीएम केजरीवाल की गैर-मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता चुनावी कैंपेन संभाल रही थीं। मगर, मीडिया का अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था। उनके आने से दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह पर प्रचार को धार मिलने के साथ-साथ सियासी लाभ भी मिल सकता है। केजरीवाल सियासी रुख बदलने के माहिर खिलाड़ी हैं। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह आक्रमक प्रचार करेंगे, उससे उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लाभ मिल सकेगा। सीएम भगवंत मान पंजाब तक ही अपना असर दिखा सकते हैं। वो दिल्ली की सियासत पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे।

राणा का कहना है कि आगे देखना है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में किसके लिए कितना प्रचार करते हैं, क्योंदि दिल्ली में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। सीएम केजरीवाल अभी तक अदालत में अपनी बेगुनाही के बातें रख रहे थे, लेकिन अब जनता के बीच भी रख सकेंगे। वो जनता की सियासी नब्ज को समझते हैं और उसे मोड़ना उन्हें बाखूबी आता है।

वरिष्ठ पत्रकार युसुफ अंसारी कहते हैं कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा हैं। केजरीवाल देश के उन नेताओं में हैं, जिन्हें बीजेपी के सियासी नैरेटिव को काउंटर करना बाखूबी आता है। बीजेपी और पीएम मोदी जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पर खड़ी नजर आ रही है और राममंदिर से लेकर हिंदू-मुसमलान का एजेंडा सेट कर रही है, उसे केजरीवाल बखूबी मोड़ना जानते हैं। केजरीवाल के बाहर आने के बाद पार्टी के उस नैरेटिव को बल मिलेगा कि उन्हें फंसाया गया है ।युसुफ अंसारी कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार को धार मिलेगी। गठबंधन के मंच से केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर अब पहले से ज्यादा आक्रमक नजर आ सकते हैं, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकती है। दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी दो चुनाव से लगातार जीत रही है, लेकिन कांग्रेस-अअढ गठबंधन के चलते इस बार चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। अब केजरीवाल के बाहर आने से और भी लाभ मिल सकता है क्योंकि वो साहनुभूति को भी भुनाना बखूबी जानते हैं।

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार और लोक संसद के संयोजक रविशंकर तिवारी कहते हैं कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने से दिल्ली की सियासत पर कोई खास सियासी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल के जेल में रहने से जो साहनुभूति आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही थी, वो अब खत्म हो सकती है। उनके बाहर आने से बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है, क्योंकि अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया बल्कि चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दी है। बीजेपी और पीएम मोदी ने चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। केजरीवाल के बाहर आने के बाद विपक्ष के मंच पर प्रचार करने के लिए उतरेंगे तो प्रधानमंत्री और बीजेपी उसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है ।वो कहते हैं कि देश में जनता के बीच यह एक छवि बनती जा रही थी कि नेता भ्रष्टाचार करने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। मोदी ने बड़े-बड़े भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करके यह छवि तोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार-बार यह कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी, उससे भी सरकार की प्राथमिकता साफ नजर आती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव को लगातार सजायाफ्ता बता रहे हैं। उसी तरह केजरीवाल के खिलाफ भी यही चीज इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं दिल्ली का सियासी मिजाज देखें को राजधानी के लोग लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जगह पर बीजेपी को ही पसंद करते , 2014 और 2019 के नतीजे बता रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल के बाहर आने से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है बल्कि दांव उल्टा पड़ सकता है।

वरिष्ठ पत्रकार अरुण राघव का भी मानना है कि केजरीवाल के बाहर आने से दिल्ली की सियासत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दी है, जिसका मतलब यह नहीं होता है कि बरी हो गए हैं। दिल्ली में पढ़ी-लिखी जनता है और केजरीवाल इसीलिए सियासी तौर पर सफल रहे हैं कि क्योंकि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था और अब उसी जाल में खुद फंस गए हैं। पहले दो विधानसभा चुनावों में केजरीवाल अजेय लग रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे उनके घोटालों की जानकारी लोगों हो रही है, उनसे जनता का मोहभंग हुआ है ।वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता अपना मूड बना चुकी है। केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष किस मूंह से जवाब देगा। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में पहले से दो धड़े हैं। हाल में अरविंदर लवली और राजकुमार चौहान जैसे नेता साथ छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं उनकी दलित समुदाय में पकड़ कमजोर हुई है। दलित समुदाय से आने वाले दो विधायकों का मोहभंग हुआ है, जिसमें एक बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल का जादू दिल्ली में फीका पड़ चुका है।

भारत एवं कनाडा के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर

-ललित गर्ग

कनाडा में रविवार को वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालसा दिवस समारोह के दौरान खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने के बाद भारत सरकार जो सख्ती दिखाई है, वह आवश्यक एवं समयोचित कदम है। इस घटना पर भारत का चिंतित होना एवं कनाडा को चेताया जाना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय में कनाडा के उप-उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में गहरी आपत्ति जताई गई है। कनाडा सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिये अनेक बार भारत विरोधी घटनाओं में संदेहास्पद एवं विवादास्पद भूमिका का निर्वाह करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की मर्यादाओं को धुंधलाया है। कनाडा की धरती से खालिस्तानी समर्थक अलगाववाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता रहा है। इस तरह की घटनाओं से कनाडा में अपराध का माहौल बना हुआ है। इससे कनाडा के नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। जिससे भारत में भी स्थितियां संकटपूर्ण बनी है। पिछले साल खुद ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से निज्जर हत्याकांड में भारत के शामिल होने का निराधार आरोप लगाया था। भारत के मांगने के बाद भी आज तक उनकी सरकार इस आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाई है। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाकर दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया था। भारत ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद से कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आ गई और दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की बजाय खतरनाक मोड़ पर पहुंच गये हैं।

रविवार के खालसा दिवस समारोह में न केवल खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए बल्कि ऐसे बैनर प्रदर्शित किए गए, जिनमें भारत-विरोध के त्रासद एवं राष्ट्र-विरोध के भ्रामक, झूठे एवं बेबुनियाद आरोप थे। अफसोस और चिंता की बात यह रही कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तो इन सब भारत-विरोधी घटनाओं को रोकने की या इन्हें गलत बताने की कोई कोशिश की। इस पूरे मामले में ट्रूडो का व्यवहार आपत्तिजनक बना, दो देशों के बीच खटास घोलने वाला एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का रहा। जिसे दोनों देशों के राजनयिक पैमाने पर उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह कनाडा अपने देश की राजनीतिक जरूरतों के चलते भारत के साथ अपने रिश्ते इस मोड़ पर ले आया हैं, जहां उनके बीच विश्वास, भरोसे, आपसी सहयोग और संवाद की कमी है, तो यह अकारण नहीं है।

भले ही लगभग आठ लाख कनाडाई सिखों की वहां की राजनीति में सक्रिय भागीदार हैं। सिख समुदाय की जरूरतों एवं उनके शांतिपूर्ण जीवन के लिये कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता में कोई आपत्ति नहीं हैं। सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करने के वायदे यदि वहां की सरकार करती है तो अच्छी बात है। भले ही कनाडा सरकार सिखों के सामुदायिक केंद्रों, गुरुद्वारा समेत पूजास्थलों की सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ भारत एवं कनाडा के बीच उड़ानें और रूट बढ़ाने को लेकर भारत के साथ नए समझौते करें, लेकिन इन स्थितियों के बीच खालिस्तानी अलगाववाद को प्रोत्साहन देना भारत के लिये असहनीय है। भारत बार-बार इस बात को दोहरा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह अलगाववादी और अतिवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना न केवल दोनों देशों के रिश्तों के लिए बल्कि खुद कनाडा के लिए भी खतरनाक है। भारत जिस तरह से लम्बे समय तक खालिस्तानी आतंकवाद को झेला है, कनाडा में इन तत्वों को प्रोत्साहन देकर कनाडा आतंकवादी गतिविधियों का केन्द्र बन सकता है, जो उसके लिए नुकसानदेह ही साबित होने वाला है।

निश्चित ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकी फल-फूल रहे हैं। खालिस्तानी न केवल भारतीय राजनयिकों को धमका रहे हैं बल्कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। कनाडा की धरती पर हर किस्म के खालिस्तानी चरमपंथी ही नहीं पल रहे हैं बल्कि वहां भारत से भागे गैंगस्टर और नशे के तस्कर भी शरण पा रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारत ने कनाडा को जो खरी-खोटी सुनाई, वह इसलिए आवश्यक थी, क्योंकि वहां की ट्रूडो सरकार अपने भारत विरोधी रवैये से बाज नहीं आ रही है। वह जिस तरह खालिस्तानी अतिवादियों को संरक्षण दे रही है, उसकी मिसाल यदि कहीं और मिलती है तो वह पाकिस्तान में। कनाडा अपने भारत विरोधी रवैये के कारण पाकिस्तान सरीखा बनता जा रहा है। कनाडा अपने हितैषी एवं पडोसी देशों से दूरियां बना रहा है। खालिस्तान समर्थन एवं प्रोत्साहन के चलते कनाडा में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अपने देश के साथ दुनियाभर में वह आलोचकों के निशाने पर हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों पर नियंत्रण रखने में कथित नाकामी के चलते ट्रुडो को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते जी-20 बैठक में उन्हें भारत और सदस्य देशों का ठंडा रिस्पांस मिला। भारत में खास अहमियत नहीं मिलने से खिसियाए ट्रुडो को कनाडा के मीडिया ने भी आड़े हाथ लिया है।

ट्रुडो सरकार पर भारत के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाने और व्यापार वार्ता के बारे में अंधेरे में रखने के आरोप भी लगे हैं। घरेलू राजनीतिक हितों के लिए ट्रुडो भारत के साथ लड़ाई मोल लेकर अपने देश का भारी आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि भारत अब दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कनाडाई में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात और व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर यहां की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। भारत की नाराजगी बेवजह नहीं है, क्योंकि कनाडा भारत के विरोध में लगातार सक्रिय हैं, कनाडा ने ही किसानों के आंदोलन के समर्थन में अतिश्योक्तिपूर्ण सहयोग होने दिया। जबकि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव और आपसी भरोसा रहना जरूरी है। खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठे थे। लेकिन अमेरिका ने इस मसले पर सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय भारत सरकार से सीधी बातचीत की। भारत ने भी अमेरिकी सरकार की ओर से मुहैया कराए गए सबूतों को गंभीरता से लिया। इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच शुरू हुई। अच्छी बात यह भी है कि इस मामले को दोनों देशों के संबंधों के खटास का माध्यम नहीं बनने दिया। जांच के निष्कर्षों को दोनों देशों ने स्वीकार किया एवं बेवजह का विवाद खड़ा नहीं होने दिया। कनाडा को भी अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए एवं निज्जर हत्याकांड में भारत की अगर कोई भूमिका है तो उसके सबूत भारत सरकार को देने चाहिए। कोरे आरोप लगाकर आपसी संबंधों को बिगाड़ने से परहेज करना चाहिए। अपनी भूमि का उपयोग भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करती गतिविधियों के लिये कत्तई नहीं करने देना चाहिए। बात कनाड़ा के साथ-साथ अन्य देशों पर भी लागू होती है जो अपने राजनीतिक हितों के लिये खालिस्तान समर्थक या अन्य भारत विरोधी आन्दोलनों को जगह देते हैं, लेकिन इन देशों ने भी समझा है और समझना ही होगा कि किसी देश के अन्दरूनी मामलों में दखलअंदाजी करना उनके लिये ही हानिकारक होने वाला है। भारत अब एक महाशक्ति है, कनाड़ा जैसे देशों की भारत-विरोधी गतिविधियों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पडेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जापान को पीछे छोड़ सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत

जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे शोध संस्थान एंबर की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। भारत 2015 में नौवें स्थान पर था। पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर काफी जोर दे रहा है, और यह कामयाबी इसी का परिणाम है। भारत से आगे अब केवल चीन और अमेरिका ही रह गए हैं। एंबर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू शीर्षक से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन का 5.5 फीसदी सौर ऊर्जा के रूप में हुआ। वैश्विक ट्रेंड के अनुरूप भारत ने पिछले साल कुल बिजली उत्पादन का 5.8 फीसदी सौर ऊर्जा से हासिल किया, जो 2015 में 0.5 प्रतिशत था। पवन और सौर ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि ने वैश्विक बिजली मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 30 फीसदी से अधिक और पूर्ण स्वच्छ उत्पादन (परमाणु समेत) को लगभग 40 फीसदी तक पहुंचा दिया है। परिणामस्वरूप, दुनिया की बिजली की कार्बन तीव्रता रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जो 2007 में अपने चरम से 12 फीसदी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि और भी अधिक हो सकती थी, लेकिन चीन और दुनिया के अन्य हिस्सों में सूखे के बीच जलविद्युत उत्पादन पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत दुनिया में सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है, जबकि सबसे महंगा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कनाडा है।

दुनिया में चौथी सबसे बड़ी वृद्धि

भारत में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में जो वृद्धि की है, वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि थी। भारत इस मामले में चीन, अमेरिका और ब्राजील से पीछे रहा। इन चारों देशों की सौर ऊर्जा वृद्धि में हिस्सेदारी 2023 में 75 फीसदी रही। 2023 में वैश्विक सौर उत्पादन 2015 की तुलना में छह गुना अधिक था, जबकि भारत में यह 11 फीसदी से अधिक रहा। तीन गुना नवीकरणीय क्षमता बढ़ाने की योजना... अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन परिदृश्य के अनुसार, 2030 तक सौर ऊर्जा वैश्विक बिजली उत्पादन का 22 फीसदी तक बढ़ जाएगी। भारत 2030 तक नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करने की योजना बनाने वाले कुछ देशों में से एक है। एंबर के विश्लेषण के अनुसार, इस क्षमता को पूरा करने के लिए भारत को वार्षिक क्षमता वृद्धि उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

-डॉ. अजय कुमार चतुर्वेदी डीन. आई ई सी विश्वविद्यालय

अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के सियासी मायने को ऐसे समझिए

हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी थी कि अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाने वाली ईडी परेशान हो गई। आनन-फानन में ईडी ने एक हलफनामा दायर करके उनके अंतरिम जमानत का विरोध किया और कुछ अकाट्य दलीलें भी दी। जिस पर केजरीवाल की लीगल टीम ने भी कड़ी आपत्ति जताई। जिसके दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के एक साहसिक निर्णय से जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के चुनावों के दौरान बाहर आने और चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी जताने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। समझा जाता है कि कोर्ट के इस उदार पहल से भारत में एक नई सियासी क्रांति का आगाज हो सकता है। लिहाजा, इस निर्णय के सफेद और स्याह पक्ष पर चर्चा करने से पहले यह बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे और पिछले 50 दिन से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आगामी एक जून 2024 तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ऐसा इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में विगत 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के इस निर्णय की तब बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना बन चुकी है। इसी मामले में गत 8 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान ही न्यायमूर्ति खन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले भी यानी गत 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा था कि मामले की सुनवाई जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कोर्ट लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी थी कि अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाने वाली ईडी परेशान हो गई। आनन-फानन में ईडी ने एक हलफनामा दायर करके उनके अंतरिम जमानत का विरोध किया और कुछ अकाट्य दलीलें भी दी। जिस पर केजरीवाल की लीगल टीम ने भी कड़ी आपत्ति जताई। जिसके दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। यही वजह है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने के सियासी और न्यायिक मायने तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि यह एक असाधारण न्यायिक आदेश है, जो अब बौद्धिक विमर्श का मुद्दा भी बन चुका है। समझा जा रहा है कि कोर्ट के ताजा निर्देश से जहां देश में जनतांत्रिक भावनाओं को बल मिलेगा, वहीं भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल राजनेताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि जेल से बाहर रहने का एक अमोघ कानूनी हथियार कोर्ट के फैसले से उन्हें मिल चुका है। लिहाजा, आने वाले दिनों में जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगे जाने के मामले बढ़ेंगे।

बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल को किसी भी तरह की विशेष राहत देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिया जाना समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसा होगा। इससे ऐसी नजीर कायम होगी कि सभी अपराध करने वाले अनैतिक राजनेता चुनाव की आड़ में जांच को नजरअंदाज करेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर आम चुनाव। यदि वे गिरफ्तार किए जाते हैं तो प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगेंगे। दो कदम आगे की सोचते हुए उसने तर्क दिया कि आजतक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वह व्यक्ति स्वयं भी प्रत्याशी क्यों न रहा हो, जबकि केजरीवाल तो उम्मीदवार भी नहीं हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि अपराधी जेल से ही चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उन्हें कभी इस आधार पर जमानत नहीं मिली। वैसे भी चुनाव प्रचार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार। लिहाजा ऐसा होने से कानून का उल्लंघन करने वाले हर अपराधी को राजनीतिज्ञ बनने और वर्ष भर प्रचार के मोड में रहने का प्रोत्साहन मिलेगा। राजनेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता।

ईडी ने अपनी दलील में चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार, जिसे कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार माना है, वह भी हिरासत के दौरान नहीं रहता। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) जेल में बंद व्यक्ति के मतदान के अधिकार में कटौती की बात करती है। यह चीज देखने लायक है कि पिछले पांच सालों में करीब 123 चुनाव हुए हैं और अगर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाने लगे तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार कर-के जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव तो सालभर चलने वाली गतिविधि है। हर राजनीतिज्ञ हर स्तर पर यह दलील दे सकता है कि अगर उसे जमानत नहीं दी गई तो उसे न भरपाई होने वाला नुकसान होगा। ईडी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस समय सिर्फ पीएमएलए कानून में ही बहुत से नेता जेल में हैं। उनके मामलों को जांचने के बाद सक्षम अथॉरिटी ने उनकी हिरासत को सही ठहराया है। बहुत से नेता पीएमएलए के अलावा अन्य अपराधों में जेल में होंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ विशेष व्यवहार करने और उनकी विशेष मांग स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

उसने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल ने कई समन के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश न होने के पीछे पांच राज्यों में चुनाव का यही आधार दिया था। ऐसे में अगर कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी तो उनके द्वारा आप के स्टार प्रचारक होने के आधार पर प्रचार के लिए समन को नजरअंदाज करने का कारण बनाये जाने पर न्यायिक मुहर लग जाएगी। साथ ही प्रचार के लिए अन्तरिम जमानत से प्रचार की इच्छा रखने वाले नेताओं का एक अलग वर्ग बन जायेगा। हालांकि कोर्ट ने ईडी की एक न सुनी और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र को किंतु-परन्तु के आधार पर नहीं, बल्कि स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों के आधार पर ही चलाया जाएगा। संभव है कि अगली संसद इससे सबक लेगी और नेताओं के लिए आवश्यक कानून बनाएगी या फिर पूर्व की विसंगतियों को दूर करेगी। यह स्वाभाविक सवाल है कि जब चुनावी मौसम हो और दल विशेष का प्रमुख नेता ही जेल में हो तो उसकी पार्टी को सही जनादेश कैसे मिल पाएगा। शायद इसलिए कोर्ट ने अंतरिम जमानत की नई राह दिखा दी और सियासी नकेल अपने हाथों में रख ली।

- कमलेश पांडेय

संपादकीय

अंक नहीं जीवन

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

इस वर्ष एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे सुर्खियों में रहे। इसमें अच्छी और सुहानी लगने वाली बातों के समांतर अंकों और 'रैंक' को ही जीवन का सब कुछ समझने वाली आज की पीढ़ी के बीच से परीक्षा में असफलता के भय होने, ग्रेड या रैंक कम आने, अपने आपको माता-पिता और शिक्षकों की आशा के अनुरूप खरा साबित न होने पर आत्महत्या किए जाने की खबरें भी आईं। यह निश्चित ही बेहद चिंता का विषय है । परीक्षाओं के नतीजे आने के बाद बच्चों के बीच से आत्महत्या की घटनाएं आमतौर पर हर वर्ष देखने में आती हैं, पर इसका कुछ समाधान अभिभावक, शिक्षक और प्रशासन निकाल नहीं पाते हैं और न ही ऐसी स्थिति बनाई जाती है कि आज के बच्चे इस पर विचार करें कि कामयाबी अगर अच्छा है तो कम अंक या नाकामी खुद को बेहतर करने और अगली कामयाबी का रास्ता है। बच्चों को यह क्यों नहीं समझाया जा सकता है कि क्या जीवन का लक्ष्य केवल परीक्षा ही पास करना है ! अगर अंक कम आ गए या नतीजे खराब रहे तो जीवन तो खत्म नहीं हो जाता। जीवन के मुकाम कुछ और करके भी हासिल किए जा सकते हैं । मगर भविष्य मानो स्कूली परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंकों के दायरे में ही कैद कर दिया जाता है और अभिभावक से लेकर विद्यार्थी तक इसी चक्र में अपना सोचना - समझना केंद्रित कर लेते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो सामने आने ही हैं । देखा जाए तो आज के स्कूली शिक्षा के समूचे ढांचे में पढ़ाई से लेकर परीक्षा और नतीजे के बीच दिखावे की संस्कृति में बच्चों के अभिभावक ही ज्यादा जिम्मेदार नजर आते हैं, जो अपनी अधूरी महत्त्वाकांक्षाओं की भूख की वजह से बच्चों पर दबाव बनाते हैं कि वे नब्बे या सौ फीसद अंक नहीं लाएं। सबसे अव्वल आएं। वहीं स्कूलों में भी बच्चों पर दबाब बनाया जाता है। ऐसे में स्कूल की कक्षाओं के अलावा ट्यूशन, कोचिंग, परीक्षा के तनाव और बोझ के साथ इंटरनेट, टीवी के चक्रव्यूह में फंसे बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जबकि पढ़ाई के बाद बेहतर भविष्य बनाने के लिहाज से देखें तो उसमें अंकों के निर्धारण का कोई आकलन नहीं होता है। बढ़ती महत्त्वाकांक्षा के चलते बच्चे तीन घंटे की परीक्षा में पूरे साल की पढ़ाई का, अपनी योग्यता का सही प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं । इस स्थिति की जटिलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कहां एक समूचा व्यक्तित्व बनने के लिए बच्चे अपना जीवन - सफर शुरू करते हैं और फंस जाते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने और अव्वल लाने की होड़ में । इस होड़ का हासिल यह है कि जिन बच्चों को पढ़ना, खेलना-कूदना और आनंद उठाना था, उनमें से कई पढ़ाई से उपजे तनाव और हताशा के चलते आत्महत्या करने से भी नहीं चूक रहे । दिखावे के अंको का छलावा बाल मन को लगातार आकर्षित कर रहा हैं। बच्चे बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को ही अपने जीवन की आधारशिला, अंतिम सच, करियर का सब कुछ मान बैठे हैं। जबकि यही अंतिम सच नहीं है। सच यह है कि अंकों का जीवन में कोई मूल्य नहीं हैं, क्योंकि अंकों या डिग्री से किसी की भी योग्यता का सही मूल्याकंन नहीं किया जा सकता। कितने ही आइएएस, कलेक्टर, खिलाड़ी, अभिनेता, गायक, कारोबारी, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि में बेहद साधारण किस्म के विद्यार्थी रहे।

माँ की गोद एक शरण स्थान है, जहां हमें सुकून मिलता है सभी दुखों का इलाज होता है

माँ दिवस 12 मई 2024 - हे माँ ! तुम्हारे साथ माँ दिवस मनाना है, आओ इस लोक में या बुला लो परलोक में

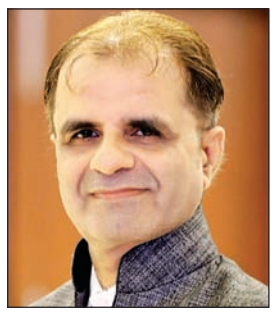

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

माँ धरती पर भगवान का रूप होती है,माँ का स्थान हमारे जीवन में अद्वितीय होता है : एडवोकेट किशन भावनानी

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर पृथ्वी की 84 लाख योनियों में से अगर दो जीवों के जीवन के अनमोल अद्वितीय व दिल से जुड़े अनमोल रिश्ते के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाब दूंगा, माँ और उसका बच्चा।वाकई मेरा मानना है कि शायद हर व्यक्ति का जवाब यही होगा,क्योंकि एक माँ ही है, जो अपने बच्चों पर मातृत्व प्रेम का असीम खजाना लुटा देती है। अगर हर व्यक्ति अपने बचपन से आज तक के पलों को याद करे तो उसे यही महसूस होगा। आज जिसके पास इस पृथ्वी पर माँ हयात यानें जीवित है, वह मांका प्यार वात्सल्य पा रहा है, तो सचमुच उससे अधिक भाग्यशाली जीव इस पृथ्वी पर नहीं होगा। आज हम यह जानने की कोशिशभी नहीं करेंगे कि माँ दिवस कब से और क्यों मनाना शुरू हुआ। बल्कि हमें सिर्फ यह याद रखना है कि 12 मई तो क्या साल के 365 दिन ही मां दिवस है।क्योंकि मांहमारी भगवान है, दूसरा इसके बिना जीवन शून्य है। मां और बच्चे का अनमोल रिश्तों के पल मानवीय जीव को ही नहीं पृथ्वी की सभी 84 लाख योनियों के प्राणियों में अगर देखा जाए तो हमें इस रिश्ते के महत्व को करीब सेसमझेंगे। मसलन एक गाय कुत्ता बिल्ली सहित ऐसे पालतू जीवों के अगर छोटे से बच्चों को अगर हम द्वेष भावना से क्लेश से हाथ लगाएंगे या कहीं ले जाएंगे तो उनकी मां हम पर झपटा मारेगी, हमला करेगी! यह है माँ। मैं अगर माँ के साथ में अपनी सच्चाई बताऊं तो 20 नवंबर 2020, धनतेरस के दिन से मैं अपनी मां के प्यार से वंचित हो गया हूं क्योंकि इसी दिन मेरी आंखों के सामने मेरी मां को साइलेंट अटैक आया था और मेरे नजरों के सामने, मेरे से बात करते हुए, मैन दुनियां से ओझल होते हुए अपनी आंखों से देखा था वह पल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा और हमेशा सोचता हूं, चिट्ठी ना कोई संदेश ना जाने कौनसा देश जहां तुम चले गए, इसीलिए ही कहता हूं जिनके पास माँ है वह जीवन में भाग्यशाली जीव है। मां के गहरे असीम प्यार को हम करीबी से महसूस कर सकते हैं, जिनके घर में छोटे दूध मुहें बच्चे हैं, तो हम देखेंगे की उस मां का अपने बच्चों पर कितना केयर रहता है।अपना पूरा समय वह बच्चों केलालन पोषण में लगा देती है, क्योंकि वह मां बच्चे के रोनें या नहीं सोने पर सारी रात आंखों में कांटे डालकर जैसे तैसे बिता देता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे घर में अभी दो छोटे बच्चे हैं, कुमार और रूहान जिनकी परवरिश उनकी माएं कर रही है, तो एक मां और एक बच्चे की परवरिश की गहराई का एहसास मुझे होता है। मेरा मानना है कि जो मानवीय जीव अपनी मां का अपमान करते हैं उसे दुख देते हैं, घर से निकाल देते हैं या माँ की शान में कोई कृत्य करते हैं, तो उनसे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है उनसे बड़ा कोई दुराचारी नहीं है, उनको इस योनि में उनके इस कृत्य का हजार गुणा फल जरुर मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति ने अपनी मां का सम्मान करते हुए मां दिवस 12 मई 2024 को पूरा दिन मां के साथ बिताना चाहिए, उसकी छत्रछाया में उसके चरणों में बैठकर उनसे वातार्लाप करना, खेलना हंसमुख मजाक कर उन्हें खुशी देना चाहिए, फिर ब माँ को और क्या चाहिए। अगर उसकी औलाद उनको खुशियां देती है तो मां के मुख से ऐसी दुआएं निकलती है जो उन बच्चों का यह लोक तो क्या परलोक भी सवेरा हो जाता है। अपने बारे में मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि 12 मई 2024 को अदृश्य रूप से ही सही मेरी मां जरूर आएगी, क्योंकि मैंने मन से कह दिया है माँ तुम्हारे साथ मैं माँ दिवस मनाना चाहता हूं आ जाओ इस लोक में या फिर बुला लो परलोक में। चूंकि मां की गोद एक शरण स्थान है, जहां हमें सुकून मिलता है, सभी दुखों का इलाज होता है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे माँ धरती पर भगवान का रूप होती है माँ का स्थान हमारे जीवन में अद्वितीय होता है। साथियों बात अगर हम माँ की करें तो, हम में से हर कोई अपनी मां से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। ये जीवन की शुरूआत से होता है और जीवन के अंत तक बना रहता है। मां हर किसी के लिए वो खास इंसान होती है जिससे एक बच्चा अपने जीवन की शुरूआती गुण सीखता है। हम बड़े हो जाते हैं मां बूढ़े होने लगती है और फिर इस व्यस्त जीवन में हम मां के पास ही लौटना भूल जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अपने मां के पास लौटने का दिन है मां दिवस। इसे मानने की शुरूआत भी ऐसी ही कहानी से हुई थी। माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, वह हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे हम कितने भी दूर हों। उनकी गोद एक शरणस्थान है,जहाँ हमें सुकून मिलता है और सभी दुखों का इलाज होता है। माँ हमारी दुआ होती है, हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है और हमारी अनमोल सम्पत्ति होती है।कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ भी इंसान हैं, उनकी भी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिशें होती हैं। शायद वो कभी घूमने जाना चाहती थीं, या कोई नया शौक अपनाना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने हमारी परवरिश के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। मां दिवस 12 मई के इस अवसर पर, आइए हम ये जरूर करें कि हम उनकी ख्वाहिशों को जानने की कोशिश करें और उन्हें पूरा करने में उनकी मदद करें। अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, उनकी पसंद की फिल्म देखें, या उनकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें स्पेशल फील कराएं। यकीन मानिए, ये छोटी-छोटी चीजें ही उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देंगी। माँ शब्द जितना छोटा है, उसका महत्व उतना ही ज्यादा है। दुनियां की हर एक मां को समर्पित है मातृ दिवस। मां की दुआएं हमारी मुसीबतों से इस कदर टकराती हैं, जमाने की हर बलाए उनके काले टीके से घबराती हैं। किसी ने हमसे पूछा स्वर्ग कहां है, हमने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके घर में मां है वो जगह स्वर्ग है !माँ के प्यार से ज्यादा कुछ नहीं अनमोल होता है। साथियों बात अगर हम माँ दिवस 12 मई को मनाने की करें तो, मातृ दिवस के इस शुभ अवसर पर, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। माँ वह स्तंभ हैं जो हमारे परिवार को संभालती हैं। वो सुबह जल्दी उठकर रात देर तक काम करती हैं ताकि हम खुश रह सकें। वो न सिर्फ हमारे भोजन का ध्यान रखती हैं बल्कि हमारे अच्छे संस्कारों का भी ध्यान रखती हैं। कभी-कभी हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनकी हर बात हमारे भले के लिए ही होती है। इस मौके पर, मैं अपनी माँ से माफी माँगता हूँ उन सब लम्हों के लिए जब मैंने उन्हें दुखी किया और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनके हर त्याग के लिए। मां दिवस हर इंसान के लिए एक विशेष दिन है क्योंकि यह हमें हमारी एकमात्र दुनिया (माँ) को उसके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद कहने का मौका देता है जो उसने पूरी जिंदगी दी है।अपने विचारों को ऐसे शब्दों की भाषा में पिरोना चाहता हूं ताकि दूर गगन में बैठी मेरी माँ सुन सकें और मेरे जीवन में उनके महत्व को महसूस कर सकें। मां दिवस के इस शुभ अवसर पर, दूर गगन में बैठी और मां दिवस पर अदृश्य रूप से मेरे सामने आई अपनी माँ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं हर जगह हर स्थिति में चाहे वह खुशी हो या गम तुम्हारा साथ मैं महसूस कर रहा हूं मां दिवस पर हे मां तुझे प्रणाम वंदन। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि माँ दिवस 12 मई 2024-हे माँ ! तुम्हारे साथ माँ दिवस मनाना है,आओ इस लोक में या बुला लो परलोक में।माँ की गोद एक शरण स्थान है,जहां हमें सुकून मिलता है सभी दुखों का इलाज होता है।माँ धरती पर भगवान का रूप होती है, माँ का स्थान हमारे जीवन में अद्वितीय होता है।

12 मई मातृत्व दिवस पर विशेष

माँ की अदम्य शक्ति और समर्पण को सम्मानित

चुनौतियों को पार करके एक सफल उद्यमी बनने और माँ के दायित्वों को पूरा करने वालीं प्रेमा।

चुनौतियों को पार करके एक सफल उद्यमी बनने और माँ के दायित्वों को पूरा करने वालीं एमेजॉन की ट्रकिंग पार्टनर प्रेमा मदर्स डे के अवसर पर माँ की अदम्य शक्ति और समर्पण को सम्मानित किया जाता है। इस दिन घरों में उनकी दायित्वपूर्ण भूमिका और कार्यस्थल पर उनके कौशल की सराहना की जाती है। जिन नौकरियों में पहले महिलाओं का प्रतिनिधित्व शून्य या बहुत कम हुआ करता था, अब वहाँ महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ती जा रही है, जो अपनी प्रतिभा, मल्टीटास्किंग और दबाव संभालने के कौशल द्वारा संगठन को आगे बढ़ा रही हैं। आज महिलाएँ बाधाओं को पार कर रही हैं, कार्यस्थल पर बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी क्षमता के साथ प्रोफेशनल जीवन में सफलता प्राप्त कर रही हैं, और साथ-साथ एक माँ या केयरगिवर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों में संतुलन भी बना रही हैं। प्रेमा की कहानी इस ट्रेंड का एक अप्रतिम उदाहरण है।

वे एक सिंगल मदर हैं, जिन्होंने न केवल बढ़ता हुआ ट्रकिंग व्यवसाय संभाला, बल्कि दूसरों को भी इस गतिशील उद्योग में आने की प्रेरणा दी। प्रेमा (55 साल) ने अपने पति की असामयिक मृत्यु के बाद व्यक्तिगत चुनौतियों के बीच 2017 में एमेजॉन के ट्रकिंग पार्टनर के रूप में अपना सफर शुरू किया। अपनी बेटी की देखभाल करने की जिम्मेदारी और करियर परिवर्तन के बीच तालमेल बनाते हुए, उन्होंने अडिग इच्छाशक्ति का परिचय दिया। फाइनेंस और मार्केटिंग की बैकग्राउंड के बावजूद प्रेमा ने लॉजिस्टिक्स की दुनिया में प्रवेश किया। एमेजॉन के ट्रकिंग पार्टनर प्रोग्राम की मदद से उन्होंने अपने छोटे से संचालन, सिमर एक्सप्रेस सॉल्यूशंस को बढ़ाकर एमेजॉन पर एक सफल ट्रकिंग बिजनेस बना दिया और उल्लेखनीय वृद्धि एवं सफलता हासिल की। कोरोना महामारी के दौरान भी अपने बिजनेस की प्रवृत्ति और एमेजॉन के सहयोग से प्रेमा ने अनुकूलन के अवसरों का लाभ उठाया और मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी इच्छाशक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती चली गईं। उन्हें अपनी इस मेहनत का फल मिला और पिछले कुछ सालों में उनके बिजनेस ने अपने राजस्व में 55 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। उनकी कहानी उनकी इच्छाशक्ति और दृढ़निश्चय का उदाहरण है, जिसकी मदद से उन्होंने मातृत्व की जिम्मेदारियों में संतुलन बिठाते हुए प्रोफेशनल उपलब्धियाँ हासिल कीं। प्रेमा ने सफल ट्रकिंग कंपनी चलाते हुए अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने की अपनी बेटी की इच्छाओं को पूरा करने में मदद की। जीवन के हर दायित्व में सफल होने की उनकी प्रतिबद्धता सभी माँओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है, जो अपारंपरिक क्षेत्रों में सफल होने की उनकी क्षमता को दशार्ता है। प्रेमा ने कहा, एमेजॉन इंडिया के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। इससे मुझे एक माँ के दायित्वों में संतुलन बिठाते हुए एक सफल करियर का निर्माण करने में मदद मिली। मैं अन्य महिलाओं को भी लॉजिस्टिक्स में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यह एक गतिशील उद्योग है, जो विकास और स्वतंत्रता का सफल मार्ग प्रदान करता है। मैं अपनी बेटी, अपनी टीम और एमेजॉन से मिले बहुमूल्य सहयोग के लिए उनकी आभारी हूँ। प्रेमा के साथ काम करने के अलावा एमेजॉन भारत में 350 से ज्यादा ट्रकिंग पार्टनर्स के साथ काम करता है। ये पार्टनर्स पूरे देश में ग्राहकों के पैकेजेस का ऑन-टाईम, भरोसेमंद और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करते हैं। एमेजॉन इन ट्रकिंग कंपनियों के ड्राईवर्स के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा लाभ और सुरक्षित ड्राईविंग एवं प्रभावशाली पैकेज डिलीवरी के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान प्रदान करता है।

केजरीवाल निर्दोष नहीं शराब घोटाले में, चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर हैं

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 50 दिन तक तिहाड़ जेल की हवा खाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अब वह एक जून तक जेल के बाहर रहेगें और चुनाव प्रचार कर सकेंगे। जेल से बाहर आते ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल को ह्यभारत माता की जयह्व, ह्यवंदे मातरमह्व और ह्याइंकलाब जिंदाबादह्व के क्रांतिकारी नारे याद आ गए। इन्हीं नारों के जरिए केजरीवाल ने माहौल बांधने की कोशिश की। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद मुख्य आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें इस घोटाले का किंगपिन यानि कि सरगना करार दिया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी हो, लेकिन, वो चुनाव परिणाम नहीं देख पाएंगे। दरअसल, गुरुवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून को अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मियाद 5 जून तक बढ़ाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वोटिंग से 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार थम जाता है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। आप पार्टी के अनुसार केजरीवाल को जमानत मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉफ्रेंस करके कहा कि बजरंगबली का उन पर आशिर्वाद है। जमानत मिलने से दिल्ली नहीं पूरा देश खुश है। उनको सियासी षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था, ताकि लोकसभा चुनाव से दूर रहें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा, ह्य सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तानाशाही का अंत होगा। सत्यमेव जयते। देश देखेगा केजरीवाल का कमाल। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। यह फैसला आज के राजनीतिक माहौल के लिए काफी सकारात्मक होगा और विपक्ष को फायदा होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अंततः सत्य और न्याय की जीत होगी। केजरीवाल की बेगुनाही और एनडीए/बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति बिना किसी संदेह के बाहर हो जाएगी। हालांकि, बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में केजरीवाल लिप्त हैं। ये कोर्ट में साफ हो गया है। एक जून के बाद उनको जेल जाना ही होगा। केजरीवाल के जेल से बाहर आने को लेकर सियासी नफा-नुकसान पर सभी के अपने-अपने दावे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि , सीएम केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार ठंडा पड़ा हुआ था। उन्हें लीडरशिप की जरूरत महसूस हो रही थी। जमानत मिलने और जेल से बाहर आने से चुनाव पर सियासी प्रभाव जरूर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के लोगों के हौसले बुलंद होंगे और कार्यकताओं में उत्साह भरेगा। केजरीवाल के जेल में रहने के चलते उनकी पार्टी प्रचार का माहौल नहीं बना पा रही थी। मगर, अब उनके बाहर से आने से सियासी बज क्रिएट होगा। सीएम केजरीवाल की गैर-मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता चुनावी कैंपेन संभाल रही थीं। मगर, मीडिया का अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था। उनके आने से दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह पर प्रचार को धार मिलने के साथ-साथ सियासी लाभ भी मिल सकता है। केजरीवाल सियासी रुख बदलने के माहिर खिलाड़ी हैं। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह आक्रमक प्रचार करेंगे, उससे उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लाभ मिल सकेगा। सीएम भगवंत मान पंजाब तक ही अपना असर दिखा सकते हैं। वो दिल्ली की सियासत पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे। राणा का कहना है कि आगे देखना है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में किसके लिए कितना प्रचार करते हैं, क्योंदि दिल्ली में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। सीएम केजरीवाल अभी तक अदालत में अपनी बेगुनाही के बातें रख रहे थे, लेकिन अब जनता के बीच भी रख सकेंगे। वो जनता की सियासी नब्ज को समझते हैं और उसे मोड़ना उन्हें बाखूबी आता है। वरिष्ठ पत्रकार युसुफ अंसारी कहते हैं कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा हैं। केजरीवाल देश के उन नेताओं में हैं, जिन्हें बीजेपी के सियासी नैरेटिव को काउंटर करना बाखूबी आता है। बीजेपी और पीएम मोदी जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पर खड़ी नजर आ रही है और राममंदिर से लेकर हिंदू-मुसमलान का एजेंडा सेट कर रही है, उसे केजरीवाल बखूबी मोड़ना जानते हैं। केजरीवाल के बाहर आने के बाद पार्टी के उस नैरेटिव को बल मिलेगा कि उन्हें फंसाया गया है।युसुफ अंसारी कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार को धार मिलेगी। गठबंधन के मंच से केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर अब पहले से ज्यादा आक्रमक नजर आ सकते हैं, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकती है। दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी दो चुनाव से लगातार जीत रही है, लेकिन कांग्रेस-अआढ गठबंधन के चलते इस बार चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। अब केजरीवाल के बाहर आने से और भी लाभ मिल सकता है क्योंकि वो साहनुभूति को भी भुनाना बखूबी जानते हैं। वहीं, वरिष्ठ पत्रकार और लोक संसद के संयोजक रविशंकर तिवारी कहते हैं कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने से दिल्ली की सियासत पर कोई खास सियासी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल के जेल में रहने से जो साहनुभूति आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही थी, वो अब खत्म हो सकती है। उनके बाहर आने से बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है, क्योंकि अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया बल्कि चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दी है। बीजेपी और पीएम मोदी ने चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। केजरीवाल के बाहर आने के बाद विपक्ष के मंच पर प्रचार करने के लिए उतरेंगे तो प्रधानमंत्री और बीजेपी उसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है।वो कहते हैं कि देश में जनता के बीच यह एक छवि बनती जा रही थी कि नेता भ्रष्टाचार करने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। मोदी ने बड़े-बड़े भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करके यह छवि तोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार-बार यह कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी, उससे भी सरकार की प्राथमिकता साफ नजर आती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव को लगातार सजायाफ्ता बता रहे हैं। उसी तरह केजरीवाल के खिलाफ भी यही चीज इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं दिल्ली का सियासी मिजाज देखें को राजधानी के लोग लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जगह पर बीजेपी को ही पसंद करते , 2014 और 2019 के नतीजे बता रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल के बाहर आने से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है बल्कि दांव उल्टा पड़ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण राघव का भी मानना है कि केजरीवाल के बाहर आने से दिल्ली की सियासत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दी है, जिसका मतलब यह नहीं होता है कि बरी हो गए हैं। दिल्ली में पढ़ी-लिखी जनता है और केजरीवाल इसीलिए सियासी तौर पर सफल रहे हैं कि क्योंकि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था और अब उसी जाल में खुद फंस गए हैं। पहले दो विधानसभा चुनावों में केजरीवाल अजेय लग रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे उनके घोटालों की जानकारी लोगों हो रही है, उनसे जनता का मोहभंग हुआ है।वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता अपना मूड बना चुकी है। केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष किस मूंह से जवाब देगा। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में पहले से दो धड़े हैं। हाल में अरविंदर लवली और राजकुमार चौहान जैसे नेता साथ छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं उनकी दलित समुदाय में पकड़ कमजोर हुई है। दलित समुदाय से आने वाले दो विधायकों का मोहभंग हुआ है, जिसमें एक बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल का जादू दिल्ली में फीका पड़ चुका है।

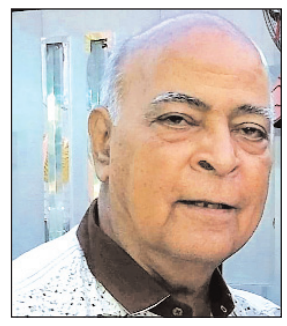

लेखक
अशोक भाटिया
वसई पूर्व, मुंबई

'मां'

यह इक शब्द ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, सृष्टि इसके ही इर्द-गिर्द चलायमान है। हमारा यह स्थूल देह उसी के गर्भ से निर्मित है। आभारी हैं हम ,जिनसे यह अस्तित्व बना है। मां के कदमों में जन्नत है, बस सदा उनकी छत्र-छाया मिले, यही मन्नत है। एक घटना का जिक्र करते हुए याद आया गुलाबी साड़ी में अप्सरा सी दिख रही
अपनी मां से उस बच्ची ने पूछा 'मां कहो ना, क्या बड़ी होकर मैं भी आप सी सुंदर दिखाई दूंगी' तो मां ने कहा "हां मेरी लाडो तू मेरे कोख से जाई है, कोई और नहीं मेरी ही तो परछाई है" और तब वो नन्हीं परी दर्पण में स्वयं को निहार कर बहुत खुश हो उठी, मां और बच्चों का मध्य ऐसा पावन रिश्ता है, जिससे हृदय के कंवल रुपी पुष्प प्रस्फुटित हो उठते हैं। सच यही है कि मां ईश्वर की बनाई हुई सबसे अनमोल कृति है। देवी माँ ने जब श्री विष्णु जी को अनंत ब्रह्मांड के दर्शन करकमलों के एक नख में करवाए तो ह्रीं नाद के दर्शन हुए। मां की ऐसी पारलौकिक छवि के आगे समस्त संसार नतमस्तक है। मां के अनमोल प्यार-दुलार से बढ़ कर और कोई माया नहीं है। मां का स्वरूप देवी का है, क्योंकि वो जगधात्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब कुछ है, जो हर बच्चे को अति प्यारी है। जन्म और मृत्यु के बीच झूल कर अपनी संतान को जन्म देने वाली जगत जननी मां इस धरा पर स्तुत्य है। स्नेह, धैर्य, ममता एवं करुणा की प्रतिमूर्ति, वात्सल्य की प्रतीक, माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इस चराचर जगत में, जिधर भी नजर डाल कर देखते हैं और जो दृश्यमान होता है, शायद ही वो मां से अधिक बलवान होता है। एक बहुचर्चित फिल्म में दो बेटों का संवाद कि "मेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है और तुम्हारे पास क्या है" और जवाब में यह डायलॉग "मेरे पास मां है।" जैसे कानों में सहस्त्र? सितार बज उठते हैं, इस के बाद तो कहने को कुछ शेष ही नहीं बचता है। मां के लिए मन के असंख्य भाव हिलोरें लेते हुए बस यही कहते हैं कि मां तेरे प्रीति के पल ने आंसुओं को हंसाया है मां तेरे भीगे आंचल में भरपूर सुकून पाया है सहस्त्र ढाल बन कर हर बाधाओं से बचाया है मां तेरे गोद में ममत्व छांव जहां मीठी नींद ने अपना सुंदर सा घर बनाया है। भावनाओं का कोई अंत नहीं है, मां के लिए हृदय में प्रेम रुपी अथाह सागर लबालब उमड़ रहा है,अंतिम दोहों के साथ एक सार्थक संदेश के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूं...
मां मूरत भगवान की, जो मांगे सो देय।
ममता की बरसात कर, विपदा सब हर लेय।।
(गूगल साभार)
मां की सेवा जो करे, धन्य वही संतान
सुख ऐश्वर्य मान मिले, कहे सारे पुराण।।
(स्वरचित सृजन)

मधु भूतड़ा 'अक्षरा'
गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सप्रर्टस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कॉमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र \ 9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

सम्पादकीय

अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में

सर्वोच्च अदालत ने लोक सभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और जांच एजेंसी से इसका जवाब मांगा।अदालत ने पांच सवाल पूछे और उनके जवाब लेकर आने का निर्देश दिया। दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत महत्त्वपूर्ण है। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के संबंध में है। न्यायिक कार्यवाही के बिना, जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में कार्यवाही कर सकते हैं।अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं। हमें बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां है। क्या हम सीमा को बहुत विस्तृत बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी है, उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों। केजरीवाल 21 मार्च से शराब नीति घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल इस गिरफ्तारी से पहले ही सार्वजनिक तौर पर कई मर्तबा दोहरा चुके थे कि मोदी सरकार लोक सभा चुनाव के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।दिल्ली सरकार के नेता पहले ही जेल में हैं। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता विभिन्न राजनैतिक दलों के लिए चुनौती बनती जा रही है। सत्ताधारी दल की यह जिम्मेदारी है कि वह अन्य विपक्षी दलों के साथ पूर्वाग्रह भरा बर्ताव करने से बचे। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 में स्पष्ट प्रावधान है, कोई भी गिरफ्तारी इसके अधीन ही होनी चाहिए। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बता रहे हैं।यह कहना गलत नहीं है कि चुनाव के दरम्यान लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं तथा नोटिस भी थमाए जा रहे हैं या छापे तक डाले जा रहे हैं। दरअसल, केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनके उत्तर मिलने चाहिए। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती।बेशक, न्यायिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाला कोई भी राजनीतिज्ञ यदि किसी तरह के घोटाले में शामिल है तो उसे दंडित करने के लिए अदालतें हैं। अदालतोंपर पहले ही लंबित मामलों का दबाव है।उस पर मोदी सरकार लगातार आरोपियों को भाजपा में शामिल कर उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर स्पष्ट संकेत दे रही है। यह अपने आप में गलत संदेश दे रहा है। बावजूद इसके अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में है, जो मूकदर्शक जरूर है, लेकिन अपना निर्णय समय आने पर देगी।

सुप्रीम कोर्ट में खुली ईडी की कलई

सनत जैन

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडी के वकीलों के तमाम विरोध के बावजूद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर किस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं को जेलों में बंद करके रखा जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उजागर हो गया। न्यायपालिका की भूमिका भी अब स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ गई है। जांच एजेंसियां यदि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। ऐसी स्थिति में संविधान ने न्यायपालिका को सर्वोच्चता दे रखी है। ताकि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न कर सकें। पहली बार ईडी को सुप्रीम कोर्ट में मात खानी पड़ी है। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी न्यायाधीश पीएमएल कानून के तहत जो शक्तियां ईडी को मिली हैं, उन शक्तियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी किस तरह से कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। दो–दो साल तक आरोपियों को जेल में बंद रखते हैं। तारीख पर तारीख और चार्ज सीट पर चार्ज सीट का जो खेल खेल रहे हैं। आरोपियों को अपनी कस्टडी में रखकर उनसे मनचाहा बयान दबाव बनाकर लेते हैं। किस तरह लोगों को फंसाते हैं। किस तरह से उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस तरह से इस कानून का दुरुपयोग किया गया है। यह बात अब खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं की थी, बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे, कि केंद्रीय परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कानून और नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। उन्होंने अवैध गिरफ्तारी के विरोध में अपनी सारी बहस को सीमित रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे खुलासे किये। शराब घोटाले में किस तरह से आम आदमी पार्टी और उनके प्रमुख नेताओं के खिलाफ कई वर्षो से जांच चल रही है। सैकड़ों छापे डाले गए। जिन लोगों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी, उनके बयान कस्टडी में रखकर जबरिया लिए गए हैं। लंबे समय तक जेल में जिन आरोपियों को रखा गया। जिन लोगों ने बयान दिए थे। जिनके बयान पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके एक राजनीतिक दल के साथ रिश्ते और चुनावी चंदा तक की बातें सुप्रीम कोर्ट में आईं। किस तरह केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने तथ्यों को छुपाया है। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में इसका खुलासा होता चला गया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की खंडपीठ ने इस सारे मामले को जब अच्छे तरीके से समझ लिया। तब जाकर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए दी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में उनका चुनाव कार्य में भाग लेना, कितना आवश्यक है। यह सुप्रीम कोर्ट ने समझा, पहली बार ईडी के वकीलों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में न केवल अंतिम जमानत का फैसला दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है, कि यदि इस तरीके की अवैध गिरफ्तारी की गई है तो हम इस मामले में जल्द ही निर्णय लेंगे। जिस तरह से सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सभी आपत्तियों को संविधान पीठ ने दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तथा न्यायपालिका की विश्वसनीयता और सर्वोच्चता को लेकर लोगों के मन में एक विश्वास जागा है। कानून के राज में सभी कानून से बंधे हैं। चाहे वह न्यायपालिका हो, जांच अधिकारी हो, सरकार हो या नागरिक हों। सभी को नियम और कानून का पालन करना अनिवार्य है।

गर्मी जल्दी आई साथ में प्यास भी गहराई

पंकज चतुर्वेदी

इस बार गर्मी जल्दी आई और साथ में प्यास भी गहराई। केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी हर घर जल योजनाङ्क ने बढ़ते ताप के सामने दम तोड़ दिया। आखिर, धरती का सीना चीर कर गहराई से पानी उलीचने से हर एक का कंठ तर होने से तो रहा। वैसे हकीकत तो यह है कि अब देश के 32 फीसद हिस्से को पानी की किल्लत के लिए गरमी के मौसम का इंतजार भी नहीं करना पड़ता– बारहों महीने, तीसों दिन जेठ ही रहता है। कुछ दशक पहले पलट कर देखें तो आज पानी के लिए हाय–हाय कर रहे इलाके अपने स्थानीय स्रोतों की मदद से ही खेत और गले, दोनों के लिए अफरात पानी जुटाते थे। एक दौर आया कि अंधाधुंध नलकूप रोपे जाने लगे, जब तक संभलते जब तक भूगर्भ का कोटा साफ हो चुका था। समाज को एक बार फिर बीती बात बन चुके जल–स्रोतों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है–तालाब, कुएं, बावड़ी। लेकिन एक बार फिर पीढि ों का अंतर सामने खड़ा है, पारंपरिक तालाबों की देखभाल करने वाले लोग किसी ओर काम में लग गए और अब तालाब सहेजने की तकनीक नदारद हो गई है। तभी बीते तीन दशक में केंद्र और राज्य की अनेक योजनाओं के तहत तालाबों से गाद निकालने, उन्हें सहेजने के नाम पर अफरात पैसा खर्च किया गया और नतीजा रहा वही ढाक के तीन पात!ङ्भारत के हर हिस्से में वैदिक काल से लेकर ब्रितानी हुकूमत के पहले तक सभी कालखंडों में समाज द्वारा अपनी देश–काल–परिस्थिति के मुताबिक बनाई गई जल संरचनाओं और जल पणालियों के कई प्रमाण मिलते हैं, जिनमें तालाब हर जगह हैं। रेगिस्तान में तो उन तालाबों को सागर की उपमा दे दी गई तो कन्नड में कैरे और तमिल में ऐरी। यहां तक कि ऋग्वेद में भी सिंचित खेती, कुओं और गहराई से पानी खींचने वाली प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो (ईसा से 3000 से 1500 साल पूर्व) में जलापूर्ति और मल निकासी की बेहतरीन पणालियों के अवशेष मिले हैं। ईसा से 321–297 साल पहले, कौटिल्य का अर्थशास्त्र बानगी है जो बताता है कि तालाबों को राज्य की जमीन पर बनाया जाता था। समाज ही तालाब गढ़ने का सामान जुटाता था। जो लोग इस काम में असहयोग करते या तालाब की पाल को नुकसान पहुंचाते उन्हें राज्य–दंड मिलता।

भारत में अंगदान की कमी से जा रही लोगों की जान

तीन लाख से अधिक रोगियों की प्रतीक्षा सूची और अंग के इंतजार में हर दिन कम से कम 20 लोगों की मृत्यु के साथ, भारत में अंग दान की कमी, विशेष रूप से मृतक दान, भारी नुकसान उठा रही है। भारत में मृतक अंगदान की दर पिछले एक दशक से प्रति दस लाख की आबादी पर एक दाता से कम रही है। भारत को इसे प्रति मिलियन जनसंख्या पर 65 दान तक बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ना होगा। देश में लगभग 600 मेडिकल कॉलेज और 20 से अधिक एम्स हैं। अगर हमें हर साल उनसे एक-एक दान भी मिले तो हम बेहतर स्थिति में रहेंगे।ह्न दुनिया भर में भी, अंगों की आवश्यकता वाले केवल 10% रोगियों को ही समय पर अंग मिल पाते हैं। स्पेन और अमेरिका में बेहतर अंग दान प्रणाली है, जहां प्रति मिलियन 30-50 दान की दर है। मरीजों के परिवारों को आगे आने और दान करने में मदद करने के लिए ट्रॉमा और आईसीयू डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना समय की मांग है, कई संभावित मामलों की उपलब्धता के बावजूद, भारत में अंग दान की कम दर मस्तिष्क मृत्यु या मस्तिष्क स्टेम मृत्यु मामलों की अपर्याप्त पहचान और प्रमाणीकरण के कारण हो रही है। अंगदान के मामले में देश का वार्षिक औसत अब भी प्रति दस लाख लोगों पर एक से भी कम दाता है। सड़क परिवहन के आंकडों के मुताबिक भारत में हर साल, करीब 150, 000 लोग सड़कों पर मारे जाते हैं। इसका मतलब औसतन हर रोज सड़कों पर 1000 से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और 400 से ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं।

डॉ सत्यवान सौरभ
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

देश में तीन लाख मरीज अंगदान का इंतजार कर रहे हैं और देश में दाताओं की संख्या में वृद्धि मांग के अनुरूप नहीं है; विशेषज्ञों का कहना है कि देश को तत्काल मृतक दान दर बढ़ाने की जरूरत है, और आईसीयू डॉक्टरों और परिवारों के बीच इस बारे में अधिक जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे एक मृतक दानकर्ता कई जिंदगियां बचा सकता है। तीन लाख से अधिक रोगियों की प्रतीक्षा सूची और अंग के इंतजार में हर दिन कम से कम 20 लोगों की मृत्यु के साथ, भारत में अंग दान की कमी, विशेष रूप से मृतक दान, भारी नुकसान उठा रही है। भारत में मृतक अंगदान की दर पिछले एक दशक से प्रति दस लाख की आबादी पर एक दाता से कम रही है।

भारत को इसे प्रति मिलियन जनसंख्या पर 65 दान तक बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ना होगा। देश में लगभग 600 मेडिकल कॉलेज और 20 से अधिक एम्स हैं। अगर हमें हर साल उनसे एक-एक दान भी मिले तो हम बेहतर स्थिति में रहेंगे।ह्न दुनिया भर में भी, अंगों की आवश्यकता वाले केवल 10% रोगियों को ही समय पर अंग मिल पाते हैं। स्पेन और अमेरिका में बेहतर अंग दान प्रणाली है, जहां प्रति मिलियन 30-50 दान की दर है। मरीजों के परिवारों को आगे आने और दान करने में मदद करने के लिए ट्रॉमा और आईसीयू डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना समय की मांग है, कई संभावित मामलों की उपलब्धता के बावजूद, भारत में अंग दान की कम दर मस्तिष्क मृत्यु या मस्तिष्क स्टेम मृत्यु मामलों की अपर्याप्त पहचान और प्रमाणीकरण के कारण हो रही है। अंगदान के मामले में देश का वार्षिक औसत अब भी प्रति दस लाख लोगों पर एक से भी कम दाता है।

सड़क परिवहन के आंकडों के मुताबिक भारत में हर साल, करीब 150, 000 लोग सड़कों पर मारे जाते हैं। इसका मतलब औसतन हर रोज सड़कों पर 1000 से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और 400 से ज्यादा लोग दम तोड़ देते हैं। अंग दान में मृत डोनर के अंगों- जैसे हृदय, यकृत (लिवर), गुर्दे (किडनी), आंतें, आंखें, फेफड़े और अग्न्याशय (पैनक्रियाज) को निकाल कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसे जीवित रहने के लिए उनकी जरूरत है। एक मृत डोनर, जिसे कैडेवर भी कहा जाता है, इस तरह नौ लोगों की जान बचा सकता है। हालांकि हेल्थ प्रोफेशनल आमतौर पर अंगदान के विषय पर मृतक के परिजनों से बात करने में अटपटा महसूस करते हैं। डॉक्टर मृतक के अंगों को दान देने के बारे में पूछने से कतराते हैं। कोई इस बारे में प्रोत्साहन भी नहीं है और बदले की कार्रवाई का डर भी रहता है।

जनता अनिच्छुक और अविश्वासी है क्योंकि वे मस्तिष्क मृत्यु, अंग दान के विचार या इसके फायदों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। मृत्यु के बाद शरीर के बारे में सांस्कृतिक रीति-रिवाज सहमति में बाधा डाल सकते हैं, और कुछ धार्मिक मान्यताएँ अंग दान पर रोक लगाती हैं।भारत में पर्याप्त प्रत्यारोपण केंद्र, आवश्यक प्रशिक्षण वाले चिकित्सा पेशेवर या अंगों की पुनर्प्राप्ति, संरक्षण और परिवहन के लिए संसाधन नहीं हैं। अंग दान के लिए परिवार की सहमति प्राप्त करना अक्सर आवश्यक होता है। यह एक लंबी और भावनात्मक रूप से कठिन प्रक्रिया हो सकती है, जो दान में देरी कर सकती है या उसे रोक भी सकती है। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां अंग उपलब्ध हैं, कई रोगियों की पहुंच प्रत्यारोपण सर्जरी और पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल की उच्च लागत के कारण और भी सीमित है।

अंग विफलता वाले कई मरीज अंग की तीव्र कमी के परिणामस्वरूप प्रत्यारोपण का इंतजार करते समय मर जाते हैं।अगों की अत्यधिक आवश्यकता के कारण अवैध अंग व्यापार नेटवर्क को बढ़ावा मिलता है, जो कमजोर लोगों को नैतिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के साथ-साथ शोषण के खतरे में डालता है। अंगों की सीमित आपूर्ति के कारण स्वास्थ्य संबंधी असमानताएं बढ़ जाती हैं, जिससे पैसे वाले लोगों के लिए इसकी संभावना अधिक हो जाती है। जीवनरक्षक प्रत्यारोपण प्राप्त करें। डायलिसिस और अन्य सहायक देखभाल उन कई संसाधनों में से हैं जिन पर अंतिम चरण के अंग विफलता वाले रोगियों के प्रबंधन के कार्य द्वारा भारी कर लगाया जाता है।

सभी बातों पर विचार करने पर, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निम्न अंगदान दरों से बहुत प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप टाली जा सकने वाली मौतें, अनैतिक व्यवहार और जीवन रक्षक देखभाल तक असमान पहुंच होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को अंग प्रत्यारोपण तक उचित पहुंच मिले, इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जिसमें नैतिक विचार, कानूनी सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और सार्वजनिक शिक्षा शामिल है। एक मृत अंग दाता आठ लोगों की जान बचा सकता है। दान की गई दो किडनी दो रोगियों को डायलिसिस उपचार से मुक्त कर सकती हैं।

दान किए गए एक लीवर को प्रतीक्षा सूची के दो रोगियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। दो दान किए गए फेफड़ों का मतलब है कि दो अन्य रोगियों को दूसरा मौका दिया गया है, और एक दान किए गए अग्न्याशय और दान किए गए हृदय का मतलब दो और रोगियों को जीवन का उपहार प्राप्त करना है। एक ऊतक दाता - कोई व्यक्ति जो हड्डी, टेंडन, उपास्थि, संयोजी ऊतक, त्वचा, कॉर्निया, श्वेतपटल, और हृदय वाल्व और वाहिकाओं को दान कर सकता है। 75 लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। भारत में अंग दान की प्रतिज्ञा को वास्तविक दान में तब्दील करने की जरूरत है और इसके लिए मेडिकल स्टाफ को शिक्षित करने की जरूरत है। उन्हें मस्तिष्क मृत्यु और अंग दान के महत्व के बारे में परिवारों को पहचानने, पहचानने, सूचित करने और परामर्श देने में सक्षम होना चाहिए।

संकुचित व षड्यंत्रकारी चुनावी विमर्श अत्यंत चिंतनीय

जो खिलाफ हैं वह हराम जादे हैं।इसके साथ ही स्वयं बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाली यही भाजपा अपने विरोधी दलों को अल्पसंख्यक परस्त व मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दलों के रूप में पूरे जोर शोर से प्रचारित कर रही है।अपने इस ह्यअनैतिकह्न अभियान में वह वर्तमान चुनावी बेला में सार्वजनिक मंचों से जिन शब्दों व वाक्यों का इस्तेमाल कर रही है वह भारतीय राजनीति के इतिहास का अब तक का सबसे गिरा व निम्नस्तरीय चुनाव अभियान है।यह इस बात का भी परिचायक है कि अबकी बार चार सौ पार का हवाई नारा देने वाली भाजपा व इसके शीर्ष नेता समझ चुके हैं कि जनता अब उनके विघटनकारी मंसूबों को समझ चुकी है।और 400 पार की बात तो दूर इस बार तो उनकी सत्ता में वापसी पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है।गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या स्थित विवादित मंदिर मस्जिद मुकददमे का निर्णय सुनाया गया। इसी फैसले में केंद्र सरकार से एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण करने को कहा गया। यहाँ यह भी काबिल–ए–गौर है कि मंदिर–मस्जिद अदालती वाद परिवाद में मुद्दई के रूप में न तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था न विश्व हिन्दू परिषद् न ही भाजपा।परन्तु केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार होने के नाते बड़ी ही चतुराई से ट्रस्ट के गठन से लेकर मंदिर निर्माण व उद्घाटन तक के इस पूरे प्रकरण का भाजपा द्वारा निजीकरण कर लिया गया।

निर्मल रानी
लेखक वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार हैं

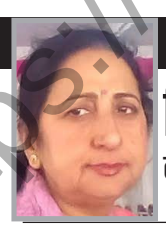

विगत चार दशकों से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर राजनीति कर स्वयं को स्थापित करने की कोशिश करती रही है। आखिरकार धार्मिक ध्रुवीकरण व राम मंदिर की राजनीति ने उसे केंद्रीय सत्ता में आने में मदद की और यह भाजपा का लोकप्रिय मुद्दा बन गया। अब वही भाजपा इससे भी दो कदम आगे बढ़कर जहाँ सर्वव्यापी मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपना निजी ह्यभगवानह्न समझने लगी है वहीँ अपने विरोधी दलों को राम विरोधी तो राम द्रोही आदि प्रचारित कर रही है। इसी दल की एक सांसद यहाँ तक कह चुकी है कि जो हमारे साथ हैं वह रामजादे हैं और जो खिलाफ हैं वह हराम जादे हैं। इसके साथ ही स्वयं बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाली यही भाजपा अपने विरोधी दलों को अल्पसंख्यक परस्त व मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दलों के रूप में पूरे जोर शोर से प्रचारित कर रही है। अपने इस ह्यअनैतिकह्न अभियान में वह वर्तमान चुनावी बेला में सार्वजनिक मंचों से जिन शब्दों व वाक्यों का इस्तेमाल कर रही है वह भारतीय राजनीति के इतिहास का अब तक का सबसे गिरा व निम्नस्तरीय चुनाव अभियान है। यह इस बात का भी परिचायक है कि अबकी बार चार सौ पार का हवाई नारा देने वाली भाजपा व इसके शीर्ष नेता समझ चुके हैं कि जनता अब उनके विघटनकारी मंसूबों को समझ चुकी है। और 400 पार की बात तो दूर इस बार तो उनकी सत्ता में वापसी पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या स्थित विवादित मंदिर मस्जिद मुकददमे का निर्णय सुनाया गया। इसी फैसले में केंद्र सरकार से एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण करने को कहा गया। यहाँ यह भी काबिल-ए-गौर है कि मंदिर-मस्जिद अदालती वाद परिवाद में मुद्दई के रूप में न तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था न विश्व हिन्दू परिषद् न ही भाजपा। परन्तु केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार होने के नाते बड़ी ही चतुराई से ट्रस्ट के गठन से लेकर मंदिर निर्माण व उद्घाटन तक के इस पूरे प्रकरण का भाजपा द्वारा निजीकरण कर लिया गया। यहाँ तक कि 22 जनवरी 2024 को हुये मंदिर उद्घाटन के दौरान इसके प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक विधि विधान सम्बन्धी तौर तरीकों व समय को लेकर देश के चारों शंकराचार्यों सहित तमाम संतों महंतों द्वारा इसका कितना तार्किक विरोध किया गया। परन्तु उन सब की अनसुनी कर दी गयी। और मंदिर ट्रस्ट से लेकर इसके उद्घाटन तक को पूर्णतः भाजपाई इवेंट के रूप में पेश किया गया। और अब उसी आधार पर यह कहकर वोट माँगा जा रहा है कि ह्यजो राम को लाये हैं हम उनको लाएंगे।

देश के चारों शंकराचार्य ही नहीं बल्कि हजारों वरिष्ठ संतों ने तथा भाजपा विरोधी दलों ने यह बखूबी समझ लिया था कि ट्रस्ट गठन से लेकर प्राणप्रतिष्ठा तक का पूरा कार्यक्रम पूरी तरह राजनैतिक व अनैतिक है। इसी लिये जहां शंकराचार्यों ने इस आयोजन में शिरकत नहीं की वहीँ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी 22 जनवरी के इस ह्यराजनैतिक आयोजनह्न से दूरी बनाये रखी। इतना ही नहीं बल्कि कई प्रमुख केंद्रीय मंत्री व भाजपाई मुख्यमंत्री भी अभी तक अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर दर्शन करने नहीं गए हैं। परन्तु भाजपा के निशाने पर केवल कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के नेता हैं। भाजपा इसे लेकर ऐसे ऐसे दुष्प्रचार कर रही है ताकि वह किसी तरह कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के अन्य दलों व उनके नेताओं को राम विरोधी साबित कर सके। अफसोस की बात तो यह है कि कल के धर्मनिर्पेक्षतावादी जो आज भगवा रंग में रंग रहे हैं उनसे भी भाजपा यही कहलवा रही है कि कांग्रेस राम विरोधी है। और कांग्रेस अयोध्या मंदिर दर्शन करने का विरोध करती है।

जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट अयोध्या दर्शन करने जा चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ राम मंदिर जा चुके। सांसद दीपेंद्र हुडा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेसे तमाम कांग्रेस नेता 22 जनवरी के बाद अयोध्या जा चुके हैं। परन्तु कांग्रेस आला कमान ने किसी नेता से इस विषय पर कोई सवाल नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस शुरू से यही मानती आ रही है कि धर्म व धर्म पालना किसी भी व्यक्ति का आस्था सम्बन्धी अत्यंत निजी विषय है। इसकी पालना करने या न करने का प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है। कांग्रेस ने न तो कभी राम के नाम पर वोट माँगा न ही राम के विरोध के नाम पर। परन्तु दुष्प्रचार की इंतेहा यह कि नरेंद्र मोदी स्वयं यह कह रहे हैं कि मैं ह्यलोकसभा चुनाव में 400 सीट इसलिए जीतना चाहता हूं कि ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक (मुसलमानों) का है। लेकिन जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेक्युलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा, और ये हजारों वर्ष पुराने भारत को, उसकी इस संतान की गारंटी है।ह्नह्न देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ यह वाक्यविपक्षी दलों के लिये कितनी कुंठा से भरा व हताशा से परिपूर्ण प्रतीत होता है? आज देश मंहगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमेरिकी डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में आ रही अभूतपूर्व गिरावट, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, (पीएसयू) के चंद निजी हाथों में सौंपे जाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रहा है। परन्तु सरकार के पास इनका न तो कोई जवाब है न ही इनके समाधान की कोई नीति। 2019 का चुनाव इसी मोदी सरकार ने मुफ़्त राशन पाने वाले

जमानत से जनमत तक का सफर

राकेश अचल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अक्षय तृतीया के दिन जमानत के रूप में नवजीवन मिल गया। जमानत अंतरिम है और केजरीवाल को 2 जून को दोबारा अदालत के समक्ष समर्पण करना होगा ,लेकिन वे अपनी जमानत की अवधि में अठारहवीं लोकसभा के लिए होने वाले शेष चार चरणों के चुनाव में खुलकर न सिर्फ प्रचार कर पाएंगे बल्कि भाजपा की उन तमाम साजिशों को भी बेनकाब भी कर पाएंगे जो दस साल से विपक्ष के खिलाफ की जा रहीं हैं।

अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा हुआ की वे 50 दिन की जेल यात्रा कर आये। स्वाधीनता से पहले जेल यात्राओं को एक तरह का बलिदान माना जाता था। आजादी के बाद जेल यात्राओं का रंग ही बदल गया। अब नेता भ्ष्टार्चार के आरोपों में जेल जाते हैं। जनांदोलनों के चलते जेल जाने वालों की संख्या लगातार घटी है। केजरीवाल हालाँकि आंदोलन की कोख से निकले ही नेता हैं, लेकिन हैं तो पुराने नौकरशाह। इसीलिए वे भाजपा के मोदी और शाह से टक्कर ले पा रहे हैं। उन्हें जेल भी शायद इसीलिए जाना पड़ा लेकिन कानून ने उनकी मदद की और अंततः अंतरिम जमानत दिला दी। लोकसभा चुनाव के चार चरण अरविंद केजरीवाल के बिना समपन्न हो गए। विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन को केजरीवाल से जो लाभ मिलना चाहिए था ,उतना नहीं मिल पाया। लेकिन जमानत पर आने के बाद वे बीस दिन में इतना कुछ काम कर लेंगे की भाजपा सरकार को चुनौती दी जा सके। अरविंद पहले भाजपा की बी टीम समझे जाते थे किन्तु बाद में वे इस छवि से बाहर निकल आय। उन्होंने शराब घोटाले में अपने आपको लपेटे जाने के बाद भाजपा के खिलाफ कमर कास ली थी। केजरीवाल और उनकी पार्टी की हैसियत इस समय कांग्रेस को छोड़ दीगर क्षेत्रीय दलों से कहीं ज्यादा है। उनकी अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी एक से अधिक राज्यों में सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल एंड कम्पनी दिल्ली से बाहर पहले पंजाब तक ले गयी और बाद में उसने गोवा,गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को अपदस्थ करने के महाअभियान में शामिल है। आपको पता ही है की भाजपा की इस समय सिट्टी–पिट्टी गुम है। भाजपा अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के बजाय उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जो की उसे कॉंग्रेसने दिए हैं। भाजपा अब मोदी जी के चेहरे और मोदी जी की गारंटियों पर चुनाव नहीं लड़ रही। चुनाव जीतने के लिए भाजपा को हारकर हिन्दू–मुसलमान पर आना पड़ा। मतदाताओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों से आतंकित करने के लिए पहले मंगलसूत्र छीने जाने ,बाद में विरासत पर कार लगाए जाने और सबसे बाद में अंकल सैम पित्रोदा के निजी बयानों का इस्तेमाल करने पर विवश होना पड़ा। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद अब भाजपा कौन से हुआ खड़ा करेगी ये कहना कठिन है। केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत का इस्तेमाल जनमत को आईएनडीआईए के पक्ष में बनाने के लिए कार सकते है। वे मुख्त वक्ता हैं। दिल्ली में उनकी पार्टी की राज्य सरकार है। सबसे बड़ी बात तो ये हैं की वे कंगाल नहीं हैं। पंजाब में भी उनकी सरकार है। दिल्ली की जनता उन्हें पसंद करती है। इसका असर दिल्ली की ७ लोकसभा सीटों के अलावा दुसरे राज्यों पर भी पडेगा। अब विपक्ष के पास राहुल हैं ,अखिलेश भी हैं और केजरीवाल भी। ये तिकड़ी भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। भाजपा जितने हौवे मतदाताओं को भयभीत करने के लिए खड़े कर सकती थी ,वो कर चुकी। अरविंद को भाजपा हौवे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे प्रखर वक्ता हैं ,नेता है और मोदी से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। मोदी जी की घबड़ाहट और केजरीवाल की रण में वापसी के चलते चुनाव के शेष चार चरण और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी कोई 260 सीटों के लिए मतदान होना बाकी है। इन सीटों में से अरविंद केजरीवाल कितनी सीटों को प्रभावित कर सकते हैं कहना कठिन है ,लेकिन ये लगभग तय है की भाजपा के 370 बनाम 400 पार का लक्ष्य अब भाजपा के लिए आसान नहीं है। केजरीवाल को मिली जमानत इसी तरह के दूसरे मामलों में विचाराधीन कैदी की तरह जेलों में बंद दुसरे जन नेताओं के लिए भी नजीर का काम कर सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सन्मार्ग
पटना, रविवार, 12 मई 2024
www.live7tv.com

आचार्य चाणक्य ने ऐसी महिलाओं को भी गलत माना है जो सिर्फ अपनी चलाती हैं और घर में किसी बात नहीं सुनती। उनका कहना है जो महिलाएं अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चलती। पति, संतान और माता-पिता के बारे में जरा भी नहीं सोचतीं ऐसी महिलाओं से दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है। ऐसी महिलाएं अपने साथ-साथ उन लोगों का भी नुकसान करवा देती हैं, जो उनसे जुड़े होते हैं।

चाणक्य

लोकसभा चुनाव में हवा नहीं, हक की बात, समझिए बिहार की चुनावी स्थिति

उदय चंद्र

पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव एकतरफा होगा। लेकिन, बिहार को देखकर पता चलता है कि क्यों मुकाबला उम्मीद से अधिक करीबी हो सकता है और कैसे गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर है।

मुश्किल में थी बीजेपीः बिहार के सीएम और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने जनवरी में दोबारा पाला बदला। उससे पहले तक लग रहा था कि बीजेपी को राज्य में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। पड़ोसी राज्य यूपी के विपरीत बिहार में बीजेपी के पास कोई प्रमुख क्षेत्रीय नेता नहीं था। न तो पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश पर्याप्त लग रहे थे और न ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। विपक्ष ने बिहार की तरह पूरे देश में जातिगत जनगणना का वादा कर हिंदुत्व के रथ को एक बार फिर से रोक दिया था।

ओबीसी पर नजरः बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं। इसी बीच ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी ने आखिरी प्रयास किया। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। नीतीश बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत कम थे।

कमजोर कड़ीः आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सहयोगियों से पिछड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी थे। जेडीयू के जातीय समीकरण सबसे अच्छे फिट बैठते हैं बीजेपी के साथ। वहां उम्मीद रहती है कि बीजेपी का परंपरागत सवर्ण वोटर पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को भी वोट देगा। नीतीश के लिए तीसरी अहम बात यह हुई कि एनडीए में जाकर वह चिराग पासवान पर भी नजर रख सकते हैं, जो पिछले चुनाव में उनके धुर विरोधी थे।

मंदिर का असरः एनडीए इस बार 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहता है, जब उसने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन, उसका समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। बीजेपी के धुर समर्थकों को छोड़कर अयोध्या का राम मंदिर बहुत कम लोगों को उत्साहित कर रहा है। वोटरों का ध्यान भविष्य के वादों पर केंद्रित है। आरजेडी के युवा चेहरे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार में जाति जनगणना का श्रेय ले रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने इसके लिए अनिच्छुक नीतीश कुमार पर दबाव डाला था।

नया समाजवादः जाति जनगणना पर आधारित नैशनल पॉलिसी का वादा कर कांग्रेस का घोषणापत्र शायद और आगे निकल गया। दिल्ली के गलियारों में इसे मंडल 2.0 के तौर पर देखा जा रहा है। हकीकत में यह डिजिटल युग के लिए नया समाजवाद है, जो जितनी आबादी उतना हक के विचार पर आधारित है। तेजस्वी का नया समाजवाद उस राजनीति से ऊपर उठना चाहता है, जिसमें किसी से उसकी जाति पूछी जाती है। बिहार में अगड़ी जातियां यानी ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत आबादी के छठे हिस्से से भी कम हैं। ऐसे में जाति जनगणना का मुद्दा एक मजबूत चुनावी गठबंधन बना सकता है।

मजबूत विपक्षः कई जिलों में, जहां मुस्लिमों की संख्या आबादी के पांचवें हिस्से के करीब है, विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। यह स्थिति खासकर मध्य और दक्षिण बिहार में है। इसके अलावा, आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने लाखों नई नौकरियों का वादा किया है। यह सीधे तौर पर बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को जाहिर करता है।

हिंदुत्व को टक्करः दिल्ली की सुर्खियों से दूर बिहार में हिंदुत्व को एक नया प्रतिद्वंद्वी मिला है। यह प्रतिद्वंद्वी है जाति, वर्ग और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राजनीति का मिश्रण। अब बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उसका झुकाव अगड़ी जातियों की ओर नहीं है। लेकिन, साथ में उसे अगड़े वोटबैंक को भी साधे रखना है।

कठिन चुनावः दोनों विरोधी एक समान मजबूत हैं। ऐसे में स्विंग वोटर को दो विरोधी धारणाओं के बीच चुनाव करना होगा। एक पक्ष मजबूत व्यक्तित्व केंद्रित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वादा करता है। साथ में, कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों तक लाभ पहुंचा रहा है। दूसरा पक्ष सामाजिक न्याय की नई राजनीति की पेशकश कर रहा। ऐसे में सात चरणों में बिहार में मतदाताओं को कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ेगा। इस बात की संभावना है कि निर्णय बंटा हुआ हो। ऐसे चुनाव में जहां कोई राजनीतिक हवा न चल रही हो, वहां राजनेता वोटरों से व्यावहारिक अपील करने के लिए मजबूर होते हैं। मतदाताओं को भी उतने ही कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं।

काम पर मुहरः लोकतांत्रिक जीवन में, सभी राजनीतिक दलों में करिश्माई नेता फले-फूले। फिर हमने देखा कि उनकी अपील का चुनावों पर असर घटता गया। एक बार जब जादू टूटता है तो मतदाता अक्सर भ्रमित और निराश हो जाते हैं। नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को राजनेताओं द्वारा अधिकतर अनदेखा किया जाता है, फिर चाहे वे लेफ्ट से हों या राइट से या फिर बीच से। चुनावों में जहां एक भावना प्रबल नहीं होती, मतदाता निर्णय के माध्यम से विकल्प चुनते हैं कि कौन उनके लिए क्या कर सकता है।

हक की बातः बिहार में ही सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वह बुद्ध हुए। अब यह राज्य हमें ज्ञान दे सकता है कि मतदाता यह निर्णय कैसे लेते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं। जब कोई हवा कमजोर होती है या खत्म होती है, तो लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाता। वास्तव में यह तब पनप सकता है। रोजमर्रा के जरूरी मुद्दों पर वोटर एक-दूसरे से असहमत हो सकते हैं और राजनेताओं को भी इन मुद्दों पर बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह राजनीति में हक का दायरा बढ़ता है।

(ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

यात्रियों की मुसीबत

एयर इंडिया एक्सप्रेस को लगातार दूसरे दिन गुरुवार को बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसल करनी पड़ी। हालांकि सहयोगी कंपनी एयर इंडिया उसकी मदद के लिए आगे आई और खबर है कि करीब 20 रुटों पर पर वह उड़ानें संचालित कर रही है। फिर भी एयर इंडिया एक्सप्रेस को 85 फ्लाइट कैंसल करनी पड़ीं। कंपनी ने बुधवार को भी 80 से ज्यादा फ्लाइट कैंसल की थी। निश्चित रूप से इससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। करीब एक महीने के अंतर पर यह दूसरा मौका है जब टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी के यात्रियों को इस तरह की परेशानियों से दो-चार होना पड़ा है। अप्रैल में ग्रुप की कंपनी विस्तारा को अचानक पायलटों के छुट्टी पर चले जाने से 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। दरअसल, टाटा ग्रुप में अलग-अलग एयरलाइन कंपनियों के विलय की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में अलग-अलग कंपनियों में सैलरी स्ट्रक्चर की रीबैलेंसिंग का चुनौतीपूर्ण काम होना है। यह बिजनेस डिसिजन ग्रुप का आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से इसका असर उड़ानों के रद्द होने के रूप में सामने आ रहा है और जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, उससे साफ है कि यह काम कुशलता से नहीं किया जा रहा। देश का एविएशन सेक्टर कई तरह के दबावों से जूझ रहा है। हालांकि यह कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर को पीछे छोड़ चुका है। एयर ट्रैफिक मूवमेंट के जो आंकड़े 2022 में 18 करोड़ से कुछ ज्यादा थे, 2023 में वे 32 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। लेकिन यात्रियों की इस बढ़ी हुई संख्या की जरूरतें पूरी करने वाले विमानों की संख्या महामारी-पूर्व के दौर के मुकाबले और कम हो गई है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि हवाई किराए में अच्छी बढ़ोतरी हो चुकी है। दूसरी बात यह कि जब भी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की जाती हैं तो यात्रियों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। इन हालात में उनके लिए वैकल्पिक फ्लाइट्स का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर जनवरी-मार्च तिमाही की बात की जाए तो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट के करीब 90% हिस्से पर इंडिगो और टाटा ग्रुप एयरलाइंस का कब्जा दिखता है। मार्केट पर दो बड़े खिलाड़ियों का वर्चस्व कॉम्पिटिशन के लिहाज से कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। इससे किराए के नीचे आने की उम्मीद भी नहीं बन रही। बहरहाल, ऊंचे किराए और मुनाफे की तगड़ी संभावना के बीच यात्रियों की परेशानी की मौजूदा स्थिति स्वीकार्य नहीं हो सकती। एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए को कंपनियों से यह सुनिश्चित करवाना चाहिए कि उनकी आंतरिक समस्याओं का खामियाजा यात्रियों को न भुगतना पड़े।

बहनजी के फैसले के पीछे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी...

अजय बोस

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी और भतीजे आकाश आनंद को धूमधाम से राजनीति में लाने के बमुश्किल पांच महीने बाद ही पद से बर्खास्त कर दिया। आकाश आनंद की बर्खास्तगी का यह कठोर कदम उनकी पार्टी और समर्थकों के लिए बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव के बीच में उनके इस निर्णय ने पार्टी को अजीब स्थिति में ला दिया है, जिससे पार्टी का चुनावी अभियान भी बाधित हो रहा है। माना जा रहा है कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को सत्ताधारी दल के दबाव में बर्खास्त किया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। असल में, इससे उनका व्यक्तिगत अहंकार भी उजागर होता है, जिसके चलते बहनजी एक चुने हुए उत्तराधिकारी को भी शक्तियां सौंपने के प्रति अनिच्छुक हो गई। उल्लेखनीय है कि सीतापुर में चुनावी रैली के दौरान दिए गए आनंद के भड़काऊ भाषण के तत्काल बाद यह विवादास्पद निर्णय लिया गया है। बताया जाता है कि उस रैली में उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, जो बुआ मायावती को भी ठीक नहीं लगी। बसपा के इस युवा नेता के साथ चार अन्य लोगों-बसपा उम्मीदवार महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और रैली आयोजक विकास राजवंशी पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ की गई आक्रामक टिप्पणियों को लेकर मायावती अपने भतीजे से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें निजी तौर पर चेताया गया था कि अगर बसपा ने ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजनीतिक जीवन के शुरूआती वर्षों में काफी तेज-तर्रार थीं और अपने विरोधियों के खिलाफ तीखे भाषण देती थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलने में काफी सावधानी बरती है।

ऐसी अफवाहें भी हैं कि बहनजी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उनके साथ गुप्त समझौता किया है। हालांकि भाजपा के साथ उनका कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है और वह अपने भाषणों और ट्वीट में सरकार की सांकेतिक रूप से आलोचना भी करती रही हैं। अन्य विपक्षी दल उन पर आरोप लगाते हैं कि वह भाजपा विरोधी वोटों को बांटने के लिए विधानसभा व लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं। बदले में उन्हें पिछले कई दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार के मामलों में राहत मिली हुई है। फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण समय में अपने भतीजे को पद से हटाने के पीछे सरकारी दबाव के अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं। जब बीमार कांशीराम ने बसपा की बागडोर उन्हें सौंपी थी, उस समय भी उन्होंने किसी अन्य पार्टी नेता के साथ सत्ता साझा करने से इन्कार कर दिया था और पार्टी नेताओं से सिर्फ वफादारी ही नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की मांग की थी। वैसे भी आजकल ज्यादातर पार्टियों में एक सर्वोच्च नेता का वर्चस्व बढ़ रहा है और बसपा में तो बहनजी एक अनोखे पद पर आसीन हैं ही। दिलचस्प तथ्य यह है कि पांच साल पहले जब नरेंद्र मोदी और भाजपा ने दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी, तो उसके एक हफ्ते बाद ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया था। कुछ वर्षों बाद बसपा सुप्रीमो ने सार्वजनिक रूप से आनंद की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें पार्टी में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती ने लंबे समय से अपने कानूनी सलाहकार और विश्वासपात्र रहे सतीशचंद्र मिश्र पर वरीयता देते हुए आनंद को अपने बाद पार्टी का दूसरा स्टार प्रचारक बनाया था। इसलिए कुछ महीने पहले जब मायावती ने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, तो ऐसा लगा कि बसपा ने अब अपने भविष्य की रूप-रेखा तैयार कर ली है, जो एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। इससे भी बड़ी बात यह कि आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता की काट माना जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश में बसपा के गढ़ में सेंध लगाना चाह रहे हैं। लेकिन भतीजे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते वक्त भी बहनजी ने स्पष्ट संदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश एवं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में पार्टी से जुड़े सभी मामले वह स्वयं देखेंगी, जबकि आनंद देश के अन्य राज्यों का कामकाज संभालेंगे। लेकिन 2024 के संसदीय चुनाव प्रचार की गर्मी जैसे ही बढ़ने लगी, वह उत्साही युवा यह भूल गया कि उसकी अहंकारी बुआ ने उसके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी है। बताया जाता है कि आनंद ने अपने उग्र चुनावी भाषणों से युवा दलितों के बीच खुद को फायरब्रांड नेता के रूप में पेश करने के लिए भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की। आनंद की चुनाव प्रचार की यह उग्र बयानबाजी उनकी डरी-सहमी बुआ से बिल्कुल अलग थी, जो उसकी बर्खास्तगी का कारण बनी। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि अपने उभरते हुए दलित युवा नेता और कुशल वक्ता को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए पद से हटाकर बहुजन समाज पार्टी, जो कभी दलित राजनीति की ताकत मानी जाती थी, ने अपने राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है, और अपने पुराने खोखले आवरण में सिमट गई है। मायावती ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को भाजपा सरकार पर हमले के बाद यह कहकर हटा दिया कि वह अभी परिपक्व नहीं है। इससे एक स्वतंत्र नेता के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। बसपा का जनाधार पहले ही काफी घट चुका है। ऐसे में, इससे दलित उपजाति जाटव का भी उससे मोहभंग होगा। इससे भाजपा और इंडिया गठबंधन, दोनों को लाभ हो सकता है। इसके अलावा दलित मतदाताओं की मतदान करने में भी रुचि घटेगी।

भारत में उद्योगों के लिए आईबीसी कोड और समयबद्ध अनुपालन का महत्व

धनेंद्र कुमार

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 में अनेक महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं जिनके फलस्वरूप देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही अनेक कानूनों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया, जिससे उद्यमों की सुगमता को बढ़ावा मिला, और विश्व बैंक की तालिका में भारत का स्थान ऊपर आ गया,और देश में नए पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिला।

दिवालियापन के लिए कानून (आईबीसी): इन सुधारों में एक महत्वपूर्ण सुधार दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 था। पूंजी निवेश की सुगमता के अतिरिक्त, यदि उद्यम में वांछित सफलता ना मिले तो इससे उद्यम से बाहर जाने के मार्ग भी सुगम होता हैं। आईबीसी के अनुसार जो संसद द्वारा 2016 में अधिनियमित किया गया था, दिवालिएपन के समाधान के लिए एक वन-स्टॉप शाप द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और दिवालिया हो रहे उद्यम के लिए, देनदारों और लेनदारों के बीच संतुलन बनाकर, एक कानूनी रूप-रेखा की स्थापना की गई। इसके अनुसार किसी ऋणी के दिवालिया होने पर एक निश्चित प्रकिया पूरी करने के बाद, उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है। इनके फलस्वरूप देश के बैंकिंग क्षेत्र को यह सुविधा मिल गई कि वे इस प्रक्रिया का पालन कर अपने ऋण की वसूली कर पाएं, इनके फलस्वरूप देश के बैंकिंग क्षेत्र की हालत काफी सुधर गई, एनपीए धीरे-धीरे काफी कम हो गए और नए पूंजी निवेश द्वारा नए उद्यमों को बढ़ावा मिला।

क्या होता है नॉन-परफार्मिंग एसेट (एनपीए)? : जब कोई लोन या बकाया राशि लम्बे समय तक अदा नहीं होती, तो कुछ परिस्थितियों में उनका वर्गीकरण एनपीए में कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में, जब ऋण लेने वाला देयता को पूरा करने में अक्षम होता है, लेंडर लोन एग्रीमेन्ट को टूटा हुआ मानते हैं और एनपीए लेंडर पर वित्तीय बोझ बढ़ा देते हैं, और इनसे रेगुलेटरों को संकेत मिलता है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और लेन-देन अवरूद्ध हो जाता है। आईबीसी के बाद देश के बैंकिंग संस्थानों को इस समस्या से निदान पाने के लिए एक न्यायपूर्ण और प्रभावी प्रणाली मिल गई। लेकिन इसके अनुपालन में कुछ समय से काफी अड़चनें आ रही हैं, जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। आईबीसी के अर्न्तगत नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) को दिवाला समाधान प्रक्रिया की निगरानी करने और इसके सुचारू और शीघ्र संचालन को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था। इसके अर्न्तगत एक समर्पित निर्णायक प्राधिकारी नामित करना होता है। आरपी समाधान प्रक्रिया के दौरान दिवालिया इकाई के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। हालांकि, शुरूआत में इसमें अच्छी प्रगति हुई लेकिन हाल ही में दिवाला आवेदनों की लंबितता और उन्हें हल करने में लगने वाला अधिक समय चिंता का विषय बन गया है। इसके अर्न्तगत ऐसी किसी जूझती हुई कम्पनी के भविष्य पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला ऋणदाताओं की समिति पर निर्भर होता है, जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय ऋणदाता शामिल होते हैं, और जो संकटग्रस्त कंपनियों के समाधान या परिसमापन पर निर्णय लेती है। हालांकि यह प्रणाली अच्छी तरह से कानूनन बनाई गई है, लेकिन हाल के कई मामलों के समयबद्ध निपटान, मूल्य क्षरण को रोकने और इष्टतम रिकवरी में सफल नहीं रहे हैं।

आईबीसी की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारण : इन प्रमुख मुद्दों में से एक विशेष रूप से एनसीएलटी में मामलों का बैकलॉग है। समाधान प्रक्रिया में देरी न केवल ऋणों की समय पर वसूली में रूकावट डालती है, बल्कि परिसंपत्ति मूल्य के क्षरण को भी बढ़ाती है। इसके अलावा, सीओसी सदस्यों के बीच मतभेद और कानूनी व्याख्या में अस्पष्टताएं आईबीसी की प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। इसके अलावा कुछ लेनदारों या पूर्व प्रवर्तकों की सहमति या अपीलों के कारण समाधान योजनाओं में भी देरी होती है और लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजियां मामलों को लटका देती हैं।उ उदाहरण के लिए, राठी टीएमटी सरिया मामले में आवेदक ने एक योजना प्रस्तुत की जिसे फरवरी 2020 में सीओसी द्वारा अनुमोदित कर किया गया। लेकिन एनसीएलटी की सहमति से पहले, एक सीओसी सदस्य ने एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दिया, जिसे जुलाई 2023 में एनवीएलटी ने खारिज कर दिया। सीओसी सदस्य ने इसके विरूद्ध एनसीएलएटी जो अपीलिय फोरम है के समक्ष अपील दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया। ऐसे में मंजूरी मिलने में लगभग तीन साल लग गए। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज भी इसी तरह की चुनौती का सामना कर रही है। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने अगस्त 2019 में एसबीआई के आवेदन को अनुमति दे दी। वेदांता समूह की यूनिट टिन्न स्टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने नवम्बर 2020 में समाधान योजना प्रस्तुत की। यद्यपि एनसीएलटी ने जून 2021 में योजना को मंजूरी दे दी, फिर भी इसे कुछ सीओसी सदस्यों द्वारा चुनौती दी गई। कुल मिलाकर मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, यह एक और उदाहरण है जहां अच्छी क्षमता वाली कम्पनी कानूनी दाँव-पेंच में फंस गई है। आबीसी कानून देश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, और व्यवहारिक रूप से जंहा सफलता न मिलने पर कम्पनी दिवालिया हो रही हो, प्रतिकूल परिणामों को कम करने के लिए एक प्रभावशाली कदम है। यह ध्यान में रखते हुए कि एक दिवालिया कंम्पनी का मूल्य तेजी से गिरता जाता है, एनसीएलटी और एनसीएलएटी के लिए संहिता के तहत प्रदान की गई समयसीमा का कड़ाई से पालन करना, प्रणालीगत कमजोरियो पर ध्यान देना और प्रक्रियात्मक स्तर पर प्रभावशीलता को बढ़ाना आवश्यक है ताकि समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और कार्यवाही में तेजी लाकर मामले का निपटान किया जा सके।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

https://t.me/AllNewsPaperPdf

मुद्दों से भटकते राजनेता

हम कहते नहीं थकते कि देश का विकास कुलांचे भर रहा है। हम दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था हैं। अभी पांचवें स्थान पर हैं व जल्दी ही तीसरे स्थान पर होंगे। ये ज्ञान की सदी है। 21वीं सदी भारतीय युवाओं की है। हम चांद पर पहुंचे। हमने मंगल के दरवाजे पर दस्तक दी। हमारी ओलंपिक में उपलब्धियां रहीं। पैरा ओलंपिक में हमारे मेडलों का सैकड़ा पहली बार आया। अकसर ये हमारे मीडिया की सुर्खियां हुआ करती थीं। लेकिन सवाल है कि आम चुनाव के तीसरे चरण तक आते-आते देश का राजनीतिक विमर्श इतना नकारात्मक क्यों हो गया? आखिर क्यों हम देश की जनता को सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव में मतदान करने के लिये प्रेरित नहीं कर सकते? अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मुद्दों में नकारात्मकता व आक्रामकता क्यों है? क्यों राजनीतिक दलों के नेता आमने-सामने बैठकर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों व भविष्य के एजेंडे को लेकर जनता से रूबरू नहीं होते? अमेरिका व अन्य विकसित देशों में शीर्ष राजनेताओं द्वारा लंबी बहसों से जनता को समझाने का प्रयास किया जाता रहा है। आखिर अमृत काल के दौर में पहुंचकर भी देश में मतदाता इतना जागरूक क्यों नहीं हो पाया है कि उसे क्षेत्रवाद, धर्म-संप्रदाय, जातिवाद और अन्य संकीर्णताएं न लुभा सकें? क्यों चुनाव आयोग की मुहिम में बरामद रिकॉर्ड मूल्य की वस्तुओं में आधा मूल्य नशीले पदार्थों का होता है? क्यों छोटे-छोटे प्रलोभनों के जरिये मतदाता बहकते हैं? कहीं न कहीं हमारे नेताओं ने देश के जनमानस को पूरी तरह लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने के बजाय संकीर्णता के शार्टकट से अपना उल्लू सीधा करना चाहा है। निस्संदेह, देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। सोशल मीडिया के जरिये समाज में जागरूकता आई है। लोग सार्वजनिक विमर्श में अखबार व अन्य मीडिया की भाषा बोलते नजर आते हैं। तो फिर वे मतदान करते समय क्यों बहक जाते हैं? आखिर क्यों कहा जाता है कि फलां जगह पचास प्रतिशत या साठ प्रतिशत मतदान हुआ है? आखिर पचास प्रतिशत या चालीस प्रतिशत वोट न देने वाले लोग कौन हैं? यहां एक तथ्य यह भी है कि यदि आम चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग धर्म, सांप्रदायिकता, क्षेत्र, जाति व अन्य संकीर्णताओं का सहारा ले रहे हैं तो कहीं न कहीं एक वजह यह भी है कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी लोग इन मुद्दों की तरफ आकर्षित होते हैं? कई जगह सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनावों में नाराजगी दिखाई देती है तो जनता फिर दूसरे राजनीतिक दल को सत्ता सौंप देती है। यह उसके पास विकल्प न होने की स्थिति होती है, लेकिन फिर दूसरा दल भी उन्हीं संकीर्णताओं को अपना एजेंडा बनाकर चुनाव मैदान में आ जाता है। सवाल यह है कि किसी दल ने अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं क्यों नहीं उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया जाता है?

अरविन्द केजरीवाल की जमानत पर उठते सवाल

कमलेश पांडे

बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल को किसी भी तरह की विशेष राहत देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिया जाना समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसा होगा। इससे ऐसी नजीर कायम होगी कि सभी अपराध करने वाले अनैतिक राजनेता चुनाव की आड़ में जांच को नजरअंदाज करेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर आम चुनाव। यदि वे गिरफ्तार किए जाते हैं तो प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगेंगे। दो कदम आगे की सोचते हुए उसने तर्क दिया कि आजतक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वह व्यक्ति स्वयं भी प्रत्याशी क्यों न रहा हो, जबकि केजरीवाल तो उम्मीदवार भी नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के एक साहसिक निर्णय से जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के चुनावों के दौरान बाहर आने और चुनाव प्रचार में अपनी भागीदारी जताने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। समझा जाता है कि कोर्ट के इस उदार पहल से भारत में एक नई सियासी क्रांति का आगाज हो सकता है। लिहाजा, इस निर्णय के सफेद और स्याह पक्ष पर चर्चा करने से पहले यह बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे और पिछले 50 दिन से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आगामी एक जून 2024 तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

ऐसा इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में विगत 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के इस निर्णय की तब बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना बन चुकी है। इसी मामले में गत 8 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान ही न्यायमूर्ति खन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले भी यानी गत 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा था कि मामले की सुनवाई जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कोर्ट लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है।

हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी थी कि अगर चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाने वाली ईडी परेशान हो गई। आनन-फानन में ईडी ने एक हलफनामा दायर करके उनके अंतरिम जमानत का विरोध किया और कुछ अकाट्य दलीलें भी दी। जिस पर केजरीवाल की लीगल टीम ने भी कड़ी आपत्ति जताई। जिसके दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

यही वजह है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिलने के सियासी और न्यायिक मायने तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि यह एक असाधारण न्यायिक आदेश है, जो अब बौद्धिक विमर्श का मुद्दा भी बन चुका है। समझा जा रहा है कि कोर्ट के ताजा निर्देश से जहां देश में जनतांत्रिक भावनाओं को बल मिलेगा, वहीं भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल राजनेताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि जेल से बाहर रहने का एक अमोघ कानूनी हथियार कोर्ट के फैसले से उन्हें मिल चुका है। लिहाजा, आने वाले दिनों में जेल में बंद भारतीय राजनेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगे जाने के मामले बढ़ेंगे।

बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल को किसी भी तरह की विशेष राहत देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिया जाना समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसा होगा। इससे ऐसी नजीर कायम होगी कि सभी अपराध करने वाले अनैतिक राजनेता चुनाव की आड़ में जांच को नजरअंदाज करेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर आम चुनाव। यदि वे गिरफ्तार किए जाते हैं तो प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगेंगे। दो कदम आगे की सोचते हुए उसने तर्क दिया कि आजतक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद व्यक्ति स्वयं भी प्रत्याशी क्यों न रहा हो, जबकि केजरीवाल तो उम्मीदवार भी नहीं हैं। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि अपराधी जेल से ही चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उन्हें कभी इस आधार पर जमानत नहीं मिली। वैसे भी चुनाव प्रचार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार। लिहाजा ऐसा होने से कानून का उल्लंघन करने वाले हर अपराधी को राजनीतिज्ञ बनने और वर्ष भर प्रचार के मोड में रहने का प्रोत्साहन मिलेगा। राजनेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता।

ईडी ने अपनी दलील में चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार, जिसे कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार माना है, वह भी हिरासत के दौरान नहीं रहता। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) जेल में बंद व्यक्ति के मतदान के अधिकार में कटौती की बात करती है। यह चीज देखने लायक है कि पिछले पांच सालों में करीब 123 चुनाव हुए हैं और अगर किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाने लगे तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार करके जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव तो साल भर चलने वाली गतिविधि है। हर राजनीतिज्ञ हर स्तर पर यह दलील दे सकता है कि अगर उसे जमानत नहीं दी गई तो उसे न भरपाई होने वाला नुकसान होगा।

ईडी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस समय सिर्फ पीएमएलए कानून में ही बहुत से नेता जेल में हैं। उनके मामलों को जांचने के बाद सक्षम अथॉरिटी ने उनकी हिरासत को सही ठहराया है। बहुत से नेता पीएमएलए के अलावा अन्य अपराधों में जेल में होंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ विशेष व्यवहार करने और उनकी विशेष मांग स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।

उसने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल ने कई समन के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश न होने के पीछे पांच राज्यों में चुनाव का यही आधार दिया था। ऐसे में अगर कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी तो उनके द्वारा आप के स्टार प्रचारक होने के आधार पर प्रचार के लिए समन को नजरअंदाज करने का कारण बनाये जाने पर न्यायिक मुहर लग जाएगी। साथ ही प्रचार के लिए अन्तरिम जमानत से प्रचार की इच्छा रखने वाले नेताओं का एक अलग वर्ग बन जायेगा। हालांकि कोर्ट ने ईडी की एक न सुनी और अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र को किंतु-परन्तु के आधार पर नहीं, बल्कि स्पष्ट और पारदर्शी नीतियों के आधार पर ही चलाया जाएगा। संभव है कि अगली संसद इससे सबक लेगी और नेताओं के लिए आवश्यक कानून बनाएगी या फिर पूर्व की विसंगतियों को दूर करेगी। यह स्वाभाविक सवाल है कि जब चुनावी मौसम हो और दल विशेष का प्रमुख नेता ही जेल में हो तो उसकी पार्टी को सही जनादेश कैसे मिल पाएगा। शायद इसलिए कोर्ट ने अंतरिम जमानत की नई राह दिखा दी और सियासी नकेल अपने हाथों में रख ली।

https://t.me/Newspaperpdf

बिहार की सियासी जमीं पर भगवा लहराने उतर रहे पीएम मोदी

शोभित सुमन

(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् में डॉक्टोरल फेलो)

पीएम मोदी भी उसी रणनीति के तहत पहली बार बिहार में दो दिवसीय अपने चुनावी दौरे पर हैं। 2014 में भी उन्होंने पटना के गांधी मैदान में चुनावी सभा की थी। ऐसे में बिहार से वे पूर्वांचल की कई सीटों को भेदने की तैयारी में लग गए हैं। बिहार से सटे अन्य राज्यों की सीटों पर भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार राजनीति का गढ़ रहा है ऐसे में यहां से जो राजनीतिक हवा उठती है उसका असर दिल्ली की सियासी फिज़ाओं तक होता है। ऐसे में यह माना जाता है कि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों का रास्ता बिहार और उत्तरप्रदेश के रास्ते ही है। उनकी यह कोशिश है कि अब अगली बार जब वे प्रधानमंत्री बनें तो इन्हीं राज्यों से अधिकांश सीटें उन्हें हासिल हो। इसके लिए ही वे यतन कर रहे हैं। भाजपा सत्ता में फिर से काबिज हो रही है इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन एनडीए के 400 सीटों के आंकड़े को पार करना मुश्किल है। अभी की चुनावी हवा के अनुसार बिहार और उत्तरप्रदेश में कुछ सीटों का नुकसान तो भाजपा को हो सकता है। जिसकी भरपाई भाजपा पश्चिम बंगाल और दक्षिण के राज्यों में ज्यादा सीटें लाकर कर सकती है।पिछले तीन चरण में बिहार में पहले की अपेक्षा मतदान का प्रतिशत कम रहा है। अमूमन यह माना जाता है कि मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है तो उसका फायदा भाजपा को ही मिलता है। मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग अधिक हो रही है वहीं हिंदू बहुल इलाकों में मतदान का प्रतिशत भी कम है। अब आगे जिन सीटों पर मतदान होना है वे सीटें भाजपा के फायरब्रांड नेताओं की ही सीटें हैं। ऐसे में मोदी के आने से यह उम्मीद जताई जा रही की इन सीटों पर मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मोदी के बिहार आने से यहां उसके सहयोगी दलों की सीटों में भी इजाफा होनी की उम्मीद है। ऐसे में जो चुनावी पिच एनडीए ने सेट की है उस पर वह खरा उतरने का प्रयास भी कर रही है। ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव का ना ही सही 2014 के लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस इस बार भी दोहराया जा सके।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व रोड शो के लिए पटना तैयार दिख रहा है। यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री का पटना की सड़कों पर चुनावी रोड शो होगा। यह रोड शो तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा होगा। इस रोड शो में भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं के अलावा साधु-संत भी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मंत्रोच्चार से प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके माध्यम से पीएम पाटलिपुत्र लोकसभा और पटना साहिब लोकसभा सीट की जनता के वोटबैंक को भी साधने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पूरे बिहार में यह संदेश जाएगा कि भाजपा मजबूती से अपने किलेबंदी में लग गई है। मोदी यह जानते हैं कि यह चुनाव उनका अंतिम चुनाव है। इसलिए वे इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस चुनाव में भाजपा के लिए 370 पार के आंकड़े को साधने का प्रण उन्होंने लिया है उसके लिए वे प्रतिबद्ध भी दिख रहे हैं। इसी क्रम में बिहार की सियासी जमीं पर वे भगवा लहराने के लिए स्वयं इस रण में उतर गए हैं। पूरे देश में पीएम धुआंधार प्रचार और रोड शो कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी जिस जोश और उमंग के साथ वे चुनावी सभाएं कर रहे हैं वह तारीफ के काबिल है। वहीं, विपक्ष की अगर बात की जाए तो वह इस चुनावी प्रचार और सभाओं में भी पीछे दिख रहा है।

बिहार में हुए पिछले तीन चरण के चुनाव में अधिकतर सीटों पर एनडीए के सहयोगी दल ही चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा की अधिकांश सीटों पर अगले चरणों में चुनाव होना है। ऐसे में इस रोड शो से भाजपा को काफी उम्मीदें हैं। पीएम पटना से पूरे बिहार में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने का संदेश इससे दे पाएंगे। बिहार में भाजपा जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वह उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का दंभ भी भरेगी। लोकसभा चुनाव में सीटों की बात की जाए तो यह तो तय है कि सबसे अधिक सीटें तो भाजपा को ही मिलेगी। भाजपा को जेडीयू के जनाधार का वोट तो मिल जाएगा लेकिन जेडीयू को भाजपा का वोट कम मिल सकता है। अगर देखा जाए तो नीतीश के खिलाफ तो बिहार में माहौल है इसमें कोई संदेह नहीं है। एनडीए को उन सीटों पर नुकसान हो सकता है जिस पर उनके सहयोगी दल जेडीयू चुनाव लड़ रही है। राजद की नजर भी उन्हीं सीटों पर है। राजद एक खास रणनीति के तहत जेडीयू के कोर वोटर रहे कुशवाहा वोटरों में सेंधमारी कर सकती है। यही कारण है कि राजद ने अधिक से अधिक सीटों पर कुशवाहा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस को 3 सीटों पर काफी उम्मीदें हैं। जिसमें कटिहार, किशनगंज और भागलपुर है। बिहार में कई सीटों पर एनडीए के पसीने छूटे हुए हैं। यही कारण है कि भाजपा अब अपने सहयोगी दलों के साथ सामाजिक समीकरण बदलने का प्रयास कर रही है। ऐसे में एनडीए का यह प्रयास है कि उसका आधार वोट तो उसे मिले ही इसके साथ ही अन्य जातियों का वोट बैंक भी इस लोकसभा सीट से उस लोकसभा सीट तक स्थानांतरित किया जा सके।

पीएम मोदी भी उसी रणनीति के तहत पहली बार बिहार में दो दिवसीय अपने चुनावी दौरे पर हैं। 2014 में भी उन्होंने पटना के गांधी मैदान में चुनावी सभा की थी। ऐसे में बिहार से वे पूर्वांचल की कई सीटों को भेदने की तैयारी में लग गए हैं। बिहार से सटे अन्य राज्यों की सीटों पर भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार राजनीति का गढ़ रहा है ऐसे में यहां से जो राजनीतिक हवा उठती है उसका असर दिल्ली की सियासी फिजाओं तक होता है। ऐसे में यह माना जाता है कि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों का रास्ता बिहार और उत्तरप्रदेश के रास्ते ही है। उनकी यह कोशिश है कि अब अगली बार जब वे प्रधानमंत्री बनें तो इन्हीं राज्यों से अधिकांश सीटें उन्हें हासिल हो। इसके लिए ही वे यतन कर रहे हैं। भाजपा सत्ता में फिर से काबिज हो रही है इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन एनडीए के 400 सीटों के आंकड़े को पार करना मुश्किल है। अभी की चुनावी हवा के अनुसार बिहार और उत्तरप्रदेश में कुछ सीटों का नुकसान तो भाजपा को हो सकता है। जिसकी भरपाई भाजपा पश्चिम बंगाल और दक्षिण के राज्यों में ज्यादा सीटें लाकर कर सकती है।पिछले तीन चरण में बिहार में पहले की अपेक्षा मतदान का प्रतिशत कम रहा है। अमूमन यह माना जाता है कि मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है तो उसका फायदा भाजपा को ही मिलता है। मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग अधिक हो रही है वहीं हिंदू बहुल इलाकों में मतदान का प्रतिशत भी कम है। अब आगे जिन सीटों पर मतदान होना है वे सीटें भाजपा के फायरब्रांड नेताओं की ही सीटें हैं। ऐसे में मोदी के आने से यह उम्मीद जताई जा रही की इन सीटों पर मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मोदी के बिहार आने से यहां उसके सहयोगी दलों की सीटों में भी इजाफा होनी की उम्मीद है। ऐसे में जो चुनावी पिच एनडीए ने सेट की है उस पर वह खरा उतरने का प्रयास भी कर रही है। ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव का ना ही सही 2014 के लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस इस बार भी दोहराया जा सके।

इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो फिर से लौट आएगा आतंकवाद का दौर: योगी

मुख्यमंत्री ने कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीटों के लिए चुनावी जनसभा को किया संबोधित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ कानपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो देश में एक बार फिर आतंकवाद और नक्सलवाद का दौर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि संविधान संशोधन का डर फैलाने वाली कांग्रेस ने सबसे पहले भारतीय संविधान में संशोधन करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी को रौंदने का कार्य किया था। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा के एजेंडे में अयोध्या का विकास नहीं, बल्कि अयोध्या में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना था।

सीएम योगी शनिवार को यहां छावनी विधानसभा क्षेत्र में कानपुर और अकबरपुर लोकसभा सीटों के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां कानपुर से पार्टी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर से बीजेपी प्रत्याशी देवेन्द्र सिंह भोले के लिए जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि कानपुर को मां गंगा के आशीर्वाद से उर्वरता और उद्यमिता का वरदान मिला है। ये क्रांति धरा होने के साथ ही देश के विकास की ऊर्जा की भूमि भी है। चौथे चरण में कानपुर की जनता को निर्णय लेना है। आज पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है %फिर एक बार मोदी सरकार और अबकी बार 400 पार। 400 पार में कानपुर और अकबरपुर की सीटें भी शामिल होंगी। सीएम योगी ने कहा कि बीते 10 साल में मोदी ने बिना रुके, बिना थके और बिना डिगे देश की अहर्निश सेवा की है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि मोदी जी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है, हमारी सीमाओं को सुरक्षित किया है, विकास को गति दी है, गरीब कल्याण के साथ ही नागरिकों के जीवन में परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन नकारात्मक राजनीति के कारण अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। इनको पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। इनको आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या के समाधान की नहीं आतंकियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की चिंता होती है। इनकी चिंता थी कि जैसे भी हो अयोध्या में राममंदिर का निर्माण न हो।

रामद्रोहियों की राजनीति परिवार के लिए होती है

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ उन्नाव

राम भक्तों की राजनीति राष्ट्र के लिए होती है। वहीं रामद्रोहियों की राजनीति परिवार के लिए होती है। वह अपने परिवार से ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दिया है। वर्तमान में यह पांच सीटों पर लड़ रहे हैं। अभी इनके बच्चे और नाती पोते होने दीजिये, वह भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे लोगों की वजह से ही विकास कार्य ठप पड़ते हैं। देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। सुरक्षा खतरे में पड़ती है और माफिया हावी होते हैं। यह जनता का खून चूसते हैं और बेटी-व्यापारी असुरक्षित होते हैं। वहीं जब राजनीति राष्ट्र के लिए होती है तो दुनिया में देश का सम्मान होता है। देश की सीमाएं सुरक्षित होती हैं और विकास के बड़े-बड़े कार्य होते हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जनता जनार्दन को प्राप्त होता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी और सांसद साक्षी महाराज के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रही थी।

मुख्यमंत्री योगी का तंज

4 जून के बाद राहुल गांधी गाएंगे 'चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना'

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ नई दिल्ली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जून को मतगणना के दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक और चुनावी हार की भविष्यवाणी की है। योगी ने कहा, 4 जून के बाद इनका पूछने वाला कोई नहीं होगा..ये गाएंगे, 'चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। बीते शनिवार की रात एक टीवी शो में सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा- 'राहुल मुझसे लिखित में ले सकते हैं कि उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में सभी सीटें हार जाएगा।' योगी का यह जवाब कन्नौज रैली में राहुल की उस टिप्पणी के जवाब में था जिसमें उन्होंने कहा था,मुझसे लिखित में ले लीजिए, बीजेपी यूपी में अधिकतम सीटें हारेगी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, राहुल गांधी का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जब भी उन पर कोई संकट आता है तो वह देश छोड़कर उस जगह चले जाते हैं, जहां के बारे में उन्हें सबसे अच्छा पता होता है। इस बार भी 4 जून के बाद वह यह हिंदी फिल्म गाना गाएंगे- चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। मुख्यमंत्री ने कहा, फिलहाल के लिए, उन्हें एक खूबसूरत सपने में जीने दें... 4 जून के बाद, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होगा । योगी ने कहा, 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ दो विधायक हैं. उनके पास अर्थी उठाने के लिए 4 विधायक नहीं हैं। अगली बार, वे ये दो सीटें भी हार जाएंगे। मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें यूपी में 80 सीटें जीतने का इतना ही भरोसा था, तो उन्होंने वायनाड में जाकर चुनाव क्यों लड़ा और जब उन्होंने यहां चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ा?

लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर योगी ने जोरदार बयान देते हुए कहा, %%कोई अगर या मगर नहीं है। 4 जून के नतीजे मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे. ..भारत की जनता मोदी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती है। मैंने यूपी के अलावा कई राज्यों की यात्रा की है, जहां लोग उनका दिल से सम्मान करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताते हुए कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगा, बल्कि पड़ोसी देशों से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसियों को नागरिकता देगा। कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा गजवा-ए-हिंद के बारे में बोलने पर योगी ने कहा, कयामत के दिन तक गजवा-ए-हिंद नहीं होने वाला है. भारत, भारत ही रहेगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी द्वारा दिए गए वोट जिहाद के आह्वान पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। वोट के लिए जिहाद करेंगे, तो जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नुम मिलेगा।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने मुसलमानों से मोदी को हराने के लिए सामूहिक रूप से वोट करने की अपील की, इस पर योगी ने जवाब दिया, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों के दौरान, मोदी जी ने जाति और धर्म को किनारे रख के सभी समान रूप से सामाजिक कल्याण लाभ दिए। जो लोग हमारे समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते। वे हमेशा चाहेंगे कि मुसलमान लुंगी पहनें और दौड़ें। यूपी के मुख्यमंत्री, जिनसे अब तक राज्य में सक्रिय अधिकांश माफिया संगठनों को डर था, ने चेतावनी दी। 4 जून के बाद, हमारी सरकार यूपी को माफिया मुक्त राज्य घोषित करने के लिए एक निश्चित कट-ऑफ तारीख देगी। दूसरी बात, सभी माफिया नेताओं द्वारा अर्जित संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा और गरीबों, अनाथों, महिला संरक्षण गृहों, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए घरों, अस्पतालों और अच्छे स्कूलों के लिए घरों में परिवर्तित किया जाएगा, पहले चरण में, माफिया नेताओं को लक्षित किया जाएगा, और दूसरे चरण में, उनके गुर्गों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हमारी कार्य योजना तैयार है।

अमित शाह आज करेंगे प्रतापगढ़ रायबरेली, गोण्डा में जनसभा

लखनऊ। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार 12 मई को प्रतापगढ़, रायबरेली, गोण्डा के प्रवास पर रहेंगे। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे नगर पंचायत हीरागंज, नायर देवी धाम, महेशगंज, प्रतापगढ़ में आयोजित कौशाम्बी लोकसभा की जनसभा को सम्बोधित करेगे तथा दोपहर 01 बजे राजकीय इण्टर कॉलेज मैदान, रायबरेली में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे। इसके पश्चात् दोपहर 03 बजे शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इण्टर कालेज (टॉमसन इण्टर कालेज), सिविल लाइन, गोण्डा में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह रविवार 12 मई को गोरखपुर एवं देवरिया के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह अंबिका मैरिज हॉल, पीपी गंज, गोरखपुर तथा दोपहर 03 बजे नन्दना वार्ड मैदान, बरहज, देविरया में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कान्ताकर्दम रविवार 12 मई को गोरखपुर के प्रवास पर रहेंगी। कान्ताकर्दम सुबह 11 बजे झूंगिया बाजार, गोरखपुर में आयोजित अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित करेंगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला रविवार 12 मई को गोरखपुर के प्रवास पर रहेंगे। गोविन्द नारायण शुक्ला सुबह 11 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में संगठनात्मक बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता डा. समीर कुमार सिंह रविवार 12 मई को बलिया के प्रवास पर रहेंगे। डा. समीर कुमार सिंह सायं 04 बजे पाण्डेय पैलेस, बैरिया, बलिया में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।

इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए की समर्थन की घोषणा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रति बढ़ते जनता के रूझान से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता एवं संस्थाएं स्वत: अपील कर समर्थन और सहयोग की घोषणा कर रही है। संयुक्त जनादेश पार्टी लखनऊ के अध्यक्ष भगवान दीन 'बबलू' श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर भरोसा करते हुए समर्थन पत्र देकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत में सहयोग और केन्द्र की सरकार में शीर्ष पद पर बिठाने का संकल्प जताया है। समाजवादी आंदोलन पार्टी बिजनौर के अध्यक्ष अकबर अली तथा ओबीसी, एससी, एसटी, एवं माइनॉरिटी एकता महागठबंधन के संयोजक राजकुमार सैनी पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने लोकसभा चुनाव में साम्प्रदायिक ताकतों को हराने और भारत के संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन देने और मुस्लिम समाज और पार्टी के सभी पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं से इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की है।

अबकी बार मोदी की गारंटी ही चलेगी: बृजेश पाठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शनिवार को रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में रिफॉर्म क्लब में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता यहाँ पिकनिक और पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देगी। सियासी पिकनिक मनाने आने वाले गांधी परिवार की अबकी बार रायबरेली से छुट्टी होगी। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से हारे तो वायनाड चले गये। इस बार उन्हें वहां भी हार का अंदेशा हुआ तो वे अब रायबरेली आकर यहां अपने पूर्वजों की याद दिलाकर वोट मांग रहे हैं। जनता सब जानती है, जो राहुल पांच साल तक न अमेठी आये और न रायबरेली। अब जनता इनके झाँसे में नहीं आएगी। अबकी बार मोदी की गारंटी ही चलेगी। पाठक ने कहा कि, अहंकारी गठबंधन के वे लोग 12 लाख करोड़ रुपये के घोटालों और भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सभी भ्रष्टाचारी आपस में मिलकर रैली निकाल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के लिए मौन व्रत रख रहे हैं। मोदी अपनी बात पर क़ायम हैं। भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है तो ये सभी एक जुट होकर अपने आपको बचाने के लिए सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी बेल पर हैं, सोनिया जी बेल पर हैं, केजरीवाल भी 20 दिन के लिए बेल पर हैं।

इंडी भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है: केशव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सलोन रायबरेली में अमेठी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मौर्य ने कहा कि सपा सरकार का था नारा, खाली प्लाट हमारा। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। उन्होंने कांग्रेस व सपा समेत इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है। इन लोगों ने देश और समाज को लूटने का कार्य किया है। इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहा और अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया। उन्होंने कहा, कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी पहले भी फ्लॉप हो चुकी है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा पैसा जनता के खाते में पहुंच रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी और महाठगबंधन के लोग होते तो गरीबों का हक का पैसा मिलजुल कर खा गए होते। केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि संविधान खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो संविधान खतरे में है और ना ही लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में है तो राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं का राजनैतिक भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादों को पूरा करते हुए कश्मीर से धारा 370 हटा दिया। भव्य राममंदिर का निर्माण हो गया। मौर्य ने कहा कि पाकिस्तान के विरुद्ध एयर और सर्जिकल स्ट्राइक 56 इंच के सीने की दम की बदौलत होता है। आपको याद ही होगा कि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को खदेड़ते हुए हमारे जांबाज कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फोन कर चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के भीतर हमारा कैप्टन सही सलामत भारत नहीं पहुंचता है, तो विश्व के नक्शे से हमेशा-हमेशा के लिए पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। विश्व देख रहा था कि अभिनंदन शान से भारत लौटे।

रक्षा मंत्री को हराइए, अग्निवीर से मुक्ति पाइए: कांग्रेस

अग्निपथ जैसी योजना लाकर देश की सेना और सैनिकों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया: अभय दुबे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कांग्रेस ने कहा है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी उत्तर प्रदेश का, शहादतों की वीरगाथा का एक गौरवशाली इतिहास है। भारत मां की स्वतंत्रता, अस्मिता और भूभागीय अखंडता के लिए उत्तर प्रदेश के वीरों ने तत्परता से अपने प्राणों की आहुति दी है। 1857 की क्रांति के शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर हो, रानी झांसी हो, बेगम हजरत महल हो, मंगल पाण्डेय हो या कारगिल के शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय भारत मां के इन रणबांकुरों ने अपने प्राणों की परवाह किये बिना उत्तर प्रदेश की मिट्टी को गौरवान्वित किया है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे , मीडिया विभाग के चेयरमैन पूर्व मंत्री डॉ. सीपी राय, अखिल भारतीय कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर गरिमा मेहरा दसौनी, चित्रा बाथम, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, शुचि विश्वास ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यूपी के कंधों पर आज एक महत्वपूर्ण दायित्व है, वह दायित्व है भारत मां की रक्षा का, क्योंकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं, और उत्तर प्रदेश से ही चुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आते हैं। आज भारत माँ की अस्मिता और भूभागीय अखण्डता चीन की सेना ने खंडित की है, मगर रक्षा मंत्री दम साधे और होंठ सिये बैठें हैं और प्रधानमंत्री 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भी चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं। उक्त दोनों नेताओं ने न सिर्फ भारत की सीमाओं की सुरक्षा से समझौता किया है, अपितु अग्निपथ जैसी योजना लाकर देश की सेना और सैनिकों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना ना तो सदन की सहमति से लाई गई न ही भारतीय सेना की। हाल ही में पूर्व थल सेना अध्यक्ष एमएम. नरवणे ने अपनी प्रकाशित पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' में खुलासा किया है कि अग्निपथ योजना के एलान ने तीनों सेनाओं को चौंका दिया था। इतना ही नहीं नरवणे ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि अग्निवीरों का वेतन सिर्फ 20 हजार रुपये ही निर्धारित किया गया था फिर सेना के हस्तक्षेप के बाद इसे 30 हजार रुपये किया गया। अग्निपथ योजना में 17 से 21 वर्ष के युवाओं की भर्ती का प्रावधान है।

सपा प्रमुख ने समाजवादी पीडीए यात्रा निकालकर किया जनसंपर्क

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अखिलेश यादव ने आज कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के विधूना में समाजवादी पीडीए यात्रा निकाल कर जनसम्पर्क किया और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को रिकार्ड मतों से जिताने की अपील की। जनसम्पर्क कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी। उन्होंने जनसम्पर्क के दौरान लोगों से मिलकर अपने लिए वोट मांगे। जनसम्पर्क के मौके पर भारी संख्या में किसान, नौजवान, वकील, महिलाएं और बुजुर्ग लोग जुट गए। इस अवसर पर यादव ने कहा कि जब से चुनाव शुरू हुआ है समाजवादी लोग प्रचार कर रहे हैं। घर-घर जा रहे हैं। यह क्षेत्र पुराने समय से समाजवादी रहा है। यहां के लोगों ने डॉ. राममनोहर लोहिया से लेकर नेताजी, धनीराम वर्मा तक सबका स्वागत और सम्मान किया। हम लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि यहां के लोग हमें इस बार ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। भाजपा बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का संविधान हम सभी को न्याय और अधिकार दिलाता है। आगे बढ़ने का अवसर देता है। संविधान देश की संजीवनी है। हम सब की जिम्मेदारी है, भाजपा की सरकार बदल कर बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें। यादव ने कहा कि भाजपा ने सत्ता और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया है।

भाजपा सरकार के फैसलों से देश और जनता का बहुत नुकसान हुआ है। भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंचा दिया है। हर वर्ग परेशान है। चुनावी चंदा के नाम पर वसूली की। भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि विधूना के लोगों ने समाजवादी आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। हमेशा समाजवादियों की मदद की है। कार्यकर्ता, नेता घर-घर जाकर लोगों से वोट मांगे, वोट डलवाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह 2024 का चुनाव देश और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। भाजपा सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, नौकरियां छीनी है। इस सरकार में भर्ती परीक्षाओं के जितने पेपर हुए सब लीक हो गए। सरकार नौकरी, आरक्षण नहीं देना चाहती है। इसीलिए जानबूझकर पेपर लीक कराये है। नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया है। भाजपा हटेगी तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी। संविधान और लोकतंत्र बचेगा। महंगाई कम होगी। अन्याय खत्म होगा। किसानों की कर्जमाफी होगी। लोगों को राशन के साथ आटा और मोबाइल डाटा मुफ्त मिलेगा। महिलाओं की मदद की जायेगी।

इंडिया गठबंधन की एकजुटता से परेशान हैं भाजपा नेता: अविनाश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में लोकसभा चुनाव लखनऊ एवं मोहनलालगंज और लखनऊ पूर्वी विधानसभा के उप चुनाव के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पाण्डेय उपस्थित हुए।

बैठक को सम्बोधित करते हुए अविनाश पाण्डेय ने कहा कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता से भाजपा की सरकार और उनके नेता परेशान हैं। उनको लगने लगा है कि जिस तरह से जनता का भरपूर समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मिल रहा है उससे उनकी झूठ की दुकान पूरी तरह बंद होने वाली है। श्री पाण्डेय ने कहा कि लगभग 63 प्रतिशत वोट इंडिया गठबंधन के साथ साफ-साफ दिखाई दे रहा है। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, एवं शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष दव्य अमित श्रीवास्तव त्यागी एवं डॉ. शहजाद आलम, तथा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जय सिंह जयंत एवं महानगर अध्यक्ष फाखिर सिद्दीकी ने की।

चौथे चरण के मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

13 लोकसभा सीटों व ददरौल विधानसभा उप चुनाव के लिए कल होगा मतदान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के चतुर्थ चरण की 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 136-ददरौल विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के लिए 13 मई, 2024 को होने वाले मतदान को सकुशल, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने के लिए 12 मई, 2024 (रविवार) को मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसके लिए चतुर्थ चरण के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के निर्देश दिये गये हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चतुर्थ चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 27-शाहजहांपुर (अ.जा.), 28-खीरी, 29-धौरहरा, 30-सीतापुर, 31-हरदोई(अ.जा.), 32-मिश्रिख (अ0जा0), 33-उन्नाव, 40-फर्रूखाबाद, 41-इटावा (अ0जा0), 42-कन्नौज, 43-कानपुर, 44-अकबरपुर, 56-बहराइच (अ.जा.) लोकसभा सीट प्रदेश के 13 जनपदों में शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, फर्रूखाबाद, एटा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, बहराइच आते हैं। 136-ददरौल विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र शाहजहांपुर जनपद में आता है। उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केन्द्रों एवं मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैय्या कराने के निर्देश दिये गये है। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के दृष्टिगत मेडिकल किट उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की जा सके।

प्रवासी मतदाताओं को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा: नवदीप रिणवा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान चतुर्थ चरण की 13 लोकसभा सीटों तथा ददरौल विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए 13 मई (सोमवार) को मतदान होगा। मतदान के समय ऐसे मतदाता जिनके पास अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र न हो, वे 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्ड मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं की पहचान के लिए अनुमन्य होंगे। रिणवा ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पोलिंग बूथ पर ले जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सुभाषित — जीवनमें यदि सफलता चाहते हैं तो कर्म और लोककल्याणमें समन्वय जरूरी है। तभी जीवनका समग्र विकास हो पायेगा। ❐ हितोपदेश

अब राहत देनेका समय

देशकी तीनों सरकारी तेल कम्पनियोंने वित्त वर्ष २०२३-२४ के दौरान रिकार्ड लाभ अर्जित किया है, जिसके परिणामस्वरूप इन कम्पनियोंको ८६ हजार करोड़ रुपयेका शुद्ध लाभ हुआ। विगत दस वर्षोंके दौरान इन कम्पनियोंका शुद्ध लाभ २०६ प्रतिशत और राजस्व १२५ प्रतिशत बढ़ा है। यह बात अलग है कि आलोच्य वित्त वर्षकी अन्तिम तिमाहीमें इन कम्पनियोंके लाभमें अवश्य कमी आयी है लेकिन पूरे वित्त वर्षका प्रदर्शन अप्रत्याशित रूपसे बहुत अच्छा रहा। तीनों तेल कम्पनियों-इण्डियन आयल (आईओसी), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) के शुद्ध लाभमें क्रमशः २६८, २२९ और १,१६० प्रतिशतकी भारी वृद्धि इस बातका संकेत है कि इनकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है। मौजूदा सरकारमें सरकारी तेल कम्पनियोंकी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है जिसकी वजहसे वह वैश्विक अनिश्चितताके माहौलमें भी देशकी जनताके हितोंकी रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनेकी स्थितिमें है। सरकार इन कम्पनियोंको ज्यादा निवेश करनेको प्रोत्साहित भी कर रही है, क्योंकि इनकी वित्तीय स्थिति पर्याप्त मजबूत है। सरकारी अधिकारियोंका मानना है कि मुनाफा ज्यादा होनेके कारण ही जब यूक्रेनपर रूसके हमलेके बाद वैश्विक बाजारमें कच्चे तेलकी कीमतोंमें काफी ज्यादा अस्थिरता आयी थी तब भी घरेलू बाजारमें पेट्रोल और डीजलकी कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ायी गयीं। देशमें ६ अप्रैल, २०२२ से लेकर १४ मार्च, २०२४ तक पेट्रोल और डीजलके खुदरा मूल्यमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, जबकि कच्चे तेलकी कीमतें १३० डालर प्रति बैरलतक बढ़ गयीं। यह अच्छी बात है कि वैश्विक बाजारमें अनिश्चितताके बावजूद उपभोक्ताओंपर विशेष बोझ नहीं डाला गया लेकिन जिस प्रकारसे सरकारी तेल कम्पनियोंकी वित्तीय स्थितिमें अप्रत्याशित रूपसे मजबूती आयी है, उसे देखते हुए अब आम उपभोक्ताओंको राहत देनेका समय आ गया है। तेलकी खुदरा कीमतोंमें बड़ा हिस्सा करोंका होता है। इसलिए अब पेट्रोल और डीजलको वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरेमें लाना चाहिए। इससे दोनों पेट्रोलियम पदार्थोंकी कीमतोंमें अच्छी गिरावट आ जायगी। लम्बे अरसेसे पेट्रोल और डीजलको जीएसटीके दायरेमें लानेका आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन इस दिशामें कोई प्रगति नहीं हुई। यदि पेट्रोल और डीजल जीएसटीके दायरेमें लाया जाता है तो इससे मुद्रास्फीतिमें भी कमी आयगी और महंगीकी मार भी कम हो जायगी। तेल कम्पनियों और सरकारको इसपर गम्भीरतासे विचार करनेकी जरूरत है।

वसीयत पंजीकरणमें राहत

उत्तर प्रदेशकी इलाहाबाद उच्च न्यायालयने वसीयत पंजीकरणमें बड़ी राहत दी है। न्यायालयने उसकी पंजीकरणकी अनिवार्यताको खत्म कर दिया और २३ अगस्त, २००४ के तत्कालीन सरकारके उस संशोधनको भी शून्य करार दे दिया है, जिसमें वसीयतनामेका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। उच्च न्यायालयने इस संशोधन कानूनको भारतीय पंजीकरण कानूनके विपरीत बताया है। वसीयतके पंजीकरण होनेपर ही वैध होनेका लोगोंमें बने संशयको लेकर उच्च न्यायालयने अपने इस आदेश साफ कर दिया है कि वसीयत पंजीकृत हो या न हो परन्तु वह अवैध नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय भी अपने एक पूर्वके आदेशमें कह चुका है कि रजिस्ट्रेशन एक्टके तहत वसीयतका पंजीकरण कराना ऐच्छिक है। किसी भी वसीयतकी वैधता या अवैधता इस बातपर निर्भर नहीं करती है कि वसीयतको पंजीकृत किया गया था कि नहीं। एक वसीयत जिसे पंजीकृत करा दिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें छल नहीं हुआ है, दस्तावेज बिल्कुल सच्चा है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि अबतकके रिकार्ड और मुकदमोंको देखते हुए कहा जा सकता है कि जिन वसीयतको पंजीकृत कराया गयाहै, उसको साबित करनेकी सम्भावना बढ़ जाती है। वसीयतको पंजीकृत करानेकी सलाह इसलिए दी जाती है कि यदि वसीयत खो जाय या खराब हो जाय तो सब रजिस्ट्रार कार्यालयसे वसीयतकी प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। वसीयत पंजीकृत हो या नहीं, परन्तु यह एक कानूनी दस्तावेज है। वसीयत बताती है कि वसीयत कर्ताके न रहनेपर सम्पत्ति किसे और कैसे बांटना है। वसीयत लिखनेवाला व्यक्ति अपने जीवनकालमें वसीयत कई बार बदल सकता है, परन्तु उसकी लिखी आखिरी वसीयत ही मान्य होती है। यदि वसीयत किये बिना किसीकी मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूपसे उसकी सम्पत्तिका उत्तराधिकार कानूनोंके अनुसार विभाजन या वितरण किया जाता है, जबकि वसीयत लिखकर व्यक्ति न केवल इच्छानुसार अपनी सम्पत्तिका बंटवारा कर सकता है, बल्कि अपने उत्तराधिकारियोंको पारिवारिक विवाद, कानूनी उलझनों और खर्चोंसे भी बचा सकता है।

लोक संवाद

सर्वाधिक भरोसेमंद पेशा

महोदय,-प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस १२ मईको पूरे विश्वमें मनाया जाता है। बहुतसे देशोंमें ६ मईसे १२ मईतक नर्सिस सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष २०२४ का थीम है हमारी नर्सें, हमारे भविष्य, रोगी देखभालकी आर्थिक शक्ति। नर्सें लोगोंकी सेहतको बनाये रखनेमें नींवका पत्थर होते हुए अपने आप आर्थिक और सामाजिक समस्याओंसे हमेशा संघर्षशील हैं। इसलिए इस वर्षके थीममें प्रमुखतासे नर्सिंग पेशे-क्षेत्रमें रणनीतिक निवेशके ऊपर जोर देता है। नर्स किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालीका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। वे चिकित्सा प्रतिष्ठानमें प्रवेश करनेसे लेकर बाहर निकलनेतक अपने मरीजोंकी भलाईके लिए जिम्मेदार हैं। वे चिकित्सा देखभाल प्रदान करनेके लिए डाक्टरोंके साथ सांझेदारी करती हैं। वे मरीजोंके स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण संकेतोंकी निगरानी करती हैं। इस वजहसे नर्सिंगका पेशा दुनियाभरमें सबसे भरोसेमंद पेशोंमेंसे एक पेशा बन गया है। पहले इसे एक मामूली पेशेके रूपमें देखा जाता था, परन्तु फ्लोरेंस नाइटिंगेलने नर्सिंगको एक संघटित पेशा बनाया। १८६० में पहला आधिकारिक नर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाकर और नर्सोंके दिन-प्रतिदिनके कामकाजमें चिकित्सा और देखभालके आधुनिक विचारोंको एकीकृत करके नर्सिंग पेशेकी स्थितिको ऊंचा उठानेमें मदद की। नाइटिंगेलने देखभालके मानक स्थापित किये। पूरे विश्वमें नर्सिंग क्षेत्रमें क्या नये विकास-अनुसंधान हुए, उन सबके अवलोकनके लिए १९६५ में दुनियाभरमें २० मिलियनसे अधिक नर्सोंका प्रतिनिधित्व करने वाले १३० से अधिक राष्ट्रीय नर्सिस संघोंका एक संघ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंगने १२ मईको पहली बार फ्लोरेंस नाइटिंगेलके जन्मदिनके उपलक्ष्यपर नर्सोंका जश्न मनाया। १९७४ में आधिकारिक तौरपर इसे अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस नाम दिया गया था। एक अनुमानके अनुसार २०३० तक सारे संसारमें १८ मिलियन स्वास्थ्य कर्मचारी कम होंगे, इसके लिए अधिक भर्ती, प्रशिक्षण आदिके लिए ठोस काररवाईपर जोर दिये जानेकी आवश्यकता है। सारे विश्वमें नर्सिसकी १० मिलियनतककी कमी है। २०१८ में एक अध्ययनके अनुसार जिन रोगियोंको गहन देखभालकी आवश्यकता होती है, वे अपना ८६ प्रतिशतसे ८८ प्रतिशत समय नर्सके साथ बिताते हैं। नर्सिंग एक विविध क्षेत्र है। -**सत्यपाल वशिष्ठ, वाया ईमेल।**

निर्यातमें विविधताका सुखद असर

सरकारने प्याजके निर्यातसे प्रतिबंध हटा दिया है। यह फैसला प्याजके मौजूदा रबी पैदावारके अच्छे होने और खरीफके दौरान बढ़िया पैदावारकी संभावनाको देखते हुए किया गया है। सरकारने प्याज निर्यातकी न्यूनतम कीमत ५५० डॉलर प्रति टन तयकी है और इसपर ४० फीसदीका निर्यात शुल्क भी लगेगा। इससे प्याज किसानोंकी आयमें वृद्धि होगी।

❐ **डा. जयंतीलाल भंडारी**

देशमें प्याजकी पैदावार करनेवाले किसानोंकी आयमें वृद्धि होगी। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष दिसंबर, २०२३ में केन्द्र सरकारने वर्ष २०२२ के खरीफ पैदावारकी स्थितिको देखते हुए प्याज निर्यातको प्रतिबंधित कर दिया था। इसका असर घरेलू बाजारमें खास तौरपर दिखा है। इस दौरान देशमें प्याजकी कीमतें अमूमन स्थिर रही हैं। चूंकि वर्ष २०२३-२४ में २.५५ करोड़ टन प्याज उत्पादनकी संभावना है। जो देशकी मांग और निर्यात मांगको देखते हुए पर्याप्त है। अभी निर्यात प्रतिबंधित होनेके बावजूद बंगलादेश, भूटान, यूएई, श्रीलंका आदिको कुछ मात्रामें प्याजकी आपूर्ति की गयी है। निश्चित रूपसे प्याज निर्यातसे प्याज उत्पादक किसानोंको लाभ होगा। दरअसल घटते हुए वैश्विक व्यापार और घटते हुए वैश्विक निर्यातके बीच भारतसे निर्यातके सूझ-बूझपूर्ण निर्णय लिये जाने होंगे। यद्यपि भारतसे पिछले कुछ वर्षोंमें लगातार रिकॉर्ड निर्यात हुए हैं, लेकिन अब भीषण होते हुए इसरायल-ईरान टकरावसे गहराती हुई नयी वैश्विक व्यापार चुनौतियोंके बीच भारतको निर्यात बढ़ाने एवं आयात घटानेकी विशेष रणनीतिके साथ आगे आना होगा। खास तौरसे हालमें २८ अप्रैलको प्रकाशित आर्थिक टैंक ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिवकी रिपोर्टके मुताबिक भारतके वस्तु आयातमें चीनकी जो हिस्सेदारी बढ़कर ३० फीसदीके चिंताजनक स्तरपर पहुंचते हुए १०१ अरब डालरकी ऊंचाईपर पहुंच गयी है, उसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानोंसे नियंत्रित करना होगा। गौरतलब है कि हालमें वाणिज्य मंत्रालयकी तरफसे जारी आंकड़ोंके मुताबिक पिछले वित्त वर्ष २०२३-२४ में भारतसे माल एवं सेवाओंका कुल निर्यात ७७६.७८ अरब डालर रहा, जो वित्त वर्ष २०२२-२३ में ४४७.४० अरब डालर रहा था। ऐसेमें गत वित्त वर्षमें सेवा निर्यात ३.५ प्रतिशतकी वृद्धिके साथ ३३९.६२ अरब डालरका रहा, जबकि वस्तु निर्यात ३.११ प्रतिशतकी गिरावटके साथ ४३७.०६ अरब डालर रहा। जहां पिछले वर्षमें कुल आयात ८५४.८० अरब डालरका रहा, वहीं वर्ष २२.२३ में कुल आयात ८९८ अरब डालर मूल्य का रहा था। ऐसेमें पिछले वर्ष आयातमें कमीसे कुल व्यापार घाटेमें ३६ प्रतिशतकी कमी दर्ज की गयी है। पिछले वर्षमें आयातमें गिरावटकी बड़ी वजह तेलका कम आयात था। कच्चे तेलकी कीमतें कम रहनेसे बीते वर्षमें तेलके आयातपर करीब १६ फीसदी कम खर्च हुआ। निश्चित रूपसे बीते कुछ वर्षोंमें भारतके निर्यातका एक चमकदार पहलू सेवा निर्यात है। भारत डिजिटल माध्यमसे मुहैया करायी गयी सेवाओंके निर्यातमें वैश्विक बाजारमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। डिजिटल माध्यमसे सेवा निर्यातके तहत कम्प्यूटर नेटवर्कका इस्तेमाल कर शिक्षा, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, गेमिंग, मनोरंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदिके लिए दक्ष ऑपरेटर, कुशल प्रोग्रामर और कोडिंग विशेषज्ञ द्वारा दी जानेवाली सेवाएं शामिल हैं। भारतमें बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की तेजीसे नयी स्थापनाओंके कारण भी सेवा निर्यात बढ़ रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वर्ष २०१५-१६ से लगाकर वर्ष २०२२-२३ के बीच भारतमें जीसीसीकी संख्या ६० फीसदी बढ़कर १६०० से अधिक हो गयी है। विश्व व्यापार संघटनकी रिपोर्टके अनुसार डिजिटल माध्यमसे जुड़ी हुई सेवाओंके तेजीसे बढ़ते निर्यातके कारण इस क्षेत्रमें भारत जर्मनी और चीनको पीछे छोड़ते हुए दुनियामें अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंडके बाद चौथे क्रमपर आ गया है। इस समय भारतके प्रमुख निर्यात बाजारोंमें अमेरिका, यूएई, यूरोपीयन यूनियन, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलयेशिया, बंगलादेश, नीदरलैंड, चीन एवं जर्मनी शामिल हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारतसे दवाओंका निर्यात २०२३-२४ में २७.९ अरब डालर पहुंच गया है। २०२२-२३ के दौरान यह आंकड़ा २५.४ अरब डालर रहा था। सरकार द्वारा प्रमुख दवा सामग्री और जेनेरिक दवाओंके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देनेके लिए जो दो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गयी हैं, उनका लाभ दवा निर्यातमें मिलने लगा है। आईफोनके निर्यातमें भी भारत उभरकर दिखाई दे रहा है। आईफोन निर्माता कम्पनी एपलने पिछले वर्षमें भारतसे दस अरब डालरके आईफोनका निर्यात किया, जो अभीतकका रिकॉर्ड है। कम्पनीने पीएलआई योजनाके तहत पिछले वित्त वर्ष २०२३-२४ में जो फोन बेचे, उनकी कीमत २०२२-२३ में बिके आईफोनकी कीमतसे दोगुनी करीब एक लाख करोड़ रुपये रही है। भारतमें यह पहला मौका है, जब किसी कम्पनीने इतनी अधिक कीमतका अपना कोई उपभोक्ता उत्पाद निर्यात किया है। एपल दुनियाभरमें वैल्यू चेन रखनेवाली पहली ऐसी कम्पनी है, जिसने भारतको घरेलू बाजारके बजाय निर्यातके लिए अपना केन्द्र बना लिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि युद्धजनित आर्थिक चुनौतियोंके बीच भारतके लिए वैश्विक व्यापार और निर्यात बढ़ाने हेतु मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की अहमियत और बढ़ गई है। भारतने अबतक तीन एफटीए किये हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मई २०२२ में लागू द्विपक्षीय कारोबारमें पिछले दो वर्षोंमें १५ फीसदीकी वृद्धि देखनेको मिली है। यूएईए भारतका दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाके साथ भी हुए एफटीएसे भारतका ऑस्ट्रेलियाके साथ भी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। विगत १० मार्चको भारत और चार यूरोपीय देशोंके समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) के बीच निवेश और वस्तुओं एवं सेवाओंके दोतरफा व्यापारको बढ़ावा देनेके लिए किया गया एफटीए भी अत्यधिक उपयोगी है। दुनियामें भू राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, उससे कच्चे तेलके दामके साथ-साथ आपूर्ति संकट बढ़नेकी चिंताएं मुंहबाएं खड़ी हैं। इससे भारतके वैश्विक व्यापार एवं निर्यातपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसेमें भारतको निर्यात बढ़ाने एवं चीनसे आयात घटानेकी नयी रणनीतिके साथ आगे बढ़ना होगा। देशमें उच्च ब्याज दरों और मांगमें कमीके कारण निर्यातके मोर्चेपर जूझ रहे छोटे निर्यातकोंको कम ब्याज दरोंपर ऋण मुहैया कराने एवं बैंकको इसके बदले सरकारसे मुआवजा दिये जानेके लिए लागू की गयी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम (आईईएस) की जो अवधि ३० जून, २०२४ को समाप्त हो रही है, उसे एक वर्षके लिए और आगे बढ़ाया जाना लाभप्रद होगा। जिस तरह विकसित अर्थव्यवस्थावाले कई देश लम्बे समुद्री आवागमनसे पहुंचनेवाले दूरदराजके देशोंकी बजाय अपने तटके आसपासके देशोंमें कारोबारपर जोर दे रहे हैं, वैसी रणनीतिपर भारतको भी ध्यान देना होगा। यद्यपि भारतको दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यातमें तुलनात्मक रूपसे बढ़त हासिल है लेकिन यह बात ध्यानमें रखी जानी होगी कि अब सेवा निर्यातके क्षेत्रमें भी लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसी स्थितिमें भारतसे डिजिटल सेवा निर्यातमें तेजीसे वृद्धिके लिए सेवाओंकी गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षाको लेकर और अधिक प्रयास करना होंगे।

युद्धजनित आर्थिक चुनौतियोंके बीच भारतके लिए वैश्विक व्यापार और निर्यात बढ़ाने हेतु मुक्त व्यापार समझौतोंकी अहमियत और बढ़ गयी है। भारतने अबतक तीन एफटीए किये हैं। भारत और यूएईके बीच मई २०२२ में लागू द्विपक्षीय कारोबारमें पिछले दो वर्षोंमें १५ फीसदीकी वृद्धि देखनेको मिली है। यूएई भारतका दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाके साथ भी हुए एफटीएसे भारतका ऑस्ट्रेलियाके साथ भी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है।

विचारणीय है जनसंख्या असंतुलन

प्रधान मंत्रीकी आर्थिक सलाहकार परिषदने मुस्लिम संख्या वृद्धिके तथ्य उद्‌घाटित किये हैं। परिषदने दुनियाके १६७ देशोंके जनसांख्यकीय चरित्रका अध्ययन किया है। विश्वके किसी भी देशमें बहुसंख्यक आबादीकी बढ़त नहीं दिखती है।

❐ **हृदयनारायण दीक्षित**

प्रधान मंत्रीकी आर्थिक सलाहकार परिषदकी रिपोर्टके अनुसार दुनियाके किसी भी देशमें बहुसंख्यक आबादीकी बढ़त नहीं दिखाई पड़ी है लेकिन कई देशोंमें अल्पसंख्यक आबादीकी बढ़त पायी गयी है। भारतमें मुस्लिम आबादीकी संख्या बढ़ी है। मुस्लिम संख्या वृद्धिके ताजा आंकड़ोंको लेकर देशमें खासी बहस चल रही है। भारतमें हिन्दू-मुस्लिम सहअस्तित्व सामाजिक पुनर्गठनकी बड़ी चुनौती रहा है। गांधी जीने हिन्दू-मुस्लिम सहअस्तित्वके लिए आजीवन काम किया और अंतमें कहा कि इस प्रश्नपर मेरी हार हुई। मुस्लिम राजनीति अन्य पंथोंपर आक्रामक रही है। मुस्लिम साम्प्रदायिकताके कारण ही भारतका विभाजन हुआ था। गांधी जीने मोहम्मद अली जिन्नासे पाकिस्तानकी मांग न करने और साथ-साथ रहनेका आग्रह किया था। इस सम्बंधमें उन्होंने जिन्नाको (१५ सितंबर १९४४) पत्र लिखा था। उन्होंने जिन्नासे पूछा था कि मजहबके अलावा हिन्दू और मुसलमानमें क्या कोई और भी भेद है। मुसलमान शेष भारतवासियोंसे क्यों अलग हैं। जिन्नाने जवाबी पत्र (१७ दिसम्बर १९४४) में लिखा था, हम मानते हैं कि मुसलमान और हिन्दू देशकी किसी भी परिभाषाके आधारपर अलग-अलग कौमें हैं। हमारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, साहित्य, कला, कानून, परम्परा एवं इतिहास अलग-अलग है। जीवनके प्रति हमारा नजरिया भी अलग है। हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानूनके आधारपर अलग राष्ट्र हैं। यह मुस्लिम लीग और जिन्नाका घोर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण था। इस साम्प्रदायिकताके दृष्टिकोणको माने तो हिन्दू मुसलमान जब मिलकर रहते थे, तब भी मुसलमान अलग राष्ट्र थे। भारतके भीतर दो राष्ट्र थे। यह सोच अलगाववादी थी। वस्तुतः भारत प्राचीन कालसे ही एक संस्कृति आधारित राष्ट्र है। साम्प्रदायिक राजनीति स्वयंको अलग राष्ट्र मानती रही है। मजहब आधारित जनसंख्यामें बढ़त इसीलिए चिन्ताका विषय है। मजहबके आधारपर अलग राष्ट्रकी मांग करना, इसके लिए लाखों लोगोंकी हत्या हिंसा किसी भी सूरतमें उचित नहीं हो सकता। यह मानवताके विरुद्ध अपराध है। जनसंख्याके आधारपर ही मुस्लिम लीगने अलग देश मांगा। भयंकर रक्तपात हुआ। इसलिए साम्प्रदायिक आबादीकी बढ़तकी कोई भी सूचना देशको चिन्तामें डाल देती है। आंकड़ोंके निष्कर्ष सत्यके उद्‌घाटनके लिए पर्याप्त हैं। अविभाजित भारतकी अंतिम जनगणना १९४१ में हुई थी। तब हिन्दू आबादी ८४.४४ प्रतिशत थी और मुस्लिम १३.८ प्रतिशत थे। मुसलमानोंकी इस संख्यामें आजके पाकिस्तान और बंगलादेशी मुस्लिम भी सम्मिलित थे। फिर देशका बंटवारा हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ। कुल मुस्लिम आबादीकी संख्यामें पाकिस्तानी एवं बंगलादेशी मुस्लिम जनसंख्या घट गयी। स्वतंत्र भारतकी प्रथम जनगणना १९५१ में हुई। तब पाकिस्तानी एवं बंगलादेशी मुस्लिम जनसंख्या नहीं रही। इसलिए हिन्दू जनसंख्याका अनुपात ८७.२४ हो गया। मुस्लिम आबादी घटकर १०.४३ हो गयी। लेकिन ५० वर्ष बाद २००१ की जनगणनामें हिन्दू घटकर ८४.२१ प्रतिशत हो गये। मुस्लिम आबादीका अनुपात अविभाजित भारतके १३.८ प्रतिशतसे भी ज्यादा हो गया। आबादीके इसी अनुपातपर मुस्लिम लीगने अलग देशकी मांग की थी और पाकिस्तान अस्तित्वमें आया था। इस तरहकी जनसंख्या बढ़तसे एक और मजहबी साम्प्रदायिक देशकी जनसंख्या तैयार हो गयी है।

साम्प्रदायिक राजनीति आर्थिक नीतियोंसे जुड़े गरीबी-अमीरी, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि मूलभूत प्रश्नोंको महत्व नहीं देती। वे राजनीतिमें भी कट्टरपंथी मजहबी अलगाववाद चलाते हैं। साम्प्रदायिक अलगाववादी जिस देशमें रहते हैं, उस देशकी संवैधानिक व्यवस्थासे भी टकराते हैं। राजनीति वोट बैंकके तुष्टीकरणके कार्यक्रम बनाती है। कट्टरपंथी मजहबी राजनीतिकी मांगे खतरनाक हैं। वे तुष्टीकरणकी साम्प्रदायिक राजनीतिको सेकुलर कहते हैं। वस्तुतः सेकुलर विचारमें आस्था और अंधविश्वास नहीं होने चाहिए। मजहबी राजनीति सेकुलर हो ही नहीं सकती। इस्लामी विचारधाराके अंतरराष्ट्रीय विद्वान प्रोफेसर डेनियल पाइपके अनुसार, दूसरे पंथोंके विपरीत इस्लाममें सामाजिक जीवनके परिचालनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। दूसरे पंथ केवल मौलिक मूल्योंके ही उपदेश देते हैं और भौतिक विषयोंपर समय अनुसार विधान और नियम बनानेका काम समाजपर छोड़ देते हैं। इस्लामी राजनीतिक चिन्तन सुस्पष्ट ध्येय निर्धारित करता है। सभी मुसलमानोंको इन नियमोंका पालन अनिवार्य है। दूसरे पंथोंमें राजनीतिक क्रियाकलापोंके लिए लिखित आदेश नहीं है। मुस्लिम विश्वासमें ईश्वरपर विश्वासके साथ ही उनके पवित्र कानून भी हैं। यह कानून शरिया कहा जाता है। यह राजनीतिक शक्तिके रूपमें स्थापित करता है। इस्लामी राजनीतिमें मजहबकी प्रचंड प्रेरणा है। (प्रोफेसर डेनियल पाइप इन द पाथ आफ गॉड पृष्ठ तीन) गांधी जी हिन्दू मुसलमानकी साझा राष्ट्रीयता चाहते थे। वे असफल रहे। डाक्टर अम्बेडकर हिन्दू-मुसलमानके पक्षपर गांधी जीसे असहमत थे। डा. आम्बेडकरने लिखा है, गजनीके मोहम्मदने भारतपर अपने अनेक हमलोंको जेहाद छेड़नेकी संज्ञा दी थी। मोहम्मदके इतिहासकार अल उतबीने उसके हमलेके बारेमें लिखा था, उसने मंदिरोंमें मूर्तियोंको तोड़ा और इस्लामकी स्थापना की। उसने शहरोंपर कब्जा किया, नापाक कमीनोंको मार डाला। मूर्ति पूजकोंको तबाह किया और मुसलमानोंको गौरवान्वित किया। तदुपरांत वह घर लौटा और इस्लामके लिए की गयी विजयोंका ब्योरा दिया और यह संकल्प व्यक्त किया कि वह हर वर्ष हिन्दके खिलाफ जेहाद करेगा। यही स्थिति अन्य हमलोंकी भी है। हजारों मंदिर तोड़े गये थे। श्रीराम जन्मभूमि, ज्ञानवापी काशी और मथुराकी घटनाओंके प्रसंग इस समय भी ताजा हैं।

यूरोपके अनेक देश मुस्लिम आक्रामकताको लेकर चिन्तित हैं। फ्रांसमें पैगम्बरका कार्टून बनानेको लेकर भयानक हिंसा हुई। डेनमार्कमें भी ऐसी ही साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी। पाकिस्तानमें ईश निंदा कानूनके अंतर्गत ढेर सारे गैर मुसलमानोंका उत्पीड़न जारी है। अमेरिकाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटरपर भी इसी तरहका हमला हुआ था। इसलिए जनसंख्याकी बढ़तको लेकर चिन्ता स्वाभाविक है। भारतके लिए यह और भी चिन्ताका विषय है। मुस्लिम साम्प्रदायिकताके कारण ही देश टूटा था। अपनी इच्छा अनुसार जीवन ध्येय निर्धारित करना प्रत्येक मनुष्यका अधिकार है। विवेक आधारित जीवन रसका आस्वाद प्रत्येक मनुष्यकी अभिलाषा है। अपने अनुभव और विश्वासके अनुसार जीनेका अधिकार स्वाभाविक है। इसलिए कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है। अनूठा भी। किसीकी जीवन पद्धतिमें हस्तक्षेप न करना और सबको अपने ढंगसे जीवन जीनेका अवसर मिलना प्राकृतिक न्याय है। दुनियाको सुन्दर बनानेकी यह न्यूनतम शर्त है, लेकिन साम्प्रदायिक मजहबी राजनीति अपने मतको श्रेष्ठ और बाकीको इनकार करनेवाला मानती है और इनकार करनेवालोंके लिए सजाका औचित्य भी सिद्ध करती है। मुस्लिम जनसंख्याकी बढ़तके प्रभावका विवेचन जरूरी है। यह चिन्ता मुस्लिमोंके विरुद्ध नहीं है। चिन्ताका विषय आक्रामक साम्प्रदायिकता और अलगाववादसे छुटकारा पाना है। भारतके राष्ट्रजीवन एवं संविधानमें सभी आस्था समूहोंका सम्मान है। इसलिए जनसंख्याका असंतुलन गहन रूपमें विचारणीय है।

आत्मबोध

गंगा सप्तमी

❐ **सदानन्द शास्त्री**

गंगा सप्तमी वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी सप्तमीको कहा जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिन्दू मान्यताओंके अनुसार वैशाख मासकी इस तिथिको ही मां गंगा स्वर्ग लोकसे भगवान शिवकी जटाओंमें पहुंची थीं। इसलिए इस दिनको गंगा सप्तमीके रूपमें मनाया जाता है। कहीं-कहींपर इस तिथिको गंगा जन्मोत्सवके नामसे भी पुकारा जाता है। गंगाको हिन्दू मान्यताओंमें बहुत ही सम्मानित स्थान दिया गया है। पौराणिक धर्म ग्रंथोंके अनुसार जब कपिल मुनिके श्रापसे सूर्यवंशी राजा सगरके ६० हजार पुत्र जल कर भस्म हो गये, तब उनके उद्धारके लिए राजा सगरके वंशज भगीरथने घोर तपस्या की। वे अपनी कठिन तपस्यासे मां गंगाको प्रसन्न करनेमें सफल रहे और उन्हें धरतीपर लेकर आये। गंगाके स्पर्शसे ही सगरके ६० हजार पुत्रोंका उद्धार हो सका। गंगाको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। विभिन्न अवसरोंपर गंगा नदीके तटपर मेले और गंगा स्नान आदिके आयोजन होते हैं। इनमें कुम्भ पर्व, गंगा दशहरा, पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, मकर संक्रांति एवं गंगा सप्तमी आदि प्रमुख हैं। पौराणिक शास्त्रोंके अनुसार वैशाख मासमें शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिको मां गंगा स्वर्ग लोकसे शिवशंकरकी जटाओंमें पहुंची थी। जिस दिन गंगा जीकी उत्पत्ति हुई, वह दिन गंगा जयंती (वैशाख शुक्ल सप्तमी) और जिस दिन गंगाजी पृथ्वीपर अवतरित हुईं वह दिन गंगा दशहरा (ज्येष्ठ शुक्ल दशमी) के नामसे जाना जाता है। इस दिन मां गंगाका पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमीके अवसर पर्वपर मां गंगामें डुबकी लगानेसे मनुष्यके सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगामें स्नानका अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करनेसे मनुष्य सभी दुखोंसे मुक्ति पा जाता है। इस पर्वके लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरोंपर भी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदीमें स्नान करनेसे दस पापोंका हरण होकर अंतमें मुक्ति मिलती है। इस दिन दान-पुण्यका विशेष महत्व है। शास्त्रोंमें उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगामें स्नान, पुण्यसलिला नर्मदाके दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्राके स्मरण मात्रसे मोक्ष मिल जाता है।

झारखंडमें भ्रष्टाचारकी गहरी जड़ें

❐ **रोहित माहेश्वरी**

बीते कई दिनोंसे झारखंड सुर्खियोंमें है। ताजा प्रकरण, झारखंड सरकारमें ग्रामीण विकासमंत्री आलमगीर आलमसे परोक्ष रूपसे जुड़ा है। उनके निजी सचिवके घरेलू नौकरके घरसे ३५ करोड़ रुपयेसे अधिककी काली कमाइ बरामद हुई है। आश्चर्य इस बातका है कि एक नौकर स्तरका व्यक्ति कितना भी भ्रष्टाचार करे, लेकिन उसके घर बैगोंमें भरे करोड़ोंके नोट बरामद नहीं किये जा सकते। यकीनन इस सन्दर्भमें उसे बलिका बकरा बनाया गया है तो फिर सवाल है कि काली कमाईके नोट किसके हैं। क्या नौकरका घर कलेक्शन सेंटर बना था। ईडीके अफसरोंको मंत्रीके निजी सचिवपर तो शक था, लिहाजा नौकरका पीछा भी किया गया। अकसर उसके हाथमें एक बैग होता था, लेकिन घरसे बाहर आते हुए उसके हाथ खाली होते थे। अंततः ईडीने छापेमारी की तो नोटोंसे भरे बैग मिले और उसीके साथ भ्रष्टाचारका एक रहस्य खुला। सवाल मंत्रीके कारनामोंपर भी है, क्योंकि ईडीने जिन इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियोंको धरपकड़ की है, उनमेंसे कइयोंने मंत्रीकी संलिप्तताका भी खुलासा किया है। दलालोंका एक खेल उस विभागमें खेला जा रहा था। ठेका देनेके बदले तीन फीसदी दलाली ली जाती थी। मंत्री और निजी सचिवकी कटमनी ज्यादा और अलग थी। अफसरोंकी पोस्टिंग और ट्रांसफरकी बोलियां अलगसे लगती थीं। यह जांच एजेंसियोंके दुरुपयोग नहीं, बल्कि आम आदमीसे भ्रष्ट जमातने जो भी लूटा है, उसकी पाई-पाई वापस वसूली जानी चाहिए। याद कीजिए इस साल १५ अगस्तको लाल किलेकी प्राचीरसे दिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीका भाषण। ७७वें स्वतंत्रता दिवसपर प्रधान मंत्रीने तीन बुराइयोंके खिलाफ लड़ाईका आह्वान किया था, जिनका देश सामना कर रहा है- भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक २०२३ जारी किया गया। समग्र तौरपर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशकमें अधिकांश देशोंमें भ्रष्टाचारपर नियंत्रणकी स्थिति या तो काफी हदतक स्थिर या खराब रही है। भारतने भ्रष्टाचार बोध सूचकांक २०२३ में ४० अंक प्राप्त किये। असलमें झारखंड देशका गजब प्रदेश है। कभी पॉलिटिशियनपर रिश्वतखोरीका आरोप लगता है तो कभी अफसर-दलालोंका गठजोड़ भ्रष्टाचारमें लिप्त दिखाई देता है। दो आईएएस और एक चीफ इंजीनियर करप्शनके आरोपमें जेल जा चुके हैं। कभी कोयला घोटाला, कभी लौह-अयस्क घोटाला, खनन-परिवहन घोटाला, मनरेगा घोटाला, नियुक्ति घोटाला तो अब जमीन घोटाला। झारखंडमें भ्रष्टाचारकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ऊपरसे लेकर नीचेतकके अधिकारी और कर्मचारी इसमें फंसे हुए हैं। आलम यह है कि राज्यके कई आईएएस अधिकारियोंपर भ्रष्टाचारके आरोप हैं, लेकिन आजतक कार्रवाईके नामपर बस फाइल इधरसे उधरसे होती रही। झारखंडकी बदकिस्मती है कि प्रकृति उसे खूब संसाधन दिये हैं, बेशकीमती खनिज दिये हैं, लेकिन फिर भी वह गरीब और भ्रष्ट है। दरअसल झारखंडका राजनीतिक नेतृत्व फितरतसे ही भ्रष्ट रहा है। बेशक वह शिबू सोरेन हों, निर्दलीय रहा सरकार बचानेवाले सांसद हों, मुख्य मंत्री रहे मधु कोड़ा और कुछ माह पूर्वतक मुख्य मंत्री रहे हेमंत सोरेन हों, सभी दागदार और भ्रष्ट रहे हैं। जेलमें भी रहे हैं। हेमंत सोरेन अब भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलोंमें न्यायिक हिरासतमें हैं। राजनेताओंके अलावा आईएएस या अन्य शीर्ष अधिकारियोंके घरोंसे भी करोड़ोंकी नकदी बरामद की गयी है। उनके पास अकूत संपत्तियां भी मिली हैं, लिहाजा उन्हें जब्त किया गया है। कई ऐसे सफेदपोश चेहरे जेलकी सलाखों के पीछे हैं। झारखंडमें धीरज साहू जैसे कांग्रेसी सांसद भी हैं, जिनके घर और अन्य ठिकानोंसे ३५० करोड़ रुपयेसे अधिकके नकदी नोट बरामद किये गये। घरके कमरोंमें नोट ऐसे सजाये गये थे मानो नकदीका कोई शोरूम हो! काली कमाईके ये पहाड़ कैसे संजो लिये जाते हैं, आम आदमीके लिए यह आश्चर्यकी मीनारें हैं। साहू आज भी सांसद हैं। देशमें काले, भ्रष्ट नकदी पहाड़ोंके गोदाम भरे हुए हैं, प्रधान मंत्री मोदीका यह कथन कड़वा सच लगता है। देशके कई हिस्सोंमें ऐसे गोदामोंको दबोचा गया है, अदालतमें भी केस हैं, लेकिन आम आदमी न्याय का मारा है। हम मानते हैं कि ईडी मंत्रीपर साक्ष्यों और गवाहोंके बिना हाथ नहीं डालेगा, लेकिन यह भ्रष्टाचार देशके कोने-कोनेमें कबतक जारी रहेगा। घूस और दलाली तो व्यवहार बन गये हैं। प्रधान मंत्री प्रतिबद्ध दिखते हैं कि वह ऐसी एक भी पाई खाने नहीं देंगे। ऐसी चोरी बंद करके रहेंगे। भ्रष्ट लोगोंकी कमाई और लूट बंद करके रहेंगे। बेशक भ्रष्टाचारी उन्हें गालियां देते रहें। झारखंडपर १.३० लाख करोड़ रुपयेका कर्ज है। राज्यके नागरिककी औसत कमाई ७००० रुपये माहवार है। देशके राज्योंमें विकासके मद्देनजर झारखंडका स्थान ३०वां है। आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दलके नेता हैं। गठबंधन सरकारमें कांग्रेस नेतृत्वने उनका नाम सबसे पहले संस्तुत किया था। वह राज्य विधानसभाके स्पीकर भी रहे हैं। सवाल है कि एक साईकिल चलानेवाले नौकरके पास ३५ करोड़ रुपयेसे अधिकका धन कहांसे आया। इस देशके हर आम और खास आदमीको पता है कि देशमें हो रहे अपराधोंको रोकनेके लिए सैकड़ों कानून हैं। पुलिस है, सीबीआई है और नीचेसे ऊपरतक न्यायिक तंत्रका जाल है, परन्तु क्या इसके बावजूद समाजमें अपराध घट रहे हैं। नहीं, फिर भी लोगोंको लगातार बहकाया जा रहा है कि सख्त कानूनसे भ्रष्टाचार खत्म हो जायगा। जबकि अपराध शास्त्रके शोध बताते हैं कि कानूनसे केवल पांच फीसदी अपराध कम होते हैं। बाकी ९५ फीसदी अपराध कम करनेके लिए अन्य प्रयासोंकी जरूरत होती है। भ्रष्टाचार भी चूंकि एक अपराध है, इसलिए इसे समाप्त करनेसे पहले हमें समझना होगा कि यह अपराध क्यों हो रहा है। साल २०१४ में केन्द्रमें आनेके बादसे मोदी सरकारने भ्रष्टाचारको लेकर जीरो टॉलरेंसका रवैया अपनाया है, जिससे जांच एजेंसियोंने भी सरकारके साथ कदमसे कदम मिलाकर लाखों करोड़ों रुपयेकी संपत्ति अबतक जब्त की है। ईडी सहित अन्य एजेंसियोंने पिछले नौ वर्षोंमें टैक्स चोरी करनेवालोंपर जमकर एक्शन लिया है। ईडीका चाबुक केवल कारोबारियोंपर ही नहीं, बल्कि भ्रष्ट नेताओंपर भी चला है। लोकसभा चुनाव प्रचारमें पीएम मोदीने तीसरी बार सरकार बननेपर भ्रष्टाचारपर कड़े प्रहारका वादा देशवासियोंसे किया है। असलमें यदि भ्रष्टाचारपर प्रभावी रोक लग जाय तो देश विकास और समृद्धिके रास्तेपर और भी तेजीसे दौड़ने लगेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा

पटना ● रविवार ● 12 मई ● 2024

www.rashtriyasahara.com

आबादी पर सवाल

देश में हिंदुओं की आबादी में कमी आ रही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारीः राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण (1950-2015) दस्तावेज में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने खुलासा किया है। इसमें हिन्दू आबादी के 7.82 फीसद कम होने के साथ मुसलमानों की 43.15 फीसद बढ़ने की बात की गई है। सिखों की आबादी 1.24 फीसद से बढकर 1.85 फीसद तथा इसाइयों की 2.24 फीसद से बढ कर 2.36 फीसद हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बौद्ध भी बढ़े हैं, जबकि जैन व पारसियों की संख्या घटी है। यूं तो जनसंख्या के आंकड़े जनगणना के माध्यम से आते हैं। जो 2011 के बाद से नहीं हो सकी है। जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, जो करोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। इस अध्ययन में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक

आबादी में आए उतार-चढाव के अंतरराष्ट्रीय रुझान का पता लगाने के लिए 167 देश शामिल थे, जिसके मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आबादी की बढ़ोत्तरी सबसे ज्यादा हुई। जबकि बांग्लादेश में 10 फीसद व पाकिस्तान में 10 फीसद मुसलमानों की आबादी में बढ़त देखी गई। देश में मौजूदा वक्त में लोक सभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें सत्ताधारी दल पहले ही धार्मिक आधार पर बयानबाजियां करने और समाज में दरारें पैदा करने में हिचक नहीं रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट का प्रचार खास समुदाय को निशाना बनाने में सहायक साबित हो सकता है। विपक्ष भी इसे चुनावी चाल कह आरएसएस का एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहा है। वास्तव में हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाना और उनके साथ सहिष्णुता बरतना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मुसलमानों की आबादी बढ़ने के कारणों में यूं तो उनकी चार शादियां, धर्मांतरण व घुसपैठ को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि इसके पीछे अशिक्षा व जागरूकता की कमी अधिक है। विशेष समुदाय पर देश की जनसांख्यिकी बदलने के प्रयासों का आरोप मढ़ना कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता कि दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। बीते सौ वर्षों में वे 12.5 फीसद से बढकर 22.5 फीसद हो चुके हैं। इसलिए केवल भारत में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या के लिए भ्रामक प्रचार से बाज आना चाहिए। साथ ही उन्हें जागरूक करने और सेहत संबंधी फायदों के विषय में आगाह करने के प्रयास करने चाहिए।

सतर्क रहें निवेशक

शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 1,062.22 अंक यानी 1.45 फीसद गिरकर 72,404.17 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई इस भारी गिरावट से निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि डूब गई। बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि लोक सभा चुनाव के परिणामों की अनिश्चितताओं से शेयर बाजार भयभीत है। जाहिराना तौर पर देश की घरेलू (चुनाव परिणाम संबंधी) परिस्थितियां और विदेशी परिदृश्य दोनों शेयर बाजार की दृष्टि से प्रतिकूल हैं। इस कारण जहां एक ओर चौतरफा बिकवाली और दूसरी ओर विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी भी गिरावट की बड़ी वजह बताई जा रही हैं। लोक सभा चुनाव का तीसरा चरण हो चुका है और करीब आधी सीटों पर मतदान के बावजूद तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि सरकार

किसकी बनेगी। चुनाव के दौरान संपत्ति के पुनर्वितरण का मामला बहस के केंद्र में है। कांग्रेस के टेक्नोक्रेट नेता सैम पित्रोदा के एक बयान के बाद विरासत कर भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इन दोनों मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनाव सभाओं में कांग्रेस पर तीखा हमला कर रहे हैं। ज्यादातर अमीर और समृद्धशाली लोग ही शेयर बाजार में निवेश करते हैं। जाहिर है कि यह अमीर तबका भयभीत है कि अगर केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आ जाती है तो उनकी संपत्ति गरीबों में बांट देगी। विदेशी मोर्चे पर भी परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। इस्त्राइल-फिलिस्तीन और रूस-यूक्रेन युद्ध किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। गाजा के दक्षिण शहर राफा में इस्त्राइली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी है। इस्त्राइल ने अपने गॉड फादर अमेरिका की सलाह को अनसुना कर दिया है। इस्त्राइल पर हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के हमले तेज हो सकते हैं। इधर, रूस ने चेतावनी दी है कि यदि नाटो यूक्रेन में अपने सैनिक भेजता है तो परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। इन परिस्थितियों में शेयर बाजार की अनिश्चितता आगे भी बने रहने की आशंका है। ऐसे में शेयर बाजार के निवेशकों को बहुत ही चतुराई से अप ना पूंजी निवेश करना चाहिए। यह बाजार जोखिमों से भरा है और ऐसे में कमजोर दिल वालों को शेयर बाजार से दूर ही रहना चाहिए।

कटाक्ष/ कबीरदास

दोस्त-दोस्त ना रहा!

इन विरोधियों को मोदी जी कभी माफ नहीं करेंगे। दिल से माफ करना छोड़ो, कहने को भी माफ नहीं करेंगे। बताइए, पीछे पड़ पड़ के, पीछे पड़ पड़ के, बेचारे से पाप करा दिया। वही रात-दिन एक ही रट--तुम्हारा दोस्त अडानी, तुम्हारा दोस्त अंबानी। वही रात दिन एक ही शिकायत, तुम्हारे यार अडानी ये कर दिया, तुम्हारे यार अंबानी ने वो क्यों कर दिया? वही हर वक्त की तानाकशी--तुम दो, तुम्हारे दो; जो दो, अपने यारों को दो! और भी न जाने क्या-क्या! इंसान तो इंसान, भगवान के बर्दाश्त की भी एक हद्द होती है। गुस्से में साहेब के भी मुंह से निकल गया--अडानी, अंबानी यार होंगे तेरे! कमबख्तों ने डलवा दी ना पक्की दोस्ती में दरार। अब देते रहें सफाइयां; प्यार का धागा तो टूट गया! बेचारे शेयर बाजार को खामखां में तगड़ी पटकनी लग गई सो ऊपर से।

अब प्लीज कोई विरोधियों के इस पाप पर यह कहकर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करे कि टैंपो का तो इस चुनावी सीजन में विरोधियों ने एक बार जिक्र तक नहीं किया था, फिर नोटों से लदे टैंपुओं की तो बात ही कहां उठती है, लेकिन नोटों से लदे टैंपुओं की बात से ही क्या होता है? बेशक, नोटों से भरे टैंपुओं की बात मोदी जी की ऑरीजिनल थी। बोरों में भरे नोटों की बात भी उनकी ऑरीजिनल थी। काले धन के बोरों की बात भी। आखिर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, क्या दूसरों की कही बातें दोहराएगा? मोदी जी को नकलची समझ रखा है क्या? मोदी जी बोलने के लिए मुंह खोलते है, तो ऑरीजिनल विचार अपने आप झरने लगते हैं, उनके टेलीप्राम्टर से। बोलने लगते हैं तो कल्पना के प्रवाह में दूर तक बहते चले जाते हैं। इस बार प्रवाह में बहते-बहते जरा ज्यादा दूर तक निकल गए। इतनी दूर तक कि राहुल ने पूछना शुरू कर दिया कि नोटों से लदे टैंपो रिसीव करने का आप का अनुभव है क्या? टैंपो का नंबर क्या था? और न भी जाने क्या अल्लम-गल्लम। पर ये सब करा-धरा तो विरोधियों का ही है। न पब्लिक के बीच हर टैम अडानी-अंबानी करते, न साहेब को गुस्सा आता और न साहेब दोस्तों को सारे आम गाली देते। विरोधी अब कुछ भी सफाई दें, तीन दोस्तों की सालों पुरानी दोस्ती में दरार डलवाने का पाप तो उनके ही सिर पर है।

ईयू में चीन की घुसपैठ

सामयिक

प्रो. ब्रह्मदीप अलूने

मध्य और दक्षिणपूर्व यूरोप के चौराहे पर स्थित सर्बिया में हजारों लोगों ने चीन और सर्बिया के झंडे हाथों में लिए शी जिनिपंग का जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है उसने यह संदेश दिया है कि चीन को रोकने की अमेरिकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है और यह नई विश्व व्यवस्था में चीन के मजबूती से उभरने के संकेत है। दरअसल, नई विश्व व्यवस्था में शक्तियां क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में केंद्रित है इसलिए कूटनीति का संचालन इसी व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। शी जिनिपंग आर्थिक महाशक्ति बनने की चीनी प्रतिबद्धता को यूरोपीय यूनियन, आसियान और कुछेक क्षेत्रीय सहयोग मंच के जरिए बखूबी पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का चीन का ख्वाब पूरा होने की उम्मीदें भी बढ़ गई है।

बेल्ट एंड रोड चीन की विदेश नीति का केंद्र बिंदु रहा है, इसके तहत चीन ने नई सड़कें, बंदरगाह, रेलवे और आधारभूत संरचना के निर्माण में अरबों डॉलर दांव पर लगाकर अपने व्यापारिक संबंधों को दुनिया भर में विकसित किया है। चीन की ये रणनीति एशिया, इंडो पैसिफिक, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक गहरा प्रभाव छोड़ने में कामयाब रही है।

सर्बिया, मध्य बाल्कन के सुदूर दक्षिणी किनारों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है और यह देश बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है। सर्बिया में तेल, गैस, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, मैग्नीशियम तथा संगमरमर के भंडार हैं। चीन ने सर्बिया में आधारभूत ढांचे को मजबूत करके यहां के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। चीन और सर्बिया ने बेल्ट एंड रोड पहल के ढांचे के तहत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे न केवल सर्बिया में लोगों की आजीविका में सुधार हुआ है, बल्कि दोनों देशों में विकास की गति भी बढ़ी है। सर्बिया और आसपास के बाल्कन देशों में पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अरबों यूरो का निवेश किया है। मध्य यूरोप के एक और देश हंगरी और चीन का सहयोग भी नई उंचाइयों पर है। बीजिंग में हंगेरियन सांस्कृतिक केंद्र वर्षों से सफलता के साथ काम कर रहा है। बुडापेस्ट में चीन सांस्कृतिक केंद्र का जल्द ही आधिकारिक उद्घाटन किया जाएगा। हंगेरियन भाषा पाठ्यक्रम कई चीनी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हैं। कन्फ्यूशियस संस्थान और कन्फ्यूशियस क्लासरूम हंगरी में लोकप्रियता और भागीदारी प्राप्त कर रहे हैं। शी जिनिपंग ने कहा है कि हम बेल्ट एंड रोड पहल और हंगरी की पूर्वी उद्घाटन रणनीति के बीच अधिक

तालमेल बनाने के लिए हंगरी के साथ काम करेंगे और बुडापेस्ट बेलग्रेड रेलवे लिंक और अन्य महत्त्वपूर्ण सहयोग परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित विकास और अन्य उभरते क्षेत्रों में हंगरी के साथ चीन का सहयोग निरंतर मजबूत हुआ है।

यूरोप के इन दो देशों की यात्रा के पहले शी जिनिपंग फ्रांस पहुंचे थे। फ्रांस यूरोपीय संघ का अहम सदस्य होने के बाद भी कूटनीतिक स्वायत्ता को लेकर अमेरिका के खिलाफ मुखर रहा है। पिछले वर्ष मेक्रों ने चीन की यात्रा के बाद वन चाइना नीति का समर्थन किया था। यूरोपीय संघ 27 सदस्य देशों का एक मजबूत संगठन है जो व्यापार, सुरक्षा, कृषि मत्स्य पालन, पर्यावरण और जलवायु सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। वैश्विक कूटनीति में इसका अहम स्थान है। यूरोपीय संघ स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि, लोकतंत्र, आधारभूत स्वतंत्रता एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विधि के नियमों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। अमेरिका के साथ इसके गहरे आर्थिक और सामरिक सरोकार है और नाटो इसका संवर्धन करता है। इंडो पैसिफिक में चीन सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन फ्रांसिसी राष्ट्रपति मैक्रों का कहना है कि यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर देनी चाहिए। जाहिरि है चीन को लेकर यूरोपीय देशों और अमेरिका में मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं। यूरोपीय संघ में शामिल हंगरी और फ्रांस चीन के साथ सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे है। इससे अमेरिका की उस मुहिम को धक्का लगा है, जिसके अनुसार वह यूरोपीय देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता एवं समन्वय को बढ़ावा देता रहा है।

अमेरिका यूरोप में साझा विदेशी एवं सुरक्षा नीति के लिए भी प्रतिबद्धता दिखाता रहा है, लेकिन चीन के विरोध को लेकर एकरूपता दिखाई नहीं पड़ती। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में तथा चीन के यूरोप पर बढ़ते प्रभाव का असर एशिया, अफ्रीका, यूरोप से लेकर इंडो पैसिफिक पर भी पड़ सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में संचार के सुरक्षित समुद्री मार्ग को लेकर यूरोपीय संघ की स्पष्ट नीति रही है और चीन इसके मार्ग में बड़ी चुनौती नजर आता है, लेकिन अब ऐसा लगता है यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने चीन के वैश्विक प्रभावों को स्वीकार कर लिया है। चीन ने 2012 में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के इरादे से एक फोरम शुरू किया था। दक्षिण पूर्वी, मध्य और पूर्वी यूरोप में चीन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की यह कोशिश रही है की वह यूरोपीय संघ के साथ एक ऐसी वैश्विक निवेश योजना पर आगे बढ़े जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के तौर पर सामने रखा जा सके, लेकिन जमीन पर ऐसा कोई भी प्रयास सफल नजर नहीं आता। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ही अब ग्लोबल गेटवे के रूप में प्रभाव छोड़ रही है और इससे यूरोप के कई देश इनकार भी नहीं कर रहे हैं। कोविड काल में चीन ने दुनिया को चमत्कृत करते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने का इतिहास रचा था।

चीन चाहता है कि यह कारोबार और बढ़े इसके लिए चीनी राष्ट्रपति यूरोप की यात्रा पर गए थे। यह भी दिलचस्प है कि चीन की उपस्थिति से जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी और रोमानिया में विकास तो हुआ है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर भी हुए हैं। चीन ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों की मदद कर प्रतिबंध रहित समांतर वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा है। इन सबके बाद भी यूरोपीय संघ के कई देश आर्थिक प्रगति के लिए चीन को स्वीकार कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों पर गहरी चोट होने की आशंका बढ़ गई है।

चीन चाहता है कि यह कारोबार और बढ़े इसके लिए चीनी राष्ट्रपति यूरोप की यात्रा पर गए थे। यह भी दिलचस्प है कि चीन की उपस्थिति से जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी और रोमानिया में विकास तो हुआ है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर भी हुए हैं। चीन ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देशों की मदद कर प्रतिबंध रहित समांतर वैश्विक व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा है। इन सबके बाद भी यूरोपीय संघ के कई देश आर्थिक प्रगति के लिए चीन को स्वीकार कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों पर गहरी चोट होने की आशंका बढ़ गई है

क्या भारतीय चुनाव करवट ले रहा है? शेयर बाजार जैसे संकेतकों से तो लगता है कि हां! क्या इंडिया ब्लॉक, जो गठबंधन से ज्यादा राजनीतिक जोड़-तोड़ है, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है! द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश जनरल को चर्चिल की कही बात याद आ रही है- 'सबसे खराब बात है कि आप सहयोगियों से लड़ पड़ें और उससे भी खराब उनको साथ लिये बिना दूसरों से लड़े।'

एन. राम, पत्रकार
@nramind

सीएनजी | पंकज चतुर्वेदी

अब वो बात नहीं रही

राजधानी दिल्ली की हवा में इन दिनों अजब किस्म का जहर घुल रहा है। अजब इसलिए कि जिस ईंधन से वाहनों को चलाना सुरक्षित घोषित किया गया था, अब वही ईंधन दम घोंट रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) के ताजे एयर बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई 224 है और इस बार हवा का मिजाज बिगड़ने का अकारण नाइट्रोजन डाई आक्साईड (एनओ 2) का आधिक्य है। एनओ-2 की हवा में मौजूदगी कार्बन डाईआक्साइड से भी अधिक घातक होती है। सीपीसीबी का आकलन है कि एनओ 2 की मात्रा बढ़ने का कारण सीएनजी वाहनों से निकलने वाली रासायनिक गैस हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के तंत्र ने महज पीएम 2.5 और 10 को नियंत्रित करने की कोशिशें की और इसके लिए सीएनजी वाहनों की संख्या इतनी हो गई कि अब काला धुएं की जगह अदृश्य धुआं इंसानों के जीवन का दुश्मन बना है। जुलाई-21 में जारी की गई रिपोर्ट 'बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन : सैटेलाइट डाटा रिवील एयर पॉल्यूशन इन्क्रीज इन इंडियाज एट मोस्ट पॉपुलस स्टेट कैपिटल्स' में चेतावनी दे गई थी कि साल दर साल दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा में इजाफा हो रहा है। सेटेलाइट डाटा विश्लेषण के आधार पर ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा 125 फीसद तक ज्यादा रही। ग्रामीण क्षेत्रों में तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के बढ़ने के कारण खेती में अंधाधुंध रासायनिक खाद का इस्तेमाल, मवेशी पालन आदि होता है, लेकिन बड़े शहरों में इसका मूल कारण निरापद या ग्रीन फ्यूल कहे जाने वाले सीएनजी वाहनों का उत्सर्जन है। जान लें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ मिल कर बनीं गैसें-जिन्हें 'आक्साईड आफ नाइट्रोजन' कहते हैं, मानव जीवन और पर्यावरण के लिए उतनी ही नुकसानदेह हैं जितना कार्बन आक्साईड या मोनो आक्साइड। यूरोप में हुए शोध बताते हैं कि सीएनजी वाहनों से निकलने वाले नेनो मीटर (एनएम) आकार के बेहद बारीक कण कैंसर, अल्जाइमर, फेफड़ों के रोग का खुला न्योता हैं। पूरे यूरोप में इस समय

सुरक्षित ईंधन के रूप में वाहनों में सीएनजी के इस्तेमाल पर शोध चल रहे हैं। विदित हो यूरो-6 स्तर के सीएनजी वाहनों के लिए भी कण उत्सर्जन की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है और इसी लिए इससे उपज रहे वायु प्रदुषण और उसके इंसान के जीवन पर कुप्रभाव और वैश्विक पर्यावरण को हो रहे नुक्सान को नजरअंदाज किया जा रहा है। जान लें पर्यावरण मित्र कहे जाने वाले इस ईंधन से बेहद सूक्षम लेकिन घातक 2. 5 एनएम (नेनो मीटर) का उत्सर्जन पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में 100 से 500 गुना अधिक है। खासकर शहरी यातायात में जहां वाहन बहुत धीरे चलते हैं, भारत जैसे चरम गर्मी वाले परिवेश में सीएनजी वाहन उतनी ही मौत बांट रहे हैं जितनी डीजल कार-बसें नुकसान कर रही थी बस कार्बन के बड़े पार्टिकल कम हो गए हैं। यह सच है कि सीएनजी वाहनों से अन्य ईंधन की तुलना में पार्टिकुलेट मेटर 80 फीसद और हाइड्रो कार्बन 35 प्रतिशत कम उत्सर्जित होता है, लेकिन इससे कार्बन मोनो आक्साइड उत्सर्जन पांच गुना अधिक है। शहरों में स्मोग और वातावरण में ओजोन परत के लिए यह गैस अधिक घातक है। परिवेश में 'आक्साईड आफ नाइट्रोजन 'गैस अधिक होने का सीधा असर इंसान के स्वशन तंत्र पर पड़ता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2011 के एक अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सीएनजी पर्यावरणीय कमियों के बिना नहीं है, यह कहते हुए कि सीएनजी जलाने से संभावित खतरनाक कार्बोनिल उत्सर्जन की उच्चतम दर पैदा होती है।

अध्ययन से पता चला था कि रेट्रोफिटेड सीएनजी कार इंजन 30 प्रतिशत अधिक मीथेन उत्सर्जित करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में कॉनर रेनॉल्ड्स और उनके सहयोगी मिलिंद कांडलीकर ने वाहनों में सीएनजी इस्तेमाल के कारण ग्रीनहाउस गैसों कार्बन डाईआक्साइड और मीथेन के प्रभावों पर शोध किया तो पाया कि इस तरह के उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की वृद्धि है। यह जान लें कि सीएनजी भी पेट्रोल-डीजल की तरह जीवाश्म ईंधन ही है। यह भी स्वीकार करना होगा कि ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में एरोसोल (पीएम) अल्पकालिक होते हैं, उनका प्रभाव अधिक क्षेत्रीय होता है और उनके शीतलन और ताप प्रभाव की सीमा अभी भी काफी अनिश्चित है। सीएनजी से निकली नाइट्रोजन आक्साईड अब मानव जीवन के लिए खतरा बन कर उभर रही है। दुर्भाग्य है कि हम आधुनिकता के जंजाल में उन खतरों को पहले नजरअंदाज करते हैं जो आगे चल कर भयानक हो जाते हैं। जान लें प्रकृति के विपरीत ऊर्जा, हवा, पानी किसी का भी कोई विकल्प नहीं हैं। नैसर्गिकता से अधिक पाने का कोई भी उपाय इंसान को दुख ही देगा ।

पात्रता | संत राजिन्दर

इं पात्र बनना एक खाली प्याला होने की भांति है। यह जीवन जीने की एक कला है। पात्रता का अर्थ है जो प्रभु हमें दे उसे पाने के लिए हम हमेशा तैयार रहें।

यह प्रार्थना की सर्वोत्तम अवस्था है, जिसमें हम किसी वस्तु की मांग नहीं करते बल्कि केवल प्रेम और भक्ति-भाव से जो कुछ प्रभु हमें देना चाहते हैं उसे खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ हमारे लिए बेहतर होगा परमात्मा हमें वही देंगे।

हम ऐसी प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब प्रभु में हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो। प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास का पनपना बहुत जरूरी है, यह अनुभव से ही प्राप्त होता है। ज्यादातर हम प्रभु के आशीर्वाद को उसी रूप में पाना चाहते है, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी होती हों। जब प्रभु का आशीश हमें उस रूप में प्राप्त नहीं होता तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। कभी-कभी हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमारे लिए भली नहीं होती या इतनी अच्छी नहीं होती जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। जब हम प्रार्थना किसी वस्तु को पाने के लिए करते हैं, तब हो सकता है कि हमारी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाए या फिर अगली बार बिल्कुल स्वीकार न हो। इससे हमारे उदास हो जाने का खतरा बना रहता है। हम प्रभु में आस्था खो देते हैं, लेकिन जब हम ऐसी वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करते जो प्रभु हमें देना नहीं चाहते, फिर हमारे निराश होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पात्र बनकर प्रार्थना कर पाने के लिए आध्यात्मिक विकास होना बहुत जरूरी है। हमें आध्यात्मिक विकास पाने के लिए किसी अनुभवी महापुरुष के पास जाना होगा। उनके संपर्क में रहते हुए, उनकी दी हुई शिक्षाओं के अनुसार चलकर एवं आत्मिक अनुभव पाकर हमारा श्रद्धा और विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। तब हमें यह भरोसा हो जाता है कि प्रभु हमारे मित्र, शुभचिंतक व रक्षा करने वाले हैं और तब हम स्वयं को प्रभु के हवाले छोड़ देते हैं। 'तेरा भाणा मीठा लागे।' पात्रता की सर्वोच्च अवस्था है जिसमें हमारा मन शांत होता है और हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। प्रभु द्वारा दी गई देनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें खाली प्याले की तरह विनम्रता अपनानी चाहिए। यदि हम धैर्य और इंतजार करेंगे, तब हम उनसे और भी अधिक प्राप्त करेंगे जितनी कि हमारी कल्पना भी न थी।

रीडर्स मेल

बयान से मुसीबत में कांग्रेस

विदेश में रहने वाले सैम पित्रोदा के वक्तव्य से भारत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में क्षेत्रवाद की नई परिभाषा देते हुए पूर्व में रहने वाले को चीनी, दक्षिण में रहने वाले को अफ्रीकी ,उत्तर में रहने वालों को श्वेत और पश्चिम में रहने वालों को अरब की संज्ञा से नवाजा है, जिसने भारत में जारी राजनीतिक उठापटक और घमासान में आग में घी डालने का काम किया है। इससे पहले पित्रोदा ने विरासत टैक्स की भारत में वकालत की थी। हालांकि उस संदर्भ में भी कांग्रेस बचाव करते दिखाई दी थी। इस प्रकरण से कांग्रेस को ही नहीं बल्कि इण्डिया 'गठबंधन को भी लोक सभा चुनाव में भारी नुकसान होने का संकट बना रहेगा। कांग्रेसी नेतायों को बयानबाजी से हर हाल में बचाना होगा।

वीरेंद्र कुमार, गया

जल्द निकले समाधान

एअर इंडिया की उड़ाने रद्द होने से यात्रियों की परेशानी जायज है। भारत में हजारों लाखों लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का रास्ता केवल इसलिए चुनते है ताकि वो जल्दी अपनी यात्रा तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, परंतु उड़ाने रद्द होने अथवा इनमें अकारण देरी होने से सभी यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसा होने से ना केवल उनके समय बल्कि धन का भी नुकसान होता है। एयर इंडिया सहित भारत की सभी एअरलाइंस को इस विषय पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। एअर इंडिया को अपने प्रबंधन में सुधार करके यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की ओर ध्यान देना चाहिए। एअर इंडिया केवल अपनी अंदरूनी समस्याओं को आधार बनाकर यात्रियों को परेशान नहीं कर सकती। इस मामले में विमानन महानिदेशालय ने एअर इंडिया प्रबंधन से जवाब-तलब किया है। परंतु यात्रियों को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। एयर इंडिया और नागरिक विमानन निदेशालय को जल्द-से-जल्द इस समस्या के निवारण के प्रयास करने चाहिए ताकि भविष्य में यात्रियों को इस तरह की परेशानियों से बचाया जा सके।

हितेंद्र डेढा, चिल्ला गांव, दिल्ली

खाड़ी देशों में पानी अनमोल

खाड़ी के शुष्क रेगिस्तानी परिदृश्य में, जहां तेल लंबे समय से क्षेत्र का आर्थिक आधार रहा है, एक नई कहानी सामने आ रही है। खाड़ी में पानी नया तेल कहा जाने लगा है। चूंकि पानी वहां एक महत्त्वपूर्ण और सीमित संसाधन के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए उसकी उपलब्धता पर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। एक उपाय और है कि नमकीन पानी की पर्यावरणीय लागत को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाए। नमकीन पानी को कम करने और पुनः उपयोग करने के तरीकों की खोज करना इसके प्रमुख भाग हैं। अगले दशक में अनुमानित 30 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के साथ, खाड़ी को अपने जल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। जीसीसी देशों द्वारा अपने जल संसाधनों पर डीकार्बोनाइजेशन, विविधता लाने और मांग को कम करने के नेतृत्व से न केवल क्षेत्र को बढ़ते जल सुरक्षा जोखिमों के अनुकूल होने में मदद मिलेगी, बल्कि इसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य शुष्क देशों को भी मदद मिलेगी।

मनीष कुमार चौधरी, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा ● राष्ट्रीयता ● कर्तव्य ● समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।**

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, **फैक्स :** 2535935,2520760 **विज्ञापन**-3911455/434, **प्रसार**- 3911451/428

वर्ष - 18, अंक 6298 — आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07 — *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

हम तब तक सत्य पर नहीं पहुंच सकते, जब तक कि मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व को समुचित आदर न दें। इसके अभाव में हमें स्वतंत्र विचार और तर्क प्राप्त ही नहीं हो सकते।
- बर्ट्रेंड रसेल

क्यों झूठ बोलता है एक मजबूत नेता?

दूसरी नजर
पी चिदंबरम

प्रधानमंत्री ने कौन-से झूठ बोले हैं, यह तो महत्त्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ऐसे झूठ बोल क्यों रहे हैं। ध्यान दें, यह कोई एक झूठ नहीं है, यह झूठ की एक शृंखला है, और झूठ जारी है।

माननीय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, स्वघोषित 'मजबूत' नेता हैं। वे अक्सर अपने छप्पन इंच के सीने का दावा किया करते थे। उनके समर्थक खान मार्केट गुट को काबू में करने, शहरी नक्सलियों को उखाड़ फेंकने, टुकड़े-टुकड़े गैंग को खत्म करने, पाकिस्तान को सबक सिखाने, आधिकारिक सह-भाषा के रूप में अंग्रेजी को खत्म करने, मुख्यधारा मीडिया को अपने अधीन करने और भारत को विश्वगुरु बनाने का दंभ भरते रहे हैं।

एक मजबूत नेता, 303 सांसदों और 12 मुख्यमंत्रियों के साथ, अलग-अलग राज्यों में प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में अकेले भाजपा के लिए 370 (और एनडीए के लिए 400 से अधिक) सीटों की ओर बढ़ना आसान होना चाहिए था। मगर, भाजपा नेता निजी तौर पर स्वीकार करने लगे हैं कि 370 या 400 से अधिक सीटें अब हासिल नहीं हो सकतीं, अब तो अगर भाजपा को सामान्य बहुमत भी मिल जाए, तो खुशी की बात होगी।

गियर क्यों बदला?

मोदी साहब ने अपना प्रचार अभियान बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ शुरू किया था। कांग्रेस का घोषणापत्र पांच अप्रैल, 2024 को जारी हुआ; मोदी साहब ने उसे तिरस्कारपूर्वक नजरअंदाज कर दिया। भाजपा का घोषणापत्र 14 अप्रैल को जारी हुआ, लेकिन उसे लेकर कोई जश्न नहीं मना और न उसकी सामग्री को प्रचारित करने के लिए कोई प्रयास किया गया। घोषणापत्र का नाम 'मोदी की गारंटी' रखा गया। इसकी सामग्री को दरकिनार करते हुए, जब भी मोदी साहब ने किसी रैली में कोई बयान दिया, तो उन्होंने घोषणा के साथ दावा किया कि 'यह मोदी की गारंटी है'। मोदी की गारंटियों की गिनती अब मैं भूल चुका हूं। हालांकि, हकीकत यह है कि मोदी साहब ने- *बेरोजगारों के लिए नौकरियां पैदा करने* या *बढ़ती महंगाई पर काबू पाने* को लेकर कोई गारंटी नहीं दी, जो आम आदमी की दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं। मोदी साहब ने जानबूझ कर सांप्रदायिक सौहार्द, विकास, कृषि संकट, बीमार औद्योगिक इकाइयों, बहुआयामी गरीबी, वित्तीय स्थिरता, राष्ट्रीय ऋण, घरेलू ऋण, शैक्षिक मानक, स्वास्थ्य देखभाल, भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे या ऐसी सैकड़ों अन्य गंभीर चिंताओं के बारे में भी बात नहीं की- जोकि एक प्रधानमंत्री को चुनाव के दौरान करना चाहिए।

19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। मगर शायद, 21 अप्रैल को उन्हें नुकसान का अहसास हो गया, और मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा की सार्वजनिक रैलियों में कांग्रेस पर खुल कर हमला किया। उन्होंने कहा: 'कांग्रेस वामपंथियों और शहरी नक्सलियों के चंगुल में फंस गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो कहा है, वह गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा। हमारी बहनों के पास कितना सोना है, सरकारी कर्मचारियों के पास कितना पैसा है, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी बहनों का सोना समान रूप से वितरित किया जाएगा। क्या सरकार को आपकी संपत्ति लेने का अधिकार है?' हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि 19 से 21 अप्रैल के बीच मोदी साहब को कुछ जानकारी (खुफिया?) प्राप्त हुई, जिसने उन्हें गियर बदलने के लिए मजबूर कर दिया।

झूठ पर झूठ

ऊपर दिए गए अंश में हर आरोप झूठा है। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, झूठ बड़ा और अधिक अपमानजनक होता गया। *संपत्ति* से लेकर *सोना, मंगलसूत्र, स्त्रीधन* और *मकान* तक, मोदी साहब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन्हें जब्त कर लेगी और मुसलमानों, घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को वितरित कर देगी। एक अन्य रैली में, मोदी साहब धर्म-आधारित कोटा और विरासत कर पर कूद पड़े। झूठ का कोई अंत नहीं था। मोदी ने 'भैंसों पर विरासत कर' जैसा आर्थिक विचार-रत्न भी उछाला और कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास दो भैंसें हैं, तो एक छीन ली जाएगी।

इसका तात्कालिक उद्देश्य स्पष्ट था। इस तरह भारतीय मुसलमानों को काले रंग से पोत कर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना और हिंदू मतदाताओं को एकजुट करना था।

प्रधानमंत्री ने कौन-से झूठ बोले हैं, यह तो महत्त्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ऐसे झूठ बोल क्यों रहे हैं। ध्यान दें, यह कोई एक झूठ नहीं है, यह झूठ की एक शृंखला है, और झूठ जारी है। एक प्रधानमंत्री, जो 370 या 400 से अधिक सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है, वह अपने विरोधियों के बारे में लापरवाही से झूठ नहीं बोलेगा। वह विपक्षी दलों को अपने कीर्तिमान पर बहस में शामिल होने की चुनौती देगा। मुख्य युद्धक टैंक के रूप में मोदी साहब का झूठ चुनना- उनका कीर्तिमान नहीं- एक रहस्य है, जिसे सुलझाया जाना बाकी है।

आत्म-संशय क्यों?

मान लीजिए कि मोदी साहब को ईवीएम में बंद रहस्यों का पता चल गया है। इस पर उनका चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जमीनी हालात 2019 की स्थिति से बहुत अलग हैं। अव्वल तो यह कि मोदी साहब चुनाव का 'नैरेटिव' गढ़ नहीं कर पाए हैं। वे बहस की शुरुआत नहीं करते, कांग्रेस के घोषणापत्र पर प्रतिक्रिया देते हैं, भले वह काल्पनिक हो। दूसरे, वे अपने वादे को कांग्रेस के वादे से मिलाने और मतदाताओं का ध्यान खींचने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा, लोग भाजपा के थकाऊ नारों से नाराज हैं, लेकिन मोदी '*अच्छे दिन आने वाले हैं*' जैसा कोई नया नारा नहीं गढ़ पाए हैं। चौथा, कम मतदान फीसद ने उन्हें परेशान कर दिया होगा, क्योंकि यह एक संकेत हो सकता है कि उनके वफादार मतदाता मतदान केंद्रों पर नहीं गए। आखिरकार, मतदान केंद्रों पर आरएसएस स्वयंसेवकों की अनुपस्थिति और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ने भाजपा खेमे में खतरे की घंटी बजा दी होगी।

संभव है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को उल्लेखनीय लाभ मिले। क्या इस तरह के 'लाभ' से भाजपा को 'शुद्ध घाटा' होगा, यह लाख टके का सवाल है। संभव है कि मोदी साहब भी यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हों कि 2024 का चुनाव किसी भी राज्य में (गुजरात के संभावित अपवाद को छोड़कर) विजेता का चुनाव नहीं है। मोदी साहब ने शायद यह निष्कर्ष निकाला हो कि उन्हें आभासी लाभ को नहीं, बल्कि संभावित शुद्ध घाटे की गणना करनी चाहिए। हो सकता है कि उस विचार ने उन्हें चिंता में डाल दिया हो और चिंता झूठ में तब्दील हो रही हो।

मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि लोग किस तरह मतदान करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि लोग मोदी साहब के झूठ को समझ गए हैं। और लोगों को हैरानी हो रही है कि एक 'मजबूत' नेता को झूठ क्यों बोलना चाहिए।

थकान से बोझिल चुनाव

वक्त की नब्ज
तवलीन सिंह

मतदान का तीसरा दौर समाप्त होने के बाद क्या कहा जा सकता है प्रचार के बारे में? मुद्दों के बारे में? चुनाव के रुख के बारे में? सबसे महत्त्वपूर्ण सीख जो मिली है अभी तक, वह यह कि चुनाव आयोग को कोई तरीका ढूंढ़ना होगा मतदान के दिन इतना लंबा न खींचने का। बेशक टेस्ट मैच को टी-20 की शक्ल देना मुश्किल है, लेकिन इतना लंबा टेस्ट मैच भी नहीं होना चाहिए कि चुनाव का सारा मजा ही उड़ जाए।

इतना लंबा चुनाव है इस बार कि मतदाता थके से लग रहे हैं अभी से। मुंबई में मतदान को अभी दस दिन बाकी हैं, लेकिन यहां न प्रचार की धूमधाम दिख रही है और न मतदाताओं में कोई उत्साह। ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं सिर्फ तब जब कहीं जाना जरूरी हो जाए। मैंने जब एक-दो लोगों से बात की चुनाव की हवा के बारे में तो उन्होंने साफ कहा कि इसके बारे में वे सोच ही नहीं रहे हैं। 'कोई उत्साह नहीं है जी, लोग ऊब गए हैं'।

यह बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री के उस भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने पहली बार अंबानी-अडाणी के नाम लिया किसी आमसभा में। ऐसा क्यों किया, समझना मुश्किल है। ऐसा करने से नुकसान उनका ही हुआ निजी तौर पर। भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 'शहजादे' पिछले पांच सालों में दो नामों की माला जपते रहे हैं- अंबानी-अडाणी, अंबानी-अडाणी, लेकिन चुनाव शुरू होने के बाद इन उद्योगपतियों के नाम लेना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है और अपने सवाल का जवाब भी दे दिया। गड़गड़ाती आवाज में कहा- कांग्रेस के शहजादे को बताना चाहिए कि कितना 'माल उठाया है'। क्या टेंपो भर-भर के आया है कालाधन बोरियों में डाल कर?

मैंने जब प्रधानमंत्री की यह बात सुनी तो हैरान रह गई। मोदी इतने मंजे हुए राजनेता हैं कि इस तरह की गलती बहुत कम करते हैं। गलती का नतीजा आया उनके भाषण के तुरंत बाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 'एक्स' पर कहा, 'दोस्त दोस्त ना रहे' और इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने खूब मजा लेते हुए प्रधानमंत्री के भाषण को भुनाया। राहुल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जानते हैं कि कालाधन उनको भेजा गया है टेंपो में भरके तो ईडी और सीबीआइ को क्यों नहीं भेजा गया है अंबानी और अडाणी पर छापा डालने? प्रियंका ने यहां तक कहा कि पहले आप बताएं, कितना माल आपको मिला है इनसे, फिर हम बताएंगे। कांग्रेस की मीडिया टीम ने गिन कर बताया कि चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद राहुल गांधी ने एक सौ तीन बार अडाणी का नाम लिया है। मोदी पहली दफा 'बैकफुट' पर नजर आए।

उनको बचाया तो सैम पित्रोदा ने। अभी कांग्रेस के आला नेता ठीक करने में लगे हुए थे उस नुकसान को, जो सैम पित्रोदा ने पहुंचाया था विरासत कर लगवाने की बात करके, कि एक चोट ऐसी लगाई पित्रोदा साहब ने कि उनको आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस पार्टी के विदेशी सचिव के पद से। पित्रोदा क्यों अमेरिका में बैठकर घड़ी-घड़ी पत्रकारों से कांग्रेस की नीतियों पर बातें करते हैं, मुश्किल है समझना। इस बार बहुत वाहियात बात निकली उनके मुंह से। कोशिश कर रहे थे साबित करने की कि भारत विविधिताओं का देश है, लेकिन मिसाल ढूंढ़ी भारतीयों की चमड़ी के रंग को लेकर। पित्रोदा की नजर में उत्तर में रहने वाले भारतीय गोरों की तरह दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब की तरह दिखते हैं, पूरब के लोग चीनी दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी दिखते हैं।

यकीन करना मुश्किल है कि यह व्यक्ति कभी राजीव गांधी का इतना खास सलाहकार हुआ करता था कि इसको भारत की तमाम व्यवस्था को सुधारने का काम दिया गया था। 'मिशन' थे इनके पास हरियाली लाने के, ऊर्जा पैदा करने और ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन की तारें बिछाने के। यह बात अलग है कि इस टेलीफोन वाले मिशन के पूरा होने तक सेलफोन आ गए देश में, सो पित्रोदा का यह मुख्य मिशन नाकाम हुआ। बाकी मिशन भी उड़ान नहीं भर पाए, लेकिन मालूम नहीं क्यों राहुल गांधी पित्रोदा पर इतना विश्वास करते रहे हैं कि उनके हर विदेशी दौरे में उनके बगल में बैठे दिखते हैं पित्रोदा। इन विदेशी दौरों में अक्सर राहुल भैया कुछ न कुछ ऐसा कह डालते हैं, जिसको लेकर लाभ होता है सबसे ज्यादा मोदी को।

मतदान का तीसरा दौर समाप्त होने के बाद क्या कहा जा सकता है प्रचार के बारे में? मुद्दों के बारे में? चुनाव के रुख के बारे में? सबसे महत्त्वपूर्ण सीख जो मिली है अभी तक, वह यह कि चुनाव आयोग को कोई तरीका ढूंढ़ना होगा मतदान के दिन इतना लंबा न खींचने का। बेशक टेस्ट मैच को टी-20 की शक्ल देना मुश्किल है, लेकिन इतना लंबा टेस्ट मैच भी नहीं होना चाहिए कि चुनाव का सारा मजा ही उड़ जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतदाता थके से लग रहे हैं, राजनेता भी थके से लग रहे हैं, इतना कि हर हफ्ते कोई नया मुद्दा सबसे बड़ा बन जाता है। अगले हफ्ते तक उसको भुला कर कोई नया मुद्दा खोजते फिरते हैं प्रधानमंत्री। 'बैकफुट' पर अगर दिख रहे हैं तो शायद इसलिए कि उनके मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन राहुल भैया और प्रियंका बहन अपने मुद्दों पर अडिग हैं।

प्रियंका गांधी ने साबित कर दिया है कि अपने भाई से कहीं ज्यादा अच्छी प्रचारक हैं। सो, मोदी के हर नए मुद्दे का उनके पास जवाब हाजिर रहता है। मोदी राहुल को शहजादे कहते हैं तो जवाब में प्रियंका मोदी को शहंशाह बुला कर कहती हैं कि मेरे भाई कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं लोगों की समस्याओं को समझने और उधर हैं शहंशाह जो महलों के बाहर नहीं निकलते हैं। मोदी ने खूब कोशिश की है अपने आपको गरीब घर के बेटे के रूप में पेश करने की। इस बार यह पत्ता चल नहीं रहा है। न ही राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। पूरी तरह संभव है कि मोदी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन इस सप्ताह उन्होंने एक ऐसी गलती की है, जो भविष्य में भारी पड़ सकती है।

समय की अवधारणा और अवतार

चिंतन
विनोद शाही

वेदों, उपनिषदों और षड्दर्शनों में समय या काल की बहुत सूक्ष्म व्याख्या मिलती है। उसे बौद्ध सर्वास्तिवाद ने अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। पर उनके मत के निरीश्वरवादी होने के कारण, ब्राह्मणवाद उसे स्वीकार नहीं कर पाया। तब अवतारवाद की पीठ पर सवार भक्तिवाद को लाया गया। वह आसान रास्ता था, इसलिए जल्द ही लोकप्रिय हो गया।

जब किसी महानायक को अवतार बना दिया जाता है, तो उसके जीवन के सामान्य क्रियाकलाप, लीला में बदल जाते हैं। लीला का मतलब है कि वह जो करता है, वह समय में बंधा हुआ नहीं होता। समय में बंधना, कार्य-कारण शृंखला से बंधना है। समय में जो पहले घटा है उसे कारण, और जो बाद में घटता है उसे कार्य कह दिया जाता है। इस तरह परंपरा, मनुष्य को अपने मुताबिक ढालने लगती है। इससे मनुष्य कुछ भी खुद करने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाता। इस गुलामी से छूटने को हमारे यहां भव-बंधन तोड़ना कहा गया। जो इससे बंधा नहीं है, उसे लीलाधर अवतार बना दिया जाता है। यह माना गया कि कर्म उसे बांधते नहीं, पर वह अपनी मर्जी से कर्मों के बंधन में बंधने का अभिनय करता है। कर्म-फल के रूप में सुख-दुख का अनुभव भी करता है। पर उसके लिए वह वास्तविकता नहीं, अभिनय है। इसलिए उसे लीला कह दिया गया।

जब इस अवतारवाद और लीला की धारणाओं को लाया गया, तो उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि अगर कोई चाहे तो जीवन को अभिनय मान सकता है और मृत्यु तक को लीला। वह अहं से मुक्त होकर समझ सकता है कि मुझसे जो कर्म हो रहे हैं, उन्हें मैंने नहीं किया, प्रकृति ने मुझसे करवा लिया है। इस समझ को ज्ञानमार्ग कहा गया। या वह कर्मफल का मनसा परित्याग कर सकता है। फिर उसे उसके परिणाम की फिक्र नहीं होगी। यह भी जीवन-मुक्त होने का एक तरीका है।

अवतार का मतलब है, जो पहले से ही जीवन-मुक्त है। समय के चक्र के पार खड़ा है। पर वह समय में प्रवेश करता है। फिर वह ऐसी लीला करता है कि हमें लगे कि समय चक्र या भव बंधन को तोड़ना मुमकिन है। तो, इसका जो उद्देश्य था, वह सबको समय में होकर पार झांकने की राह पर ले जाना था। पर हुआ यह कि लोग अवतार जैसा जीवन जीने के बजाय, मानने लगे कि यह तो अवतारों के वश की बात है। हमारे हिस्से तो भक्ति आती है। तो अवतारवाद के पीछे-पीछे जो भक्तिवाद चला आया, उसने अवतारवाद के पीछे खड़े, समय के बहुमूल्य दर्शन को पतनशील बना दिया।

राम और कृष्ण, दोनों ऐसे अवतारों की तरह विकसित हुए, जिन्होंने समय के चक्र को दो अलग दिशाओं से तोड़ने का रास्ता खोला। राम जीवन से होकर समय के पार होने के रास्ते पर गए और कृष्ण समय के पार खड़े होकर जीवन में उतर सकने की लीला करते रहे।

पुराण का अर्थ है, वह जो पुराना है, वह समय के साथ हमेशा नया होता है। यानी पुराना कुछ नहीं होता। वह जो पुराना है, वह नष्ट नहीं होता। वही नित नूतन होता रहता है। नए में पुराना छिपा पड़ा रहता है। वेद, उपनिषद और शास्त्रीय दर्शन, समय की इन गुत्थियों को बारीकी से खोलते हैं। पुराणकाल उसके बाद का है। यानी ईसा की पहली शती से थोड़ा पहले।

वेदों, उपनिषदों और षड्दर्शनों में समय या काल की बहुत सूक्ष्म व्याख्या मिलती है। उसे बौद्ध सर्वास्तिवाद ने अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। पर उनके मत के निरीश्वरवादी होने के कारण, ब्राह्मणवाद उसे स्वीकार नहीं कर पाया। तब अवतारवाद की पीठ पर सवार भक्तिवाद को लाया गया। वह आसान रास्ता था, इसलिए जल्द ही लोकप्रिय हो गया। उसे बौद्ध मत के प्रभाव को आठवीं शताब्दी के बाद, भारत में प्रायः निर्मूल कर देने में सफलता मिल गई। बाद में लिखे गए भागवत पुराण ने इस भक्तिवाद को जनमानस के हृदय में प्रतिष्ठित करने में अपार सफलता पाई। इन पुराण कथाओं ने अवतारों के लीला-गायन की इतनी अहमियत दी कि भारत में सगुण भक्ति का आंदोलन ही प्रकट हो गया।

राम और कृष्ण की इन पुराण सम्मत लीलाओं में मौजूद समय की अवधारणा दो तरह की है। राम की लीलाओं में निहित समय की अवधारणा प्रच्छन्न रूप में बौद्ध हीनयान से मिलती-जुलती लगती है, जबकि कृष्ण की लीलाएं सर्वास्तिवाद के अधिक निकट हैं। बौद्ध दर्शन में समय के रहस्य को समझाने के लिए उसकी तुलना नदी के प्रवाह से की गई है। नदी में दिखाई देने वाला जल हर क्षण नया होता है। मृत्यु को भी समय प्रवाह में उपस्थित एक नए क्षण की तरह जीने को वहां निर्वाण कहा गया। नागार्जुन और दिंङनाग क्षण को इतना अधिक महत्त्व देते हैं कि वही जीवन के रहस्य को खोलने के द्वार में बदल जाता है।

ये चिंतक क्षण में शताधिक विभाग करते हुए, समय के पार मौजूद शून्य में ठहरने की बात करते हैं। कृष्णलीला में, शून्य की विराटता को, विश्व रूप की विराटता बना दिया गया। जहां जरूरत पड़ती है, कृष्ण अपने इस विराट रूप को प्रकट कर देते हैं। तब देखने वाले को लगता है कि समय का प्रवाह, भूत-वर्तमान-भविष्य सहित, उनके विराट-रूप में तत्क्षण घटित हो चुका है। राम और कृष्ण के अवतारवाद के गठन में बौद्ध दर्शन और उसके क्षणवाद की जमीन को हम आज भी पहचान सकते हैं। पर बदकिस्मती से हमारे अवतारवाद ने अपनी वह दार्शनिक जमीन खो दी है।

डरो-डराओ वीर कहाओ

बाखबर
सुधीश पचौरी

डर का आदान-प्रदान हो रहा है। एक कहता है, ये ऐसा कर देंगे तो दूसरा कहता है, वो वैसा कर देंगे, यानी उनसे डरो और मुझे वोट दो। इस चुनाव की संचालक शक्ति 'डर' है, डराओ और वोट लो... मैं तुम्हें डर दूंगा... तुम मुझे वोट दो..!

एक दिन खबर आई कि राहुल रायबरेली से लड़ेंगे... फिर सीधे दृश्य कि राहुल रायबरेली पहुंचे... राहुल ने पर्चा भरा।

पक्षधर मगन कि कमाल का 'मास्टर स्ट्रोक' है... राहुल शतरंज के मंजे खिलाड़ी हैं!

भाजपा के एक प्रवक्ता का जवाब आया कि काहे के मंजे हुए खिलाड़ी? जो खिलाड़ी आखिर में अपनी आसन्न हार देख अचानक समर्पण कर दे, वह शतरंज के खेल में 'कायर' कहलाता है, क्योंकि वह दूसरे को उसकी तयशुदा जीत से वंचित कर देता है!

इसी बीच पीएम ने कटाक्ष किया कि 'डरो मत'...'भागो मत...' इसके बाद देर तक 'ताताथैया' होता रहा कि 'वो डर गए हैं'...कि 'ये डर गए हैं'।

सच, आज की राजनीति 'डरो-डराओ, गुर्रो-गुर्राओ और फिर भी वीर कहाओ' छाप है।

इसी बीच आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपनी 'क्लोजर रिपोर्ट' में बताया कि वेमुला अपनी जाति के जाली सर्टिफिकेट की पोल खुलने से डरा हुआ था... उसने आत्महत्या की थी... गजब कि इतने दिन भी 'हत्या' का 'झूठ' पसरा रहा!

फिर एक दिन दिल्ली के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली समेत चार और बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो लिए।

मगर फिर एक दिन हरियाणा की भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने वाले तीन स्वतंत्र विधायकों को कांग्रेस ने अपना बनाकर प्रतिशोध पूरा किया। सच, चुनावों ने राजनीति को भी 'प्रतिशोध की भाषा' से भर दिया है।

और सर जी! ये चुनाव ऐसे हैं, जिसमें बंगाल के राज्यपाल तक को कहना पड़ रहा है कि मुझे 'फंसाने' की योजना है! उन पर 'यौन शोषण' का आरोप लगाया गया है।

फिर एक दिन लालू ने कह दिया कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए और सारी बहसें विपक्ष द्वारा 'कोटे के भीतर कोटा देने' बरक्स 'आरक्षण खत्म करने' के 'आरोप प्रत्यारोपों' पर अटकी रहीं।

एक आरोप लगाता कि ये 'संविधान बदल देंगे' तो दूसरा आरोप लगाता कि ये 'ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा छीनकर मुसलमानों को दे देंगे... तीन सौ सत्तर वापस ले आएंगे..!'

डर का आदान-प्रदान हो रहा है। एक कहता है, ये ऐसा कर देंगे तो दूसरा कहता है, वो वैसा कर देंगे, यानी उनसे डरो और मुझे वोट दो। इस चुनाव की संचालक शक्ति 'डर' है, डराओ और वोट लो... मैं तुम्हें डर दूंगा... तुम मुझे वोट दो..!

फिर एक दिन प्रधानमंत्री ने 'दो शहजादों' को यह कह कर इज्जत बख्शी कि एक शहजादे दिल्ली में हैं, दूसरे बिहार में हैं। एक दिल्ली को अपनी जागीर समझता है, दूसरा बिहार को... जाहिर है कि जवाब में विपक्ष ने भी पीएम को जवाबी इज्जत बख्शी!

एक दिन पीएम ने एक रैली में कह दिया कि यह चुनाव 'वोट जिहाद' और 'रामराज्य' के बीच है। आपको तय करना है कि भारत में 'वोट जिहाद' चलेगा या 'रामराज्य' चलेगा? क्या संविधान इसकी अनुमति देता है... इस पर विपक्ष की वही 'ताकधिनाधिन' सामने आई कि असली मुद्दों की जगह मोदी नफरत की राजनीति करते हैं...

कुछ चैनल 'कम वोटिंग' के कारण तलाशते रहे। एक चर्चक ने बताया कि वोट 'ट्रांसफर' करने में 'कनफ्यूजन' है, इसलिए वोट कम हो रहा है, लेकिन भाजपा का काडर प्रतिबद्ध है अपने बूथ के वोटर को निकाल के लाता है... फिर भी असलयित चार जून को ही मालूम पड़ेगी..!

इसके बाद एक बार फिर 'अंकल सैम' का अवतरण हुआ। इस बार वे भारत के लोगों की 'नस्ली मैपिंग' करते दिखे कि पश्चिमी भारत के लोग 'अरब' जैसे लगते हैं, पूर्वी भारत के लोग 'चीनी' जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग 'वाइट' जैसे दिखते हैं और दक्षिण के 'अफ्रीकी' जैसे दिखते हैं...

इतना कहना था कि भाजपा ने तुरंत कहा कि ये घोर आपत्तिजनक बयान है। अब विषय राजनीति का नहीं रह गया, भारत के 'अस्तित्व' का हो गया है..!

उधर मोदी बरसे कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं, ये चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। मेरे देश के लोगों को इतनी बड़ी गाली दे दी... ये अमेरिका में शहजादे के 'फिलासफर गाइड' हैं। एक चर्चक ने कहा, यह देश को बांटने वाला बयान है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।

पिटाई होते देख कांग्रेस ने इस बयान से अपने को अलग किया। अगले दिन, सैम पित्रोदा के 'ओवरसीज कांग्रेस' के 'इनचार्ज' पद से 'इस्तीफे' की खबर ने इस विवाद को ठंडा किया।

बहरहाल, सप्ताह का सबसे 'कटखना' विवाद भाजपा की टिकट पर लड़ती नवनीत राणा के 'पंद्रह सेकंड लगेंगे...' वाले बयान से पैदा हुआ। जवाब में ओवैसी बोले कि '...पंद्रह घंटे ले लो, छोटे को मैंने रोक के रखा है... तुमको नहीं मालूम कि वो क्या है... उसे छोड़ दूं क्या... बोल दूं क्या... बताओ, कहां पे आना है?'

इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत हुई और मामला भी दर्ज हुआ।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

मानव मन की जटिलता

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'जाओ फांसी लगा लो' कहने को आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में रखने से मना कर दिया। अदालत आपत्तिजनक बयानों से जुड़े आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जटिलताओं को दूर करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी। तटीय कर्नाटक के उडुपी में गिरजाघर में पादरी की मौत के सिलसिले में हत्या के लिए उकसाने के आरोपों से जुड़ी याचिका पर अदालत ने यह कहा। आरोप है कि पादरी और याचिकाकर्ता की पत्नी के दरम्यान दैहिक संबंध थे। दोनों के बीच हुई बहस में उसने पादरी को मरने के लिए कहा। एकल जज की पीठ ने सर्वोच्च अदालत के पूर्व निर्णयों के आधार पर कहा सिर्फ बयानों को उकसाने वाला नहीं माना जा सकता। अदालत ने पिता और पादरी होने के बावजूद मानव मन की जटिलताओं का जिक्र करते हुए मामले को खारिज कर दिया। जिम्मेदार और धार्मिक पद पर होने के बावजूद सामाजिक मूल्यों का अनादर करने वाला शख्स आत्मग्लानि के चलते भी जिंदगी समाप्त कर सकता है। अपने समाज में साल दर साल आत्महत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सिर्फ एक साल (2022) में प्रति दिन 468 लोगों ने अपनी जान ली। खुद की जान लेने वालों में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर सामाजिक-पारिवारिक कारणों से लोग खुदकुशी कर लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अपनी जिंदगी से उकता कर, निराश होकर या आवेश में आत्महत्या करने वाले भी मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार होते हैं, जिसके संकेत वे लगातार अपने करीबियों, परिवार या मित्रों को देते रहते हैं, जिसकी प्रायः अनदेखी की जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानसिक प्रताडऩा, उलाहनों, उत्पीडऩ और दोष मढ़े जाने से आजिज आकर भी लोग अपनी जान ले लेते हैं। मगर इस मामले में केवल कहासुनी के दौरान मरने का ताना देना ही काफी नहीं कहा जा सकता। आत्म-गलानि भरे उपासकों के पाप-स्वीकरण सुनने वालों के प्रति आम जन जो सम्मान का भाव रखता है, उसका दुष्चरित्र होना, सामाजिक तौर पर अस्वीकृत और तिरस्कृत होता है। इसी सब से भयभीत होकर मृतक को यह कदम उठाना पड़ा होगा।

हम लड़ रहे हैं दुनिया का सबसे महंगा चुनाव

आरती कुमारी

आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। भारत के संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार संपन्न हुए इन चुनावों में उस समय मात्र 10.50 करोड रुपए खर्च हुए थे। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाकर अपनी पुरातन राजतंत्रीय व्यवस्था को विदा कर दिया था। तब लोगों ने सोचा था कि अब बड़ी सहजता से अपने बीच के लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर शासन अपने हाथ में लेकर चलाएंगे। बहुत बड़ी आशाओं और सपनों के साथ हमने आगे बढ़ाना आरंभ किया। कुछ देर पश्चात ही हमें पता चल गया कि हम गलत दिशा में आगे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ परिवारों ने पुरानी राजतंत्रीय व्यवस्था के नए संस्करण के रूप में राजनीतिक दल आधुनिक लोकतंत्र में लड़ने वाली फौज के रूप में खड़े किए, उन पर अपना एकाधिकार किया और धीरे-धीरे देश की सारी राजनीति पर अपना शिकंजा कस लिया। शासन सत्ता को हथियाने की आपाधापी में जब भारत के लोकतंत्र ने कुछ और दूरी तय की तो कई चीजें अस्त-व्यस्त होती चली गईं। बाहुबली और धनबली लोगों ने सज्जनों का राजनीति में प्रवेश सर्वथा बाधित कर दिया । जिन लोगों को देश का जनप्रतिनिधि बनाकर उनके माध्यम से जन सेवा और राष्ट्र सेवा कराने का सुनहरा सपना लोकतंत्र ने भारत के लोगों को दिखाया था , वे जनसेवी और राष्ट्र सेवी लोग विधानमंडलों के दरवाजे को देख भी ना पाएं, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। 1957 के लोकसभा चुनाव आए तो अब तक का सबसे सस्ता चुनाव उस समय हमने होता हुआ देखा। उन चुनावों में केवल 5.9 करोड रुपए ही सरकारी स्तर पर खर्च हुए। इसके बाद 1962 के चुनाव में 7.3 करोड़, 1967 के चौथी लोकसभा चुनाव पर10.8 करोड़ , पांचवी लोकसभा के 1971 के चुनाव में 11.6 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद 1977 में जब छठी लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय खर्चा एकदम दुगुने से भी अधिक बढ़ा। तब सरकारी स्तर पर 23 करोड़ रूपया चुनाव पर खर्च हुआ। 1980 में यह खर्च बढ़कर 54.8 करोड़, 1984- 85 में 81.5 करोड़, 1989 में 154.2 करोड़ और 1991 – 92 में बढ़कर 359.1 करोड़ हो गया। यह खर्चा 1952 के चुनाव की अपेक्षा 35 गुना अधिक था। 1996 के लोकसभा चुनाव के समय इस खर्चे में वृद्धि होकर 597.3 करोड़ का खर्च हुआ । जबकि 1998 के चुनाव के समय 666.2 करोड़, 1999 के चुनाव में 947.7 करोड़, 2004 के लोकसभा के चुनाव में 1016.1 करोड़, 2009 के चुनाव पर 1114.4 करोड़ , 2014 के लोकसभा चुनाव पर 3870.3 करोड़ और 2019 के लोकसभा चुनाव पर 9000 करोड़ रूपया खर्च हुआ। अब खबर आ रही है कि 2024 में संपन्न हो रहे लोकसभा चुनाव पर यह खर्च बढ़कर 1.20 लाख करोड़ का होने जा रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो भारत में ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक जितना चुनाव खर्च होता है यदि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी उसको जोड़कर देखा जाए तो यह 10 लाख करोड़ से भी ऊपर चला जाता है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी धनराशि हमारे देश के कई राज्यों के बजट से भी अधिक है। जिस फिजूलखर्ची की प्रतीक राजशाही से बचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकशाही को देश में स्थापित किया था, क्या उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा होगा कि यह भविष्य में जाकर इतनी महंगी हो जाएगी कि फिजूलखर्ची भी इसे देखकर अपने आप को लज्जित अनुभव करने लगेगी? इतनी बड़ी धनराशि को देखकर लगता है कि हम अपने लिए जनप्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं बल्कि राजा चुन रहे हैं । जिनके लिए राजकोष पर इतना अधिक भार देश की अर्थव्यवस्था को झेलना या ढोना पड़ रहा है । यह तो हुआ चुनाव खर्च , जो 5 वर्ष में आधुनिक राजा महाराजाओं के चुनाव पर हमें खर्च करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त उनके वेतन, भत्ते सुविधा, सरकारी आवास, सुरक्षा आदि पर होने वाले खर्च को भी यदि इसमें जोड़ा जाए तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब आते हैं समस्या के एक दूसरे पहलू पर। हमारा मानना है कि यह समस्या ही वर्तमान में भारत में व्याप्त बेरोजगारी, भुखमरी, अपराध और गरीबी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसको समझने पर पता चल जाता है कि वर्तमान भारत की बेरोजगारी, भुखमरी, अपराध और गरीबी की समस्याओं का मूल कारण भी यह लोकतंत्र ही बन चुका है। कहा जाता है कि लोकतंत्र इन सबसे लड़ता है, पर यदि भारत की सामाजिक समस्याओं को समझा जाए तो पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र इन सारी समस्याओं को पैदा करता है। समझने की बात है कि भारत में ग्राम प्रधान से लेकर संसद तक के चुनाव में खड़े होने वाले लोग मोटा धन पानी की तरह बहाते हैं। इसमें दो राय नहीं हैं कि अनेक लोग भारत में इस समय ऐसे हैं जो राज्यसभा सांसद बनने के लिए कई सौ करोड़ रुपए देने को तैयार बैठे हैं। यही लोग जब किसी पार्टी से लोकसभा में जाने के लिए चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी पानी की तरह पैसा बहाते हैं। चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी नए सिरे से अगले चुनाव लड़ने की तैयारी करता है । जिसके लिए वह पहले दिन से ही पैसा जोड़ना आरंभ करता है। इसके लिए उसे पार्टी में बड़े नेताओं का संरक्षण पाने के लिए वहां भी 'चढ़ावा' चढ़ाना पड़ता है। अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, उन सब की सारी आर्थिक जिम्मेदारियों को सहन करना पड़ता है। तब उसे इस सारे खर्चे को निकालने के लिए लोगों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करना और अपराध के माध्यम से लोगों में डर पैदा करने जैसे हथकंडों को अपनाना पड़ता है। आज की राजनीति का सच यह है कि जो इन सब कामों को कर सकता है, वही राजनीति में टिक सकता है। ऐसा न करने वालों को या तो राजनीति छोड़ देती है या वह राजनीति को छोड़कर चला जाता है। राजनीतिक लोगों की यह ' समाज सेवा' ही देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि को फैलाती है। निश्चित रूप से हम इस समय विश्व का सबसे महंगा चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद और विधायक से अलग हमारे देश में जिला परिषदों के चुनाव भी होते हैं। जिसके अध्यक्ष के लिए पार्टियों में बड़ी मारामारी होती है। यदि बात एनसीआर की करें तो यहां पर जिला परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए लोग बहुत मोटा धन खर्च करते हैं। यहां तक कि ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए भी लोग एक-एक वोटर को बड़ी-बड़ी गाड़ी गिफ्ट में दे देते हैं। राजनीतिक दलों को सच्चाई की पता है, पर पता होते हुए भी उपचार करने को कोई तैयार नहीं है। इस प्रकार के राजनीतिक दुराचरण के चलते सज्जनों का राजनीति में प्रवेश कुंठित हो गया। है। देश से बाहर कितना काला धन है ? इस पर अक्सर लेख लिखे जाते हैं,चर्चाएं होती हैं। राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर कीचड़ उछलते रहते हैं कि अमुक पार्टी के अमुक नेता ने इतना काला धन ले जाकर विदेश में जमा कर दिया है? पर इस पर चर्चा नहीं होती कि राजनीतिक लोगों के द्वारा देश के चुनाव को ही कितना महंगा कर दिया गया है? ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक की सीट को खुले आम लोग खरीद रहे हैं। सीटें नीलाम हो रही हैं। उसके साथ-साथ लोकतंत्र नीलाम हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। .....और हम सब मौन होकर देखने के लिए अभिशप्त हैं। ऐसे में प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हमारे लिए राजतंत्रीय व्यवस्था ही उपयुक्त नहीं थी ? जिसमें बैठे लोग कम से कम धन के भूखे तो नहीं थे। हमने 'भूखों' को 'राजा' बनाने के लिए देश के संसदीय लोकतंत्र की खोज की थी या फिर राजाओं को भूखों की सेवा करने के लिए संसदीय लोकतंत्र को स्थापित किया था? निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने राजाओं को अर्थात देश के जनप्रतिनिधियों को भूखों की सेवा करने के लिए ही संसदीय लोकतंत्र को स्थापित किया था। हमने ही भूखों को अर्थात सर्वथा निकृष्ट और वाहियात लोगों को राजा अर्थात अपना जन प्रतिनिधि बनाकर देश के संसदीय लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। ऐसे निकृष्ट लोगों के कारण ही देश का संसदीय लोकतंत्र का चुनाव महंगा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को चुनाव सुधार की दिशा में काम करते हुए इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।

केजरीवाल निर्दोष नहीं शराब घोटाले में, चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर हैं

अशोक भाटिया

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में 50 दिन तक तिहाड़ जेल की हवा खाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अब वह एक जून तक जेल के बाहर रहेगें और चुनाव प्रचार कर सकेंगे। जेल से बाहर आते ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल को 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के क्रांतिकारी नारे याद आ गए। इन्हीं नारों के जरिए केजरीवाल ने माहौल बांधने की कोशिश की। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 140 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद मुख्य आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें इस घोटाले का किंगपिन यानि कि सरगना करार दिया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी हो, लेकिन, वो चुनाव परिणाम नहीं देख पाएंगे। दरअसल, गुरुवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून को अंतरिम जमानत दी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मियाद 5 जून तक बढ़ाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वोटिंग से 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार थम जाता है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। आप पार्टी के अनुसार केजरीवाल को जमानत मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉफ्रेंस करके कहा कि बजरंगबली का उन पर आशिर्वाद है। जमानत मिलने से दिल्ली नहीं पूरा देश खुश है। उनको सियासी षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था, ताकि लोकसभा चुनाव से दूर रहें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा, ' सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तानाशाही का अंत होगा। सत्यमेव जयते। देश देखेगा केजरीवाल का कमाल'। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। यह फैसला आज के राजनीतिक माहौल के लिए काफी सकारात्मक होगा और विपक्ष को फायदा होगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अंततः सत्य और न्याय की जीत होगी। केजरीवाल की बेगुनाही और एनडीए/बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति बिना किसी संदेह के बाहर हो जाएगी। हालांकि, बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में केजरीवाल लिप्त हैं। ये कोर्ट में साफ हो गया है। एक जून के बाद उनको जेल जाना ही होगा। केजरीवाल के जेल से बाहर आने को लेकर सियासी नफा-नुकसान पर सभी के अपने-अपने दावे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि , सीएम केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार ठंडा पड़ा हुआ था। उन्हें लीडरशिप की जरूरत महसूस हो रही थी। जमानत मिलने और जेल से बाहर आने से चुनाव पर सियासी प्रभाव जरूर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के लोगों के हौसले बुलंद होंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगा। केजरीवाल के जेल में रहने के चलते उनकी पार्टी प्रचार का माहौल नहीं बना पा रही थी। मगर, अब उनके बाहर से आने से सियासी बज क्रिएट होगा। सीएम केजरीवाल की गैर-मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता चुनावी कैंपेन संभाल रही थीं। मगर, मीडिया का अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था। उनके आने से दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह पर प्रचार को धार मिलने के साथ-साथ सियासी लाभ भी मिल सकता है। केजरीवाल सियासी रुख बदलने के माहिर खिलाड़ी हैं। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह आक्रमक प्रचार करेंगे, उससे उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लाभ मिल सकेगा। सीएम भगवंत मान पंजाब तक ही अपना असर दिखा सकते हैं। वो दिल्ली की सियासत पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे। राणा का कहना है कि आगे देखना है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में किसके लिए कितना प्रचार करते हैं, क्योंदि दिल्ली में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। सीएम केजरीवाल अभी तक अदालत में अपनी बेगुनाही के बातें रख रहे थे, लेकिन अब जनता के बीच भी रख सकेंगे। वो जनता की सियासी नब्ज को समझते हैं और उसे मोड़ना उन्हें बाखूबी आता है। वरिष्ठ पत्रकार युसुफ अंसारी कहते हैं कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा हैं। केजरीवाल देश के उन नेताओं में हैं, जिन्हें बीजेपी के सियासी नैरेटिव को काउंटर करना बाखूबी आता है। बीजेपी और पीएम मोदी जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पर खड़ी नजर आ रही है और राममंदिर से लेकर हिंदू-मुसमलान का एजेंडा सेट कर रही है, उसे केजरीवाल बखूबी मोड़ना जानते हैं। केजरीवाल के बाहर आने के बाद पार्टी के उस नैरेटिव को बल मिलेगा कि उन्हें फंसाया गया है।युसुफ अंसारी कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार को धार मिलेगी। गठबंधन के मंच से केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर अब पहले से ज्यादा आक्रमक नजर आ सकते हैं, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकती है। दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी दो चुनाव से लगातार जीत रही है, लेकिन कांग्रेस-AAP गठबंधन के चलते इस बार चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। अब केजरीवाल के बाहर आने से और भी लाभ मिल सकता है क्योंकि वो साहनुभूति को भी भुनाना बखूबी जानते हैं। वहीं, वरिष्ठ पत्रकार और लोक संसद के संयोजक रविशंकर तिवारी कहते हैं कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने से दिल्ली की सियासत पर कोई खास सियासी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल के जेल में रहने से जो साहनुभूति आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही थी, वो अब खत्म हो सकती है। उनके बाहर आने से बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है, क्योंकि अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया बल्कि चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दी है। बीजेपी और पीएम मोदी ने चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। केजरीवाल के बाहर आने के बाद विपक्ष के मंच पर प्रचार करने के लिए उतरेंगे तो प्रधानमंत्री और बीजेपी उसे राजनीतिक मुद्दा बना सकती है।वो कहते हैं कि देश में जनता के बीच यह एक छवि बनती जा रही थी कि नेता भ्रष्टाचार करने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। मोदी ने बड़े-बड़े भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करके यह छवि तोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार-बार यह कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई जारी रहेगी, उससे भी सरकार की प्राथमिकता साफ नजर आती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव को लगातार सजायाफ्ता बता रहे हैं। उसी तरह केजरीवाल के खिलाफ भी यही चीज इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं दिल्ली का सियासी मिजाज देखें को राजधानी के लोग लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जगह पर बीजेपी को ही पसंद करते , 2014 और 2019 के नतीजे बता रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल के बाहर आने से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है बल्कि दांव उल्टा पड़ सकता है। 'वरिष्ठ पत्रकार अरुण राघव का भी मानना है कि केजरीवाल के बाहर आने से दिल्ली की सियासत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सिर्फ चुनाव के प्रचार के लिए जमानत दी है, जिसका मतलब यह नहीं होता है कि बरी हो गए हैं। दिल्ली में पढ़ी-लिखी जनता है और केजरीवाल इसीलिए सियासी तौर पर सफल रहे हैं कि क्योंकि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था और अब उसी जाल में खुद फंस गए हैं। पहले दो विधानसभा चुनावों में केजरीवाल अजेय लग रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे उनके घोटालों की जानकारी लोगों हो रही है, उनसे जनता का मोहभंग हुआ है।वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता अपना मूड बना चुकी है। केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष किस मूंह से जवाब देगा। केजरीवाल को लेकर कांग्रेस में पहले से दो धड़े हैं। हाल में अरविंदर लवली और राजकुमार चौहान जैसे नेता साथ छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं उनकी दलित समुदाय में पकड़ कमजोर हुई है। दलित समुदाय से आने वाले दो विधायकों का मोहभंग हुआ है, जिसमें एक बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल का जादू दिल्ली में फीका पड़ चुका है।

मेष राशिःआज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। मेहनत से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के कॉलेज के स्टूडेंट्स को नये प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। बड़ों का सहयोग आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

वृष राशिः आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। आज हर कोई आपकी बातों से प्रभावित होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेगी। आज आप धार्मिक कार्यों में रूचि लेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। शिक्षकों से कुछ नया सीखने को मिलेगा।

मिथुन राशिः आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आप ज्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताएंगे। आज आपके लिए कोई फैसला करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऑफिस में काम ज्यादा होने के कारण जीवनसाथी के साथ कहीं जाने का प्लान कैंसिल हो जायेगा। किसी काम में अनुमान से ज्यादा धन लाभ होगा। लवमेट देर तक बात करेंगे, कहीं घूमने का प्लान बनायेंगे।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। साझेदारी में किसी डील को फाइनल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके दांपत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज भावुकता में आकार कोई निर्णय लेने से बचे। परिवार वालों के साथ अलग-अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे।

सिंह राशिः आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आप किसी रिश्तेदार से मिलने, उनके घर जायेंगे। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। कॉम्पटीशन की तैयारी कर रहे छात्र तैयारी जारी रखेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा।

कन्या राशिः आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज कोई मित्र आपसे मिलने आपके घर आ सकते है। बच्चे आपको कोई शुभ समाचार देंगे, जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसी रचनात्मक कार्य में आपका नाम होगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नये कदम उठायेंगे। फिल्म जगत से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, जिससे अच्छा धन लाभ होगा।

तुला राशिः आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आस्था में बढ़ोतरी होगी। आज आप अपने कार्यों में जल्दबाजी करने से बचे आज ऑफिस में सहकर्मी आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढिय़ा है। छात्र आज कोई कम्प्यूटर कोर्स सीखने का मन बनाएंगे। दाम्पत्य रिश्ते में आ रही समस्याएं खत्म होंगी।

वृश्चिक राशिः आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल होने से परिवार वालों के साथ घर पर ही पार्टी करेंगे। इस राशि के शिक्षकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों को आज सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर में आज अविवाहित लोगों के विवाह की बात होगी।

धनु राशिःआज का दिन आपको समाज में मान-सम्मान दिलाने वाला होगा। लोग आपसे जुडऩे की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगो को किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर मिलेगा। लवमेट एक दूसरे पर भरोसा बनाये रखें, रिश्तों में और मजबूती आयेगी।

मकर राशिः आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं योजना बनायेंगे। पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ बनाया हुआ लॉन्ग ट्रिप का प्लान आज कैंसिल हो सकता है। संगीत में रुझान रखने वाले लोगों को आज कहीं परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। **कुंभ राशिः** आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके कार्यों में आपको आसानी से सफलता मिलती जायेगी। दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। लवमेट के रिश्तों में चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जायेंगे।

मीन राशिः आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़े हुए ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। आज फर्नीचर खरीदने के लिए दिन शुभ है। वैवाहिक जीवन में नई-नई खुशियां आएंगी।जीवनसाथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। आज किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचे। साझेदारी का व्यापार कर रहे व्यापारी आज बैठकर अपने व्यापार को बढ़ाने का प्लान बनाएंगे।

भारत में हिंदुओं की वृद्धि दर में कमी के लिए फर्जी सेकुलरिज्म जिम्मेदार!

मनोज कुमार अग्रवाल

अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के नतीजों को लेकर काफी चर्चा हो रही है यह रिपोर्ट है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी की एक अध्ययन रिपोर्ट । ईएसी पीएम रिपोर्ट में 65 सालों के अंदर हिंदुओं की आबादी घटने की जानकारी दी गई है। अध्ययन के मुताबिक भारत में 1950 से लेकर 2015 तक बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी 7.8 प्रतिशत घट गई है तो वहीं कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समाज की आबादी में काफी इजाफा हुआ है।रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कम हुई है तो वहीं जैन और पारसियों की संख्या भी घटी है। इसके विपरीत ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट की मानें तो 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में मुस्लिम समाज की आबादी में 43.15 फीसद की बढ़त दर्ज किया गया है तो वहीं सिखों में 6.58 फीसद, ईसाइयों में 5.38 फीसद और बौद्ध में बहुत थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके लिए दुनियाभर के 167 देशों का अध्ययन किया गया है। इसके लेखकों ने कहा है कि दुनिया के ट्रेंड को देखते हुए भारत में एक स्थिरता पाई गई है, रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके मुताबिक चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों के साथ ही कुछ पूर्वी अफ्रीकी देशों की जनसंख्या में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में भारत की अपेक्षा अधिक गिरावट दर्ज की गई है। 167 देशों में बहुसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी 1950-2015 से औसतन 22 प्रतिशत कम हो गई है। इसके अलावा 35 उच्च आय वाले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में 29 प्रतिशत की औसत गिरावट दर्ज की गई है, जो कि वैश्विक औसत 22 प्रतिशत से अधिक है। 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदू 84. 6प्रतिशत थे, लेकिन 2015 तक घटकर 78 प्रतिशत हो गए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि पहले 9.84 फीसद मुसलमान थे, जबकि अब 14.09 प्रतिशत हो गए हैं। भारत के साथ ही म्यांमार में भी बहुसंख्यक आबादी में तेजी से कमी दर्ज की गई है। म्यांमार में 10 फीसद और भारत में 7.8 फीसद बहुसंख्यक आबादी कम हुई है। यहीं भारत के पड़ोसी देशों में से एक नेपाल में भी बहुसंख्यक समुदाय हिंदू दर्ज की की आबादी में 3.6 फीसद की गिरावट गई है। है। बता दें कि जहां एक ओर भारत में बहुसंख्यक समाज की संख्या घटी है तो वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में बहुसंख्यकों की आबादी में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इन दोनों देशों में मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है। बांग्लादेश में 18.5 फीसद आबादी बड़ी है तो वहीं पाकिस्तान में 3.75 फीसद और अफगानिस्तान में (0.29 फीसद मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ी है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय हनफी मुस्लिम की संख्या में 3.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं बांग्लादेश में कुल मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 10 फीसद की बढ़ोतरी हुई है, बता दें कि 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार में भी बहुसंख्यक समाज की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। म्यांमार में थेरवाद बौद्धों की बहुसंख्यक आबादी है। इन 65 सालों में यहां पर इनकी आबादी में 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। मालदीव में बहुसंख्यक समुदाय शफोई सुत्री की आबादी में 1.47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है तो वहीं भारत और म्यांमार के अलावा नेपाल में भी बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 3.6 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है लेकिन बहुसंख्यक बौद्ध आबादी वाले भारत के पड़ोसी देश भूटान और श्रीलंका में क्रमशः 17.6 फीसद और 5.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अब बचे हुए चुनावों में यह मुद्दा बड़े जोर-शोर से उठेगा। इसके सियासी नफा-नुकसान का आकलन राजनीतिक गलियारों में किया जाने लगा है। जबकि कुछ लोगों ने ऐसी रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछा है कि जब अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो यह आंकड़े कितने आधिकारिक हैं और कितने मान्य हैं। इस पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर हिन्दुत्ववादी होने के आरोप लगते हैं तो कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप हैं । चुनावों के समय यह आरोप-प्रत्यारोप ज्यादा ही बढ़ जाता है। इस बार भी भाजपा जहां श्रीराम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 हटाने और पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिन्दुओं, सिखों, ईसाइयों व जैनियों को नागरिकता देने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए के नाम पर वोट मांग रही है। वहीं, विपक्षी दल कभी मुस्लिमों का आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं तो कभी जातीय जनगणना की और कभी सबकी संपत्ति लेकर गरीबों में बांटने की विवादास्पद बयान बाजी कर रहे हैं । गौर तलब है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य सकारात्मक है और इसमें कहा गया कि संबंधित आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 'समाज में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण है। यह रिपोर्ट अमेरिका जैसे उन पश्चिमी देशों के मुंह पर भी तमाचा है जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोप लगाकर भारत पर सवाल उठाते रहते हैं। रिपोर्ट के आते ही राजनीतिक बवाल मच गया। जहां भाजपा ने हिंदुओं की जनसंख्या घटने और मुस्लिमों की आबादी बढ़ने पर चिंता जताई है, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दल रिपोर्ट आने से इसके जारी करने के समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किन्तु इस रिपोर्ट से एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या देश में हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा है? क्या मुस्लिम आबादी धीरे-धीरे हिंदुओं से अधिक हो जाएगी? इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों में संतान पैदा करने की प्रवृत्ति अधिक है। इसमें शिक्षा भी एक कारक है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद व्यक्ति अपनी संतानों के बेहतर पालन-पोषण की सोचने लगता है और उसी अनुसार अपना परिवार बढ़ाता है, जबकि कम शिक्षित या अशिक्षित लोगों की सोच ऐसी नहीं होती। कुछ क्षेत्र विशेष में कथित धर्मगुरु मुस्लिमों को इस तरह भी बरगलाते हैं कि बच्चे पैदा करोगे तो वोट की ताकत बढ़ेगी और देर-सवेर हम गजवा ए हिंद' का सपना पूरा कर लेंगे। यह भी कटु सच है कि इस देश में पिछले लम्बे कालखंड में हिन्दुओं को जाति में बांट कर मुस्लिम समुदाय को बहुसंख्यकों से अधिक सरकारी सुविधाएं देकर उनके वोट पाने की नीति अपनायी गयी जबकि उनके सामाजिक विकास और कट्टरपंथी सोच को कम करने और उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया वरन उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए चरमपंथी विचारों को अपनाने व प्रसार करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया। इस का परिणाम है कि हिन्दू समुदाय अपने घर में भी दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया और हर स्तर पर अल्पसंख्यकों में भी सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यक को बढ़ावा देने की राजनीति तमाम कथित सेकुलर दलों ने की। इतना ही नहीं सेकुलरिज्म के नाम पर हिन्दुओ का उत्पीड़न और कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों का संरक्षण भी इन तथाकथित सेकुलर मुसलिम परस्त दलों द्वारा किया गया। गौर तलब है कि यदि भारत की आबादी इसी तरह बढ़ती रही संसाधन इसका बोझ सहन नहीं कर पाएंगे। हम चीन को भी पीछे छोड़ कर दुनिया के सबसे जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं, यदि अब भी सरकार ने कड़ाई से हम दो-हमारे दो जैसा कोई नियम-कानून बनाकर उसका कड़ाई से पालन नहीं करवाया तो खाने के लिए अन्न भी बाहर से आयात करना पड़ेगा। यदि देश को विकसित बनाना, अपना भविष्य सुखी एवं समृद्ध बनाना है तो जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना ही होगा। धर्म कोई भी हो, यदि आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो न देश विकसित हो पाएगा और न ही भविष्य सुखी एवं सुरक्षित हो पाएगा। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि 1950 के दशक में में पाकिस्तान में हिन्दू आबादी 12% के करीब थी जो आज घट कर एक प्रतिशत रह गयी है देश के नौ राज्यों में हिन्दू आबादी अल्पसंख्यक हो चुकी है ऐसे में देश के भोगोलिक व सामाजिक स्वरूप को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन पैसठ साल के कालखंड में ऐसी राजनीतिक विचारधारा पल्लवित हुयी जिसका उद्देश्य सत्ता में बने रहने के लिए हिन्दुओं को स्वर्ण दलित पिछड़े अगड़ी और विभिन्न जातियों में बांट कर जातीय विद्वेष पैदा कर मुस्लिम गठजोड़ से येन-केन प्रकरण सत्ता हासिल कर भ्रष्टाचार करना रहा। देश में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्चता देने वाली और बिना तुष्टिकरण सबको समान अवसर देने व समान नागरिक कानून लागू करने पर ही यह अव्यवस्था दूर हो सकती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

नासमझ के लिए विफलता दुख है, समझदार के लिए आगे की तैयारी

अनावश्यक संदेह

चौथे चरण के मतदान की तैयारी के बीच अनेक विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग को जिस तरह निशाने पर लिया जा रहा है, उसके पीछे सस्ती राजनीति ही अधिक दिखती है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में किन कारणों से समय लगता है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता उसे कठघरे में खड़ा करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तो इस संदेह तक भी पहुंच गए कि कहीं मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में कथित देरी का कारण चुनाव परिणामों को प्रभावित करना तो नहीं है? उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी गई अपनी चिट्ठी में उस पर अन्य अनेक आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने न केवल उनके सभी सवालों के विस्तार से जवाब दिए, बल्कि यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि वह भ्रम फैलाने और पक्षपातपूर्ण नैरेटिव खड़ा करने का काम जानबूझकर कर रहे हैं। खरगे ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि आखिर मतदान के दिन शाम को जारी होने वाले आंकड़े और कुछ दिन बाद बताए जाने वाले आंकड़ों में अंतर क्यों होता है? यह अनावश्यक प्रश्न है, क्योंकि ऐसा सदैव होता है और सभी को यह भी पता है कि ऐसा क्यों होता है।

क्या नेतागण इससे अनजान हैं कि हर संसदीय क्षेत्र के पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी अपने बूथ के मतदान प्रतिशत की जानकारी सेक्टर अफसर के जरिये रिटर्निंग अफसर को भेजते हैं। फिर रिटर्निंग अफसर यह जानकारी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को भेजते हैं और इसके बाद उसे चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाता है? क्या यह प्रक्रिया चंद घंटों में पूरी हो सकती है? मल्लिकार्जुन खरगे की चिट्ठी के बाद जिस तरह विपक्षी दलों के कुछ नेता अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचे, उससे यही पता चलता है कि उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर हैरानी नहीं कि कुछ लोग अपनी शिकायतों को याचिका की शक्ल देकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। इनमें वे भी हैं, जो यह मांग कर रहे थे कि या तो मतपत्रों से चुनाव हों या फिर शत प्रतिशत वीवीपैट का मिलान किया जाए। यह और कुछ नहीं, उस जमाने में लौटने की कोशिश थी, जब मतपत्र और मतपेटियां लूटी जाती थीं और नतीजे आने में समय भी लगता था और संसाधन भी। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने शत प्रतिशत वीवीपैट के मिलान की मांग खारिज करते हुए ईवीएम पर भरोसा जताया, लेकिन उस पर संदेह करने वाले अभी चैन से नहीं बैठे हैं। उनकी ओर से ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार का सिलसिला कायम है। निःसंदेह चुनाव आयोग की किसी खामी या गलती पर उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी साख को चोट पहुंचाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाए जाएं।

सजग मतदान

मतदान का अर्थ ही है मतभेद को अपने मत के माध्यम से प्रकट करना, लेकिन जब यह मनभेद और मारपीट में बदल जाए तो न ही इसे लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा कहा जा सकता है और न ही समाज के लिए स्वस्थ आचरण। उत्तर प्रदेश में बरेली के एक गांव में मुस्लिम महिला के साथ इसे लेकर हुई मारपीट की घटना पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यहां तीसरे चरण में मतदान हुआ था। मतदान के बाद उक्त महिला ने गांव लौटकर अपने सहधर्मियों को यह बात बता दी कि उसने किस दल को और किन मुद्दों पर वोट दिया है। यह बात मनभेद रखने वालों को इतना चुभ गई कि उन्होंने उस महिला की झोपड़ी में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की और आग लगाने एवं जान से मारने की धमकी दी। अपेक्षा की जानी चाहिए कि मुकदमा दर्ज करने वाली पुलिस इस दिशा में विधिसम्मत कार्रवाई करेगी, लेकिन इससे सभी को सबक लेने की आवश्यकता है। सात चरणों में मतदान हो रहे हैं और अभी तीन चरणों का ही मतदान हुआ है। आधी से अधिक लोकतांत्रिक लड़ाई शेष है, लेकिन यह सभी को ध्यान में रखना जरूरी है कि लोकतांत्रिक लड़ाई निजी वैमनस्यता में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। यह बात याद रखना नेता-कार्यकर्ता के लिए भी आवश्यक है और मतदाता के लिए भी। कई बार मतदाता अतिउत्साह में अपने मतदान को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने लगते हैं और कई बार विरोधी दल के समर्थक को चिढ़ाने की मंशा से भी। दोनों ही बातें उचित नहीं हैं। हमारे यहां मतगणना तक मतदान को गुप्त रखने की व्यवस्था है तो इसीलिए कि दो पक्षों के राजनीतिक मतभेद मनभेद में न बदलें। मत देकर आप अपना मंतव्य तो प्रकट कर ही चुके होते हैं, फिर भला मतगणना तक प्रतीक्षा में क्या हानि होगी। महत्वपूर्ण यह है कि मतदान अवश्य करें और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को करें, किंतु सजग होकर सकारात्मक सोच के साथ।

कांग्रेस की मुसीबत बने बड़बोले नेता

संजय गुप्त

बात केवल नाना पटोले, मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा की ही नहीं है। कांग्रेस के कुछ और नेता भी पार्टी की किरकिरी कराने वाले बयान दे रहे हैं

कांग्रेसी नेता किस तरह अपने बेतुके बयानों से कांग्रेस का ही नुकसान करने में लगे हुए हैं, इसका ताजा उदाहरण हैं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया तो राम मंदिर का शुद्धीकरण किया जाएगा। उनके इस बयान पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर ही थी कि मणिशंकर अय्यर एक वीडियो में अपना पाकिस्तान प्रेम व्यक्त करते और यह कहते दिखे कि उसे सम्मान देना चाहिए और उससे बात की जानी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि बीते दस वर्षों में पाकिस्तान को कोई इज्जत नहीं दी गई। वह पहले भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुके हैं। नाना पटोले और मणिशंकर अय्यर के पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी की थी। उन्होंने भारत की आबादी की विविधता को विदेशी नस्लों से जोड़ कर यह बताया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैसे अलग-अलग देशों जैसे दिखते हैं। उनके हिसाब से दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकियों, पूरब के चीनियों, पश्चिम के अरबों और उत्तर भारत के श्वेतों जैसे दिखते हैं। वह एक तरह से भारत में विभाजन पैदा करने वाले उस आर्य-अनार्य सिद्धांत को भी हवा देते देखे, जिसे कुछ विदेशियों और वामपंथियों ने गढ़ा है। उनकी टिप्पणी में नस्ली सोच भी नजर आया। अमेरिका में रहने के नाते उन्हें यह अच्छे से पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में नस्ली टिप्पणियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। पिछली सदी में जब नस्ल के आधार पर समाज को बांटा जाता था, तब न जाने कितने ही गृहयुद्ध और युद्ध हुए और उनका दुष्परिणाम पूरे विश्व ने भुगता। न जाने कितने ही देश बिखर गए और करोड़ों लोगों को पीड़ा उठानी पड़ी।

जब कांग्रेस सैम पित्रोदा का बचाव करने की स्थिति में नहीं रही तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे पार्टी ने तत्काल स्वीकार कर लिया, लेकिन यह कहना कठिन है कि इतने मात्र से वह राजनीतिक नुकसान से बच जाएगी। ध्यान रहे इसके पहले चुनाव के दौरान ही वह भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की पैरवी कर कांग्रेस के लिए कठिनाई खड़ी कर चुके हैं। कांग्रेस को उनके इस बयान से भी किनारा करना पड़ा था। इसके पहले 2019 में भी उन्होंने सिख विरोधी दंगों पर हुआ तो हुआ...वाली टिप्पणी करके कांग्रेस को उसी तरह नुकसान पहुंचाया था, जैसे 2014 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को कांग्रेस के दफ्तर में चाय की दुकान खोलने लायक बताकर

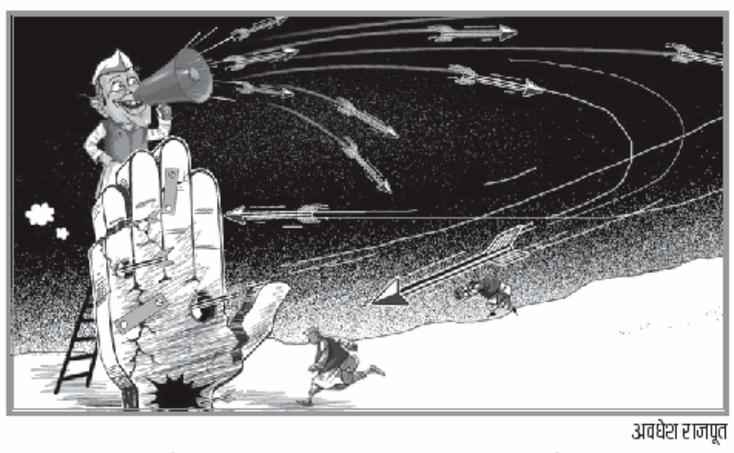

अवधेश राजपूत

पहुंचाया था। चूंकि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार भी रहे हैं, अतः यह माना गया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह विरासत टैक्स वाले सुझाव पर अमल कर सकती है। इस आशंका को इससे भी बल मिला, क्योंकि राहुल गांधी संपत्ति का सर्वे कराने की बात बार-बार कर रहे हैं। इसी कारण भाजपा विरासत टैक्स पर कांग्रेस को घेरते हुए उसके खिलाफ एक विमर्श खड़ा करने में सफल रही। सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को भारत के विचार के प्रतिकूल भी बताया। ध्यान रहे कांग्रेस नेता और खासकर गांधी परिवार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। इस परिवार के सदस्य अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं और जब द्रमुक के नेताओं ने सनातन धर्म को मिटाने की बातें की थीं, उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा था। इससे यही संदेश निकला कि वह अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रही है। इसका संकेत तब भी मिला, जब उसने घोषणा पत्र में पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया।

इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने के लिए किस तरह रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर समिति का गठन किया। इन दोनों ने मुस्लिम आरक्षण का आधार तैयार करने का ही काम किया। रंगनाथ मिश्र आयोग ने तो यहां तक पैरवी की थी कि उन मतांतरित दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस्लाम या ईसाइयत को ग्रहण कर लिया है। यह एक खतरनाक सुझाव था और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा भी। कांग्रेस तुष्टीकरण का खेल पहले भी खेलती रही है। सबसे शर्मनाक उदाहरण शाहबानो का मामला था। तुष्टीकरण के चलते ही आपातकाल के दौरान संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया और इसके बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकपरस्ती का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज तक कायम है। इसी के तहत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने समस्त मुस्लिम समाज को पिछड़ा मानकर ओबीसी आरक्षण दे दिया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति भी जताई, लेकिन कांग्रेस यह कहने को तैयार नहीं कि वह इस तरह मजहब के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। इस पर हैरानी नहीं कि भाजपा ने मजहब आधारित आरक्षण को एक मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के इतिहास में जाकर देखा जाए तो उसने वोट बैंक की राजनीति के लिए जाने-अनजाने कई बार समाज में खाइयां बनाने की कोशिश की है। इसी कारण उसका राजनीतिक रूप से पतन हुआ, लेकिन वह सबक नहीं सीख रही है।

बात केवल नाना पटोले, मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा की ही नहीं है। कांग्रेस के कुछ और नेता भी पार्टी की किरकिरी कराने वाले बयान देते चले आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमले के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के बारे में यह कह दिया कि वह पाकिस्तान आतंकी अजमल कसाब नहीं, बल्कि आरएसएस की विचारधारा वाले पुलिस अफसर की गोली का निशाना बने थे। जब इस बात का विरोध हुआ तो शशि थरूर ने आगे आकर यह मांग कर दी कि विजय वडेट्टीवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। क्या उन्हें नहीं पता कि जब इस मामले की जांच हुई थी, तब केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी? उस दौरान वह खुद मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे। बीते दिनों ही पंजाब कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ हमले को भाजपा की नौटंकी बता दिया। इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस के नेता जो मन में आ रहा है, वह बोल दे रहे हैं। ऐसा शायद इसीलिए है, क्योंकि यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं।

response@jagran.com

नाकाम नेताजी की समाजसेवा

हास्य-व्यंग्य

कमल किशोर सक्सेना

लल्लू पहलवान के स्कूल में प्रवेश लेना बहुत ही आसान है। मुश्किलें तो उसके बाद शुरू होती हैं

लल्लू पहलवान के पिता कल्लू पहलवान का पुश्तैनी काम लूटमार करना था। सरकार से 'लोहा लेना' उनका प्रिय काम था। किसी ने सुझाया कि सरकार से लोहा ही लेना है तो राजनीति में प्रवेश कर जाएं। वह इस पर विचार कर ही रहे थे कि एनकाउंटर को प्राप्त हो गए। लल्लू पहलवान ने अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लिया। कुछ दिन गलत कामों में ''नाम'' कमाने के बाद वह राजनीति में उतरने का सोचने लगे। एक दल की सदस्यता भी ले ली, लेकिन उस दल में दाल नहीं गली तो दूसरे का हाथ थाम लिया। वहां भी ''समाजसेवा'' में नाकामी मिली तो फिर किसी ने सुझाया कि स्कूल खोल लें। समाजसेवा का एक तरीका यह भी है। इस तरीके में पैसा भी बनेगा और राजनीति में आगे बढ़ने के चांस भी बढ़ जाएंगे। बात जंच गई। लल्लू पहलवान ने धूमधाम से स्कूल खोल दिया। पिता की याद में नाम रखा-केपी पब्लिक स्कूल। बोर्ड पर यह भी लिखवाया-हमारे यहां हिंदी को पढ़ाई भी अंग्रेजी माध्यम से होती है। स्कूल में प्रवेश लेना बहुत ही आसान है। मुश्किलें तो उसके बाद शुरू होती हैं। इन मुश्किलों के बारे में लल्लू पहलवान का मानना है कि आसानी से प्राप्त चीज की कद्र नहीं होती।

केपी पब्लिक स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने के लिए एक प्रवेश फार्म मिलता है। कीमत सिर्फ एक हजार रुपये। यह फार्म स्कूल के काउंटर नंबर एक के अलावा पहलवान के जिम और दूध डेरी से भी प्राप्त किया जा सकता है। फार्म को एक विशेष प्रकार के पेन से भरना होता है। इसकी कीमत है फकत पांच सौ रुपये। फार्म और पेन खरीदने के बाद इसे आप खुद नहीं भर सकते। यह काम काउंटर नंबर पांच पर बैठा क्लर्क करेगा, जो इसके एवज में आपसे केवल दो सौ रुपये लेगा। फार्म पर आपको अपनी, बच्चे और अपने मकान की फोटो भी लगानी होगी। साथ ही अपने आयकर रिटर्न की कापी भी संलग्न करनी होगी। अब इसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बैंक खाते के कैंसिल्ड चेक के साथ जमा कर दीजिए। यह काम काउंटर नंबर नौ पर होगा। स्कूल से सिर्फ उन्हीं लोगों के पास फोन आएगा, जिनके फार्म पूरी तरह ठीक से भरे हुए होंगे। आपकी ये दलील किसी सूरत में मान्य नहीं होगी कि फार्म स्कूल क्लर्क ने ही भरा था। स्कूल से काल आने का पैसा भी आपको ही देना होगा। इसके बाद बच्चे और उसके माता-पिता का अंग्रेजी में इंटरव्यू होगा, जिसमें इंटरव्यू लेने वाला तो गूगल की मदद ले सकता है, किंतु देने वाला नहीं। इंटरव्यू के दौरान आपको चाय, काफी, नाश्ता, पानी आदि सब स्कूल की ओर से मिलेगा, मगर हर चीज का शुल्क देना होगा। इस दौरान यदि आपकी सेहत खराब हो जाती है तो स्कूल आपको चिकित्सकीय सुविधा भी शुल्क लेकर मुहैया करा सकता है। बच्चे का प्रवेश होने की सूचना आपको घर पर भेज दी जाएगी।

बच्चे के दाखिले के बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाना तो बनता ही है। इसके लिए आपको स्कूल परिसर में बने मंदिर की शरण में आना होगा। जहां स्कूल के पुजारी आपसे ग्यारह सौ रुपये दक्षिणा लेकर प्रसाद चढ़ा देंगे। अब असेंबली हाल से बच्चे की स्कूल ड्रेस, बेल्ट, कोट, स्वेटर, जूते-मोजे, टिफिन बाक्स, पानी की बोतल आदि सामग्री खरीदनी होगी। किताब-कापी, ज्योमेट्री बाक्स आदि स्टेशनरी का सेट लल्लू पहलवान की दुकान से भी उचित मूल्य पर खरीदा जा सकता है। बच्चे के लिए रिक्शा या स्कूल बस लगाना भी अनिवार्य है। ये सारी सुविधाएं पहलवान ट्रांसपोर्ट सर्विस में उपलब्ध हैं। साथ ही स्कूल द्वारा अधिकृत पार्लर पर ही बच्चे के बाल कटवाए जा सकते हैं। जूता फटने की स्थिति में नया खरीदना होगा। यदि प्रबंधन समझता है कि मरम्मत से काम चल जाएगा तो स्कूल से मान्यता प्राप्त मोची से काम कराना होगा। अंत में बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आपको स्कूल की तरफ से एक एल्युमिनियम का कटोरा भेंट किया जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है।

response@jagran.com

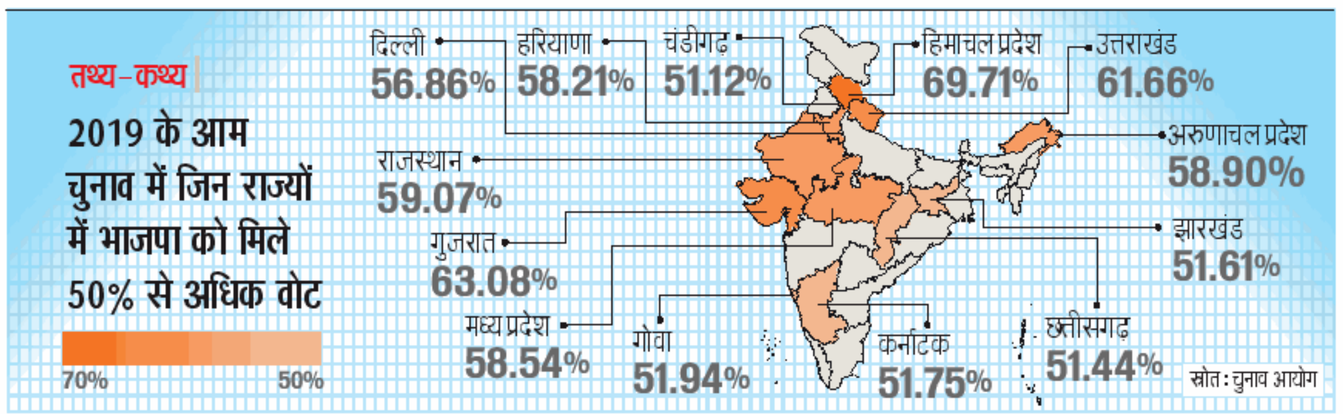

ऊर्जा

आत्मघाती शोर

वातावरण में व्याप्त शोर को लेकर प्रायः चिंता व्यक्त की जाती है। इसे नियंत्रित करने के कई वैज्ञानिक उपाय हो रहे हैं। शोर किसी को भी प्रिय नहीं, किंतु अन्य का। अवसर आने पर अपना किया शोर उल्लास का रूप ले लेता है। मनुष्य सारी अपेक्षाएं दूसरों से रखता है। स्वयं के पक्ष को प्रमाणित करने में उसे सिद्धता प्राप्त है। इसी कारण शोर निरंतर बढ़ता जा रहा है। शोर रुक नहीं रहा, क्योंकि इसके मूल स्रोत पर दृष्टि नहीं जा रही है।

वास्तविक शोर तो मन का है। मनुष्य के अंदर अथाह लालसाएं, कामनाएं पल रही हैं। एक लालसा पूर्ण होती है चार नई लालसाएं जन्म ले लेती हैं। पदार्थवाद और प्रतिस्पर्धा ने इसे और हवा दी है। मन में बस रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने मनुष्य के विवेक का हरण कर लिया है। उचित-अनुचित का उसे बोध ही नहीं रहा। अपनी क्षमता और योग्यता को अनदेखा कर वह सभी कुछ चाहता है, जो अपने संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों के पास देखता है। परिचित के पास कार है तो उसे भी कार चाहिए। यह लालसा अंदर का शोर है। कार क्रय कर लेना बाहर का शोर है। कार क्रय कर लेने मात्र से शोर थमता नहीं, बल्कि बढ़ जाता है। कार की सुरक्षा, उपयोग, इसमें लगी पूंजी का क्षय आदि अंदर और बाहर भी शोर उत्पन्न करते रहते हैं। जीवन दुखों से भर जाता है। शोर रुकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने उसे रोकने का यत्न ही नहीं किया है। इसके लिए संतोष, संयम और विवेक चाहिए, जो मन की सिद्धि से ही प्राप्त होता है। मनुष्य को जीवन इस शोर के लिए नहीं, उस परम आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, जो एकांत में परमात्मा का ध्यान करने से प्राप्त होता है। ध्यान तभी लगता है जब संसार का मोह विलुप्त हो जाए। मन की अंतर्दृष्टि जागृत हो जाए।

सुख और आनंद मन के अंदर हैं। इन्हें प्रकट करने के लिए मन को विकारों से रिक्त और संतोष, संयम से युक्त करना होता है।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

कृत्रिम कोशिकाओं से जगी उम्मीद

मुकुल व्यास

कृत्रिम कोशिका तकनीक हमें प्रकृति द्वारा किए गए कार्यों को दोबारा करने में सक्षम बनाएगी

हमारे शरीर के भीतर विभिन्न अंगों की कोशिकाएं विशिष्ट तरह के कार्य करती हैं। शोधकर्ता इन कोशिकाओं की खूबियों को कृत्रिम कोशिकाओं में उतारना चाहते हैं। नेचर केमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में नार्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शरीर की कोशिकाओं की तरह दिखने और कार्य करने वाली कृत्रिम कोशिकाएं बनाने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जीवन के आवश्यक निर्माण खंडों, डीएनए और प्रोटीन में हेरफेर करके ऐसी कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। इस तरह की उपलब्धि पहली बार हासिल हुई है। इससे रिजेनरेटिव मेडिसीन, शरीर में दवाओं की डिलिवरी और नैदानिक उपकरणों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। विज्ञानी ऐसे कपड़े या ऊतक बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो अपने पर्यावरण में बदलाव के प्रति संवेदनशील हों और गतिशील तरीके से व्यवहार करें।

कोशिकाएं और ऊतक खास प्रोटीनों से बनते हैं। कोशिका का ढांचा बनाने के लिए प्रोटीन आवश्यक होते हैं। इस ढांचे को साइटोस्केलेटन कहा जाता है। इसके बिना कोशिकाएं कार्य नहीं कर सकतीं। साइटोस्केलेटन कोशिकाओं को आकार और पर्यावरण की प्रतिक्रिया में लचीला होने की अनुमति देता है। शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक प्रोटीन का उपयोग किए बिना साइटोस्केलेटन के साथ कोशिकाएं बनाईं, जो आकार बदल सकती हैं और अपने परिवेश पर प्रतिक्रिया कर सकती हैं। इसके लिए एक नई पेप्टाइड-डीएनए तकनीक का उपयोग किया। पेप्टाइड एमिनो एसिड की छोटी सी शृंखला है।

डीएनए आम तौर पर साइटोस्केलेटन में प्रकट नहीं होता। विज्ञानियों ने डीएनए के अनुक्रमों की फिर से प्रोग्रामिंग की, ताकि वे वास्तुशिल्प सामग्री के रूप में कार्य करें और पेप्टाइड्स को एक साथ बांधें। इस प्रोग्राम की गई सामग्री को जब पानी की एक बूंद में रखा गया, तो संरचनाओं ने आकार ले लिया। इस तरीके से डीएनए की प्रोग्रामिंग करने की क्षमता का मतलब है कि विज्ञानी विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए कोशिकाएं बना सकते हैं और बाहरी तनावों के प्रति कोशिका की प्रतिक्रिया को भी ठीक कर सकते हैं। जीवित कोशिकाएं कृत्रिम कोशिकाओं की तुलना में अधिक जटिल हैं। उनका व्यवहार अधिक अप्रत्याशित होता है। जैविक कोशिकाओं के विपरीत कृत्रिम कोशिकाएं 50 डिग्री सेल्सियस पर भी स्थिर थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञानी असाधारण क्षमताओं वाली कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की कोशिकाएं मानव जीवन के लिए अनुपयुक्त वातावरण में भी कार्य कर सकेंगी। यह शोध हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी चीज जीवन बनाती है। यह कृत्रिम कोशिका तकनीक हमें प्रकृति द्वारा किए गए कार्यों को दोबारा करने में सक्षम बनाएगी।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

कौन बनेगा मंत्री

अभी चार चरणों का मतदान बाकी है और चुनाव परिणाम आने में तीन हफ्ते से अधिक का समय बचा है, लेकिन मोदी 3.0 में संभावित मंत्रियों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा मुख्यालय में अगली मोदी सरकार में कई मंत्रियों के पत्ते कटने और नए नेताओं को अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़कर किसी भी मंत्री का पद सुरक्षित नहीं है। बड़े मंत्रियों के विभागों में भारी पैमाने पर फेरबदल हो सकता है और जीतकर आने के बावजूद कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पार्टी गलियारों में ऐसे नेताओं के पक्ष और विपक्ष में तरह-तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, मगर हकीकत यह भी है कि इन नेताओं को भी नेतृत्व के मन की कोई थाह नहीं।

राजनीतिज्ञ नौकरशाह

सत्ता-सियासत में वैचारिक और राजनीतिक लाइन की जैसी साफ तस्वीर चुनावों के मौसम में दिखती है वैसी सामान्य दिनों में नजर नहीं आती। सामाजिक,

राजरंग

आर्थिक और कला की दुनिया के लोग भी किसी न किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध के बहाने अपनी राजनीतिक-वैचारिक धारा का खुलेआम इजहार करने से गुरेज नहीं करते। नौकरशाही के एक वर्ग की राजनीतिक निकटता की चर्चाएं होती हैं या सवाल उठते हैं, मगर ऐसा विरले ही हुआ हो कि अधिकारी किसी राजनीतिक सत्ता का खुलेआम समर्थक बनकर सामने आ जाएं। गत दिनों जब आयरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत अखिलेश मिश्रा का सरकार के शिखर नेतृत्व के बचाव में बयान आया तब विपक्षी दलों ने इसकी जमकर आलोचना की। कांग्रेस से लेकर वामपंथी दलों के नेताओं ने उनकी बर्खास्तगी की मांग तक कर डाली, लेकिन चुनाव में विरासत टैक्स लगाने का विवाद उठा तब एक बड़े अधिकारी ने एक्स पोस्ट पर कांग्रेस और उसके नेतृत्व की खिंचाई कर डाली। उन पर विपक्षी खेमे से कोई टिका-टिप्पणी नहीं आई। जब इसका कारण जानने की कोशिश हुई तो एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा कि यूपीए के दौर में ये उसके भी करीबी माने जाते थे।

काम का दबाव

चुनाव चरम पर है तो एक अधिकारी को फोन करके पूछा कि इन दिनों आप फुर्सत में होंगे। चाय पर चर्चा का समय तो होगा। इस पर तपाक से बोले, नहीं भाई, होमवर्क पूरा कर रहा हूं और जैसे-जैसे चुनाव खत्म होने के करीब आ रहा, इस होमवर्क को पूरा करने का तनाव बढ़ता जा रहा है। वैसे यह बच्चों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का होमवर्क नहीं, सरकार के दिए टास्क को पूरा करने की चुनौती है, क्योंकि चार जून को चुनाव परिणाम आने के बाद महकमों से कभी भी अपने भविष्य के एजेंडे का होमवर्क दिखाने को कहा जा सकता है। ऐसे में जोखिम लेने की गुंजाइश नहीं। फुर्सत तो चुनाव खत्म होने के बाद ही मिल पाएगी।

कोर्ट में राजनीति की चर्चा नहीं

चुनाव के मौसम में शायद ही कोई जगह राजनीति की चर्चाओं से अछूती हो और अदालत भी अपवाद नहीं। खासकर तब जब राजनीति के माहिर खिलाड़ी वकील के तौर पर दलील दें तो उनके मायने निकाले जाते हैं चाहे वे कितनी भी सफाई दे दें। हाल ही में शीर्ष अदालत में बंगाल सरकार और केंद्र के बीच का एक मामला चल रहा था तो राज्य सरकार की पैरोकारी कर रहे एक जानेमाने वकील और सांसद ने जज से पीएमएलए की जमीनी हकीकत देखने की बात कही। उनका इशारा आजकल मनी लांड्रिंग में तमाम नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की ओर था, मगर जज ने आगे मौका नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उन्हें टोका कि अपने केस के दायरे से बाहर न जाएं। वकील साहब कानूनविद् के साथ अनुभवी नेता हैं, सो तुरंत कहा हम अदालत में राजनीति और राजनीति में अदालत की चर्चा नहीं करते। न्यायाधीश भी उनकी चतुराई पर मुस्कुराए बिना नहीं रहे और कहा कि सांसदों से यह चीज वह सीखते हैं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

अनावश्यक संदेह

चौथे चरण के मतदान की तैयारी के बीच अनेक विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग को जिस तरह निशाने पर लिया जा रहा है, उसके पीछे सस्ती राजनीति ही अधिक दिखती है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में किन कारणों से समय लगता है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता उसे कठघरे में खड़ा करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तो इस संदेह तक भी पहुंच गए कि कहीं मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में कथित देरी का कारण चुनाव परिणामों को प्रभावित करना तो नहीं है? उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी गई अपनी चिट्ठी में उस पर अन्य अनेक आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने न केवल उनके सभी सवालों के विस्तार से जवाब दिए, बल्कि यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि वह भ्रम फैलाने और पक्षपातपूर्ण नैरेटिव खड़ा करने का काम जानबूझकर कर रहे हैं। खरगे ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि आखिर मतदान के दिन शाम को जारी होने वाले आंकड़े और कुछ दिन बाद बताए जाने वाले आंकड़ों में अंतर क्यों होता है? यह अनावश्यक प्रश्न है, क्योंकि ऐसा सदैव होता है और सभी को यह भी पता है कि ऐसा क्यों होता है। क्या नेतागण इससे अनजान हैं कि हर संसदीय क्षेत्र के पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी अपने बूथ के मतदान प्रतिशत की जानकारी सेक्टर अफसर के जरिये रिटर्निंग अफसर को भेजते हैं। फिर रिटर्निंग अफसर यह जानकारी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को भेजते हैं और इसके बाद उसे चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाता है? क्या यह प्रक्रिया चंद घंटों में पूरी हो सकती है? मल्लिकार्जुन खरगे की चिट्ठी के बाद जिस तरह विपक्षी दलों के कुछ नेता अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचे, उससे यही पता चलता है कि उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर हैरानी नहीं कि कुछ लोग अपनी शिकायतों को याचिका की शक्ल देकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। इनमें वे भी हैं, जो यह मांग कर रहे थे कि या तो मतपत्रों से चुनाव हों या फिर शत प्रतिशत वीवीपैट का मिलान किया जाए। यह और कुछ नहीं, उस जमाने में लौटने की कोशिश थी, जब मतपत्र और मतपेटियां लूटी जाती थीं और नतीजे आने में समय भी लगता था और संसाधन भी। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने शत प्रतिशत वीवीपैट के मिलान की मांग खारिज करते हुए ईवीएम पर भरोसा जताया, लेकिन उस पर संदेह करने वाले अभी चैन से नहीं बैठे हैं। उनकी ओर से ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार का सिलसिला कायम है। निःसंदेह चुनाव आयोग की किसी खामी या गलती पर उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी साख को चोट पहुंचाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाए जाएं।

कर्तव्य है मतदान

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब निर्णय की बारी जनता की है। सोमवार को राज्य में पांच सीटों पर मतदान होगा, जिसमें जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। पिछले तीन चरणों के चुनाव में मतदान प्रतिशत आशा के अनुरूप नहीं रहा है। यह आशा की जानी चाहिए कि मतदाता आने वाले चरणों में इसकी भरपाई कर जागरूकता का परिचय देंगे। चुनाव केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया भर नहीं है, अपितु एक मतदाता का वह अधिकार है, जिसमें स्वेच्छा से वह अपना प्रतिनिधि चुनता है। एक-एक वोट से ही कोई सरकार तय होती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मतदान के दिन इस अधिकार का प्रयोग करें। बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही जागरूक राज्य है, जहां लोगों में इसको लेकर व्यापक समझ है। सबसे बड़ी बात तो यह कि लोकतंत्र का प्रस्फुटन ही यहीं से हुआ, जब उस प्राचीन समय में भी निर्णय जनमत से होते थे। यहां की मिट्टी ने प्रजातंत्र की जो परिभाषा गढ़ी, उसे निरंतर मजबूती देना सभी का कर्तव्य है। यह तभी होगा, जब मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें होंगी। हर मतदाता इसके लिए उत्साहित होगा। यह ध्यान रखना होगा कि अपने अधिकार के प्रयोग के प्रति उदासीनता स्वयं पर ही भारी पड़ती है। मौसम भी ठीक हो चुका है। इसकी तैयारी अभी से कर ली जानी चाहिए कि मतदान के दिन पहला कार्य मत देना ही हो। निर्वाचन आयोग भी इसे लेकर लगातार अभियान चला रहा है। लोगों को जानकारी दी जा रही है। प्रशासन इसमें तत्परता से जुटा हुआ है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक-एक मतदाता तक पर्ची पहुंच जाए। मतदान केंद्रों पर पेयजल आदि की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद भी यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका निराकरण तत्काल किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है, महापर्व है।

विभिन्न सामाजिक-स्वयंसेवी संगठनों का भी दायित्व बनता है कि वे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से उनकी पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा?

आज का सवाल

क्या टी-20 विश्व कप में विराट कोहली को ओपनिंग करना चाहिए?

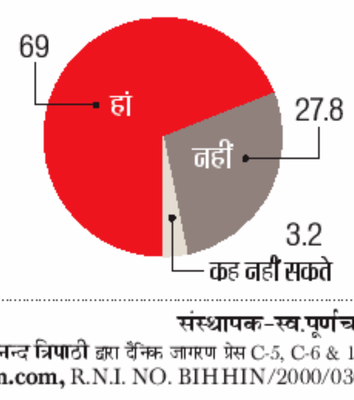

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कांग्रेस की मुसीबत बने बड़बोले नेता

संजय गुप्त

बात केवल नाना पटोले, मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा की ही नहीं है। कांग्रेस के कुछ और नेता भी पार्टी की किरकिरी कराने वाले बयान दे रहे हैं

कांग्रेसी नेता किस तरह अपने बेतुके बयानों से कांग्रेस का ही नुकसान करने में लगे हुए हैं, इसका ताजा उदाहरण हैं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया तो राम मंदिर का शुद्धीकरण किया जाएगा। उनके इस बयान पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर ही थी कि मणिशंकर अय्यर एक वीडियो में अपना पाकिस्तान प्रेम व्यक्त करते और यह कहते दिखे कि उसे सम्मान देना चाहिए और उससे बात की जानी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि बीते दस वर्षों में पाकिस्तान को कोई इज्जत नहीं दी गई। वह पहले भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुके हैं। नाना पटोले और मणिशंकर अय्यर के पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी की थी। उन्होंने भारत की आबादी की विविधता को विदेशी नस्लों से जोड़ कर यह बताया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैसे अलग-अलग देशों जैसे दिखते हैं। उनके हिसाब से दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकियों, पूरब के चीनियों, पश्चिम के अरबों और उत्तर भारत के श्वेतों जैसे दिखते हैं। वह एक तरह से भारत में विभाजन पैदा करने वाले उस आर्य-अनार्य सिद्धांत को भी हवा देते देखे, जिसे कुछ विदेशियों और वामपंथियों ने गढ़ा है। उनकी टिप्पणी में नस्ली सोच भी नजर आया। अमेरिका में रहने के नाते उन्हें यह अच्छे से पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में नस्ली टिप्पणियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। पिछली सदी में जब नस्ल के आधार पर समाज को बांटा जाता था, तब न जाने कितने ही गृहयुद्ध और युद्ध हुए और उनका दुष्परिणाम पूरे विश्व ने भुगता। न जाने कितने ही देश बिखर गए और करोड़ों लोगों को पीड़ा उठानी पड़ी।

जब कांग्रेस सैम पित्रोदा का बचाव करने की स्थिति में नहीं रही तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसे पार्टी ने तत्काल स्वीकार कर लिया, लेकिन यह कहना कठिन है कि इतने मात्र से वह राजनीतिक नुकसान से बच जाएगी। ध्यान रहे इसके पहले चुनाव के दौरान ही वह भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की पैरवी कर कांग्रेस के लिए कठिनाई खड़ी कर चुके हैं। कांग्रेस को उनके इस बयान से भी किनारा करना पड़ा था। इसके पहले 2019 में भी उन्होंने सिख विरोधी दंगों पर हुआ तो हुआ...वाली टिप्पणी करके कांग्रेस को उसी तरह नुकसान पहुंचाया था, जैसे 2014 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को कांग्रेस के दफ्तर में चाय की दुकान खोलने लायक बताकर पहुंचाया था। चूंकि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार भी रहे हैं, अतः यह माना गया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह

अवधेश राजपूत

विरासत टैक्स वाले सुझाव पर अमल कर सकती है। इस आशंका को इससे भी बल मिला, क्योंकि राहुल गांधी संपत्ति का सर्वे कराने की बात बार-बार कर रहे हैं। इसी कारण भाजपा विरासत टैक्स पर कांग्रेस को घेरते हुए उसके खिलाफ एक विमर्श खड़ा करने में सफल रही। सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को भारत के विचार के प्रतिकूल भी बताया। ध्यान रहे कांग्रेस नेता और खासकर गांधी परिवार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। इस परिवार के सदस्य अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं और जब द्रमुक के नेताओं ने सनातन धर्म को मिटाने की बातें की थीं, उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा था। इससे यही संदेश निकला कि वह अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रही है। इसका संकेत तब भी मिला, जब उसने घोषणा पत्र में पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया।

इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने के लिए किस तरह रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर समिति का गठन किया। इन दोनों ने मुस्लिम आरक्षण का आधार तैयार करने का ही काम किया। रंगनाथ मिश्र आयोग ने तो यहां तक पैरवी की थी कि उन मतांतरित दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस्लाम या ईसाइयत को ग्रहण कर लिया है। यह एक खतरनाक सुझाव था और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा भी। कांग्रेस तुष्टीकरण का खेल पहले भी खेलती रही है। सबसे शर्मनाक उदाहरण शाहबानो का मामला था। तुष्टीकरण के चलते ही आपातकाल के दौरान संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया और इसके बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकपरस्ती का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज तक कायम है। इसी के तहत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने समस्त मुस्लिम समाज को पिछड़ा मानकर ओबीसी आरक्षण दे दिया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति भी जताई, लेकिन कांग्रेस यह कहने को तैयार नहीं कि वह इस तरह मजहब के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। इस पर हैरानी नहीं कि भाजपा ने मजहब आधारित आरक्षण को एक मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के इतिहास में जाकर देखा जाए तो उसने वोट बैंक की राजनीति के लिए जाने-अनजाने कई बार समाज में खाइयां बनाने की कोशिश की है। इसी कारण उसका राजनीतिक रूप से पतन हुआ, लेकिन वह सबक नहीं सीख रही है।

बात केवल नाना पटोले, मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा की ही नहीं है। कांग्रेस के कुछ और नेता भी पार्टी की किरकिरी कराने वाले बयान देते चले आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमले के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के बारे में यह कह दिया कि वह पाकिस्तान आतंकी अजमल कसाब नहीं, बल्कि आरएसएस की विचारधारा वाले पुलिस अफसर की गोली का निशाना बने थे। जब इस बात का विरोध हुआ तो शशि थरूर ने आगे आकर यह मांग कर दी कि विजय वडेट्टीवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। क्या उन्हें नहीं पता कि जब इस मामले की जांच हुई थी, तब केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी? उस दौरान वह खुद मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे। बीते दिनों ही पंजाब कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ हमले को भाजपा की नौटंकी बता दिया। इससे तो यही पता चलता है कि कांग्रेस के नेता जो मन में आ रहा है, वह बोल दे रहे हैं। ऐसा शायद इसीलिए है, क्योंकि यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं।

response@jagran.com

नाकाम नेताजी की समाजसेवा

हास्य-व्यंग्य

कमल किशोर सक्सेना

लल्लू पहलवान के स्कूल में प्रवेश लेना बहुत ही आसान है। मुश्किलें तो उसके बाद शुरू होती हैं

लल्लू पहलवान के पिता कल्लू पहलवान का पुश्तैनी काम लूटमार करना था। सरकार से 'लोहा लेना' उनका प्रिय काम था। किसी ने सुझाया कि सरकार से लोहा ही लेना है तो राजनीति में प्रवेश कर जाएं। वह इस पर विचार कर ही रहे थे कि एनकाउंटर को प्राप्त हो गए। लल्लू पहलवान ने अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लिया। कुछ दिन गलत कामों में ''नाम'' कमाने के बाद वह राजनीति में उतरने का सोचने लगे। एक दल की सदस्यता भी ले ली, लेकिन उस दल में दाल नहीं गली तो दूसरे का हाथ थाम लिया। वहां भी ''समाजसेवा'' में नाकामी मिली तो फिर किसी ने सुझाया कि स्कूल खोल लें। समाजसेवा का एक तरीका यह भी है। इस तरीके में पैसा भी बनेगा और राजनीति में आगे बढ़ने के चांस भी बढ़ जाएंगे। बात जंच गई। लल्लू पहलवान ने धूमधाम से स्कूल खोल दिया। पिता की याद में नाम रखा-केपी पब्लिक स्कूल। बोर्ड पर यह भी लिखवाया-हमारे यहां हिंदी की पढ़ाई भी अंग्रेजी माध्यम से होती है। स्कूल में प्रवेश लेना बहुत ही आसान है। मुश्किलें तो उसके बाद शुरू होती हैं। इन मुश्किलों के बारे में लल्लू पहलवान का मानना है कि आसानी से प्राप्त चीज की कद्र नहीं होती। चाहे वह शिक्षा हो या ऊंटनी का दूध।

केपी पब्लिक स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने के लिए एक प्रवेश फार्म मिलता है। कीमत सिर्फ एक हजार रुपये। यह फार्म स्कूल के काउंटर नंबर एक के अलावा पहलवान के जिम और दूध डेरी से भी प्राप्त किया जा सकता है। फार्म को एक विशेष प्रकार के पेन से भरना होता है। इसकी कीमत है फकत पांच सौ रुपये। फार्म और पेन खरीदने के बाद इसे आप खुद नहीं भर सकते। यह काम काउंटर नंबर पांच पर बैठा क्लर्क करेगा, जो इसके एवज में आपसे केवल दो सौ रुपये लेगा। फार्म पर आपको अपनी, बच्चे और अपने मकान की फोटो भी लगानी होगी। साथ ही अपने आयकर रिटर्न की कापी भी संलग्न करनी होगी। अब इसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बैंक खाते के कैंसिल्ड चेक के साथ जमा कर दीजिए। यह काम काउंटर नंबर नौ पर होगा। स्कूल से सिर्फ उन्हीं लोगों के पास फोन आएगा, जिनके फार्म पूरी तरह ठीक से भरे हुए होंगे। आपकी ये दलील किसी सूरत में मान्य नहीं होगी कि फार्म स्कूल क्लर्क ने ही भरा था। स्कूल से काल आने का पैसा भी आपको ही देना होगा। इसके बाद बच्चे और उसके माता-पिता का अंग्रेजी में इंटरव्यू होगा, जिसमें इंटरव्यू लेने वाला तो गूगल की मदद ले सकता है, किंतु देने वाला नहीं। इंटरव्यू के दौरान आपको चाय, काफी, नाश्ता, पानी आदि सब स्कूल की ओर से मिलेगा, मगर हर चीज का शुल्क देना होगा। इस दौरान यदि आपकी सेहत खराब हो जाती है तो स्कूल आपको चिकित्सकीय सुविधा भी शुल्क लेकर मुहैया करा सकता है। बच्चे का प्रवेश होने की सूचना कूरियर का शुल्क लेकर आपको घर पर भेज दी जाएगी।

बहुत जतन और परिश्रम से बच्चे के दाखिले के बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाना तो बनता ही है। इसके लिए आपको स्कूल परिसर में बने मंदिर की शरण में आना होगा। जहां स्कूल के पुजारी आपसे ग्यारह सौ रुपये दक्षिणा लेकर प्रसाद चढ़ा देंगे। अब असेंबली हाल से बच्चे की स्कूल ड्रेस, बेल्ट, कोट, स्वेटर, जूते-मोजे, टिफिन बाक्स, पानी की बोतल आदि सामग्री खरीदनी होगी। किताब-कापी, ज्योमेट्री बाक्स आदि स्टेशनरी का सेट लल्लू पहलवान की दुकान से भी उचित मूल्य पर खरीदा जा सकता है। बच्चे के लिए रिक्शा या स्कूल बस लगाना भी अनिवार्य है। ये सारी सुविधाएं पहलवान ट्रांसपोर्ट सर्विस में उपलब्ध हैं। साथ ही स्कूल द्वारा अधिकृत पार्लर पर ही बच्चे के बाल कटवाए जा सकते हैं। जूता फटने की स्थिति में नया खरीदना होगा। यदि प्रबंधन समझता है कि मरम्मत से काम चल जाएगा तो स्कूल से मान्यता प्राप्त मोची से काम कराना होगा। अंत में बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ आपको स्कूल की तरफ से एक एल्युमिनियम का कटोरा भेंट किया जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ सकती है।

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मघाती शोर

वातावरण में व्याप्त शोर को लेकर प्रायः चिंता व्यक्त की जाती है। इसे प्रदूषण की श्रेणी में रखा गया है और नियंत्रित करने के कई वैज्ञानिक उपाय हो रहे हैं। शोर किसी को भी प्रिय नहीं, किंतु अन्य का। अवसर आने पर अपना किया शोर उल्लास का रूप ले लेता है। मनुष्य की विडंबना है कि वह सारी अपेक्षाएं दूसरों से रखता है। स्वयं के पक्ष को प्रमाणित करने में उसे सिद्धता प्राप्त है। इसी कारण शोर निरंतर बढ़ता जा रहा है। शोर रुक नहीं रहा, क्योंकि इसके मूल स्रोत पर दृष्टि नहीं जा रही है।

वास्तविक शोर तो मन का है। मनुष्य के अंदर अथाह लालसाएं, कामनाएं पल रही हैं। एक लालसा पूर्ण होती है चार नई लालसाएं जन्म ले लेती हैं। पदार्थवाद और प्रतिस्पर्धा ने इसे और हवा दी है। मन में बस रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने मनुष्य के विवेक का हरण कर लिया है। उचित-अनुचित का उसे बोध ही नहीं रहा। अपनी क्षमता और योग्यता को अनदेखा कर वह सभी कुछ चाहता है, जो अपने संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों के पास देखता है। परिचित के पास कार है तो उसे भी कार चाहिए। यह लालसा अंदर का शोर है। कार क्रय कर लेना बाहर का शोर है। कार क्रय कर लेने मात्र से शोर थमता नहीं, बल्कि बढ़ जाता है। कार की सुरक्षा, उपयोग, इसमें लगी पूंजी का क्षय आदि अंदर और बाहर भी शोर उत्पन्न करते रहते हैं। जीवन दुखों से भर जाता है। शोर रुकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने उसे रोकने का यत्न ही नहीं किया है। इसके लिए संतोष, संयम और विवेक चाहिए, जो मन की सिद्धि से ही प्राप्त होता है। मनुष्य को जीवन इस शोर के लिए नहीं, उस परम आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, जो एकांत में परमात्मा का ध्यान करने से प्राप्त होता है। ध्यान तभी लगता है जब संसार का मोह विलुप्त हो जाए। मन की अंतर्दृष्टि जागृत हो जाए।

सुख और आनंद मन के अंदर हैं। इन्हें प्रकट करने के लिए मन को विकारों से रिक्त और संतोष, संयम से युक्त करना होता है।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

तथ्य-कथ्य

2019 के आम चुनाव में जिन राज्यों में भाजपा को मिले 50% से अधिक वोट

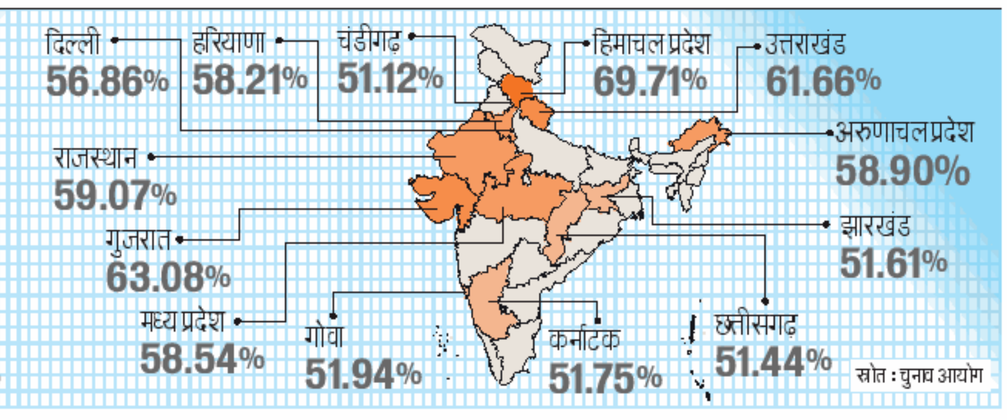

कौन बनेगा मंत्री

अभी चार चरणों का मतदान बाकी है और चुनाव परिणाम आने में तीन हफ्ते से अधिक का समय बचा है, लेकिन मोदी 3.0 में संभावित मंत्रियों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा मुख्यालय में अगली मोदी सरकार में कई मंत्रियों के पत्ते कटने और नए नेताओं को अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन अटकलों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़कर किसी भी मंत्री का पद सुरक्षित नहीं है। बड़े मंत्रियों के विभागों में भारी पैमाने पर फेरबदल हो सकता है और जीतकर आने के बावजूद कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। पार्टी गलियारों में ऐसे नेताओं के पक्ष और विपक्ष में तरह-तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, मगर हकीकत यह भी है कि इन नेताओं को भी नेतृत्व के मन की कोई थाह नहीं।

राजनीतिज्ञ नौकरशाह

सत्ता-सियासत में वैचारिक और राजनीतिक लाइन की जैसी साफ तस्वीर चुनावों के मौसम में दिखती है वैसी सामान्य दिनों में नजर नहीं आती। सामाजिक, आर्थिक और कला की दुनिया के लोग भी किसी न किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध के बहाने अपनी राजनीतिक-वैचारिक धारा का खुलेआम इजहार करने से गुरेज नहीं करते। नौकरशाही के एक वर्ग की राजनीतिक निकटता की चर्चाएं होती हैं या सवाल उठते हैं, मगर ऐसा विरले ही हुआ हो कि अधिकारी किसी राजनीतिक सत्ता का खुलेआम समर्थक बनकर सामने आ जाएं। इसमें भी दिलचस्प यह है कि गत दिनों जब आयरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत अखिलेश मिश्रा का सरकार के शिखर नेतृत्व के बचाव में बयान आया तब विपक्षी दलों ने इसकी जमकर आलोचना की। कांग्रेस से लेकर वामपंथी दलों के नेताओं ने उनकी बर्खास्तगी की मांग तक कर डाली, लेकिन चुनाव में विरासत टैक्स लगाने का विवाद उठा तब एक बड़े अधिकारी ने एक्स पोस्ट पर कांग्रेस और उसके नेतृत्व की खिंचाई कर डाली। राजदूत के मुकाबले ज्यादा हाईप्रोफाइल होने के बाद भी उनके इस राजनीतिक लाइन पर विपक्षी खेमे से कोई टिका-टिप्पणी नहीं आई। जब इसका कारण जानने की कोशिश हुई तो हल्के-फुल्के अंदाज में एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने कहा कि यूपीए के दौर में ये उसके भी करीबी माने जाते थे। फिर भला ऐसे मौसमी लोगों की बातों को तवज्जो देकर उनकी राजनीति को फलने-फूलने का मौका ही क्यों दिया जाए।

राजरंग

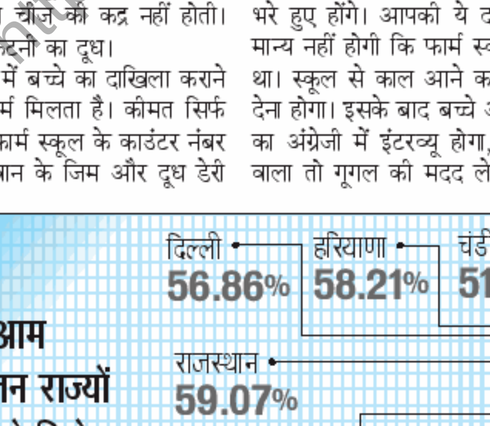

काम का दबाव

चुनाव चरम पर है तो एक अधिकारी को फोन करके पूछा कि इन दिनों आप फुर्सत में होंगे। चाय पर चर्चा का समय तो होगा। इस पर तपाक से बोले, नहीं भाई, होमवर्क पूरा कर रहा हूं और जैसे-जैसे चुनाव खत्म होने के करीब आ रहा, इस होमवर्क को पूरा करने का तनाव बढ़ता जा रहा है। वैसे यह बच्चों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का होमवर्क नहीं, सरकार के दिए टास्क को पूरा करने की चुनौती है, क्योंकि चार जून को चुनाव परिणाम आने के बाद सभी महकमों से कभी भी अपने भविष्य के एजेंडे का होमवर्क दिखाने को कहा जा सकता है। ऐसे में जोखिम लेने की गुंजाइश नहीं। चाय पर चर्चा की फुर्सत तो चुनाव खत्म होने के बाद ही मिल पाएगी।

कोर्ट में राजनीति की चर्चा नहीं

चुनाव के मौसम में शायद ही कोई जगह राजनीति की चर्चाओं से अछूती हो और अदालत भी अपवाद नहीं। खासकर तब जब राजनीति के माहिर खिलाड़ी वकील के तौर पर दलील दें तो उनके मायने निकाले जाते हैं चाहे वे कितनी भी सफाई दे दें। हाल ही में शीर्ष अदालत में बंगाल सरकार और केंद्र के बीच का एक मामला चल रहा था तो राज्य सरकार की पैरोकारी कर रहे एक जानेमाने वकील और सांसद ने जज से पीएमएलए की जमीनी हकीकत देखने की बात कही। उनका इशारा आजकल मनी लांड्रिंग में तमाम नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की ओर था, मगर जज ने आगे मौका नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उन्हें टोका कि अपने केस के दायरे से बाहर न जाएं। वकील साहब कानूनविद् के साथ अनुभवी नेता हैं, सो तुरंत कहा हम अदालत में राजनीति और राजनीति में अदालत की चर्चा नहीं करते। न्यायाधीश भी उनकी चतुराई पर मुस्कुराए बिना नहीं रहे और कहा कि सांसदों से यह चीज वह सीखते हैं।

पोस्ट

चुनाव आयोग द्वारा राज्यों के डीजीपी को सीधा हटा दिया जाता है या उनका पक्ष जानने के लिए कोई नोटिस भी दिया जाता है? जरूरी है उनका पक्ष भी जानना, अन्यथा शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका रहती है।

आरके विज@ipsvijrk

हालांकि कांग्रेस यह कह रही है कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें हटाया गया है।

आदेश रावल@AadeshRawal

हेमंत सोरेन को अंदर क्यों रखा गया है? केजरीवाल को जिन शर्तों के साथ छोड़ा है, उन्हीं शर्तों के साथ उनको भी छोड़ो। दिलीप मंडल@Profdilipmandal

एक बात साफ है कि मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कारों में आमूलचूल बदलाव किया है। इन्हें पारिवारिक पुरस्कार की पहचान से निकालकर जनता का पुरस्कार बना दिया है। इसके चलते ही हम एक-एक हीरे के बारे में जान पा रहे हैं।

सुहेल सेठ@Suhelseth

जापान को पीछे छोड़ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। अंकित कुमार अवस्थी@kaankit

जनपथ

नेता जी करते रहें एक नहीं सौ पाप,
उनकी खातिर तो सदा खून रहें सौ माफ।
खून रहें सौ माफ मिलेगी तुरत जमानत,
किंतु नागरिक आम झेलता रहता शामत।
दिल्ली में भी एक घटी है घटना ताजी,
करते दिखें प्रचार जमानत पा नेता जी!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 30

****

amarujala.com
अमर उजाला

नई जमीन

“ देश में रोजगार की मात्रा वस्तुओं व सेवाओं के लिए लोगों की प्रभावी मांग के स्तर पर निर्भर करती है। -जॉन मेनार्ड कीन्स

तकनीकी कारोबारों में रोजगारों का कत्लेआम मचा है। तकनीक की दुनिया के छोटे-बड़े सितारे कर्मचारियों को ऐसे निकाल रहे हैं, मानो प्रलय आ गई हो। इस साल ही दिग्गज तकनीकी कंपनियों में करीब 75,000 लोगों की नौकरी चली गई है। भारत में भी स्टार्ट-अप कंपनियां रोजगारों की कब्रगाह बन गई हैं।

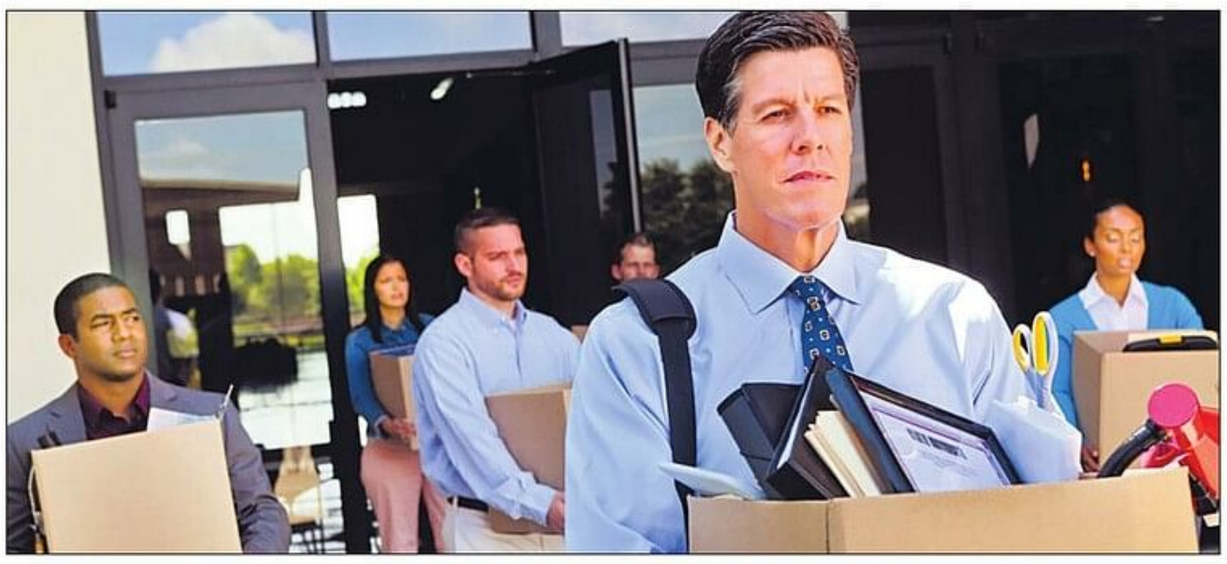

रोजगारों की कब्रगाह बनतीं कंपनियां

जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन जैक वेल्श ने ही मास ले-ऑफ यानी सामूहिक छंटनी की कुख्यात परंपरा शुरु की थी। 1980 से 1985 के बीच उन्होंने जीई में हर चार में से एक कर्मचारी को निकाल दिया। उन्होंने करीब 1.18 लाख कर्मचारियों की नौकरी ली।

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ लेखक-पत्रकार

टाइम मशीन
अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ■ हर पखवाड़े

नौकरी चाहने वालों के सपनों में जो कंपनियां बसती हैं, उनमें नौकरी करने वालों के सबसे बुरे सपने हकीकत बन गए हैं। गूगल ने एकमुश्त 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कहते हैं कि यह तो बड़ी छंटनी की शुरुआत भर है। टेस्ला वाले एलन मस्क करीब 6,000 कर्मचारियों को निकाल कर भारत आते हुए चीन पहुंच गए। बीते साल उन्होंने ट्वीटर (अब एक्स) के 4,000 लोग निकाले थे। मेटा वाले जुकरबर्ग ने बीते साल 11,000 लोगों को बेरोजगार किया।

तकनीकी कारोबारों में रोजगारों का कत्लेआम मचा है। तकनीक की दुनिया के छोटे-बड़े सितारे कर्मचारियों को ऐसे निकाल रहे हैं, मानो प्रलय आ गई हो। इस साल ही दिग्गज तकनीकी कंपनियों में करीब 75,000 लोगों की नौकरी चली गई है। भारत में भी स्टार्ट-अप कंपनियां रोजगारों की कब्रगाह बन गई हैं। बायजूस, चार्जबी, ओला, मीशो, कार 24, लीड, अनएकेडमी, ब्रेनली... रोजगारों को सूली पर चढ़ाने वालों की सूची बढ़ती जा रही है।

पूरी दुनिया के लोग मास ले-ऑफ की विपत्ति से वाकिफ हो चुके हैं। सामूहिक छंटनी को यह अभागा नाम अमेरिका में मिला था, जहां करीब 40 साल पहले तक इतने बड़े पैमाने पर एक साथ रोजगार खत्म नहीं किए जाते थे। तो रोजगारों का यह संहार आया कैसे? आइए, टाइम मशीन का कंडक्टर बुला रहा है, इंजन चालू है, सीट पकड़िए, उड़ चलते हैं अतीत में।

हम 1940 के दशक में पहुंच गए हैं। 1930 की महामंदी के बाद बेरोजगारी अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक खौफ बन चुकी थी। दूसरे विश्वयुद्ध के साथ अमेरिका में युद्ध संबंधी उत्पादन 40 फीसदी बढ़ गया। नई तकनीकें, नए रोजगार आए हैं, तो मंदी का दारिद्र्य दूर हो रहा है। इस कामयाबी से अमेरिकी नीति-निर्माताओं को महसूस हुआ कि सरकारी दखल से अर्थव्यवस्था की कायापलट हो सकती है। अमेरिकी अखबारों की सुर्खियां आपकी सीट के सामने की स्क्रीन पर तैर रही हैं। यह खबर फुल इंप्लायमेंट विधेयक के मसौदे की है और वक्त है 1945 का। पूर्ण रोजगार की सरकारी गारंटी देने के लिए कानून बनाने की तैयारी दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। इस विधेयक की प्रस्तावना में लिखा है कि अमेरिका के वे सभी लोग, जो स्कूलिंग पूरी कर चुके हैं और कोई घरेलू काम नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की फेडरल सरकार इस कानून के तहत उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। याद दिला दें कि स्टीफन केम्प बेली ने इस कानून पर एक किताब लिखी थी-*कांग्रेस मेक्स ए लॉ: द स्टोरी बिहाइंड द इंप्लायमेंट ऐक्ट ऑफ 1946।* यह किताब राजनीतिक क्लासिक की गिनती में आती है।

वैसे मसौदे से कानून तक आते-आते कई बदलाव हुए। रोजगार का वादा उतना दो टूक नहीं रहा, जितना मसौदे में था। कानून यह कहता था कि राज्यों और उद्योगों की मदद से अधिकतम रोजगार दिए जाएंगे और जनता की क्रयशक्ति (पर्चेजिंग पावर) बढ़ाई जाएगी। 20वीं सदी के आठ दशकों तक दुनिया के बाजारों को सामूहिक छंटनी यानी मास ले-ऑफ नाम की बला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

अब टाइम मशीन 1980 में आ गई है। व्हाइट हाउस में रोनाल्ड रीगन विराज रहे हैं। उनकी नई आर्थिक नीति और निजीकरण की मदद से अमेरिका का कॉरपोरेट क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। एयरलाइन बाजार में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स महत्वपूर्ण बन गए हैं। यही तकनीकी लोग आकाश से जमीन तक विमानों की आवाजाही संभालते हैं। फरवरी, 1981 में अमेरिका के एविएशन रेगुलेटर फेडरल एविएशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच नए वेतनमान और सुविधाओं को लेकर बातचीत शुरू हुई। कर्मचारियों और फेडरल सरकार के बीच विवाद की खबरें बढ़ रही हैं। यह जुलाई-अगस्त,1981 है। करीब छह महीने तक सौदेबाजी के बाद सरकार और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच बातचीत टूट गई है। करीब 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हड़ताल पर चले गए।

रीगन ने दो दिन में हड़ताल खत्म करने की चेतावनी दी और अब वह होने वाला है, जो अमेरिका में कभी नहीं हुआ। रीगन प्रशासन ने 13,000 कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया। फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने नई भर्ती शुरू कर दी। इस सनसनीखेज फैसले से अमेरिका में श्रम कानूनों का चेहरा-मोहरा बदल गया। अमेरिका के उद्योगों ने इस बदलाव को लपक लिया।

अब हमारी टाइम मशीन जनरल इलेक्ट्रिक के दफ्तर के करीब मंडरा रही है, जहां कंपनी के चेयरमैन जैक वेल्श नजर आ रहे हैं। अमेरिका के तेज-तर्रार सीईओ वेल्श की किताबें आगे प्रबंधन स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। वेल्श ने 1980 में जनरल इलेक्ट्रिक की कमान संभाली थी। उस वक्त जीई केवल बल्ब और कुछ घरेलू उपकरण बनाती थी। उन्होंने दस साल में जीई को अमेरिका की सबसे मूल्यवान कंपनियों में बदल दिया। वेल्श के नेतृत्व वाले 20 वर्षों में जीई 12 अरब डॉलर से 410 अरब डॉलर की कंपनी बन गई।

वेल्श ने ही मास ले-ऑफ यानी सामूहिक छंटनी की कुख्यात परंपरा शुरू की थी। 1980 से 1985 के बीच उन्होंने जीई में हर चार में से एक कर्मचारी को निकाल दिया और करीब 1.18 लाख कर्मचारियों की नौकरी ली। न्यूट्रॉन वेल्श!! कारोबार की दुनिया वेल्श को इसी नाम से बुला रही है। वह रोजगारों के बाजार में उस न्यूट्रॉन बम की तरह बन गए हैं, जो इमारतों या संपत्ति का ध्वंस नहीं करता, मगर लोगों की जान ले लेता है।

हम देख सकते हैं कि अमेरिका में मास ले-ऑफ तेजी से बढ़ने लगे हैं। यह क्या! 1990 में एटीएंडटी के सीईओ रॉबर्ट एलन ने 50,000 कर्मचारी निकाल दिए हैं। इस 'महान' कारोबारी सूझ के बाद उनके वेतन में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अखबारों के संपादकीय उन्हें लानतें भेज रहे हैं।

अब जरा सतर्क होकर बैठिए। हम मिलने जा रहे हैं रोजगारों के सबसे बड़े संहारक यानी अलबर्ट जे डनलप से। नौकरियों के विराट ध्वंस की कोई कहानी इनके बिना पूरी नहीं हो सकती।

यह 1990 के दशक के शुरुआती वर्ष हैं। कुख्यात और निर्मम कॉरपोरेट मैनेजर अलबर्ट जे डनलप ने मुनाफे के लिए कर्मचारियों को निकालना कॉरपोरेट प्रबंधन का हिस्सा बना दिया है। इस विध्वंसक रणनीति पर डनलप की किताब *मीन बिजनेस* खासी चर्चित रही है। यह बात दीगर कि *टाइम* पत्रिका ने 2010 में डनलप को अमेरिका के सबसे बुरे बॉस में शामिल किया था। *न्यूयॉर्क टाइम्स* के पत्रकार और लेखक लुइस अचिटेल की 2006 में आई चर्चित पुस्तक *द डिस्पोजल अमेरिकन: ले-ऑफ ऐंड देयर कन्सक्वेंसेज* 19वीं सदी के अंत से लेकर 2000 के दशक तक रोजगारों की छंटनी के संदर्भों से भरपूर है। 1990 और 2000 का दशक आते-आते कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी सामान्य हो चुकी थी। कॉरपोरेट प्रबंधन के इस तरीके को प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। लोगों ने नौकरियों की छंटनी को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। निकाले गए कर्मचारियों को यह महसूस होने लगा कि यही उनकी नियति है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी की सुर्खियों के बीच टाइम मशीन का यह सफर अब खत्म हो रहा है। क्या आप भी हैरत में हैं कि अरबों डॉलर के कारोबार, शानदार भविष्य और ग्रोथ की गारंटी देने वाली महाकाय कंपनियां चुनौतियों का छोटा-सा दौर भी झेल नहीं पातीं! वेल्श और डनलप के दौर में सामूहिक छंटनी करने वालों को अमेरिकी अखबारों में 'कॉरपोरेट किलर्स' जैसे विशेषण दिए जाते थे। आज जुकरबर्ग, एलन मस्क या बायजू रविंद्रन को इन्हीं नामों से बुलाया जा सकता है? *फिर मिलते हैं, अगले सफर पर...*

कैंसर का वह जो पहला मरीज था

कॉन्स्टेन्टाइन पैनेगिर्स

मनुष्य को कैंसर से लड़ते हुए 2,400 साल हो गए, लेकिन यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।

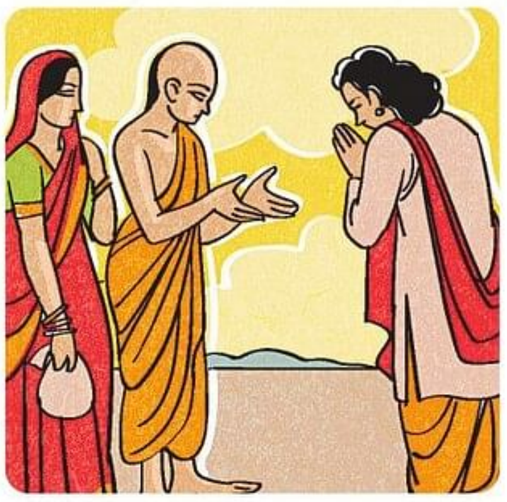

दुनिया में कैंसर का जो पहला मरीज था, उसका विवरण चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। काला सागर के नजदीक बसे हेराक्लिया नामक शहर के तानाशाह सैटिरस को कैंसर हुआ था। तब ऐसी कोई दवा ईजाद नहीं हुई थी, जो उसके दर्द को कम कर सके। आखिरकार 65 साल की उम्र में सैटिरस की जान कैंसर ने ले ली। तब तक लोग कैंसर से अपरिचित नहीं थे। ईसा पूर्व पांचवीं सदी के अंत या चौथी सदी की शुरुआत में लिखे एक ग्रंथ *डिसीजेज ऑफ वीमन* में स्तन कैंसर के विकसित होने की प्रक्रिया समझाई गई है। यूनानी शहर अब्देरा की एक महिला की छाती के कैंसर से मृत्यु हो गई, वहीं गले के कैंसर से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर द्वारा ट्यूमर जलाने के बाद बच गया। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी की शुरुआत में डॉक्टर घातक ट्यूमर को 'कार्किनो' कहते थे, जो प्राचीन ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है केकड़ा। कालांतर में लैटिन डॉक्टरों ने इस बीमारी को नाम दिया 'कैंसर', जो केकड़े को संदर्भित एक लैटिन शब्द है। आखिर कैंसर का नाम एक जानवर पर क्यों रखा गया? इसकी एक व्याख्या यह थी कि कैंसर भी केकड़े की तरह आक्रामक है और जैसे केकड़े के पंजों में फंसकर निकलना मुश्किल होता है, उसी तरह कैंसर से बचना कठिन है। ग्रीक-रोमन काल में कैंसर की वजहों को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं मिलती हैं। प्राचीन चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार, शरीर में चार अवयव होते हैं- रक्त, पीला पित्त, कफ और काला पित्त। इन चार अवयवों में संतुलन स्वस्थ होने की निशानी है। अगर किसी व्यक्ति में काले पित्त की अधिकता है, तो माना जाता था कि वह कैंसर ग्रसित हो सकता है। शुरुआत से ही यह समझ बन गई थी कि शुरुआती चरण में कैंसर को ठीक किया जा सकता है। कुछ औषधियां ककड़ी, पत्ता गोभी इत्यादि से बनाई गई थीं, वहीं केकड़े की राख व आर्सेनिक से भी कैंसर को हराने के प्रयास किए गए। ग्रीक-रोमन लोगों का मानना था कि रोगी को बार-बार उल्टी करा कर कैंसर को रोका जा सकता है। कैंसर वाले हिस्से को जलाने के भी प्रयास किए गए। पर कैंसर को लाइलाज ही माना गया। 5वीं शताब्दी में एक कुलीन महिला ने प्रार्थना की शक्ति से कैंसर ठीक करने का दावा किया, पर चिकित्सकों को भरोसा नहीं हुआ। पिछले 2,400 वर्षों में कैंसर को लेकर हमारे ज्ञान में बहुत बदलाव आए हैं। कैंसर 200 से भी ज्यादा प्रकार के होते हैं। ऐसे लोग भी प्रेरणा बने हैं, जो कैंसर प्रबंधन की बदौलत लंबे समय तक जीवित रहे। फिर भी अभी काफी शोध की जरूरत है।

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।।

अर्थात इस संसार में दिव्यज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथासमय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है।

- भीष्म पर्व, गीता 4/38
(अर्जुन के प्रति साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण का गीतोपदेश)

प्रस्तुति : विवेक चौरसिया

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

उषस्ति ने कहा, 'यदि मैं उड़द नहीं खाता, तो मेरे प्राण निकल जाते। इसलिए मैंने जूठे उड़द खा लिए। लेकिन पीने के लिए स्वच्छ जल मिल ही जाएगा। इसलिए अब तुम्हारा जूठा पीने से मुझे दोष लगेगा।'

आपद-काल में नहीं लगता कोई दोष

धूप आने दो

एक समय की बात है, जब कुरुदेश में बड़ी भयंकर ओला-वृष्टि हुई। राज्य की फसलें नष्ट हो गईं, वनस्पति को भारी क्षति हुई और प्रदेश में भयानक अकाल पड़ गया। भूख से पीड़ित प्रजा प्रदेश छोड़कर जाने लगी। उसी राज्य में उषस्ति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम आटिकी था। उषस्ति ने आटिकी के साथ राज्य छोड़ दिया। दोनों घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। उषस्ति और आटिकी ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। भूख के मारे दोनों का बुरा हाल था। उषस्ति की दशा ज्यादा खराब थी। उसे पता था, यदि उसे कुछ और समय भोजन नहीं मिला, तो निश्चित रूप से उसके प्राण निकल जाएंगे।

इसी बीच एक घर के सामने से गुजरते हुए उषस्ति ने देखा कि अंदर बैठा व्यक्ति उड़द खा रहा है। उषस्ति से रहा नहीं गया। वह घर के अंदर गया और उस व्यक्ति से थोड़ा उड़द देने को कहा। वह व्यक्ति बोला, 'आप ब्राह्मण हैं। मैं कुछ उड़द खा चुका हूं, इसलिए ये जूठे हो गए हैं। मेरे पास आपके लिए बिना जूठा उड़द नहीं हैं।'

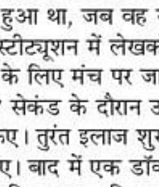

उषस्ति बोले, 'कोई बात नहीं। तुम यही उड़द मुझे दे दो।' उस व्यक्ति ने उषस्ति को थोड़े-से उड़द दे दिए। उषस्ति ने झटपट उड़द खा लिए। फिर जब उस व्यक्ति ने पीने के लिए पानी दिया, तो उषस्ति ने पानी पीने से मना कर दिया और कहा, 'मैं यह जल नहीं पी सकता, क्योंकि मुझे उच्छिष्ट-पान (जूठन खाने) का दोष लग जाएगा।'

उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, 'ब्राह्मण देवता, आपने मेरे जूठे उड़द तो खा लिए, फिर जूठा जल पीने में क्या आपत्ति है?'

उषस्ति ने कहा, 'यदि मैं उड़द नहीं खाता, तो मेरे प्राण निकल जाते। प्राणों की रक्षा के लिए उपाय करना आपद्धर्म कहलाता है। आपद्धर्म में किसी तरह का दोष नहीं लगता। लेकिन अब मेरे प्राणों पर कोई संकट नहीं है। मुझे पीने के लिए स्वच्छ जल मिल ही जाएगा। इसलिए अब तुम्हारा जूठा पीने से मुझे दोष लगेगा।' यह कहकर उषस्ति ने अपनी पत्नी को भी थोड़े-से उड़द दिए। आटिकी ने कुछ दाने खाकर अपनी भूख मिटाई और बचे हुए उड़द वस्त्र में बांधकर रख लिए।

अगले दिन उषस्ति ने पत्नी से कहा, 'मुझे पता लगा है कि इस राज्य का राजा यज्ञ कर रहा है और उसे ऋत्विज की जरूरत है। यदि राजा के पास जाऊं, तो शायद मुझे यज्ञ में कोई कार्य अवश्य मिल जाए, जिससे हमें थोड़ा धन प्राप्त होगा और हमारी स्थिति सुधर जाएगी।'

आटिकी ने तुरंत पिछले दिन के बचे हुए उड़द उषस्ति को दिए। उषस्ति उड़द खाकर राजा के यज्ञ में चला गया। वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मणों को यज्ञ-कर्म में कुछ भूल करते देखा, तो उषस्ति ने टोकते हुए कहा, 'क्या आपको पता है, आप जिन देवता की स्तुति कर रहे हैं, वे कौन हैं? यदि अधिष्ठाता को जाने बिना स्तुति करेंगे, तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा।' यह सुनकर सभी ऋत्विज उषस्ति की प्रशंसा करने लगे। राजा ने उषस्ति की बात सुनी, तो पूछा, 'हे ब्राह्मण! आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए।'

उषस्ति ने कहा, 'महाराज! मैं चक्र का पुत्र उषस्ति हूं।' राजा ने तुरंत नाम से पहचान लिया और हर्षित होकर कहा, 'आप ही उषस्ति हैं? मैंने आपका बहुत यश सुना है। मैंने यज्ञ आरंभ करने से पूर्व कुरुदेश में आपकी बहुत खोज की, किंतु आप प्रदेश छोड़कर जा चुके थे। इसलिए मुझे इस कार्य के लिए अन्य ऋत्विजों को बुलाना पड़ा। मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं यहां पधारे हैं। अब इस यज्ञ का समस्त कार्य आप ही संभालिए और इसे संपन्न कीजिए।'

उषस्ति ने कहा, 'महाराज! मैं यज्ञ तो कर दूंगा, परंतु आप इन ऋत्विजों को यज्ञ कार्य से मत हटाइए। मैं चाहता हूं कि ये लोग मेरे साथ मिलकर इस यज्ञ को संपन्न करवाएं और इन्हें भी मेरे बराबर ही दक्षिणा मिले।'

उषस्ति के स्नेहपूर्ण वचन सुनकर अन्य ऋत्विज प्रसन्न हुए और सबने मिलकर राजा का यज्ञ संपन्न करवा दिया।

अध्ययन कक्ष

नाइफ
मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर

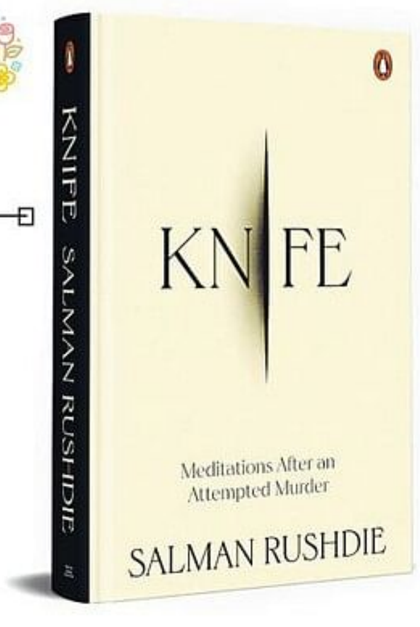

लेखक : सलमान रुश्दी

प्रकाशक : पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया
मूल्य : 506 रुपये
हार्डकवर

कट्टरता का चाकू

रुश्दी के साथ जो हुआ, वह मर्मांतक है। यह किताब कट्टरवाद के क्रूर चेहरे के साथ सच बोलने के खतरे के बारे में भी बताती है, लेकिन यह रुश्दी की यादगार कृति नहीं है।

12 अगस्त, 2022 को बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी पर तब हमला हुआ था, जब वह न्यूयॉर्क के शूटॉक्वॉ इंस्टीट्यूशन में लेखकों की सुरक्षा पर भाषण देने के लिए मंच पर जा रहे थे। हमलावर ने कुल 27 सेकंड के दौरान उन पर चाकू से 15 वार किए। तुरंत इलाज शुरू होने के कारण वह बच गए। बाद में एक डॉक्टर ने रुश्दी से कहा, जैसा कि वह इस किताब में जिक्र भी करते हैं, 'आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिसने आप पर हमला किया, उसे मालूम नहीं था कि चाकू से किसी व्यक्ति की हत्या कैसे की जा सकती है।' रुश्दी लिखते हैं, 'मेरे बाएं हाथ में गहरा घाव था। मेरी गर्दन में दो गहरे घाव थे। अगर मैं अपनी छाती की ओर देखता हूं, तो कई घाव दिखते हैं। दो और घाव दाईं ओर निचली तरफ थे और एक घाव दाहिनी जांघ के ऊपर था। मेरे मुंह के बाईं ओर एक घाव था और एक मेरे सिर पर था। एक घाव मेरी आंख में था, जो सबसे खतरनाक था, क्योंकि चाकू की धार ऑप्टिक नर्व तक धंस गई थी, यानी मेरी दृष्टि की वापसी की कोई संभावना नहीं थी।...चेहरे पर चाकू के एक हमले से वह नली नष्ट हो गई थी, जिससे मेरे मुंह में लार पहुंचता था। अब लार मेरे गाल से बह रहा था।'

रुश्दी को लंबे समय तक वेंटीलेटर पर रहना पड़ा। उनके शरीर में छोटे-छोटे बैग लगा दिए गए थे, ताकि रिसते खून और दूसरे द्रवों का बहाव रोका जा सके। उनका चेहरा इतना भयानक हो गया कि आईना दिखाने की इजाजत किसी को नहीं थी। सर्जरी के पंद्रह दिन बाद वह टहलने में सक्षम हुए, और बारह सप्ताह बाद घर लौट सके। इसके बाद भी उनकी थैरेपी चलती रही। रुश्दी लिखते हैं, 'भीषण चोट और जख्म की स्थिति में आपके शरीर की निजता का अस्तित्व खत्म हो जाता है।'

इस किताब में रुश्दी उस दिन की घटना और बाद के घटनाक्रमों का जिक्र तो करते ही हैं, यह भी बताते हैं कि पत्नी एलिजा, उनके परिवार, डॉक्टरों व फिजियोथेरपिस्ट की टीम तथा दुनिया भर में फैले अपने पाठकों और प्रशंसकों के प्रेम और समर्थन की वजह से वह स्वस्थ और सक्रिय हो पाए। रुश्दी हमलावर के बारे में बताते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए वह कट्टरवादी बना। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इस हमले का *द सैटेनिक वर्सेज* से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हमलावर ने तो उनका साहित्य पढ़ा ही नहीं है।

रुश्दी की इस किताब ने पत्रकार फिलिप लैंकॉन के संस्मरण *डिस्टरबेन्स* (2019) की याद दिला दी है, जो 2015 में *शार्ली हॉब्दो* पत्रिका पर आतंकी हमलों के बाद लिखा गया था। गौरतलब है कि *द सैटेनिक वर्सेज* के प्रकाशन पर ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने उनकी हत्या का फतवा जारी किया था। लगभग दो दशक से रुश्दी ने बाहर निकलना छोड़ दिया है, और वह न्यूयॉर्क सिटी में सामान्य जीवन जी रहे हैं। रुश्दी के साथ जो हुआ, वह मर्मांतक है। यह किताब कट्टरवाद के क्रूर चेहरे के साथ सच बोलने के खतरे के बारे में भी बताती है, लेकिन यह रुश्दी की यादगार कृति नहीं है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

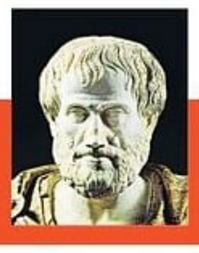

अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी।
- अरस्तु, महान दार्शनिक

गोल चबूतरा

Hindi@mithelesh

■ मिथिलेश बारिया

हंसी तो रुकी रही लबों पर...
वो आंसू ही था कमबख्त जो आंखों से निकल गया...

बहुत भीड़ थी उस बुजुर्ग के जनाजे में ...
कोई बड़ा पेड़ गिरने पर जैसे परिंदे निकल आते हैं ...

थार रेगिस्तान के द्वार का दिन

झरोखा
12 मई

आज के ही दिन थार के रेगिस्तान के बीचों-बीच शानदार महलों और दुर्गों के शहर जोधपुर की स्थापना हुई थी। जोधपुर शहर की स्थापना सन 1459 में राठौर कबीले के मुखिया राव जोधा ने की थी। आज भी इस शहर के पास शान की कई कहानियां हैं। पूरे शहर में वैभवशाली महल, किले और मंदिर, एक तरफ जहां ऐतिहासिक गौरव की गाथा कहते हैं, वही दूसरी ओर उत्कृष्ट हस्तकलाएं लोक नृत्य, संगीत और प्रफुल्ल लोग शहर में रंगीन समां बांध देते हैं। जोधपुर शहर को 'ब्लू सिटी' और 'सन सिटी' के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू सिटी इसलिए क्योंकि यहां के अधिकतर घर नीले रंग के हैं। वहीं सन सिटी, इसलिए क्योंकि विश्वभर में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा समय लगभग 8 घंटे 30 मिनट तक इसी शहर पर पड़ती हैं। जब राव जोधा ने जोधपुर शहर को बसाया तो इसे सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटुंक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया गया, जिसे जोधपुर के किले के नाम से जाना जाता है। वहीं पूरे शहर में 7 द्वार भी बनाए गए। इतिहासकार बताते हैं कि जंगली जानवरों और शहर की सुरक्षा के लिए दरवाजे नौ बजे के बाद बंद कर दिए जाते थे।

■ दिल्ली से लक्की सिंह

चुनाव हमारा सबसे बड़ा पर्व है। मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक मतदान संभव हो सके।

यह लोकतंत्र पर भरोसे की बात है

हमें करना ही चाहिए मतदान

चिट्ठी 1

अभी देश में चुनाव चल रहा है। सरकार और समाजसेवी संगठन अधिक से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। विशेष रूप से युवा मतदाताओं को इस राष्ट्रीय पर्व में भागीदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी अपीलें जारी करता है, लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी कुछ अपवादों को छोड़कर मतदान का प्रतिशत आदर्श स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है। कुछ क्षेत्रों में तो यह प्रतिशत बहुत ही कम होता है। अब उसमें भी एक बड़ी संख्या 'नोटा' पर वोट डाल रही है। सरकारी संस्थाओं, चुनाव आयोग और इससे संबंधित चुनावी अधिकारियों ने आज तक यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अधिक संख्या में देशवासी वोट डालने से कतराने क्यों लगे हैं? क्या वह लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते? या अब इस पर उनका विश्वास कम हो गया है? पूरे देश में मतदाता साक्षरता क्लब बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। लेकिन यह उद्देश्य तब ही पूरा हो सकता है, जब हम सभी देशवासियों को उनके मत का महत्व समझाने में सफल हों। विश्व में ऐसे कितने देश हैं, जहां लोकतंत्र को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। वहीं बहुत से देशों में केवल नाम का ही लोकतंत्र बाकी रह गया है, जबकि हमारे देश में आज भी स्वस्थ एवं स्वच्छ लोकतंत्र मौजूद है। पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था। जिसके लोकतंत्र की स्थिति को आप भली-भांति जानते हैं। इन सत्तर वर्षों में हमारे देश में कितनी सरकारें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आईं और गईं। आवश्यक है की देशवासियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए या शत-प्रतिशत मतदान के लिए कोई कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि सभी मतदाता कानूनन मतदान के लिए बाध्य हों।

■ डॉ. महताब अमरोहवी, अमरोहा

हर दिन 'मदर्स डे' क्यों नहीं!

चिट्ठी 2

आज मदर्स डे है। मां एक पवित्र शब्द है, जो सभी अलंकारों और परिभाषाओं से परे है। मां वह है, जो इस धरती पर साक्षात ईश्वर के रूप में मौजूद है। बस आवश्यकता है, उसकी महत्ता को समझने की और उसे सम्मान देने की। मां संस्कारों की वह गंगा है, जो अपने बच्चे को गर्भ से ही संस्कारों से सिंचित करती है। इसलिए हमें अपनी या किसी भी मां को कभी भी किसी भी हाल में दुख नहीं देना चाहिए। हमें अपने प्रति उसके निस्वार्थ प्रेम को विस्मृत नहीं करना चाहिए। हम पाश्चात्य सभ्यता की आधुनिक दौड़ में मां को भूल जाते हैं, उसके जीवन भर के उपकारों को चंद सिक्कों की खनक के आगे धूमिल कर देते हैं। इन्हीं वजहों से समाज में वृद्धाश्रमों का निर्माण हुआ है, जिसमें एक मां अपने बच्चों के होते हुए भी अलग- थलग रहकर अपने जीवन के शेष दिन इस उम्मीद में बिता देती है कि उसका बेटा किसी न किसी दिन उसे वापस लेने जरूर आएगा। कुछ के तो प्राण पखेरू भी इसी उम्मीद में उड़ जाते हैं। किसी एक दिन को मां के लिए 'मदर डे' के रूप में मना लेने भर से मां की ममता, उसके बिना शर्त प्रेम को, त्याग को या उसके किसी भी कार्य को तौला नहीं जा सकता है। यह सिर्फ एक दिखावा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि मां को हर दिन हृदय से सम्मान दिया जाए न कि किसी विशेष दिन। सोचिए, भला जिसने हमें जीवन दिया है, उसे हम क्या दे सकते हैं। मां तो वह है, जिसने ईश्वर को भी जन्मा है और ईश्वर भी मां के सामने उसका आशीर्वाद लेने के लिए नतमस्तक रहते हैं।

■ गौरव सक्सेना, इटावा

नर्सों को मिले उचित सम्मान

चिट्ठी 3

आज के ही दिन यानी 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक दयालु नर्स और समाज सेविका के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल दुनिया भर यह दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस का जन्म 12 मई, सन 1820 को उच्चवर्गीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था। इन्होंने ही नर्स के काम को दुनिया में नया आयाम दिया था। फ्लोरेंस ने क्रीमिया युद्ध में अपना फर्ज बखूबी निभाया था। उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज निर्भय होकर किया था। वह सैनिकों का इलाज करने के लिए रात के अंधेरे में लैंप लेकर जाती थीं, जिस कारण ही इन्हें 'द लेडी विद द लैंप' के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस ने नर्स के रूप में जो काम किया, उससे प्रेरित होकर सालों से लड़कियां और महिलाएं नर्सिंग को कॅरिअर के रूप में चुनती आ रही हैं। वैश्विक महामारी कोरोना और उससे पहले भी जो महामारियां आईं, उनमें भी डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का काम किया। इसलिए नर्सों को भी डॉक्टरों के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। सरकार को भी इनके भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे ये अपने देश में रहकर ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवाएं दे सकें। आज ढेर सारी महिलाएं नर्सिंग का कोर्स कर विदेशों का रुख कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में उनके काम को सम्मान नहीं मिल पाएगा।

■ राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

ललितपुर से डॉ. सुनील जैन संचय, फर्रुखाबाद से डॉ. विनोद कुमार तिवारी, रायपुर से संजीव ठाकुर, बांदा से आयूष कुमार वैश्य, लखीमपुर खीरी से सुरेश सौरभ, पटना से सरिता प्रसाद, गाजियाबाद से ललित शंकर, इलाहाबाद से सचिन कुमार सिंह, फिरोजाबाद से नितिन रावत, पटना से मुकेश कुमार मनन, शाजापुर से एमएम राजावतराज, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

अबू धाबी मंदिर में देवभूमि के सेवादार

मंदिर के निकास द्वार पर प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिलती है। खिचड़ी की खुशबू से भारत की याद आती है।

फरवरी 2024 में यूएई के अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पहले हिंदू मंदिर में विश्व के कई देशों में रहने वाले भारतीय तो दर्शन के लिए आ ही रहे हैं, दूसरे देशों के लोगों के लिए भी यह मंदिर दर्शनीय हो गया है। अबू धाबी सरकार ने इस क्षेत्र को 'कल्चरल डिस्ट्रिक्ट' का नाम देकर सनातन पद्धति का सम्मान ही किया है।

27 एकड़ जमीन पर निर्मित इस भव्य मंदिर के प्रमुख स्थल तक पहुंचने के लिए 86 सीढ़ियां हैं। बच्चों, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। मुख्य मंदिर में भगवान शंकर के परिवार के साथ ही राधा-कृष्ण लक्ष्मी-नारायण के अलावा श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की बेहद सुंदर व आकर्षक मूर्तियां विराजमान की गई हैं। मंदिर के सभी पिलरों पर सूर्य शंख व नवग्रहों की सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के खानपान के लिए भव्य रेस्तरां और सनातन पद्धति की जानकारी के देने की आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। जिसमें सनातन पद्धति से संबंधित पुस्तकों माला व मूर्ति आदि का सामान उपलब्ध हैं। अबू धाबी के हिंदू मंदिर में वहां की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा है। मंदिर प्रांगण में फोटोग्राफी वर्जित है और श्रद्धालुओं के लिए मर्यादित वस्त्र पहनना अनिवार्य है।

हिंदुओं के अलावा बड़ी संख्या में जॉर्डन, मस्कट और दुबई आदि स्थानों से मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंच रहे हैं। मंदिर के निकट अजबान रबहा नाम का एक गांव है। यहां पर रहने वाले 90 प्रतिशत लोग नौकरी-पेशा हैं।

एक और दिलचस्प बात यह है कि देहरादून के प्रेम नगर निवासी हर्षवर्धन अबू धाबी के हिंदू मंदिर में सेवादार के रूप में काम करके देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में हुई एक मुलाकात में हर्षवर्धन ने बताया कि वे पहले दुबई के होटल में काम करते थे। उनके अलावा मंदिर में अधिकांश सेवादार नेपाल और गुजरात के हैं।

■ अबू धाबी से लौटकर सुरेंद्र खुराना

एक से बढ़कर एक ओवरकोट

1936में डेनमार्क के एक कपड़ा व्यापारी एक अजीब लेकिन प्रभावी बिक्री योजना बनाई। उसने अपनी दुकान के चारों ओर 1,000 से भी अधिक ओवरकोट लटका दिए।

■ हिसार से राजेश कुमार

छायानट

'बनारसी बाबू' का गाना फिल्म 'डॉन' में

डॉन फिल्म 12 मई 1978 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एक गाना दशकों से लोगों को लुभाता रहा है-"खइके पान बनारस वाला ...।" इस गीत के लिए संगीत कल्याणजी-आनंदजी ने दिया था। लेकिन दिलचस्प किस्सा यह है कि वास्तव में यह गाना इस फिल्म के लिए नहीं था। यह गीत अंजान ने देव आनंद की फिल्म 'बनारसी बाबू के लिए लिखा था। लेकिन फिल्म बनने के दौरान इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर राजनारायण दुबे को विख्यात अभिनेता मनोज कुमार ने सलाह दी कि इस गीत को डॉन में रखना चाहिए। उनका कहना था कि इस फिल्म में यह गाना हिट साबित होगा। ऐसा ही हुआ। इस बेहतरीन गाने को रिकॉर्ड करते समय गायक किशोर कुमार को वास्तव में बार-बार पान चबाना पड़ा था। किशोर कुमार चाहते थे कि गाने के बोल वास्तविक लगें। जब गाने की शूटिंग चल रही थी, तब अमिताभ बच्चन ने एक-दो नहीं बल्कि 15-16 पान चबाए। अमिताभ चाहते थे कि पान उनके होठों को लाल करे और वैसी ही फीलिंग आए।

■ लोकेश सिंह, सिरसा

एक 'मजबूत' नेता क्यों बोलेंगे झूठ!

जिस प्रधानमंत्री को 370 या 400 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा था, वह अपने विरोधियों के बारे में इतनी लापरवाही से झूठ नहीं बोलेगा। झूठ को लड़ाई का एक मुख्य हथियार बनाना पीएम मोदी का रिकॉर्ड नहीं है। यह एक रहस्य है, जिसे सुलझाया जाना चाहिए।

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

माननीय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी हमेशा खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश करते हैं। वह अक्सर 56 इंच की छाती की बात करते हैं। उनके अनुयायी विरोध करने वाले पर लगाम लगाने, शहरी नक्सल को उखाड़ फेंकने, टुकड़े-टुकड़े गैंग को खत्म करने, पाकिस्तान को सबक सिखाने, अंग्रेजी को सहयोगी आधिकारिक भाषा की स्थिति से हटाने, मुख्यधारा की मीडिया को अपने इशारे पर नचाने और भारत को विश्वगुरु बनाने के उनके प्रयासों को अक्सर रेखांकित करते हैं।

जब एक मजबूत नेता, जिसके पास 330 सीटें लाने का अनुभव हो और जिसके 12 मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में प्रचार की कमान संभाले हुए हों, ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार की ओर बढ़ना और आसान हो जाना चाहिए। हालांकि भाजपा के नेता निजी तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं कि 370 या 400 से ज्यादा सीटें अब हासिल करना संभव नहीं दिखता। वे तो इस बात से ही खुश हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी साधारण बहुमत से ही जीत जाए।

चाल क्यों बदली ?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत बहुत ही विश्वास और दृढ़ता के साथ की। कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 अप्रैल, 2024 को जारी किया गया था, जिसे पीएम मोदी ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भाजपा का घोषणापत्र 14 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन इसमें निहित बातों के प्रचार की कोई कोशिश नहीं की गई। घोषणा पत्र का नाम ही 'मोदी की गारंटी' था। अपने घोषणापत्र की बातों को नजरअंदाज करते हुए मोदी ने जब भी किसी रैली में कोई बयान दिया, उसके साथ यह भी कहा कि 'यह मोदी की गारंटी है।' मैं मोदी की गारंटियों की संख्या गिनना भूल गया हूं। हालांकि, जो बात निकलकर सामने आई, वह यह है कि पीएम मोदी ने आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी कि बेरोजगारों के लिए 'रोजगार कैसे पैदा होंगे' या 'महंगाई कैसे कम होगी', इस पर कोई गारंटी नहीं दी। उन्होंने जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द, विकास, कृषि संकट, बहुआयामी गरीबी, वित्तीय स्थिरता, राष्ट्रीय ऋण, घरेलू ऋण, शैक्षिक मानक, स्वास्थ्य व्यवस्था, चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने के अलावा, अन्य दूसरे गंभीर मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं की।

19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के तहत 102 सीटों के लिए मतदान हुए। मतदान में थोड़ी गिरावट देखकर संभवतः इसलिए 21 अप्रैल को पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में हुई रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि "कांग्रेस वामपंथी और शहरी नक्सल के चंगुल में फंस गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो बातें कहीं वह भी काफी गंभीर और चिंताजनक है। कांग्रेस का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा। इस बात की भी जांच की जाएगी कि हमारी बहनों के पास कितना सोना है, सरकारी कर्मचारियों के पास कितना पैसा है? उन्होंने यह भी कहा कि "हमारी बहनों के पास मौजूद स्वर्ण आभूषणों को समान रूप से वितरित किया जाएगा। क्या सरकार को आपकी संपत्ति लेने का अधिकार है?" हम सिर्फ इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि 19 से 21 अप्रैल के बीच पीएम मोदी को कोई खुफिया जानकारी मिली हो, जिसने उन्हें अपनी चाल बदलने पर मजबूर कर दिया।

झूठ पर झूठ क्यों?

ऊपर दिए गए इस अंश में जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे झूठे हैं। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, झूठ बड़ा और अधिक अपमानजनक होता गया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संपत्ति से लेकर सोने, मंगलसूत्र और स्त्री धन से लेकर मकान तक, सब जब्त कर लेगी और उसे अधिक बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों और घुसपैठियों के बीच बांट देगी। एक अन्य रैली में, वे 'धर्म-आधारित आरक्षण' और 'विरासत कर' पर कूद पड़े। झूठ बोलने का कोई अंत नहीं था। इन बातों के तात्कालिक उद्देश्य स्पष्ट थे। यह सब मुस्लिमों की छवि खराब करने और मतदान का ध्रुवीकरण करने और हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए था।

प्रधानमंत्री द्वारा झूठ बोला गया, यह सोचने की बात है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री इस तरह के झूठ बोल क्यों रहे हैं? गौरतलब कि यह कोई एक झूठ नहीं है, झूठ की पूरी श्रृंखला है और लगातार जारी है। जिस प्रधानमंत्री को 370 या 400 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा था, वह अपने विरोधियों के बारे में इतनी लापरवाही से झूठ नहीं बोलेगा! वह विपक्षी दलों को अपने सबूत के साथ बहस में शामिल होने की चुनौती देंगे। झूठ को लड़ाई का एक मुख्य हथियार बनाना, पीएम मोदी का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक रहस्य है, जिसे सुलझाया जाना है।

आत्म संदेह क्यों ?

ऐसा लगता है कि पीएम मोदी को ईवीएम में बंद रहस्यों का पता था। उनकी चिंता के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जमीनी हालात 2019 की स्थिति से बहुत अलग हैं। सबसे पहली बात, पीएम मोदी चुनाव का नैरेटिव तय करने में सक्षम नहीं हैं। वह बहस की शुरुआत करने के बजाय कांग्रेस के घोषणापत्र पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, भले ही वह मनगढ़ंत हों। दूसरी बात, उनके वादे, कांग्रेस के वादों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। तीसरी बात, लोग भाजपा के थकाऊ नारों से नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी 'अच्छे दिन आने वाले हैं' जैसा कोई नया नारा गढ़ने में असमर्थ हैं। चौथी बात हो सकती है, कम मतदान प्रतिशत ने उनकी चिंता बढ़ा दी हो, क्योंकि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि भाजपा के कट्टर मतदाता मतदान केंद्रों पर आए ही नहीं। बूथों पर आरएसएस स्वयंसेवकों की गैरमौजूदगी और उनके शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ने भाजपा खेमे में खतरे की घंटी बजा दी होगी। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को ज्यादा फायदा हो। क्या इस तरह का 'लाभ' भाजपा के 'बड़ी हानि' होगी, यह लाख टके का सवाल है। यह भी संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर अब अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण साझा करें, क्योंकि 2024 का चुनाव सभी राज्यों में, अपवाद स्वरूप गुजरात को छोड़कर, विजेता का चुनाव नहीं है। पीएम मोदी ने यह निष्कर्ष निकाला होगा कि छद्म लाभ की जगह कुल हानि को गिनना चाहिए। शायद इसी बात ने उन्हें चिंता में डाल दिया होगा और उनके मुंह से झूठ निकलता जा रहा हो। मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता हूं कि लोग किस तरह से मतदान करेंगे, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि लोग मोदी के झूठ को समझ सकते हैं। शायद वे यह भी सोच रहे होंगे कि एक 'मजबूत' नेता को झूठ क्यों बोलना चाहिए?

व्यंग्य यात्रा रवींद्रनाथ त्यागी स्मृति सम्मान

खुला आकाश

- सुरेश कांत और अरविंद तिवारी को शीर्ष सम्मान, विभा रानी को शारदा त्यागी स्मृति सम्मान
- अनूप मणि त्रिपाठी सोपान सम्मान से सम्मानित

व्यंग्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रवींद्रनाथ त्यागी जी की स्मृति में 'व्यंग्य यात्रा रवींद्रनाथ त्यागी स्मृति सम्मान' वितरण समारोह का आयोजन हिंदी भवन भवन में किया गया। "व्यंग्य यात्रा रवींद्रनाथ त्यागी स्मृति शीर्ष सम्मान" सुरेश कांत और अरविंद तिवारी को प्रदान किया गया। 'व्यंग्य यात्रा रवींद्रनाथ त्यागी स्मृति सोपान सम्मान' युवा व्यंग्यकार अनूप मणि त्रिपाठी को प्रदान किया गया। 'व्यंग्य यात्रा शारदा त्यागी स्मृति सम्मान' प्रखर व्यंग्य नारी स्वर और नाट्यकर्मी विभा रानी को प्रदान किया गया। इस सम्मान के बहाने रवींद्रनाथ त्यागी जी के लेखन पर विस्तार से चर्चा हुई। आरंभिक वक्तव्य में मशहूर व्यंग्यकार प्रेम जनमेजय ने कहा, "व्यंग्य यात्रा का उद्देश्य व्यंग्य की विधा में विमर्श की जमीन तैयार करना है। व्यंग्य विमर्श को रेखांकित करने के लिए 'व्यंग्य यात्रा व्यंग्य चिंतक' सम्मान भी आरंभ किया गया है। इस सम्मान के लिए गौतम सान्याल का चयन किया गया। जल्द ही एक आयोजन में उन्हें सम्मानित किया जाएगा।" इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार बलराम ने की। पुरस्कृत साहित्यकार सुरेश कांत, अरविंद तिवारी, विभा रानी और अनूप मणि त्रिपाठी ने व्यंग्य विधा में रवींद्रनाथ त्यागी जी के योगदान पर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और चर्चित व्यंग्यकार व संपादक यशवंत व्यास ने व्यंग्य की सार्थकता पर बात करते हुए रवींद्रनाथ त्यागी जी के लेखन पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में उनकी सद्यः प्रकाशित पुस्तक 'मोहब्बत की दुकान' भी पुरस्कृत साहित्यकारों को भेंट की गई। इससे पहले, अपने स्वागत भाषण में त्यागी जी के पुत्र अशोक त्यागी ने अपने पिता से जुड़े कई दिलचस्प संस्मरण साझा किए।

अब जबकि तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं और एक दिन बाद 13 मई को चौथे चरण के चुनाव होने हैं, इस बीच दो मुद्दे मुस्लिम समाज से जुड़े हुए सामने आए हैं। आत्ममंथन और आबादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया समूह को दिए साक्षात्कार के दौरान मुस्लिम समाज से भावुक अपील की है कि वे आत्ममंथन करें कि अब तक जिन दलों ने उन्हें वोट बैंक बनाए रखा है, उन्होंने उनकी समग्र प्रगति के लिए क्या किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुस्लिम समाज दुनिया में बदल रहा है। यह बदलाव सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन आदि देशों में साफ दिखाई पड़ता है। खाड़ी के देशों में योग की ओर मुसलमानों का आकर्षण है, वे योग करते हैं, योग सिखने भारत आते हैं लेकिन भारतीय मुसलमानों ने योग को ही इस्लाम विरुद्ध मान लिया। सऊदी अरब में योग सरकारी सिलेबस का विषय है। जो विषय दुनिया के मुसलमानों के लिए इस्लाम विरोधी नहीं होता, जिसे वे अपनाते हैं, वही विषय भारत के मुसलमानों के लिए इस्लाम विरोधी क्यों हो जाता है? उन्हें समय के साथ बदलने से कौन विमुख रख रहा है? आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक, 1950 से 2015 तक की 65 साल की अवधि में बहुसंख्यक हिन्दू करीब 8 फीसदी घटे हैं और मुसलमानों की बढ़ोतरी 43.15 फीसदी हुई है। आबादी का यह असंतुलन चुनौतीपूर्ण, खतरनाक, चिन्ताजनक और विस्फोटक हो सकता है! खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है। दोनों विषयों-वोट बैंक नैरेटिव और आबादी विस्फोट का राजनीतिक आंकलन करता आजकल का यह अंक...

समग्रता में 'आत्ममंथन' की जरूरत

विश्लेषण
सुशील राजेश
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मुसलमानों से सीधे तौर पर संवाद कर आत्ममंथन की अपील की है। मुस्लिमों का दूसरा मुद्दा आबादी से जुड़ा है। 1951 में देश में करीब 3.5 करोड़ मुसलमान थे, जिनकी आबादी 2023 में बढ़ कर 20 करोड़ के पार हो गई। 1950 से 2015 तक की 65 साल की अवधि में बहुसंख्यक हिन्दू आबादी 84.68 फीसदी से घटकर 78.6 फीसदी हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84 फीसदी से बढ़ कर 14.09 फीसदी हो गई है। हिन्दू करीब 8 फीसदी घटे हैं और मुसलमानों की बढ़ोतरी 43.15 फीसदी हुई है। प्रधानमंत्री ने 'आत्मचिंतन' की नसीहत इसलिए दी है, ताकि मुसलमान सोच सकें कि जिन्होंने उन्हें वोट बैंक बनाए रखा, उन्होंने आखिर क्या दिया है? मुसलमानों को क्या फायदे मिले हैं?

आज हमारे सामने दो मुद्दे हैं। दोनों में मुस्लिम साझा बिन्दु हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार देश के मुसलमानों से ऐसी अपील की है, जो भावुक लगती है। दूसरा मुद्दा हिन्दू-मुसलमान की आबादी से जुड़ा है। फिलहाल भारत की जनसंख्या करीब 144 करोड़ है, जो विश्व में सर्वाधिक है। हालांकि 2021 में जनगणना नहीं की जा सकी, क्योंकि वह कोरोना वैश्विक महामारी का दौर था। जनगणना 2011 में की गई थी, उसके बाद 13 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन कोई अधिकृत जनगणना नहीं हुई है। 2011 में हिन्दू आबादी 79.80 फीसदी थी, जबकि मुस्लिम आबादी 14.20 फीसदी। मुसलमानों की बढ़ोतरी दर करीब 25 फीसदी थी, जबकि हिन्दुओं की बढ़ोतरी दर करीब 17 फीसदी। यानी हिन्दुओं की तुलना में मुसलमान ज्यादा बढ़ रहे थे। आज़ादी के बाद 1951 में देश में करीब 3.5 करोड़ मुसलमान थे, जिनकी आबादी 2023 में बढ़ कर 20 करोड़ के पार हो गई। अब तो यह आंकड़ा भी बदल चुका होगा! गौरतलब है कि 1951 से आज तक मुसलमानों की आबादी एक बार भी नहीं घटी, लगातार बढ़ती रही है। अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रपट के जरिये चौंकाने वाले आंकड़े और रुझान सामने आए हैं। रपट में 1950 से 2015 तक जनसंख्या के रुझान के आंकड़े दिए गए हैं। ये इस कालखंड में जनगणना के दौरान भी सामने आए होंगे तो फिर आर्थिक सलाहकार परिषद की ऐसी रपट तब क्यों सार्वजनिक की गई, जब आम चुनाव, 2024 के तीन चरण के मतदान सम्पन्न हो चुके हैं? लोकसभा की 282 सीटों, करीब 52 फीसदी, पर जनादेश ईवीएम में दर्ज हो चुका है। देश का एक तबका रपट को 'फर्जी' क्यों करार दे रहा है?

बहुसंख्यक आबादी घटी

रपट के मुताबिक, 1950 से 2015 तक की 65 साल की अवधि में बहुसंख्यक हिन्दू आबादी 84.68 फीसदी से घटकर 78.6 फीसदी हो गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84 फीसदी से बढ़ कर 14.09 फीसदी हो गई है। हिन्दू करीब 8 फीसदी घटे हैं और मुसलमानों की बढ़ोतरी 43.15 फीसदी हुई है। आबादी का यह असंतुलन चुनौतीपूर्ण, खतरनाक, चिन्ताजनक और विस्फोटक हो सकता है! भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, सर्बिया आदि देशों में आबादी के असंतुलन के कारण विभाजन देख चुका है। देश दोफाड़ हुए हैं और नए देश बने हैं। इंडोनेशिया कभी हिन्दू, बौद्ध बहुल देश था, लेकिन आज दुनिया के सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में ही रहते हैं और बौद्ध अल्पसंख्यक हो गए हैं। मलेशिया में भी मुसलमान सबसे ज्यादा तादाद में नहीं थे। रपट में भारत में मुसलमान आबादी के जो आंकड़े दिए गए हैं, उनमें वे शामिल नहीं हैं, जो जनगणना जैसे अभियानों का बहिष्कार करते रहे हैं। 65 साल की मुस्लिम आबादी में रोहिंग्या भी शामिल नहीं हैं। इस लिहाज

से मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी अधिक हो सकती है। रपट के मुताबिक, हिन्दुओं के साथ-साथ जैन और पारसी की आबादी भी घटी है। मुसलमानों के अलावा, सिख, बौद्ध, ईसाई की आबादी बढ़ी है। जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, सिख समुदाय भी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। देश में पारसियों की आबादी तो करीब 57000 बताई जाती है, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों के लिए जन-आंदोलन नहीं छेड़े। मुसलमान ही अल्पसंख्यक के तमाम फायदे उठाते रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती

मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती रही है, इसके बुनियादी कारण बांग्लादेश से घुसपैठ, धर्मान्तरण, मुस्लिम नेताओं, धर्मगुरुओं द्वारा ज्यादा बच्चे पैदा करने के आह्वान, 2011 तक ज्यादा प्रजनन दर, अशिक्षा, अज्ञानता आदि हैं। यह बढ़ोतरी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। देश के संसाधन कम पड़ सकते हैं। पहले घुसपैठ बांग्लादेश से अधिक हुई, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान विभाजन के साथ युद्ध भी हुआ। लोग बांग्लादेश से भाग कर भारत में आए। संघ-भाजपा 2 करोड़ से अधिक ऐसे घुसपैठिए मानते रहे हैं। जब म्यांमार से पलायन शुरू हुआ, तो रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत में घुसपैठ की। म्यांमार के बाद भारत में हिन्दुओं की आबादी में सर्वाधिक गिरावट हुई है। नेपाल भी बुनियादी तौर पर हिन्दू राष्ट्र है, लेकिन उसकी भी हिन्दू आबादी 3 फीसदी घटी है। रपट के मुताबिक, नेपाल में 84 फीसदी हिन्दू थे, लेकिन 1950-2015 के दौरान 81 फीसदी रह गए। रपट बताती है कि दुनिया में बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी 22 फीसदी घटी है। दुनिया में जिन देशों में हिन्दू और बौद्ध समुदायों की संख्या अच्छी-खासी थी, वह आबादी घट रही है। पाकिस्तान में करीब 80 फीसदी हिन्दू घटे हैं और बांग्लादेश में यह गिरावट करीब 66 फीसदी है। यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर हिन्दू आबादी लगातार कम क्यों होती जा रही है?

रिपोर्ट पर भी सवाल

सवाल समुदाय के लोगों की प्रजनन दर का भी है। दशकों तक मुसलमानों की औसत प्रजनन-दर 4-6 फीसदी रही, लेकिन अब 2021 वाले दौर में यह घटकर 2.36 फीसदी हो गई है। यह प्रजनन-दर हिन्दुओं में औसतन 1.94 फीसदी है। यह जनसंख्या-विस्फोट की स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जनसंख्या संबंधी कानून के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन एक सीमा के बाद उसे देश और समाज के विकास में रोड़ा भी मानते हैं। बहरहाल आबादी का यह असंतुलन इसी गति से जारी रहा, तो कई संकट उभर सकते हैं। चिंताजनक पहलू यह भी है कि भारत को किन राजनीतिक दलों की सरकारों ने घुसपैठियों की धर्मशाला बना दिया? आम चुनाव के दौरान सवाल तो इस रपट पर भी किए जा रहे हैं कि 2015 तक की रपट 2024 में सार्वजनिक क्यों की गई है? 2011 तक के अधिकृत आंकड़े तो देश के पास उपलब्ध हैं। मात्र 4 साल के अंतराल में जनसंख्या में कितने बदलाव हुए, यह आज 2024 में क्यों प्रासंगिक है? क्या आम चुनाव है, इसलिए राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं?

अपील भी नसीहत भी

बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ टीवी चैनलों को साक्षात्कार दिए थे। उनमें उन्होंने मुसलमानों को 'आत्मचिन्तन' करने की अपील भी की है और नसीहत भी दी है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज से सीधे संवाद किया है और उन्हें आत्मचिंतन करने की बात कही है कि अब तक कौन लोग, कौन दल रहे हैं, जो उन्हें केवल वोट बैंक मानते रहे हैं, उन्हें वे पहचानें। प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी का वोट बैंक या बंधक बनने के बजाय खुले दिमाग से सोचने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि एक सीधी लकीर की तरह वोट देना और वह भी हिन्दू-विरोध के नाम पर भाजपा जैसे राष्ट्रवादी दलों के खिलाफ मुसलमानों का वोट करना एक पूर्वाग्रही ट्रेंड है। प्रधानमंत्री का आशय इस ट्रेंड को बदलने की जरूरत से है। मुस्लिम वोट बैंक बन कर न रह जाएं, विवेक से मतदान का निर्णय करेंगे, तो न ही कोई उन्हें वोट बैंक जैसा व्यवहार करेगा, न ही उन्हें कोई छद्म डर से डरा सकेगा। यह समय मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टिकरण राजनीति करने वालों की पहचान करने का है और जो डर उनके मन में बिठाया गया है, उससे बाहर निकलने का है। अच्छी तादाद में मुसलमान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी भाजपा को वोट देते थे और आज प्रधानमंत्री मोदी के सूत्रवाक्य-'सबका साथ, सबका विकास...'का समर्थन करते हुए 12-15 फीसदी मुसलमान भाजपा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। यकीनन देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस अधिकांश समय सत्तारूढ़ रही। 1951 से 1975 तक तो कांग्रेस को कोई चुनौती ही नहीं थी, लिहाजा उसने अपनी चुनावी रणनीति के तहत मुसलमानों को 'वोट बैंक' की तरह बांधे रखा और दलितों, आदिवासियों, कुछ पिछड़ी जातियों में भी कांग्रेस के जनाधार बनाए। हालांकि केंद्र में वाजपेयी सरकार के 6 साल और मोदी सरकार के 10 साल के अलावा या तो कांग्रेस सत्ता में रही है अथवा बाहरी समर्थन से लड़खड़ाती सरकारें बनवाई हैं। जब कांग्रेस से अलग होकर या उसका विरोध करते हुए क्षेत्रीय दलों के उभार का दौर आया, तो मुसलमान सपा, बसपा, राजद और तृणमूल कांग्रेस की ओर भी ध्रुवीकृत हुए।

आंकलन वक्ती जरूरत

प्रधानमंत्री ने 'आत्मचिंतन' की नसीहत इसलिए दी है, ताकि मुसलमान सोच सकें कि जिन्होंने उन्हें वोट बैंक बनाए रखा, उन्होंने आखिर क्या दिया है? मुसलमानों को क्या फायदे मिले हैं? किसी प्रधानमंत्री ने शायद यह भी पहली बार कहा है कि यदि एक सांप्रदायिक वृत्तांत गढ़ने की कोशिश न की जाती और मुसलमानों के रहनुमा बनकर अपने खेमे में बांधे रखने की सियासत नहीं की गई होती, तो दौर उतने भयावह न होते! मुलायम सिंह को 'रामसेवकों' पर गोलियों की बौछार न करनी पड़ती! प्रधानमंत्री ने तीन तलाक से लेकर शाहबानों के संदर्भ भी उठाए। 'सच्चर कमेटी' के निष्कर्षों का भी जिक्र किया। सवाल नहीं, यह हकीकत है कि औसत मुस्लिमों को गरीबी, अशिक्षा, बदहाली और भुखमरी ही मिली। अब इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के जरिये वोट बैंक को भुनाने की सियासी कवायद जारी है, जिसके पलट जवाब में प्रधानमंत्री मोदी को अपने दलित, आदिवासी और ओबीसी समर्थक जमातों को विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सारांश यह है कि मौजूदा दौर में मुस्लिमों को अपनी स्थिति के बारे में सही मायने में 'आत्ममंथन' करने की जरूरत है।

क्या मुस्लिम समाज आत्मचिंतन करेंगे?

दो टूक
अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों से अपने राजनीतिक-सामाजिक व्यवहार पर आत्ममंथन करने की अपील पर गंभीर बहस होनी चाहिए। यह बात सही है कि लोकसभा चुनाव के बीच इस तरह की अपील के राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे और निकाले जा भी रहे हैं। भाजपा विरोधी यह कहकर हमला कर रहे हैं कि अपनी हार की डर से घबराकर मोदी ने मुसलमानों के सामने अपील की है । प्रधानमंत्री मोदी की छवि को विरोधियों ने ऐसे मुस्लिम विरोधी नेता की बनाने की कोशिश की है, जहां तनिक भी बाएं-दाएं दिखने पर उनकी ऐसी ही प्रतिक्रिया आती है। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के भारतीय मुसलमानों पर दिए गए वक्तव्य को किस रूप में देखा जाए? यह सच है जैसा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि मैंने पहले कभी इन विषयों पर बातचीत नहीं की। मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर ही लगाए गए। अपने मुख्यमंत्रीत्वकाल के आरंभ में अवश्य उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन बदलाव न दिखने पर इस विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। यह भी सच है कि उन्होंने पहली बार मुसलमानों से आत्ममंथन करने को कहा है। तो आखिर क्यों?

जनमत को विकृत किया

एक मीडिया समूह को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आप यदि यह सोचते रहेंगे कि सत्ता में किसे बिठाएंगे और किसे उतारेंगे, उससे अपने बच्चों का भविष्य ही खराब करेंगे। कोई चाहे इसे किस रूप में भी देखें स्वतंत्रता के बाद से पहले कांग्रेस और बाद में ज्यादातर पार्टियों ने वोट के लिए मुसलमानों के बीच जनमत को विकृत किया। दुर्भाग्य से मुसलमान समाज के पढ़े-लिखे लोगों में से बड़े वर्ग ने कभी इसका मूल्यांकन नहीं किया कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस और उसके बाद अन्य कई पार्टियों ने उनके अंदर डर पैदा कर वोट तो लिया पर उनके उत्थान, वास्तविक कल्याण या विकास के लिए जो करना चाहिए वह नहीं किया गया। ऐसे- ऐसे मुद्दे पार्टियों और सरकारों ने उठाए और उन पर काम किया जो भावनात्मक रूप से उनको छूते थे या उनके समाज में यथास्थिति को बनाए रखने वाले थे, जो उनके सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास में बाधक थे और मजहबी रूप से सच नहीं। इस चुनाव में भी लगभग यही हो रहा है। मुसलमानों के अंदर यह भय पैदा किया जा चुका है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में लौटी तो भारत में इस्लाम के लिए कयामत आ जाएगी, वो अपनी इच्छा अनुसार इस्लामी मजहब का पालन भी नहीं कर सकेंगे। यह पहला चुनाव है जहां मुसलमानों के अगुवा माने जाने वाले व्यक्तियों के बड़े समूह ने भाजपा को वोट न देने को दीन और ईमान का विषय बना दिया है। अगर समुदाय का बहुमत इस रूप में सोचता है कि एक पार्टी को सत्ता से हटाना ही इसका मुख्य कर्तव्य है और इसी में उसकी ऊर्जा और परिश्रम लग रहा है तो किसी का हित नहीं होगा। तो फिर?

आरोपों पर भी बातचीत

प्रधानमंत्री ने मुस्लिम विरोधी होने के आरोप पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि न हम इस्लाम के विरोधी हैं और न मुसलमान के। हमारा ये काम ही नहीं है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि मुसलमान इस पर विचार करें कि सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ उन्हें कांग्रेस के शासनकाल में क्यों नहीं मिला? अगर लाभ मिला होता तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए

सरकार को सच्चर समिति के माध्यम से मुसलमानों के हर क्षेत्र में पिछड़े होने की रिपोर्ट सामने नहीं लानी पड़ती। हालांकि सच्चर रिपोर्ट अतिवाद से भरी थी तथा तथ्यों के नाम से सामने रखे गए अनेक बिंदु विचारों और कल्पनाओं वाले थे। इसके बावजूद वह बताती थी कि उस समय तक की सरकारों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया या मुसलमान स्वयं उनके मतदाता के रूप में इस्तेमाल हुए, न उनका समुचित सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विकास हुआ न राजनीति के क्षेत्र में भी उस स्थान तक पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। भारतीय मुसलमानों के अगुवा वर्ग का एप्रोच सही होता तो उनकी मानसिकता बदलती और नरेंद्र मोदी सरकार दुश्मन नहीं नजर आती। इस सरकार के कार्यकाल में पंथ, मजहब, जाति या रंग के आधार पर सरकारी नीतियों में किसी तरह के भेदभाव का एक भी प्रमाण नहीं है। सच यह है कि भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं की तुलना में आबादी के प्रतिशत से ज्यादा लाभ सरकार की योजनाओं का मिला है।

साफ दिख रहा बदलाव

जो विषय दुनिया के मुसलमानों के लिए इस्लाम विरोधी नहीं होता, जिसे वे अपनाते हैं वही विषय भारत के मुसलमानों के लिए इस्लाम विरोधी हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है। यह बदलाव सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन आदि देशों में साफ दिखाई पड़ता है। ज्यादातर देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। जब नैरेटिव में फंसकर मानकर चलेंगे कि यह नेता और इसकी सरकार या पार्टी और संगठन परिवार मुस्लिम विरोधी ही है तो आप अपने संकुचित परिधि से बाहर नहीं निकल सकते। खाड़ी के देशों में योग की ओर मुसलमानों का आकर्षण है, वे योग करते हैं, योग सिखने भारत आते हैं लेकिन भारतीय मुसलमानों ने योग को ही इस्लाम विरुद्ध मान लिया। सऊदी अरब में योग सरकारी सिलेबस का विषय है। ऐसी अनेक बातें हैं जिनमें भारतीय मुसलमान के व्यवहार को देखकर हैरत होती है। उदाहरण के लिए एक साथ तीन तलाक का इस्लाम मजहब में कहीं स्थान नहीं है। शरीयत के अनुसार चलने वाले शासन के मुल्कों में भी अनेक ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ तीन तलाक को गैर इस्लामी घोषित किया हुआ है। मोदी सरकार ने इसके विरुद्ध कानून पारित किया और यह सही था, पर इसे मजहब के विरुद्ध घोषित कर आज भी मुसलमान के बड़े चेहरे आग उगलते रहते हैं। अनुच्छेद 370 का इस्लाम से क्या लेना देना था? जम्मू कश्मीर तो छोड़िए देशभर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इसे लेकर छाती पीट रहा है। गोहत्या निषेध मुसलमान के विरुद्ध कदम कैसे हो गया? समान नागरिक संहिता में किसी मजहबी कर्मकांड पर रोक नहीं है। लंबे समय से मुसलमानों के दिमाग में बिठा दिया गया कि समान नागरिक संहिता इस्लाम के विरुद्ध है।

समझने की जरूरत

इस तरह के नैरेटिव से मुस्लिम समाज को बाहर आने की आवश्यकता है। क्या प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद ऐसा लगता है कि भारतीय मुसलमान आत्ममंथन करेंगे और उन्हें वोट के रूप में देखने वाली पार्टियां ऐसा करने देंगी? इसकी उम्मीद कम है पर,मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि हमारे देश के बेईमान और पाखंडी नेताओं ने वोट के लिए सीधा अप्रोच यही बनाया कि उनके समाज के दोषों को दूर करने या उन्हें मुख्यधारा में लाने की जगह जहां जैसे हैं वैसे ही छोड़ दो और उनके हितैषी होने का प्रदर्शन करते रहो। बस रोजा के समय बड़ी इफ्तार पार्टियां दे दो, बड़े मुस्लिम चेहरों द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल हो जाओ आदि। इस तरह के तुष्टिकरण से ही आज तक उनका काम चल गया। क्या कभी मुसलमानों ने यह सोचा है कि इस तरह के व्यवहार से उन्हें प्राप्त क्या हुआ? कोई आपके लिए इफ्तार पार्टी न दे, आपके साथ नमाज अदा करने का नाटक न करे, आपकी टोपी न पहने, लेकिन आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, गरीब मुसलमानों के लिए उचित आवास दे, उनके घरों में बिजली और पानी पहुंचाए तो क्या उसे मुस्लिम विरोधी सरकार कहा जाएगा? नरेंद्र मोदी सरकार यही तो कर रही है। इसलिए मोदी ने जो कहा है उसे आम मुसलमान सकारात्मक दृष्टि से लें।

देश की एकता के लिए हो राजनीति

दरकार
सुरेश हिंदुस्थानी
राजनीतिक विश्लेषक

लोकसभा चुनाव के दौरान राजनेताओं के बयान सुनकर ऐसा लगने लगता है कि ये अपनी हदों को पार कर करने लगे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान की तारतम्यता यही है कि इस नेता ने भारत में भेद पैदा करने के प्रयास किए हैं। भारत में जिस सामाजिक विघटन की राजनीति की जा रही है, उससे समाज की शक्ति का लगातार पतन ही हुआ है। कभी तुष्टिकरण तो कभी वोट बैंक की राजनीति के बहाने सामाजिक एकता की राह में अवरोध पैदा करने के प्रयास किए गए, जिसके कारण भारतीय समाज के बीच जो विविधता की एकता को दर्शाने वाली परंपरा रही, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का अनवरत प्रयास किया गया। यह सभी जानते हैं कि जिस देश का समाज कम से कम राष्ट्रीय मामलों पर एक स्वर व्यक्त करता है, वहां किसी भी प्रकार के सामाजिक बिखराव के प्रयास धूमिल ही होते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को यह सामाजिक एकता अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाते हुए ही अपनी राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को भारत की सांस्कृतिक एकता खटकती है। ऐसे लोग कुत्सित राजनीति के माध्यम से भारतीय जनमानस में ऐसे बीज बोने का ही काम करते हैं, जो प्रथम दृष्टया विभाजनकारी ही कहे जा सकते हैं। ऐसे बयानों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए।

नफ़रत की दरार

राजनीतिक दलों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए पूर्व और पश्चिम को अलग पहचान के रूप में प्रचारित करने में जोर लगाया, तो वहीं उत्तर और दक्षिण के लोगों के मन में नफ़रत की दरार को और ज्यादा चौड़ा किया, जबकि हमारे देश के नायकों ने एक भारत के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। आज की राजनीति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि उनके सपनों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जा रहा। इसी कारण कहीं जातिवाद को हवा दी रही है तो कहीं तुष्टिकरण का प्रयास किया जा रहा है। जरूरत है हमारे राजनीतिक दल समाज को एक करने की दिशा में कदम उठाएं। इससे समाज का तो भला होगा ही, देश भी मजबूत होगा।

ऐसे बयान ही क्यों

वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अस्तित्व बरकरार रखने के जिस प्रकार का परिश्रम किया जा रहा है, वह निस्संदेह आवश्यक भी था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भी पार्टी के इस अभियान को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के

वरिष्ठ नेताओं में शामिल विदेशी अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, उसे अनजाने में दिया बयान समझकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सैम पित्रोदा कांग्रेस नेताओं के बहुत ख़ास रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी के विदेशी दौरे भी यही प्रबंधित करते हैं। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, उससे भारत की कांग्रेस ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन विदेशों में सैम पित्रोदा भारत को किस रूप में प्रस्तुत करते होंगे, इस बात का सहज़ अनुमान लगाया जा सकता है। सैम पित्रोदा के बयान का आशय यह भी निकाला जा सकता है कि वे भारत को एक देश के रूप में नहीं देख सकते। उनकी नजरों में शायद भारत की चारों दिशाओं में अलग अलग देश दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे ही बयानों के कारण कांग्रेस अपने अस्तित्व से जूझ रही है। कुछ इसी प्रकार के बयान कांग्रेस के अन्य नेता भी देते रहे हैं। एक बार मैंने अपने एक लेख में लिखा था, जिसका उल्लेख अन्य लेखक भी कर चुके हैं कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अनजाने में देश का विरोध करने लगती है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का आशय देश विरोध का नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते ही क्यों हैं, जिसका एक अर्थ ऐसा भी निकलता है, जिससे देश का विरोध होने का संकेत मिलता है।

पराजय का बोध नहीं

राहुल गांधी के इर्द गिर्द राजनीति करने वाले कांग्रेस के बड़े नेताओं के पलायन करने के बाद भी अगर शीर्ष नेतृत्व इस बात से अनभिज्ञ है कि कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? तो स्वाभाविक ही है कांग्रेस को अपनी पिछली दो शर्मनाक पराजय का बोध भी नहीं हो सकता। अभी तक के राजनीतिक इतिहास में अपने सबसे बड़े दुर्दिनों का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी समूहों में विभाजित होकर अवनति के मार्ग पर बढ़ती जा रही है। यह समस्याएं उसकी खुद की देन हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में कांग्रेस की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि आज की कांग्रेस में स्पष्ट दिशा और स्पष्ट नीति का अभाव सा पैदा हो गया है। राहुल गांधी युवाओं को आकर्षित करने में असफल साबित हुए हैं। इसमें उनकी अनियंत्रित बयानबाजी भी कारण है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार झूठे बयान दिए हैं, जिसमें वे माफी भी मांग चुके हैं। सबसे बड़ी विसंगति तो तब बनती है, जब अपने नेता के बयान को कांग्रेस के अन्य नेता समर्थन करने वाले अंदाज में निरर्थक रूप से पुष्ट करने का प्रयास करते हैं।

सफाई देने की स्थिति में नहीं

कांग्रेस अपनी कमियों को छिपाने के लिए भले ही भाजपा पर आरोप लगाने की राजनीति करे, लेकिन सत्य यह है कि इसके लिए कांग्रेस की कुछ नीतियां और वर्तमान में नेतृत्व की खामियां भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। बयानों की राजनीति के बीच कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर है। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेसी नेता सफाई भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे बयान भारत को शक्तिशाली बनाने से रोकते हैं, इसलिए यह आज की आवश्यकता है कि भारत को शक्ति संपन्न बनाने की राजनीति की जाए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid